राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या: 09

बुधवार,

02 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

नोखा के स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

124. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नोखा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकाम व कक्कू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सब-सेंटर भादला व भामटसर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) ग्राम मुकाम, पंचायत समिति नोखा एवं ग्राम कक्कू, पंचायत समिति पांचू जिला बीकानेर के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्रामों में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति नोखा एवं पांचू में आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/ गुणावगुण के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) ग्राम भादला एवं भामटसर पंचायत समिति पांचू जिला बीकानेर के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्रामों में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति पांचू में आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे दोनों पीएचसी मुकाम और कक्कू को सीएचसी में बदलने के लिए निदेशालय ने खुद तीन-तीन बार प्रस्ताव मांग रखे हैं और ये जनसंख्या आधार पर और नजदीक सीएचसी से दूरी के आधार पर भी सारे नोर्म्स पूरे करते हैं। इसी तरह सब-सेंटर भादला एवं भामटसर भी पूरे नोर्म्स तय करते हैं। आपने बजट में अन्य सैकड़ों सब-सेंटर को पीएचसी से सीएचसी में किया है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न, प्रश्न।

श्री बिहारीलाल (नोखा): जब मेरे सारे नियमों में आते हैं तो इनको भी शामिल करना चाहिये। खाली व्यक्ति या कोई चेहरा देखकर भी उसमें सलेक्ट किया जाता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं? प्रश्न पूछें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): जो मेरे पूरे मानदंडों में आते हैं, उनको करने का माननीय मंत्री जी इसमें पूरा प्रावधान करें और जनता को राहत पहुंचाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मानदंड के अनुसार आपके नोखा में 2 लाख की जनसंख्या है। वहां पर आपके एक है और एक की अभी कमी है, इसको हम स्वीकार करते हैं। परन्तु यह सभी जगह है, पूरे स्टेट में ही इस तरह की स्थिति है। जैसे-जैसे सीएचसी, पीएचसी के प्रावधान आयेंगे, उसके अनुसार उस समय विचार किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह मैं पहले ही कह चुका, जब भी बजट प्रावधान होगा तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवान पूनियां।

भादरा के किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान

125. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बलवान पूनियां)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्ष 2020-21 की रबी फसल का बीमा क्लेम की राशि का किसानों को भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व कितना भुगतान किया गया व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार की गणना के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त विधान सभा क्षेत्र के किसानों की रबी की फसलों की बीमित राशि कितनी तय हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 से हनुमानगढ़ जिले का फसल बीमा व्यवसाय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। रबी 2020-21 के लिए उक्त बीमा कम्पनी द्वारा भादरा विधान सभा क्षेत्र में अब तक 161 करोड़ 78 लाख रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान 58 हजार 901 फसल बीमा पालिसी धारक पात्र किसानों को किया गया है। शेष बीमा दावों का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज परिणामों में विसंगति बताते हुए अभी तक नहीं किया गया है। विभाग बीमा कम्पनी से शेष बीमा क्लेम का भुगतान करवाने हेतु लगातार प्रयासरत है।

(2) विभागीय अनुमान के अनुसार रबी 2020-21 के लिए भादरा विधान सभा क्षेत्र के लिए लगभग 505 करोड़ 62 लाख रुपये की बीमित राशि एवं 323 करोड़ 34 लाख रुपये का बीमा क्लेम फसल कटाई प्रयोगों अनुसार प्राप्त उपज के आधार पर योजना प्रावधानों के अंतर्गत तय हुआ है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, इस जवाब के अनुसार रबी 2020-21 का 164 करोड़ रुपये किसानों का बीमा क्लेम बाकी है। अध्यक्ष जी, सितम्बर में राज्य सरकार ने राज्यांश दे दिया था। तीन सप्ताह के बाद किसान का बीमा क्लेम आ जाना चाहिये था। अध्यक्ष जी, मेरी सीधी स्पष्ट मांग है 164 करोड़ रुपये मय ब्याज सरकार किसानों के खातों में कब तक डलवाने का काम करेगी?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 161 करोड़ 78 लाख रुपये के बीमा क्लेमों का भुगतान 58,901 फसल बीमा पालिसी बीमा धारकों को किया गया है और यह बात भी सही है कि यह जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इंडिया है, इन्होंने विसंगतियां बताते हुए

(श्री लालचन्द कटारिया)

पेमेंट को रोका है। राज्य सरकार और विभाग द्वारा भारत सरकार को लिखा गया और यह बात भी सही है कि भारत सरकार और राज्य सरकार, दोनों ने अपना-अपना राज्यांश और केन्द्रांश जमा करा दिया। यह कम्पनी 2019 से लगातार इन जिलों में काम कर रही है। अभी भी यह करीबन सात जिलों में काम कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने विसंगतियां बतायीं। भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फसल बीमा योजना के अधिकारियों ने दोनों ग्रुपों को बुलाया। हमारे राज्य के अधिकारी भी गये और भारत सरकार के और बीमा कम्पनी के, इन तीनों ने बैठकर, भारत सरकार ने हमारे फसल बीमा कटाई प्रयोग को सही माना और बीमा कम्पनी को निर्देशित किया कि वह लोगों को भुगतान करे, पर यह बताते हुए बड़ी तकलीफ है कि बार-बार पत्राचार करने के बाद और भारत सरकार का मेरे पास लिखित में भी है, उन्होंने इनको पाबंद किया है कि आप यह पेमेंट करो। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और 22.11.2021 को बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेमों का भुगतान गिरदावरी के आधार पर करने के कारण बीमा कम्पनी की शिकायत भारत सरकार से की गई। भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अध्यक्षता में दोनों पक्षों की बैठक 22.11.2021 को आयोजित की गई। भारत सरकार ने बीमा कम्पनी द्वारा गिरदावरी के आधार पर बीमा क्लेम बांटने को योजना प्रावधानों का उल्लंघन माना। भारत सरकार ने माना कि बीमा कम्पनी द्वारा उपज परिणामों पर देर से आपत्ति की गई है।

अत: भारत सरकार ने बीमा कम्पनी की समस्त आपत्तियों को निरस्त कर बीमा कम्पनी को निर्देश दिये हैं कि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर बीमा क्लेम संबंधित किसानों को दिया जाय। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और वहां के माननीय सांसद महोदय ने भी मुझे फोन किया था, वह भी प्रयासरत हैं। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं, समय तो मैं बता नहीं सकता, परन्तु निश्चित तौर पर हम यह क्लेम कम्पनी से करवायेंगे और जो 12 प्रतिशत ब्याज गाइडलाइन में है, वह भी दिलवाने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनें। 164 करोड़ का मसला है। 17.7.2019 को जो क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट दे दी गई, फसल बीमा में स्पष्ट प्रावधान है कि क्रॉप कटिंग ही फसल बीमा क्लेम का आधार है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न। श्री प्रताप सिंह। अंकित नहीं होगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। जब उन्होंने मान लिया, फिर बहस क्यों? अंकित नहीं होगा। श्री प्रताप सिंह।

धरना

CPI (M) के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

ल्हासी सिंचाई परियोजना से छबड़ा व छीपाबड़ौद को उपलब्ध पेयजल

126. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां की ल्हासी सिंचाई परियोजना से छबड़ा व छीपाबड़ौद को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परियोजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराने पर पुलिस थाना छबड़ा में मुकदमा तथा संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज करवायी गई है? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री महेश जोशी): (1) जी हां। बारां जिले की ल्हासी सिंचाई परियोजना अंतर्गत निर्मित बांध आधारित ल्हासी पेयजल परियोजना दिनांक 31.08.2016 को पूर्ण की जाकर छबड़ा एवं छीपाबड़ौद कस्बों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(2) जी हां। विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) श्री कैलाश चन्द जैन, निवासी चौधरी मौहल्ला, वार्ड नं. 17, छबड़ा द्वारा ल्हासी पेयजल परियोजना से कस्बा छबड़ा व कस्बा छीपाबड़ौद में अनुबंधक फर्म डारा कंस्ट्रक्शन एवं वितरण कम्पनी, राईबाग जोधपुर द्वारा निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति नहीं करने तथा लापरवाही करने बाबत पुलिस थाना छबड़ा में दिनांक 30.06.2021 को प्रथम सूचना

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थानाधिकारी, पुलिस थाना छबड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त प्रकरण वर्तमान में अनुसंधान में है।

(ब) दिनांक 28.06.2021 को स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा विभाग को छबड़ा कस्बे में स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसरण में, उक्त पेयजल परियोजना अंतर्गत निर्मित हैडवर्क्स खजूरिया स्थित जलशोधन संयंत्र एवं कस्बा छबड़ा स्थित स्वच्छ जलाशय तथा इसके अतिरिक्त परियोजना से पेयजल आपूर्ति के समय श्री कैलाश चन्द जैन, निवासी चौधरी मौहल्ला, वार्ड नं. 17, छबड़ा सहित कस्बे की अन्य कालोनियों एवं क्षेत्रों के 10 रहवासियों के घर स्थित नलों से विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2021 को जल प्रतिदर्श लिए जाकर, इनकी विभागीय प्रयोगशाला में जांच कराई गई। इन प्रतिदर्शों की जांच में पानी की गुणवत्ता तथा अवशेष क्लोरीन की मात्रा पेयजल हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई।

रासायनिक जांच रिपोर्ट दिनांक 02.07.2021 की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

उक्त पेयजल परियोजना अंतर्गत हैडवर्क्स खजूरिया में निर्मित जलशोधन संयंत्र में विभागीय मापदण्ड अनुरूप एलम डोजिंग, प्री एवं पोस्ट क्लोरिनेशन किया जाकर, कुल जल मांग 6.10 मिलियन लीटर प्रतिदिन के अनुरूप कस्बा छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

(कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा धरना समाप्त)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कांट्रेक्टर से जो एग्रीमेंट हो रखा है, उसके हिसाब से वहां पर कितने कर्मचारी लगने चाहिए और वर्तमान में कितने कर्मचारी लगे हुए हैं? मंत्री महोदय, कृपया उनका नाम, पता, कहां के रहने वाले हैं, यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। आप कहां जा रहे हैं?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरा दूसरा निवेदन यह है कि ल्हासी डैम, जहां से पानी की सप्लाई होती है, क्या वहां पर प्री-क्लोरिनेशन करने के लिए क्लोरिनेटर है? यदि हां, तो कब लगाया गया और अगर नहीं लगाया गया है

(श्री प्रताप सिंह)

तो संवेदक के खिलाफ विभाग ने क्या कार्यवाही की, यह भी बताने की कृपा करें।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल की गुणवत्ता के लिए तीन तरह के मानक होते हैं। एक पैरामीटर डब्ल्यूएचओ का है, एक ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्ड (आईएमआईएस) का है और तीसरा केन्द्रीय जल स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन का है। जहां तक गुणवत्ता की बात है, तीनों मानकों के अनुसार गुणवत्ता रिपोर्ट ठीक पायी गयी है। डारा कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की लिस्ट दे रखी है, वह भी अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। डी-क्लोरिनेशन नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि पेयजल की गुणवत्ता है, उसको हम नियंत्रित कर पाते। आपने मेरे से जो जानकारी चाही है, At present वह जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि दिनांक 30.06.2021 को छबड़ा के चेयरमैन श्री कैलाश चन्द जैन ने संवेदक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। गंदा पानी आ रहा था, कीड़े निकल रहे थे, इसलिए मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने फर्म से सैम्पल लिया और मैंने अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके अनुसार अधिकारियों के खिलाफ डायरेक्ट मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता था। इसलिए डीजी साहब से बात की, डीजी ने कहा कि आप परिवाद दे दें, हम उसकी एक महीने में जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन करते जा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसमें जो एक पार्ट छूटा है, वह यह है कि छबड़ा थाने में 30.06.2021 को एफआईआर दर्ज करायी। वह अभी अनुसन्धान के अन्तर्गत है। इसका निस्तारण पुलिस किस तरह से कर रही है कि इतने महीनों के बाद भी अनुसन्धान अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसन्धान गुणवत्ता के लिए किया गया। आईपीसी की धारा 269, 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। डिपार्टमेन्ट ने पानी की गुणवत्ता

(डा. महेश जोशी)

रिपोर्ट पुलिस को मुहैया करा दी। उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पायी, उस पर एफआईआर लगनी चाहिए थी, नहीं लगनी चाहिए थी, इस पर फैसला होना चाहिए था। हम इस बारे में विभाग की तरफ से डीजी, पुलिस को लिखेंगे। वे इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करके जो भी अन्तिम निष्कर्ष हैं, उस पर पहुंचे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही में डी एम एफ टी से स्वीकृत कार्य

127. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सिरोही में जिला मिनरल फंड की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा विगत तीन वर्षों में कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन से कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला मिनरल फंड में एकत्रित धन का विगत तीन वर्षों में क्या उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जिला सिरोही में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 15.02.2022 तक) में अनुमोदित किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त में से 32 कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट में संग्रहित राशि का वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 15.02.2022 तक) में किये गये उपयोग का मदवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, खान मंत्री जी ने सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में 24 दिसम्बर, 2020 को गवर्निंग काउंसिल की बैठक में जो स्वीकृतियां प्रदान कीं, मैं आपके माध्यम से उनसे

(श्री संयम लोढ़ा)

पूछना चाहता हूं कि सिलिकोसिस हास्पिटल की नवीन बिल्डिंग सिरोही, आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, कुपोषण एवं एनीमिया से ग्रसित बच्चों एवं महिलाओं को प्रोटीनयुक्त पूरक आहार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपला गोलिया, तेलपी खेड़ा, कृष्णगंज में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, विरीकी नाला डायवर्जन कार्य, ग्राम बलवंतगढ़, ग्राम पंचायत पाडीव, स्वरूपगंज-कृष्णगंज सड़क से केर दियाणजी सड़क डामरीकरण कार्य, बोगरा एनिकट गांव तेलपी खेड़ा संधारण कार्य।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। यूं लिस्ट नहीं, आप प्रश्न पूछें। लिस्ट करेंगे तो अन्तर कहां से होगा? आप यह कहें कि ये काम बाकी हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं प्रश्न ही पढ़ रहा हूं। जो स्पेसिफिक काम चालू नहीं हैं, वही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप वही सीधा पूछें कि गवर्निंग काउंसिल में जो पास हुए, वे शुरू क्यों नहीं हुए? सबको लिस्ट करने की जरूरत कहां पड़ रही है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, लम्बी संख्या है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज ब्रीफ करें। ऐसा नहीं। आपको दो प्रश्न पूछने हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप दस मिनट बोलें। आप सीधा पूछें कि गवर्निंग काउंसिल में जो पास हुए हैं। वे शुरू हुए या नहीं हुए? बात खतम हुई। उसको लिस्ट करने से क्या मतलब है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गवर्निंग काउंसिल के सारे काम नहीं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं। क्या आपको प्रश्न पूछना है? प्रश्न पूछें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जो दो करोड़ रुपये से ज्यादा के काम स्टेट को भेजे गये थे, वे चालू नहीं हुए। वे कब तक चालू हो जायेंगे?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही में डीएमएफटी के माध्यम से जो कार्य स्वीकृत हुए उसका विवरण परिशिष्ट-1 पर दिया गया है। इनमें से 32 कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं, उसका विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिन कार्यों के शुरू नहीं होने का उल्लेख किया है, ऐसे 12 कार्य हैं, जिनकी कुल लागत 39 करोड़ 65 लाख

(श्री प्रमोद भाया)

रुपये है। मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को आश्वस्त करता हूं कि स्वीकृत कार्यों के प्रति सरकार गम्भीर है और हमारा प्रयत्न रहेगा कि इसी वर्ष 2022 में ही इन कार्यों को शुरू करवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): गवर्निंग काउंसिल 24.12.2020 को हुई है, उसका रेफरेंस दिया है। इसके पहले जो 17.04.2018 से स्वीकृत थे, उन सबको एक ही स्टाक में निरस्त करने का आधार क्या था?

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, यह अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के लाभार्थी

128. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला राजसमन्द की तहसीलों में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों के कितने कार्य स्वीकृत किए गए एवं उक्त कार्यों पर स्वीकृत एवं वास्तविक परिव्यय कितना हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की ग्राम पंचायतों में उक्त अवधि में व्यक्तिगत लाभार्थियों को उक्त योजना के अंतर्गत कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किए गए? उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो गए व उन पर वास्तविक परिव्यय कितना हुआ तथा इनसे कितने श्रम दिवस सृजित हुए?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में उक्त अवधि में उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन व्यक्तिगत लाभार्थियों को कितनी राशि के किस प्रकार के कार्य स्वीकृत किए गए व स्वीकृत कार्यों की प्रगति की क्या स्थिति है? उक्त कार्यों से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जिला राजसमन्द की तहसीलों में वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों के 14706 कार्य स्वीकृत किये गये, उक्त कार्यों पर स्वीकृत राशि रुपये 4531.89 लाख के विरुद्ध राशि रुपये 1720.32 लाख का व्यय किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की ग्राम पंचायतों में उक्त अवधि में व्यक्तिगत लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत राशि रुपये 409.64 लाख के 1482 कार्य स्वीकृत किये गये। उक्त स्वीकृत कार्यों में से 635 कार्य पूर्ण हुए हैं, जिन पर राशि रुपये 218.76 लाख का व्यय हुआ है तथा इन कार्यों से 106281 श्रम दिवस सृजित हुए हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की ग्राम पंचायतों में उक्त अवधि में योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों को स्वीकृत कार्यों की राशि, प्रकार, वर्तमान स्थिति एवं दिये गये रोजगार का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि नरेगा में कुल कितने जॉब कार्ड राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में बने हैं? कितने एक्टिव हैं और कितनों के 100 दिन पूरे हो गये हैं? 1482 कार्यों में मात्र 635 कार्य ही पूर्ण हुए हैं। कार्य समय पर पूर्ण हो, इस पर आपकी क्या मानिटरिंग रहती है और उन कार्यों की समय-सीमा क्या तय है? व्यक्तिगत लाभार्थियों को...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक-एक प्रश्न पूछिए, तीन नहीं। दो का जवाब आने दें, फिर पूछ लेना।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, एक और है।

श्री अध्यक्ष: आपने दो पूछ लिए। फिर अलाउ करेंगे।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1482 में से जो बकाया शेष कार्य हैं 678, जो अभी प्रक्रियाधीन हैं, प्रोसीजर में हैं, जैसे ही आगे प्रोसीजर पूरा होगा उनका पैसा मिल जाएगा। जॉब कार्ड के माध्यम से जो व्यक्तिगत लाभ के काम हैं, वह टोटल 2498 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है और मानव दिवस 1 लाख 6 हजार 281 दिवस सृजित किये गये हैं, जॉब कार्ड के माध्यम से।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं यह जानकारी चाहती हूं कि कितने समय में वे पूर्ण होंगे? हमारी मानिटरिंग की कोई निर्धारित समय सीमा है कि हम इतने समय में इन कार्यों को पूर्ण करेंगे? दूसरा, व्यक्तिगत लाभार्थियों का पेमेंट सिस्टम क्या है और कितने क्लेम्स अभी तक पेंडिंग हैं?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रधानमंत्री आवास है, उसके कार्य का 9 माह का समय होता है। व्यक्तिगत कामों, लाभों का लगभग एक वर्ष होता है, लेकिन व्यक्तिगत काम के लाभ के अनुसार समय पर पैसा नहीं मिलना, जैसे भारत सरकार से हमें मेटेरियल का पैसा नहीं मिल पाया है। इस वजह से पेंडिंग हो जाते हैं। दूसरी जो अन्य चीजें हैं, उनकी हम मानिटरिंग कर रहे हैं। अगर कोई प्राब्लम है आपको, कोई पर्टिकुलर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, उस समस्या का समाधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

बामनवास में खाद्य सुरक्षा योजना के पात्रताधारी

129. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत तीन वर्ष में खाद्य सुरक्षा की पात्रता रखने वाले कितने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की पात्रता नहीं रखने वाले लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में सम्मिलित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की पात्रता की जांच कर अपात्रों को सूची से हटाने तथा पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत तीन वर्ष में खाद्य सुरक्षा की पात्रता रखने वाले किसी भी परिवार का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटाया गया है।

(2) जी नहीं। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थियों की आधार सीडिंग के दौरान खाद्य सुरक्षा की पात्रता नहीं रखने वाले लाभार्थियों के नाम समय-समय पर हटे हैं।

(3) वर्तमान में विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाये जाने के लिए सतत अपीलीय प्रक्रिया निर्धारित है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं खाद्य सुरक्षा के लिए, उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया कई दिन से बन्द है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कितने दिन में चालू हो जाएगी, कब तक हो जाएगी? ये प्रक्रिया चालू करने का सरकार विचार रखती है तो बताए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पात्र व्यक्तियों के नाम, यदि आपके विधान सभा क्षेत्र में ऐसे पात्र व्यक्तियों की कोई सूची है तो आप मुझे उपलब्ध करवा दें, उनको मौके पर जाकर, उनकी व्यवस्था करके उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली में स्वयं सहायता समूह की बकाया राशि का भुगतान

130. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में किस-किस स्थान पर किस-किस स्वयं सहायता समूह को कितने-कितने समय से किस-किस कार्य की कितनी-कितनी राशि किन-किन कारणों से दी जानी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया राशि का भुगतान कितनी अवधि में कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) पाली जिले में स्वयं सहायता समूहों के पूरक पोषाहार की आपूर्ति की एवज में देय बकाया राशि रुपये 5 करोड़ 52 लाख 36 हजार 619 के भुगतान हेतु बजट आबंटन किया जा चुका है। भुगतान की कार्यवाही जारी है। परियोजनावार एवं राशिवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) स्वयं सहायता समूहों के बकाया राशि के भुगतान हेतु बजट आबंटन किया जा चुका है। भुगतान की कार्यवाही जारी है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरा प्रश्न पढ़ें एक बार और माननीय मंत्री महोदय ने क्या उत्तर दिया है, उसको आप देख लें। बिलकुल गोलमाल जवाब दिया है। मैंने पूछा किस-किस सहायता समूह का, कितने-कितने समय से, किन-किन कारणों से, थोड़ा माननीय मंत्री महोदय ये बता दें, इस विलम्ब के लिए कौन-कौन जिम्मेवार है? बजट नहीं

(श्री ज्ञानचंद पारख)
था या आपके अधिकारियों की लापरवाही रही? कोई न कोई जिम्मेवार तो होगा कि चार साल से महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पेमेंट नहीं किया गया। अब मेरा प्रश्न लगने के बाद में आपने आबंटन के लिए राशि दी है। ये जो मैंने पूछा है आपको, बस इसका उत्तर दे दीजिए। मेरा वही प्रश्न है। मैं तीन नये नहीं पूछ रहा हूं। जो मैंने पूछा है, उसका जवाब दिलवा दीजिए वरना आधे घंटे की चर्चा करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न स्थगित किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आने के बाद आप दूसरी तरह से एप्लाई करें, बात करें। अगला प्रश्न। श्री समाराम गरासिया।

(प्रश्न स्थगित किया गया)

पिंडवाड़ा-आबू में विकास पथ

131. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पिण्डवाड़ा, सरूपगंज कार्यालय में रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा गौरव पथ के स्थान पर विकास पथ बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में विकास पथ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी हां। पिंडवाड़ा में एक सहायक अभियन्ता व एक कनिष्ठ अभियन्ता का पद रिक्त है तथा सरूपगंज में भी एक सहायक अभियन्ता व एक कनिष्ठ अभियन्ता का पद रिक्त है। विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों पर नियुक्ति होने पर रिक्त पदों को पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं। गौरव पथ के स्थान पर विकास पथ बनाने की घोषणा नहीं की गई है। विकास पथ का निर्माण वर्तमान सरकार की एक नवीन योजना है।

विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक विकास पथ ग्राम पंचायत अजारी में, अजारी गांव से अजारी ग्राम पंचायत मारकुण्डेश्वर जी धाम तक लम्बाई 1.00 किमी, राशि रुपये 80.00 लाख स्वीकृत होकर कार्य प्रगति पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि, मंत्री महोदय, ज्यादा लम्बे समय से रिक्त पद हैं, एक ही ए.ईएन. है, उसको ही एक्स.ईएन. का पद और ए.ईएन. का पद दिया हुआ है। दो तहसील आती हैं। ये कब तक भरेंगे? एक सवाल यह है कि जो मरम्मत का काम है, वह कब तक शुरू करेंगे?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य ने रिक्त पदों का बताया, अभी शीघ्र ही इनकी प्रक्रिया चल रही है। अभी भर्ती प्रक्रियाधीन है तो शीघ्र भर दिए जाएंगे। दूसरा, मैंने जो मरम्मत का परिशिष्ट-1 पर दिया है, वह आप एक बार पढ़ लें, कहां पर मरम्मत नहीं हुई, वह मुझे बता दें। आप परिशिष्ट-1 पढ़कर बताएं।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, स्वीकृत कब से हुआ? जैसे झाडौली-शिविरा का रोड, बिलकुल टूटा हुआ है शुरू हुआ ही नहीं है। ऐसे कई अन्य रोड हैं जो स्वीकृत तो हैं, लेकिन काम शुरू किए नहीं हैं।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वह सड़क नवीनीकरण में है। मरम्मत और नवीनीकरण दोनों अलग-अलग चीजें हैं। आपने नवीनीकरण का बोला है, शीघ्र उनको शुरू करा दिया जायेगा। उनकी एन.आई.टी. लग चुकी हैं, वर्क आर्डर हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन

132. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र में राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन करने की घोषणा की गई थी? यदि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
हां, तो उक्त घोषणानुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है? यदि हां, तो कब? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2020-21 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए सुझाव देने हेतु राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड को अधिकृत किया गया था? यदि हां, तो आयोग को अब तक कितने सुझाव प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2020-2021 के बिन्दु संख्या 54 (आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग (Economically Backward class) के उत्थान एवं कल्याण के सुझाव देने हेतु राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा) के अनुक्रम में राज्य सरकार की आदेश क्रमांक 29659 दिनांक 22.05.2020 द्वारा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन किया गया है। परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2020-2021 के बिन्दु संख्या 54 (आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग (Economically Backward class) के उत्थान एवं कल्याण के सुझाव देने हेतु राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा) के अनुक्रम में राज्य सरकार की आदेश क्रमांक 29659 दिनांक 22.05.2020 द्वारा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछडा वर्ग बोर्ड का गठन किया गया है। परिशिष्ट "अ"

(3) इस संबध में तथ्य यह है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2020.2021 के बिन्दु संख्या 54 (आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग (Economically Backward class) के उत्थान एवं कल्याण के सुझाव देने हेतु राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा) के अनुक्रम में राज्य सरकार की आदेश क्रमांक 29659 दिनांक 22.05.2020 द्वारा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन किया गया है।

दूसरा यह है कि आदेश क्रमांक 7839 दिनांक 14.02.2022 द्वारा माननीय अध्यक्ष पद पर श्री अनिल शर्मा को मनोनीत किया गया है। परिशिष्ट-"ब"

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अभी वर्तमान में उक्त बोर्ड से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने खण्ड-1 के उत्तर में यह कहा कि 22/05/2020 को आदेश क्रमांक 29659 के अन्तर्गत आपने राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया और परिशिष्ट-अ के अन्दर आपने उन उद्देश्यों का भी वर्णन किया है कि ये बोर्ड क्या-क्या काम करेगा, तो मैं आपसे सीधा एक पाइंटेड सवाल करना चाहता हूं कि जब घोषणा आपने इसकी 22/05/2020 को कर दी तो 2020-21, 2021-22 एवं अब 2022-23 के अन्दर आपने इन सारी योजना के क्रियान्वयन के लिए कितना-कितना बजट, किस-किस वर्ष में रखा? कृपया बताएं।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने योजना के बजट की बात नहीं की है। बोर्ड का गठन होता है, वह इनके आर्थिक कल्याण के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनकी स्थिति सुधारने के लिए होता है। उसके सुझाव हमें प्राप्त होंगे, उसके आधार पर हम करेंगे। आपको योजना की जानकारी चाहिये, तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन लगायें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अमृतलाल मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने प्रश्न पढ़ लिया। आप पार्लियामेंटेरियन हैं। It is an informatory question and you got the information. I have gone through it. अगला प्रश्न। अमृतलाल मीणा। I will not allow it. I said, I have gone through it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक पैसा नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please. I said, I have gone through it. आपने खुद क्वेश्चन दे दिया, it is just an informatory question. अगला प्रश्न। अमृतलाल मीणा।

उदयपुर में वन-स्टॉप-शॉप नवाचार के लाभार्थी

133. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमृतलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वन स्टाप शाप सरकार का महत्वपूर्ण नवाचार है? यदि हां, तो उक्त नवाचार के अंतर्गत जिला उदयपुर के कितने उद्यमियों को लाभान्वित किया गया व इस हेतु उक्त जिले में किन-किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नवाचार को क्रियान्विति के प्रथम चरण में 14 विभागों के अधिकारियों को 98 तरह की स्वीकृति देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है?

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में उक्त अभियान की क्या स्थिति है व इसकी क्या कार्ययोजना है? नवाचार युक्त वन स्टाप शाप उद्योग की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को दी गई, उक्त के द्वारा जन-जन लाभान्वित हो, इस हेतु योजना अनुरूप क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) जी हां। वन स्टाप शाप सरकार का एक महत्वपूर्ण नवाचार है। राजनिवेश पोर्टल के तहत उदयपुर ज़िले के कुल 9 आवेदन प्राप्त हुए, जिनको अनुमति प्रदान की जा चुकी है। संबंधित आवेदनों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

जिला उदयपुर में किसी अधिकारी की नियुक्ति वन स्टाप शाप हेतु नहीं की गई है।

(2) जी हां। वन स्टाप शाप प्रणाली के प्रथम चरण में 14 विभागों के नोडल अधिकारी 136 प्रकार की स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु पार्ट टाइम बेसिस पर बी.आई.पी. में नियुक्त किये गये हैं।

(3) इस अभियान को सफल बनाने हेतु उद्योग विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, लगता है अब, कटारिया जी को बोलें कि अलग-अलग बैठायें। यह क्या बात हुई?

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): उक्त आवेदन आनलाइन प्राप्त करने हेतु विशेष पोर्टल 'राजनिवेश' बनाया जा चुका है। 14 विभागों के उच्च अधिकारी उद्योग भवन में अलग से बनाये गये स्थान पर प्रात: 09:00 बजे से अपरान्ह 01:30 बजे तक प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को बैठते हैं।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वन स्टाप शाप के प्रचार प्रसार हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रचार-प्रसार नहीं होने की वजह से 9 आवेदन ही आये। अधिकारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा, 136 प्रकार की, कौन-कौनसी स्वीकृतियां हैं? इनकी सूची भी संलग्न नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ज़िलेवाइज अधिकारी नियुक्त नहीं किये हैं। यहां वन स्टाप शाप में, यहीं पर आयुक्त जो इन्द्रजीत सिंह जी लगाये, 14 डिपार्टमेंट के वन स्टाप शाप में बैठते हैं। जो एप्लीकेशंस आती हैं, उनका वहां निस्तारण होता है। अगर किसी कारणवश समय अवधि में कोई डिपार्टमेंट नहीं कर पाता है तो आयुक्त पावरफुल होता है।

प्रचार-प्रसार के लिए, हम इसकी कार्यशाला लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने अभी सोमवार को डिपार्टमेंट में मीटिंग ली थी। यह कह रहे हैं कि विभागवार सूची। वह मेरे पास है, आप कहें तो मैं बोल दूं, बहुत लम्बी सूची है?

श्री अध्यक्ष: आप माननीय सदस्य को भेज दें। माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बात कही, उत्तर दिया, इसमें सलूम्बर के प्रचार-प्रसार हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वह भी एक विधान सभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र से आती है, उसमें करना चाहिये, यही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्री लक्ष्मण मीणा।

बस्सी के अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की मरम्मत

134. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में माढ़ा, बिखरी जनजाति एवं माडा क्लस्टर में किस-किस कार्य के लिए कितनी राशि व्यय की गयी है तथा विभिन्न कार्यों के लिए कितने प्रस्ताव लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों की मरम्मत व रख-रखाव के लिए अतिरिक्त बजट आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में माडा, माडा क्लस्टर एवं बिखरी क्षेत्र में 117.14 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर 51.68 लाख रुपये व्यय किए गए। क्षेत्रवार, कार्यवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विभिन्न कार्यों के कुल 19 प्रस्ताव लम्बित हैं। इनका विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में विधान सभा क्षेत्र बस्सी के 10 छात्रावास एवं 1 ईएमआरएस में राशि 15.16 लाख रुपये स्वीकृत कर संबंधित छात्रावास अधीक्षक/प्राचार्य को उपलब्ध कराये गये। इस राशि में से राशि 12.43 लाख रुपये व्यय किये जाकर आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य करवाये गये। इसके अतिरिक्त 2 छात्रावासों में वर्ष 2019-20 में राशि 40.55 लाख रुपये स्वीकृत किये जाकर राशि 32.67 लाख रुपये व्यय किये जाकर वृहद मरम्मत कार्य करवाये गये। छात्रावासवार विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विभाग द्वारा वर्तमान में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बिहारीपुरा का संचालन किया जा रहा है। नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा जनजाति बहुल की ऐसी पंचायत समिति जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति व्यक्तियों की संख्या 20,000 से अधिक है तथा पंचायत समिति की कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति व्यक्ति निवास करते हों तथा जहां पूर्व में ईएमआरएस विद्यालय स्वीकृत व संचालित नहीं हो, ऐसी पंचायत समिति में वर्ष 2022 तक एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 में केन्द्र सरकार द्वारा की गई है। उक्त घोषणा में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम

(श्री लक्ष्मण मीणा)

से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, पहली बात तो यह है कि राशि बहुत कम स्वीकृत की गयी है। उसमें से भी 50 परसेंट से कम राशि खर्च हो पायी है, इसका क्या कारण है?

नम्बर दो, इन्होंने यह बताया कि एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने के लिए, या तो 2011 की सेंसस के अनुसार 20 हजार की आबादी हो, फिर बोल दिया कि उसकी आबादी 500 परसेंट एसटी की हो तभी, तो आपका कौनसा रिप्लाई ठीक है? यह बताने का कष्ट करें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार की गाइडलाइन है, 2021 में जिस ब्लाक में 20 हजार की आबादी हो या 20 हजार की आबादी के बाद ऐसा नहीं हो, तो उस ब्लाक में 50 प्रतिशत आबादी जनजाति की हो, यह भारत सरकार की गाइडलाइन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक राशि की बात है, केन्द्र सरकार से 275 और विशेष केन्द्रीय सहायता में, दो मदों में राशि आती है। विशेष केन्द्रीय सहायता में अभी किसी तरह की कोई राशि नहीं आई। उसमें अभी दूसरी गाइडलाइन आई है, जिसमें करीब 850 ग्रामों का चयन किया गया है। ग्रामवाइज डवलपमेंट की योजना बनायी गयी है। उसमें सारे गांव सम्मिलित हैं।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि आपने 117 लाख रुपये सैंक्शन किये, उसमें से 51 लाख ही खर्च हुए, उसका कारण क्या है? दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि या तो 20 हजार से अधिक की आबादी हो या 50 परसेंट एसटी की हो, तो दोनों ही कोंट्राडिक्टरी है आपका जवाब। स्पष्ट करियेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह आपको अधिकार है क्या? मैं उठ जाऊं यहां से? आप सीनियर आदमी होकर बैठे-बैठे बोलते हैं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सॉरी, सर।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि कम राशि खर्च होने के पीछे, जुलाई में हमारे विभाग से एएस प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी थी, उसकी टीएस बनकर जनवरी में आयी। हमने उसके आने के जस्ट बाद, एफएस जारी की है, इसलिए वह खर्च पूरा नहीं हुआ।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

उसके साथ, मैं माननीय सदस्य को दूसरी चीज अवगत कराना चाहता हूं। भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुरूप 20 हजार व 50 प्रतिशत वाली बात है। उसके साथ-साथ, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपके एकलव्य मॉडल विद्यालय बिहारीपुरा में 360 छात्रों के अध्ययन करने की व्यवस्था थी, उसको हम भारत सरकार में ले जाकर, 480 विद्यार्थियों की क्षमता वृद्धि के लिए व्यवस्था की गयी है, जिसकी प्रोसेस में फाइल है। हम बहुत जल्दी उसका कार्य शुरू कर देंगे। इस साल, आने वाले सत्र में, उन छात्रों को एडमिशन भी देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रदेश में चयनित महात्मा गांधी आदर्श गांव

135. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर वर्ष 2019 में प्रदेश के कितने जिलों में कितने गांव "महात्मा गांधी आदर्श गांव" के रूप में चयनित किये? जिलावार गांवों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार की ओर से उक्त चयनित गांवों को पांच वर्ष में नशामुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था? यदि हाँ, तो दिसम्बर, 2021 तक कितने गांव नशामुक्त कर दिए गए? जिलावार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त चयनित गांवों में सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी हैं? यदि हाँ, तो किन-किन गांवों में? क्या सरकार उक्त दुकानें बंद करवाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्थगित किया गया 135।

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थगित कर दिया। Please, don't ask the question. किसको, आपको बताऊंगा? आप सीनियर मैम्बर हैं, please be seated. सीनियर मैम्बर हैं, मैंने स्थगित किया है। (व्यवधान) मेरा prerogative है स्थगित करने का। मेरा प्रेरोगेटिव है स्थगित करने का (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। सीनियर आदमी होकर, please be seated.

अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा। मेरे से भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री अध्यक्ष: मैं बताऊं आपको? I am not supposed to speak on it. मैंने पोस्टपोन किया। Whom to speak? मैं नहीं बता रहा किसी को। प्लीज, आप बैठें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री अध्यक्ष: आप मुझे पूछ रहे हैं? आप सीख कर आयें, कानून-नियम पढ़कर आयें ...(व्यवधान) अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर के भवनविहीन पशु चिकित्सा केन्द्र

136. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्तमान में किराये के भवनों में संचालित नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र व उप केन्द्रों के भवनों का निर्माण कब तक करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की जनजाति क्षेत्र में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं संचालित हैं? यदि हां, तो अब तक लागू उक्त योजनाओं से टीएसपी क्षेत्र के कितने आदिवासियों को क्या-क्या लाभ मिला? जिलावार एवं विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में संचालित कुल 63 पशु चिकित्सा संस्थाओं में से 24 संस्थाएं राजकीय भवन में तथा 39 संस्थाएं पंचायत द्वारा प्रदत्त भवनों में संचालित हैं। पंचायत द्वारा प्रदत्त भवनों में संचालित 39 संस्थाओं में से 14 संस्थाओं के भवन वर्तमान में निर्माणाधीन हैं, 15 संस्थाओं के भू-स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त कर लिए गये हैं एवं 10 पशु चिकित्सा संस्थाओं हेतु भूस्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार करवाये जाते हैं।

(2) जी हां। जनजाति क्षेत्र में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

(पशुपालन मंत्री)

क्र.सं.	योजना का नाम
1.	कृत्रिम गर्भाधान
2.	बधियाकरण
3.	टीकाकरण
4.	आत्मा योजना (बीजू बकरे)
5.	जनजाति विकास (टाडा) योजना- 1. पशुपालक भ्रमण 2. बांझ पशुओं का उपचार 3. बकरी इकाई 4. सोर्टेड सीमन
6.	किसान क्रेडिट कार्ड
7.	कौशल विकास योजनान्तर्गत पशुपालक भ्रमण
8.	एस्केड जागरूकता शिविर

सरकार द्वारा लागू योजनाओं से टीएसपी क्षेत्र के लाभान्वित आदिवासियों का जिलेवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो किराये के भवन में पशु चिकित्सा केन्द्र और उप केन्द्र चल रहे हैं, वे कब तक बन जायेंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि आपके विधान सभा क्षेत्र में कोई भी किराये का भवन नहीं है, जिसमें ये संस्थाएं चालू हों। जो भवन है, वह पंचायत द्वारा जो जगह दिलायी गयी है, उसमें है। आपके यहां पर 28.08.2018 में करीबन 14 पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं, इनका काम तो चालू है और इसमें जैसा कि मैंने जवाब में यह बताया है कि जिन संस्थाओं के आपने भू-स्वामित्व के पट्टे दिये हैं, अगले वित्त वर्ष में इनका काम हम चालू करवा देंगे। बाकी जो दस पशु चिकित्सा केन्द्र हैं, जिनका हमारे भू-स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह दस्तावेज आप उपलब्ध करवा दें ताकि उसमें अगली कार्यवाही हम चालू कर सकें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमीन खां। (व्यवधान) आप और जोर से बोल लें, इनका काम तो वे ही करेंगे।

शिव तहसील के गांवों में इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल की आपूर्ति

137. श्री अमीन खां (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

तहसील शिव के कितने गांवों में अब तक इन्दिरा गांधी नहर से पीने का पानी पहुंच गया है व सरकार शेष गांवों में कब तक पानी पहुंचाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): बाड़मेर जिले की तहसील शिव में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 138 ग्रामों में से इन्दिरा गांधी नहर आधारित पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना पेयजल परियोजना के पैकेज-4अ का कार्य माह अक्टूबर, 2019 में पूर्ण किया जाकर तहसील शिव के 8 ग्रामों में पूर्ण रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

तहसील शिव के शेष 130 ग्राम सतही जल स्रोत इंदिरा गांधी नहर आधारित बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण के भाग-स (केकेडी-शिव-भाड़खा-बाड़मेर) में सम्मिलित हैं। भाग-स की प्रगतिरत इस पेयजल परियोजना का 70 प्रतिशत कार्य अब तक पूर्ण किया जाकर शेष कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। इस पेयजल परियोजना अन्तर्गत क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा तहसील शिव का कोई भी ग्राम पूर्ण रूप से अब तक लाभान्वित नहीं हुआ है परन्तु, बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना के प्रथम चरण में आधारभूत संरचनाओं के पूर्ण किये गये कार्यों के तहत निर्मित आफ-टेक शिव एवं निम्बला से निवर्तमान क्षेत्रीय जल योजनाओं अंतर्गत तहसील शिव के क्रमश: 13 एवं 12, इस प्रकार कुल 25 ग्रामों में आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

भाग-स की प्रगतिरत उक्त परियोजना से तहसील शिव के उक्त 130 ग्रामों को चरणबद्ध रूप से माह जुलाई, 2022 तक पूर्ण रूप से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

उक्त दोनों वृहद् पेयजल परियोजनाओं में तहसील शिव के कुल सम्मिलित, पूर्ण एवं आंशिक रूप से अब तक लाभान्वित तथा शेष लाभान्वित किये जाने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत तहसील शिव में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार सम्मिलित 159 ग्रामों में घर-घर क्रियाशील जल सम्बन्धों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दो वृहद पेयजल परियोजनाओं एवं इनके अतिरिक्त अन्य जल योजनाओं की स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है:-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(अ) बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण के भाग-स के अन्तर्गत तहसील शिव के 148 ग्रामों सहित बाड़मेर जिले के कुल 346 ग्रामों हेतु राशि रुपये 440.00 करोड़ तथा पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना परियोजना के पैकेज-4अ के अन्तर्गत तहसील शिव के 04 ग्रामों सहित बाड़मेर जिले के कुल 180 ग्रामों हेतु राशि रुपये 239.43 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा ये परियोजनाएं क्रमश: माह मार्च, 2024 एवं माह नवम्बर, 2023 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित हैं। परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(ब) तहसील शिव के उक्तानुसार शेष 07 ग्रामों हेतु 07 अन्य जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1129.03 लाख की जारी की जाकर, इसके विरुद्ध 05 जल योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा 02 जल योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इन जल योजनाओं को चरणबद्ध रूप से माह सितम्बर, 2022 तक पूर्ण कर तहसील शिव के उक्त समस्त 159 ग्रामों को घर-घर क्रियाशील जल सम्बन्धों द्वारा पेयजल आपूर्ति कराया जाना प्रस्तावित है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री अमीन खां (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मैं यह जानकारी चाहता हूं कि इस लिफ्ट कैनाल से पानी की योजना शिव तहसील की बनी हुई को पन्द्रह साल हो गये और इन पन्द्रह सालों में आज तक सिर्फ आठ गांवों में पानी जाता है और शिव तहसील से पानी निकलकर आगे सैकड़ों गांवों में पानी पहुंच गया और शिव तहसील के गांवों को अभी तक वंचित रखने का क्या कारण है?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी गांव को चाहे वह शिव तहसील का हो या कहीं का भी हो, कोई मंशा सरकार की नहीं होती है कि उनको वंचित रखा जाये। मैंने पूरा विवरण सदन के पटल पर रखा है। माननीय सदस्य को इसका जवाब दिया है और हमारी यह कोशिश रहेगी कि जो चरणबद्ध कार्यक्रम हमने रखा है उसको हम समय पर पूरा कर सकें और शिव तहसील के सभी ग्रामों को उसके अनुसार पेयजल उपलब्ध करवा सकें।

श्री अमीन खां (शिव): वंचित गांवों को सरकार कब तक पानी का प्रबन्ध करने का विचार रखती है?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरा जवाब इसमें लिखा है। आप एक बार देख लीजिए लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य की कोई भ्रांति होगी, कोई सवाल होगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसको दिखवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

तलछेरा (नदबई) में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना

138. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम तलछेरा में सरस का नवीन दुग्ध अवशीतन केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): जी नहीं। आरसीडीएफ से सम्बद्ध भरतपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम तलछेरा में संघ का एक दुग्ध संकलन केन्द्र कार्यरत था, जिसे संघ द्वारा पंजीकृत दुग्ध समिति के रूप में परिवर्तित करा दिया गया है। तलछेरा गांव भरतपुर दुग्ध संघ के नदबई दुग्ध मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग से संघ द्वारा दुग्ध वाहनों का संचालन कर नदबई क्षेत्र के सीमावर्ती 20 गांवों की दुग्ध समितियों एवं संकलन केन्द्रों से औसतन लगभग 700-800 लीटर प्रतिदिन दुग्ध का संकलन किया जा रहा है। लीन सीजन में इस क्षेत्र में दुग्ध संकलन घटकर मात्र 150-200 लीटर प्रतिदिन रह जाता है। तलछेरा दुग्ध संकलन केन्द्र द्वारा भरतपुर दुग्ध संघ को मात्र 60 लीटर प्रतिदिन की औसत से ही दुग्ध भेजा जा रहा है।

वर्तमान में भरतपुर जिला मुख्यालय पर संघ का डेयरी संयंत्र कार्यरत है तथा संयंत्र से नदबई क्षेत्र की दूरी भी मात्र 50 किलोमीटर है। वर्तमान में 700-800 लीटर दुग्ध का संकलन किया जा रहा है। इस गांव में तथा आस-पास के क्षेत्र में यदि दुग्ध संकलन की मात्रा के आधार पर 1000 से 1500 लीटर क्षमता हो तो बीएमसी स्थापित की जा सकती है।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया कि वहां दुग्ध अवशीतन केन्द्र के लायक दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है। वहां दुग्ध संकलन केन्द्र बनवा दीजिए। बहुत दूर लोगों को जाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि आसपास के गांवों के किसानों को जो मुख्य व्यवसाय केवल दुग्ध का ही है, उसके लिए बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्षजी, आपके

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहूंगा कि उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार तलछेरा में संकलन केन्द्र खोलने का विचार रखती है या नहीं?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, हमारी सरकार दुग्ध उत्पादकों के लिए पूर्ण समर्पित है। सरकार के गठन के बाद हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने पहले 2 रुपये लीटर सम्बल योजना लागू की, फिर उसको बढ़ाकर इस बजट में 5 रुपये की घोषणा की।

जहां तक तलछेरा का प्रश्न है, वहां पर दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति अस्तित्व में है परन्तु पिछले माह से दुग्ध संकलन घटकर चार-पांच लीटर रह जाने से यह बन्द पड़ी है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इसी माह अधिकारियों को भेजकर जांच कराऊंगा और पर्याप्त मात्रा में दूध संकलन हो सकता है तो दुग्ध संकलन केन्द्र चालू किया जायेगा। दुग्ध और अधिक बढ़ता है तो बीएमसी लगाने पर भी विचार किया जायेगा। हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। यह मैं आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में विकास कार्यों हेतु बजट का आबंटन

139. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2021 तक श्रीगंगानगर जिला परिषद् में विकास कार्यों हेतु कुल कितना बजट आबंटित किया गया? उक्त बजट में से किस-किस योजना में कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की पंचायत समिति अनूपगढ़ व घड़साना में जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक कुल कितना-कितना बजट किस-किस योजना हेतु आबंटित किया गया? उक्त में से किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना बजट व्यय किया गया? पंचायत समितिवार व ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला परिषद् श्रीगंगानगर द्वारा पंचायत समिति अनूपगढ़ व घड़साना के बजट आबंटन में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक कब-कब तथा उनके विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक श्रीगंगानगर जिला परिषद् में विकास कार्यों हेतु आबंटित किये गये बजट का योजनावार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की पंचायत समिति अनूपगढ़ एवं घड़साना में जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक आबंटित बजट एवं व्यय का योजनावार, कार्यवार, पंचायत समितिवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 के कार्यो की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी होने के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किये गये हैं? पंचायत समिति अनूपगढ़ में 2 करोड़ 24 लाख 49 हजार 534 और पंचायत समिति घड़साना में 3 करोड़ 26 लाख 1 हजार 594 की राशि के कार्य आज भी बकाया हैं। इन कार्यों का संवेदक कौन था और कब तक कार्य पूरा किया जाना था?

अध्यक्ष महोदय, समय पर काम पूरा नहीं करने पर कितनी राशि अधिरोपित रखी जाती है? माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पांच छः प्रश्न पूछ लोगे तो कैसे होगा? जवाब आने दो।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको एसएफसी, एफएफसी के, प्लस रूरल डवलपमेंट के, अलग-अलग ग्राम पंचायतवार विवरण दिया हुआ है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ब्लॉक अनूपगढ़ में 14.51 करोड़ की स्वीकृति राशि रिसीव्ड हुई थी, उसमें से 6 करोड़ 87 लाख खर्च कर दिये गये हैं और इसी तरह घड़साना में 23 करोड़ में से 10 करोड़ 3 लाख का व्यय हो चुका है। नरेगा में जो हमारी अलग-अलग योजनाएं हैं, जैसे एमएलए-लैड है, एमपी-लैड है, बीएडीपी है....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, पीछे बात कर रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, क्या कर रखा है आपने। प्लीज। बोलें मंत्रीजी।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...तो इसमें जो कार्यों की संख्या है विभिन्न योजनाओं की, एसएफसी और पंचायती राज की आरडी की, उसमें 17 हजार 614 कार्य स्वीकृत हुए थे, उनमें से 18 हजार 446 लाख के कार्य आबंटित हुए। उनकी व्यय राशि है 12 हजार 220 लाख रुपये। कार्य समय पर हो रहे हैं।

आपने जो संवेदक की बात कही है तो विभिन्न ग्राम पंचायतों की अलग-अलग एजेंसियां हैं। पर्टिकुलर किसी एजेंसी ग्राम पंचायत की है, क्योंकि एजेंसी जो बनाते हैं, उसमें वह निविदाएं डालते हैं, वह आपको जानकारी है कि कार्यकारी अध्यक्ष होता है, वीडीओ जिसको कहते हैं। बाकी लेखाधिकारी है, सरपंच है, ग्राम विकास अधिकारी सदस्य होते हैं। उनके द्वारा ये निविदाएं होती हैं। संवेदक वहां पर तय होता है। किसी संवेदक ने यदि कार्य नहीं किया है या किसी अन्य की कोई परेशानी है तो आप मुझे लिखकर दे दें। उसकी हम कार्यवाही करायेंगे, यदि समय पर कार्य नहीं हो रहा है तो।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय मंत्रीजी, ऐसी कई पंचायतें हैं। मैंने वही बतायी हैं जो बकाया है। वह क्यों नहीं हुए हैं? कब तक हो जायेंगे? पंचायत समिति घड़साना और अनूपगढ़ के बकाया जो हैं, वह कब तक काम हो जायेंगे?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किस प्रकार के वर्क हैं? या तो प्रधानमंत्री आवास का वर्क है या व्यक्तिगत है या फिर समयावधि से आगे बढ़ रहा है किसी कारणवश? वह पर्टिकुलर ग्राम पंचायतों का हमें बता दें। उनकी हम जांच करवा लेंगे। अगर सक्षम स्तर पर, स्टेट लेवल से आप करवाना चाहते हैं तो यहां से जांच करवा लेंगे और एक महीने में हम आपको, जो भी कहीं कोई किसी तरह की लापरवाही है तो उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। कालीचरणजी सराफ।

खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रताधारियों की सीमा में बढ़ोतरी

140. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने प्रतिशत पात्रताधारी चयनित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत अपात्रताधारियों के नामों को हटाकर उनसे वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2021 तक कुल कितने अपात्रताधारी चयनित लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए गए व कितनों के नाम जोड़े गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने नीतिगत निर्णय लेकर खाद्य सुरक्षा योजना को सभी वर्गों के पात्रताधारियों के लिए लागू करते हुए वर्तमान सीमा को बढ़ाये जाने का नीतिगत निर्णय लिया है? यदि हां, तो उक्त निर्णय की पालना हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत दिनांक 23.02.2022 को शहरी क्षेत्र में 35.36 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 72.68 प्रतिशत लाभार्थी चयनित हैं।

खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या शहरी क्षेत्र 6028017 (साठ लाख अट्ठाइस हजार सत्रह) एवं ग्रामीण क्षेत्र 37432670 (तीन करोड़ चौहत्तर लाख बत्तीस हजार छह सौ सत्तर) है।

(2) जी हां। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे राजकीय कार्मिकों के नामों को हटाकर उनसे वसूली की कार्यवाही करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 24.02.2020 को आदेश जारी कर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह फरवरी, 2020 से 01 जनवरी, 2021 तक अपात्र सरकारी कार्मिकों के 3,22,178 (तीन लाख बाइस हजार एक सौ अठहत्तर) परिवार सदस्यों के नाम हटे हैं। प्रदेश में इस अवधि में नये पात्र व्यक्तियों के 7,47,546 (सात लाख सैतालीस हजार पांच सौ छियालीस) नाम जोड़े गये।

(3) भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद सम्भव होने के कारण वर्तमान में दिनांक 18.05.2020 से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं।

भारत सरकार को राजस्थान में वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर सीलिंग पुन: निर्धारित करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय के

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

द्वारा माननीय प्रधान मंत्री महोदय को दिनांक 09.12.2019, 22.04.2020 25.08.2020, 20.07.2021, 29.12.2021 से अ.शा. पत्र लिखे गये हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के नोर्म्स के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितने प्रतिशत लाभार्थी चयनित किये जा सकते हैं? दूसरा प्रश्न है कि राज्य कर्मचारियों से अब तक कितनी राशि वसूल की गई है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): देखिए, भारत सरकार की शर्तों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है, जिसमें नाम जोड़े जा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में चयन सीमा 69.9 प्रतिशत जोड़ने का निर्धारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रदेश में 01.01.2020 को पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या 4.94 करोड़ तथा मई, 2020 में यह अधिकतम स्तर पर 5 करोड़ से अधिक हो गई थी। 2020 में भारत सरकार का एक आदेश आया उसके बाद, क्योंकि उन्होंने यह संख्या निर्धारित हमारी 4.34 थी जो 4.96 लाख पर चली गयी थी, उन्होंने कहा कि हमने आपकी सीलिंग निर्धारित कर रखी है। उसके बाद ये नाम काटे गये। आप ये नाम काटने की जो बात कर रहे हैं, भारत सरकार का एक आदेश आया और वह आदेश यह था कि वन नेशन वन राशनकार्ड के अनुसार आधार से इनको जोड़ा गया और आधार से जब जोड़ा गया तो नाम अपने आप ही कटे। उसमें सरकारी कर्मचारी इतनी तादाद में नहीं थे लेकिन वह लोग ज्यादा थे जिनमें आधार कार्ड जुड़ने के बाद अलग जगह जिनके नाम जुड़े हुए थे, वह नाम कट गये और उन नामों को लेकर जब टीम यहां आयी थी, मुख्य मंत्रीजी स्वयं उपस्थित थे, हमने भारत सरकार से निवेदन किया कि जो नाम हमारे कटे हैं, उन नामों को जोड़ने की हमको परमिशन दें। मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें केन्द्र सरकार की टीम ने उस वक्त तो यह माना कि जो नाम कटे हैं, वह नाम आप जोड़ सकते हैं लेकिन बाद में जब वह टीम दिल्ली गई, उसके बाद हमने कोशिश की तो उन नामों को जोड़ने की उन्होंने परमिशन नहीं दी है। जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी, वह नाम हम जोड़ने शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। बैठें माननीय सदस्य, आप सीनियर आदमी हैं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(समय: 12.00 बजे)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से पंचायत समिति हुरड़ा में हैण्डपम्प मिस्त्री एवं रिटायर फिटर को वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा कोविड-19 का हवाला देते हुए आदिवासी समुदाय के बेणेश्वर धाम में दिनांक 16 फरवरी, 2022 को आयोजित मेले पर रोक लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम से आदिवासी नाबालिग लड़की के लापता होने पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से पाली व सिरोही के लिए बनायी गयी जोयला पिकअप वेयर फोर डायवर्जन ऑफ ओल्ड रूट ऑफ सूकड़ी नदी योजना से आहोर तहसील की 17 ग्राम पंचायतों में पेयजल संकट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू की ग्राम पंचायतों को वन्यजीव अभयारण्य से मुक्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में हिन्दी मीडियम के विद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर और गंग कैनाल में पंजाब के हरिके बैराज से कैमिकल युक्त जहरीला व गंदा पानी छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के पाली पंचायत समिति में डरी ग्राम में ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक व सहायक व्यवस्थापक द्वारा किसानों के द्वारा चुकायी गयी ऋण राशि में अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से चौमूं नगरपालिका द्वारा किये

(श्री अध्यक्ष)

जा रहे भ्रष्टाचार एवं पार्किंग के नाम व्यापारियों से की जा रही उगाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से प्रशासन की अनदेखी से कोटा-बूंदी में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर सहित हाड़ौती सम्भाग में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(12) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में श्रमिकों को रोजगार देने के नाम पर मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत की नवनिर्मित सड़कों एवं पैचवर्क कार्यों में घटिया सामग्री लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल में मक्का खरीद केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शोभा चौहान एवं श्री हरेन्द्र निनामा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से नोखा पंचायत समिति क्षेत्र में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से नगर परिषद् किशनगढ़ में दो नये बड़े अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में निवासरत पाहुआ जाति को एससी/एसटी वर्ग में आरक्षण देने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा गंगानगर जिले में 02 मार्च से सिंचाई हेतु पानी बंद कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में मिसिंग सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से बीकानेर-नापासर-जसरासर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से फसल पकाव के समय बकाया के नाम पर किसानों के विद्युत कनेक्शन काटने और ट्रांसफार्मर उतारने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से खाड़ी देशों में मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले मजदूरों एवं उनके परिजनों के हितों की रक्षा हेतु योजना बनाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में प्रशासन गांवों की ओर अभियान के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों में अब तक लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करवाये जाने के संबंध में।

(10) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति जालसू को तलसील बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती निर्मला सहरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित अनुदानित छात्रावासों को भी राजकीय छात्रावासों के समान मैस भत्ते जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से उदयपुर जिले में सी.एस.आर. फण्ड से संचालित जिंक फुटबाल एकेडमी जावर माइन्स में स्थानीय आदिवासी युवाओं को प्रवेश दिलवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ा हुआ माना जावेगा।

आज अधिकांश माननीय सदस्य डिबेट में भाग लेना चाहते हैं और यूक्रेन के सम्बन्ध में भी स्टेटमेंट होगा, इसलिए 295 को पढ़ा हुआ माना गया है।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट-01 देखें।)

श्रीमती शोभा चौहान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सोजत में नवनिर्मित सड़कों व पैचवर्क कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में सड़कों की कमी है, लेकिन जो सड़कें बनी हुई हैं, उनके निर्माण के बाद शायद विभाग इनको भूल गया है। महोदयजी, सड़कों की यह स्थिति है कि सड़क पर दुपहिया और चौपहिया वाहनों का चल पाना मुश्किल है। आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। भूलवश विभाग द्वारा किसी सड़क का पैचवर्क या निर्माण कार्य करवाया गया है तो वह भी 10-15 दिन के बाद खराब हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि सड़कों के निर्माण कार्य में जो घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, सरेआम विभाग के कर्मचारी और अधिकारी एजेन्सियों के साथ मिलीभगत का खेल कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ तो सरकार को राजस्व की हानि हो रही है और दूसरी तरफ जनता को सुविधा मिल पाना मुश्किल है।

अत: महोदय जी आपसे अनुरोध है कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में नवनिर्मित सड़कों व पैचवर्क की जांच करवाएं एवं सोजत विधान सभा के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था कराएं ताकि जिन सड़कों का आजादी के बाद आज दिन तक उनका निर्माण नहीं हुआ, उनका निर्माण कराया जाये। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरेन्द्र निनामा।

घाटोल में मक्का खरीद केन्द्र की स्थापना

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद देता हूं और एक धन्यवाद माननीय सदस्य, श्री अविनाश जी को भी देता हूं कि मेरी सीट पर माइक नहीं होने से उनके माइक पर मुझे बोलने की परमिशन दी, इसलिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना लागू होने के कारण रबी और खरीफ, दोनों समय में मक्का का उत्पादन इतना होता है कि 1995, 1996 और 1997 के अन्दर पूरे भारत के अन्दर मक्का उत्पादन में बांसवाड़ा जिला प्रथम रहा, लेकिन हमारा

(श्री हरेन्द्र निनामा)

दुर्भाग्य हमारे किसानों को उचित मूल्य का भाव नहीं मिलने का कारण सरकारी दुकानें नहीं होना है। मैं मेरे घाटोल विधान सभा क्षेत्र के अन्दर घाटोल मुख्यालय पर सरकारी मक्का उत्पादन केन्द्र खोलने के लिये सरकार से मांग करता हूं।

इसके साथ ही, सन्दी जी का गढ़ा ग्राम पंचायत में भी एक केन्द्र खोलने की मांग करता हूं। गन्दोड़ा एक ऐसी जगह है मेरे विधान सभा क्षेत्र की, जो बेणेश्वर के नजदीक पड़ती है और वहां पर तहसील मुख्यालय है, वहां पर संस्कृत कॉलेज है। वहां के एरिया किसान की मक्का का बहुत उत्पादन करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बांसवाड़ा जिले के घाटोल विधान सभा क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रबी और खरीफ दोनों फसलों में मक्का उत्पादन के लिये सरकारी केन्द्र खोलें ताकि वहां के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री रमेश चन्द मीना।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

पंचायती राज विभाग

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.139(45)पंरावि/विधि/संशो/2021/860 दिनांक 06.10.2021 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को संशोधित किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)अमे/रूल्स/लीगल/पी.आर./2020/808 दिनांक 15.09.2021 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को संशोधित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

परिवहन विभाग

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या:प.6 (179)परि/कर/मु./2018-19/पार्ट-2/16827 दिनांक 20.09.2021 जिसके द्वारा सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 में यथा परिभाषित अलाभकारी संस्था द्वारा खरीदे गये एवं स्वामित्व वाले वाहनों पर देय कर का प्रतिहार किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: प.6(294)परि/कर/मु./2014/18755 दिनांक 18.10.2021 जिसके द्वारा प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/2 दिनांक 10.07.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: प.6(298)परि/कर/मु./2015/22934 दिनांक 21.12.2021 जिसके द्वारा IATO/RATO से मान्यता प्राप्त ट्यूर आपरेटर्स के वाहनों को कर में छूट प्रदान की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: प.7(3)/परि/नियम/मु./2021/15658 दिनांक 03.09.2021 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: प.7(100)(71)/परि/नियम/मु./2013/17409 दिनांक 23.09.2021 जिसके द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक परिवहन यानों का अधिग्रहण किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है; एवं
6. अधिसूचना संख्या: प.7(198)/परि/नियम/मु./2006/पार्टI/18744 दिनांक 18.10.2021 जिसके द्वारा विशिष्ट पंजीयन क्रमांक एवं पंजीयन क्रमांक रिटेंशन शुल्क के संबंध में प्रावधान किया गया है।

श्री अध्यक्ष: समिति का प्रतिवेदन, श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)। याचिका का उपस्थापन, श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित)। श्री बलवान पूनियां।

याचिका

भादरा में सड़कों का पुनर्निर्माण

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भादरा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के पुनर्निर्माण करवाये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। सब्जेक्ट पर बोल देता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, विराजें। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्या 10), श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्या 10) को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्या 10) को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022, श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की

रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक पर चर्चा। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जितना समय आपकी पार्टी ने दिया है उसी में अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करें। यूक्रेन पर 4 बजे स्टेटमेंट होगा। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): नहीं बोलना।

श्री अध्यक्ष: नहीं बोलना है? श्री मदन दिलावर।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी बजट प्रस्तुत किया है और हर बार ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। उसकी पवित्रता बनाये रखना आपकी, हमारी और सरकार की, सबकी जिम्मेदारी है। यहां बजट के माध्यम से जनता को जो बात कही जाती हैं, उसको पूरी तरह से लागू करना चाहिये अन्यथा यह जनता के साथ धोखा और उनके साथ अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं, पिछली बजट घोषणाओं के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। किस प्रकार से घोषणाएं करके राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। 2021-22 में घोषणा की गयी थी कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रदेश की सबसे गरीब सहरिया जाति व

(श्री मदन दिलावर)

विकलांगों को वर्ष में 200 दिवस रोजगार दिया जायेगा, लेकिन एक भी सहरिया जाति के व्यक्ति को 200 दिन रोजगार नहीं दिया। यह सहरिया जाति के साथ एक छलावा था।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, यह भी कहा गया कि हम अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी स्कूल नहीं खोले गये। जो हिन्दी माध्यम के विद्यालय चल रहे थे, उन्हीं का नाम बदलकर वहां अंग्रेजी पढ़ाने का असफल प्रयास हुआ। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां हिन्दी माध्यम के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम के भी पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं। यह क्या जनता के साथ धोखा नहीं है? यह धोखाधड़ी है। जनता इसका जरूर बदला लेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया था कि मिडल स्कूल के सभी छात्रों को हम नि:शुल्क यूनिफार्म उपलब्ध करायेंगे। अभी तक नि:शुल्क यूनिफार्म उपलब्ध नहीं करायी है। यह भी एक छलावा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2019-20 में यह भी घोषणा की थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के समय की जो गौरव पथ योजना है, इसको बन्द करते हैं। उसके बदले में विकास पथ योजना लाते हैं। उसमें कहा गया कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 01 किलोमीटर का विकास पथ बनाएंगे। लेकिन आपको और पूरे सदन को जानकर दु:ख होगा कि मैं अगर रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो एक भी विकास पथ पूरा नहीं बनाया गया है। केवल सुकेत में एक बनाया गया है। वह भी आधा-अधूरा है जबकि इनको सभी ग्राम पंचायतों में बनाना था। यही हाल पूरे राजस्थान का रहा है। मैं समझता हूं कि यह इस प्रकार से असत्य बजट घोषणाएं करके वाहवाही लूटने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

(समय : 12.14 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, इन्होंने 2019-20 में यह भी घोषणा की थी कि किसानों को रात्रि के स्थान पर दिन में 2 ब्लाक्स में बिजली उपलब्ध कराएंगे ताकि किसान को रात्रि में सर्दी में खेत में खड़े होकर ठिठुरते हुए अपनी फसलों को पानी नहीं देना पड़े। यह कहा था कि हम 33 केवी के सब-स्टेशनों पर 600 नये ट्रांसफार्मर्स लगाएंगे, लेकिन इनकी यह घोषणा भी टांय-टांय फिस्स रही है।

सभापति महोदय, इन्होंने यह भी कहा था कि अनुसूचित जाति,

(श्री मदन दिलावर)

जनजाति के जो बेरोजगार हैं, उनमें 50 हजार युवाओं को अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराएंगे, लेकिन पहले जो 25 हजार का चल रहा था, उसको भी पूरा नहीं कर पाये। केवल 22 हजार युवाओं को ही ऋण उपलब्ध कराकर इन्होंने इतिश्री कर ली। इनकी यह घोषणा भी टांय-टांय फिस्स हो गयी।

सभापति महोदय, इन्होंने यह भी कहा था कि टीएसपी क्षेत्र में खेरवाड़ा जिला उदयपुर, पारडा चुण्डावत जिला डूंगरपुर, पाड़ोला जिला बांसवाड़ा, टीमरवा जिला प्रतापगढ़, हनौतिया जिला बारां के जनजातीय आवासीय विद्यालयों की वर्तमान कुल छात्र क्षमता को 1 हजार 530 से बढ़ाकर 2 हजार 400 किया जायेगा, लेकिन यह भी नहीं हुआ।

सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख जरूरतमन्दों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन यह लोक-लुभावन योजना भी टांय-टांय फिस्स हो गयी।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट जो प्रस्तुत करते हैं, उसकी पवित्रता को इस सरकार ने समाप्त किया है। जो बजट घोषणा होती है जनता के लिये, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इन्होंने घोषणा की थी कि हम सभी किसानों का सभी प्रकार का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाये। इन्होंने कहा कि हमने इस वादे को पूरा कर दिया है। इससे ज्यादा असत्य क्या होगा कि इस सदन में यह जनता को बता रहे हैं कि हमने वादा पूरा कर दिया है। इस चक्कर में कई किसान अपना पूरा कर्जा नहीं चुका पाये। कर्जा नहीं चुका पाने के कारण अब उनकी जमीनों को नीलाम करने का षड्यंत्र जारी है। अब यह तर्क देते हैं कि भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है। आपने जब कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, तब तो यह नहीं कहा था कि हम भारत सरकार से सहयोग लेंगे या भारत सरकार ने हमको कहा है कि हम सहयोग करेंगे। इस प्रकार से राजस्थान की जनता के साथ अन्याय क्यों किया गया? सैकड़ों किसानों को आत्महत्या करने के लिये क्यों मजबूर किया गया? यह तो सरकार को राजस्थान की जनता को बताना होगा। यह राजस्थान के किसानों के दुश्मन साबित हो रहे हैं और उनको मरने के लिये छोड़ रहे हैं।

सभापति महोदय, यही नहीं, यह कहा गया कि राजस्थान के सभी

(श्री मदन दिलावर)

बेरोजगार युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर इनको सपने में आया कि हम इतना नहीं दे पायेंगे, तो इन्होंने बैरीकेड्स लगाये। पहले बैरीकेड्स लगाये कि 1 लाख तक को देंगे। फिर 1 लाख 60 हजार तक आये। इसके बाद इन्होंने लगाया कि 4 घंटे जो काम करेगा, उसको देंगे। यह क्या अन्याय है? बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है।

सभापति महोदय, यह कहते हैं कि इतने लोगों को हम नौकरी देंगे। वैकेंसी निकालते हैं। खुद सरकार में बैठे हुए लोग ही हजारों करोड़ रुपये कमाने के लिये पेपरों को स्ट्रांग रूम से निकालकर बेच देते हैं। उसमें सारी की सारी सरकार शामिल हो जाती है। इससे ज्यादा अन्याय बेरोजगारों के साथ क्या होगा?

सभापति महोदय, यही नहीं, राजस्थान के संविदाकर्मियों से कहा गया कि कांग्रेस की सरकार आयेगी तो सभी संविदाकर्मियों को नियमित कर दिया जायेगा, लेकिन आज सारे संविदाकर्मी, पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, शिक्षा मित्र और अन्य विभागों में जो लोग चतुर्थ श्रेणी का काम कर रहे हैं, कई छात्रावासों में रसोइया, चौकीदार, यह सब इंतजार कर रहे थे कि हमको नियमित किया जायेगा, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, अन्याय हुआ है। राजस्थान की जनता को भ्रामक प्रचार करके, भ्रामक घोषणा करके ठगने का काम इस सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, यहां यह कहा गया कि यह बजट सबके विकास के लिये है। सबके विकास के लिये कैसे हो सकता है? अनुसूचित जाति के विद्यार्थी जो छात्रावासों में पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से यह आस लगाए बैठे थे कि हमारा मैस भत्ता बढ़ेगा। हम भी ठीक प्रकार का भोजन कर पाएंगे। हम कुपोषण से बचेंगे, लेकिन उनका भी भत्ता नहीं बढ़ाया गया है। पुराने भत्ते के आधार पर ही उनको भोजन दिया जा रहा है। इस कारण से अनुसचित जाति और जनजाति के छात्र कुपोषण के शिकार होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और ओबीसी के छात्र हैं, वो छात्र भी अपनी छात्रवृत्ति बढ़ाने की आस लगाये बैठे थे कि इस बजट में हमारे ऊपर यह सरकार कृपा करेगी और छात्रवृत्ति को बढ़ायेगी ताकि हम भी ठीक प्रकार से पढ़ सकेंगे, ठीक प्रकार से हम पाठ्य सामग्री खरीद सकेंगे लेकिन उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया है बल्कि एक काम और कम किया है।

(श्री मदन दिलावर)

पोर्टल में इतनी विसंगतियां छोड़ दी गयी हैं कि उसे ठीक प्रकार से बच्चे लोड नहीं कर पा रहे हैं। अबकी बार छात्रवृत्ति लेने के लिए छात्र उस पर अपना आवेदन लोड करते, वो 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं कर पाये हैं और इस कारण से इन्होंने 50 प्रतिशत पैसा बचाया है। यह कमी इसलिए छोड़ी है इन्होंने क्योंकि छात्रवत्ति में राजस्थान सरकार को भी केन्द्र सरकार के साथ-साथ अपना शेयर देना पड़ता है। उस शेयर को बचाने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के साथ अन्याय किया है।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने यह कहा कि हम पांच साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, इससे बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ क्या हो सकता है? अभी तक दस बार बिजली के दाम बढ़ाये गये, दस बार, जनता को लूटा गया। माननीय सभापति महोदय, यह कहा गया कि हम इतने किसानों को बिजली के कनेक्शन देंगे, लेकिन डेढ़-डेढ़ साल से जिन लोगों ने बिजली के कनेक्शन के डिमांड नोट जमा करा रखे हैं उनको एक महीने पहले तक भी कनेक्शन नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि अनुसूसचित जाति, जनजाति या गरीब किसान, पैसा कहां से लायेगा, पैसा उधार लेकर आता है, अपनी पत्नी का जेवर गिरवी रखता है, यह वादा करके लाता है कि यदि मैं समय पर यह पैसा नहीं चुका पाया तो मेरा जेवर डूब जाना चाहिए, यानी आप अपना कर लेना, इस आधार पर कई बहिनों के जेवर डूब गये हैं। उन्होंने इस आशा के साथ कर्जा लिया था कि मेरे बिजली का कनेक्शन हो जायेगा, मेरे खेत में पानी आ जायेगा, अच्छी फसल निकलेगी, अगर अच्छी फसल निकलेगी तो मैं यह कर्जा चुका दूंगा तो मेरे बच्चों का पेट भी भरेगा, अच्छी फसल भी होगी, कर्जा भी चुक जायेगा, मैं खुशहाल रहूंगा, लेकिन इस सरकार ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, अन्याय किया है और अन्याय का बदला लेने के लिए लोग बिलकुल आतुर हैं, इनसे लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, ये चिकित्सा के बारे में बहुत डींग हांकते हैं, दस लाख तक कर दिया है, पन्द्रह लाख तक कर दिया है। चिकित्सा का मतलब केवल ऐलोपैथिक चिकित्सा नहीं है। ऐलोपैथिक चिकित्सा में भी आपने कौनसी घोषणाएं पूरी कर दीं? आपने 2019-20 में घोषणा की थी कि रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में, रामगंज मण्डी मुख्यालय पर ट्रोमा हास्पिटल खोला जायेगा। अब खोला जायेगा तो आज तक, तीन-चार साल से अभी तक खुला नहीं है। हमारे हाड़ौती में एक कहावत कहते हैं, नंगीन सुसाड़ा, यानी अभी कुछ

(श्री मदन दिलावर)

दिखायी नहीं दे रहा है, सुन भी नहीं रहा है बल्कि इससे पूर्व रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालय को 70 बैडेड घोषित किया गया था, उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह अन्याय है वहां की जनता के साथ।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद पर तो कुठाराघात किया है। आयुर्वेद की दवाइयां नि:शुल्क नहीं दे रहे हैं, यह इस सरकार ने तय कर लिया है। आयुर्वेद एक प्राचीन पद्धति है, जिसकी दवाइयां भी ऐलोपैथी के साथ-साथ नि:शुल्क मिलनी चाहिए थी। इन्होंने घोषणा भी की थी कि हम सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों की दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाएंगे, वो भी उपलब्ध नहीं करवा पाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट केवल हवाई है, यह कहते हैं कि हम वृद्धों का सम्मान करते हैं, वृद्धों का मान रखते हैं। इतने सारे वृद्धाश्रम चल रहे हैं, उन वृद्धाश्रमों में मैस की राशि, भोजन भत्ते की राशि थी, उसको नहीं बढ़ाया गया है बल्कि उनके लिए, उनकी सहायता के लिए जो हैल्पर रहते थे, भोजन बनाने वाले रहते थे, सुपरवाइजर रहते थे, उनका भी पैसा देना बन्द कर दिया है। ये बुजुर्गों के दुश्मन हैं, मां-बाप को भी मां-बाप नहीं समझते हैं। +++ उनको किसी भी प्रकार का सम्मान देने में इनको शर्म आती है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा अन्याय है उन लोगों के साथ। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये क्या बोले जा रहे हैं? हम सब यहां पर माता-पिता का सम्मान करने वाले हैं। हमारे यहां कहा गया है,

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।।

माननीय सभापति महोदय, आप अपने माता-पिता का कहना नहीं मानते, यह एक्सपंज करवाओ आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, इनको तो भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है। इनको तो भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है। माननीय सभापति महोदय, ये भारत माता के दुश्मन हैं।

श्री सभापति: विराजिये आप। जो भी आपत्तिजनक शब्द हैं डिलीट किया जायेगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इनको तो भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है। +++ भारत माता के। शर्म तो करो, क्या ये मां-बाप का सम्मान करते हैं?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, अनुदानित छात्रावासों के मैस का भत्ता अलग, सरकारी छात्रावासों के मैस का भत्ता अलग, ये क्या ड्रामा है भाई? मेरे यह ड्रामा समझ में नहीं आया कि अनुदानित छात्रावासों में जो बच्चे रहेंगे उनको कम रोटी खाना चाहिए इनके हिसाब से और जो सरकारी छात्रावासों में रहते हैं उनको ज्यादा रोटी खाना चाहिए, यानी अनुदानित छात्रावासों के बच्चों को भूखा मारने का पूरा षड्यन्त्र इस सरकार का चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार को चाहिए था कि वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ाती, क्योंकि इनके जैसे +++ बहुत सारे हो गये हैं। मां-बाप दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, मैंने अभी प्रारम्भ किया है।

श्री सभापति: समाप्त करें। (व्यवधान) प्लीज सहयोग करें, एक मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, ये पहले वक्ता हैं, हमारे ओपनर हैं आज के। आज के हमारे पहले वक्ता हैं।

श्री सभापति: आपने जो यह सूची दी है आसन को वह 15 मिनट के लिए है, 15 मिनट से ज्यादा 16 मिनट इनको हो गये हैं, प्लीज विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, पहले दोनों वक्ताओं को पूरा समय मिले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मुझे कोई ऐतराज नहीं है फिर मैं दूसरे वक्ता को उतना समय नहीं दूंगा बिलकुल भी। मैं अलाउ नहीं करूंगा। विराजिये आप। (व्यवधान) क्यों समय बरबाद कर रहे हैं आप? माननीय सदस्य, आप एक मिनट में समाप्त करेंगे अपना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, ये हमारे प्रखर वक्ता हैं, पहले वक्ता हैं। पहले दो नाम दिये हैं उनको तो समय दो पूरा। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग कीजिये। विराजिये आप। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य मदन दिलावर के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने यह कहा था शराब नीति की घोषणा करते समय कि हम संयम बरतेंगे शराब पीने में और पिलाने में। यह कहा गया कि संयम बरतना चाहिए। संयम इतना बरता इन्होंने माननीय सभापति महोदय, स्कूलों की दीवारों के सहारे शराब की दुकानें खोल दी हैं, मन्दिरों की दीवारों के सहारे शराब की दुकानें खोल दी हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के मोहल्लों में शराब की दुकानें खोल दी हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र का जिस गांव में दो-दो, तीन-तीन अवैध शराब की दुकानें न हों। उसके कर्मचारी ने कहा मुझे, मेरे पास वीडियो भी है। इसमें कहा गया है कि हमारे ऊपर सरकार का दबाव है कि शराब ज्यादा बेचना चाहिए इसलिए हम इनकी ब्रांचों को आंख बन्द करके स्वीकृति देते हैं और जब शान्ती धारीवालजी ने मेरे को जवाब दिया था,

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री संयम लोढ़ा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। उप नेता महोदय, यह समय कंज्यूम कर रहे हैं अपना। प्लीज विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर बात रखने का मुझे मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, हमारा कल्याण मन्त्र है,

सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥

हमारा सनातन उद्घोष है, वसुधैव कुटुम्बकम्, अनेक सन्तों ने सदैव मानव जाति का मार्गदर्शन किया, इस भारत भूमि का मार्गदर्शन किया।

सन्त कबीरदासजी ने कहा,

साईं इतना दीजिये, जा मे कुटुम्ब समाय।

मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाय॥

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का यह बजट कबीरदासजी के इस दोहे को फलितार्थ करता है। सबका साथ, सबका विकास। जब कोई बजट प्रस्तुत हो और भारतीय जनता पार्टी के ब्यावर के विधायक इस बात के लिए माला पहने कि उनके क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोला गया है। उदयपुर के विधायक इस बात में प्रसन्नता अनुभव करें कि उनके क्षेत्र में 400 केवी का जीएसएस खोला गया है और भारतीय जनता पार्टी की धौलपुर की विधायक गदगद हो जाएं कि उनके क्षेत्र में 400 केवी का जीएसएस स्वीकृत किया गया है। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के रतनगढ़ के विधायक जुलूस के रूप में सैकड़ों लोगों से अपना इस बात के लिए स्वागत करवाएं कि रतनगढ़ में जिला चिकित्सालय स्वीकृत किया गया है। यह होता है ''सबका साथ, सबका विकास'' और लगातार इन तीन सालों में मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात का प्रयास किया कि वे दलगत भावना से ऊपर उठकर, किसी भी तरह की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के हित में लोक कल्याणकारी नीतियां प्रदान करें, लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करें और सबको आगे बढ़ने का अवसर दें। ऐसा नहीं कि जब राज्य सभा के चुनाव आ जाएं तो वे लोग जो ''सबका साथ, सबका विकास'' की बात करते हैं, मुख्य मंत्री के भाई के घर पर छापा डलवा दें, कांग्रेस पार्टी के नेता धर्मेन्द्र राठौड़ के घर पर छापा डलवा दें या राजीव अरोड़ा के घर पर छापा डलवा दें या पंजाब की विधान सभा के चुनाव आएं तो मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर छापा डलवा दें। माननीय सभापति महोदय, इन सब चीजों से सार्वजनिक जीवन में कद बौना ही होता है, विराट नहीं होता। कद विराट करने के लिए महात्मा गांधी की उन भावनाओं को आत्मसात करके निर्णय लेने पड़ते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मुझसे पहले के वक्ताओं ने सरकार को कोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता जब अपनी बात कहें तो मेरी बातों का जवाब दें। क्या यह सही नहीं है कि जब राजस्थान में वसुन्धरा राजे जी की सरकार थी और आप मंत्री थे, तीन साल में सिर्फ 36 कालेज आपने खोले थे? अशोक गहलोत की सरकार ने तीन साल में 123 कालेज खोले हैं। अशोक गहलोत की सरकार की आपसे तीन गुना उपलब्धि है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, पूरे पांच सालों में आपने सिर्फ 81

(श्री संयम लोढ़ा)

कालेज खोले थे और अशोक गहलोत की सरकार ने आपके 81 कालेजों की तुलना में मात्र तीन साल में डेढ़ गुना उपलब्धियां अर्जित कीं।

माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा, जब देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी बने, उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह नरेगा कांग्रेस का स्मारक है, लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वसुन्धरा जी की सरकार ने अपने तीन साल के शासन में नरेगा में सिर्फ 6602 करोड़ रुपये खर्च किये थे, जबकि इस सरकार ने खाली तीन साल में 26 हजार 851 करोड़ रुपये नरेगा में खर्च किये हैं। माननीय सभापति महोदय, वसुन्धरा जी के पूरे पांच साल के कार्यकाल में नरेगा में मात्र 21 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए और अशोक गहलोत ने तीन साल में 26 हजार करोड़ रुपये खर्च किये। आप टिकते कहां हैं उनके सामने? इन उपलब्धियों के सामने आपकी हैसियत क्या है?

राजस्थान की जनता ने भी इन 8 उप-चुनावों में अपने मतदान के जरिये आपको यह सन्देश दे दिया कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में उनका किस रूप में भरोसा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बीजेपी की सरकार ने अपने तीन सालों में नरेगा में मात्र 2 लाख 80 हजार 920 काम पूरे किये, जबकि इस सरकार ने मात्र तीन साल में 11 लाख 43 हजार 869 काम किये नरेगा में। आपके पांच सालों के आंकड़ों को भी मैं अगर लूं तो वे भी इन तीन सालों के सामने कम हैं। इन तीन सालों में 11 लाख ...(व्यवधान) ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे।

श्री सभापति: प्लीज अपने-अपने स्थानों पर जाएं आप लोग। मिस्टर बौहरा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, तीन सालों में इनके पांच सालों के 8 लाख 8 हजार 782 कामों की तुलना में अशोक गहलोत की सरकार ने 11 लाख 43 हजार 869 काम किये हैं। मतलब आपकी पांच सालों की उपलब्धियां भी अशोक गहलोत की सरकार की तीन साल की उपलब्धियों के सामने फीकी हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि नरेगा में तीन सालों में अशोक गहलोत की सरकार ने चार गुना तो काम किया और चार गुना खर्चा किया। तीन वर्षों के कार्यकाल में अशोक गहलोत की सरकार ने 877 करोड़ रुपये निर्माण श्रमिकों को सहायता

(श्री संयम लोढ़ा)

दी, जबकि आपकी सरकार ने तीन सालों में मात्र 347 करोड़ रुपये की निर्माण श्रमिकों को सहायता दी थी।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हालात और परिस्थितियों के कारण लगातार हर स्टेट की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है, लेकिन इसके बाद भी मुख्य मंत्री महोदय ने कोरोना के कठिन समय में संकल्प किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोयेगा। राजस्थान सरकार अपने प्रबन्धन से पूरी दुनिया में नामवर हुई, किसलिए? इसलिए कि अशोक गहलोत ने हर छोटे-से-छोटे आदमी, गरीब हो, असहाय हो, लौरी वाला हो, दिहाड़ी हो, मजदूर हो, फल-सब्जी वाला हो, हरेक के लिए सहायता पैकेज घोषित किया।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, 33 लाख परिवारों को साढ़े पांच हजार रुपये की सहायता उन्होंने उस वक्त उपलब्ध करायी और कोरोना काल सहायता में हर बालक-बालिका को एकमुश्त एक लाख रुपये दिये। माननीय सभापति महोदय, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ढाई हजार रुपये प्रति महीना और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा दी जा रही है। कोरोना में जो विधवा हुई, उन्हें 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। यहां मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा, यह अच्छी बात है कि आप कोरोना विधवाओं को 1500 रुपये सहायता दे रहे हैं, लेकिन शासन के लिए, एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए विधवा-विधवा में फर्क नहीं होना चाहिये। आपके लिए कोरोना विधवा भी वैसी ही है और दूसरी सामान्य विधवा महिला भी वैसी ही है, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि यह जो पेंशन में असमानता दिखाई पड़ रही है, उसे आप समान करें और राजस्थान की सभी विधवाओं को एक समान मासिक सहायता प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्र के लिए अशोक गहलोत साहब ने इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। एक साधारण आदमी को स्थानीय निकायों के माध्यम से 50 हजार रुपये तक का लोन मिलना सम्भव हुआ। अभी तो मैंने आपसे निवेदन किया कि तीन साल की उनकी उपलब्धियां किस मुकाम तक पहुंची हैं। उन्होंने अभी यह जो बजट पेश किया, चारों तरफ कहीं बोलने के लिए शब्द नहीं हैं। राजस्थान के कोने-कोने से एक ही ध्वनि आ रही है, ''कमाल कर दिया'', ''सोचा नहीं था, ऐसा हो

(श्री संयम लोढ़ा)

सकता है?", सालों-साल सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन निर्णय करने वाले लोग कहां हैं?

मैंने इस सदन में पहले भी मामला उठाया था कि यह जो सरकारी कर्मचारियों की 'न्यू पेंशन स्कीम' है, इसके बारे में सरकार क्या पुनर्विचार करने का इरादा रखती है? 2004 में यह पेंशन की स्कीम आयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता को यह बताना चाहिये कि 1972 में जो ये सुविधाएं शुरू हुईं वे कौन-से कारण थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन स्कीम लानी पड़ी?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मनमोहन सिंह।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): या तो आप इस्तीफा दे देना या मैं दे दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक ही सरकार के अलग-अलग मुलाजिमों में फर्क। आप थल सेना को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं, आप जल सेना को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं, आप वायु सेना को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं, पर सीआरपीएफ को नहीं दे रहे हैं, सीआईएसएफ को नहीं दे रहे हैं, अपने दूसरे एम्प्लाइज को नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है? दबाव बना। अनेक राज्यों ने समितियां गठित कीं। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने तो इसे लागू भी नहीं किया, लेकिन इन सालों में किसी सरकार ने यह साहस नहीं दिखाया कि हमारे मुलाजिम जो इस गवर्नमेंट के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं उनके रिटायरमेंट के बाद उनके परिवार महफूज रहें, आर्थिक चिन्ता से मुक्त रहें। मुझे एक उदाहरण याद है सभापति महोदय। 2004 के बाद एक आईएएस के भर्ती होने के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई और इस न्यू पेंशन स्कीम से उसके परिवार को कोई लाभ नहीं मिला, न उसकी पत्नी को मिला, न किसी और को मिला। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारे भीतर की मानवता को जगाते हैं, पर सुने कौन? राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने यह क्रान्तिकारी निर्णय लिया कि हम पूरे राजस्थान के जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लोयी हैं उनको पूर्व पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे और उसके माध्यम से खाली राजस्थान को ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान की सरकारों को प्रेरित करने का काम उन्होंने किया है कि मैंने यह हिम्मत की है, आप भी हिम्मत करिये और अपने मुलाजिमों के साथ में खड़े रहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता जब यहां पर जवाब देंगे तब वे यह कहेंगे कि हम देश के प्रधान मंत्री से मिलकर उनसे यह विनती करेंगे कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाये।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मैंने सात पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखे थे जब यह कोरोना आया था। मैं बहुत छोटी जगह से आता हूं, बहुत छोटे जिले से आता हूं। हमारे जिले को भारत सरकार के नीति आयोग ने आशान्वित जिले में शामिल कर रखा है और सरकार के बहुत से पैरामीटर्स हैं उनमें हम पिछड़े हुए हैं। मैंने बारबार प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा क्योंकि मैं यह देख रहा था कि मेरे क्षेत्र के नागरिकों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सिरोही, शिवगंज छोटी नगरपालिकाएं हैं, बड़ी नहीं हैं, वहां इतनी इण्डस्ट्री भी नहीं हैं, इतने उद्योग-धन्धे भी नहीं है और लोगों के सामने उस दौरान खाने-पीने का संकट आकर खड़ा हो गया। ठीक है, जन-सहयोग से, दूसरे तरीके से, सरकार के सहयोग से वे चीजें हुई। हमने प्रधान मंत्री जी से और लोक सभा के अध्यक्ष जी को मैंने व्यक्तिगत कहा कि आप छोटी नगरपालिकाओं के अन्दर शहरी रोजगार योजना शुरू करिये। प्रधान मंत्री जी को सात बार पत्र लिखे कि नरेगा के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 करिये। उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी, पर मैं अपने हृदय के अन्त:तल से मुख्य मंत्री अशोक गहलोत का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि आपने शहरी रोजगार योजना शुरू करने का निर्णय किया है। मैं आपका इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने नरेगा के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 करने का निर्णय किया और स्टेट फण्ड से करने का निर्णय किया।

माननीय सभापति महोदय, यह सदन दलगत राजनीति के आधार पर खाली आरोप-प्रत्यारोप का मंच नहीं है। इस सदन से राजस्थान के करोड़ों लोगों को यह उम्मीद है कि ऐसा नतीजा सामने आये जिससे उनके जीवन में उत्थान आये, उनके बच्चों के जीवन में उत्थान आये तो क्यों राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसदों को और हमारे प्रतिपक्ष के नेता को इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? राजस्थान के संसाधन सीमित हैं, कोरोना की मार, अर्थव्यवस्था की मार, हर जगह आवक घट रही है और दूसरी तरफ भारत सरकार जिस तरीके से बहुत प्लानिंग के तहत पेट्रोल पर सैस लगा दिये, आपने डीजल पर सैस लगा दिये, और दूसरी एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी लगा दी और वह लाखों-करोड़ रुपया जो भारत सरकार को प्राप्त होता है उसमें कोई हिस्सा राजस्थान सरकार को नहीं मिलता। उसका कोई डिवोल्यूशन नहीं है। वह सारा पैसा अपने तरीके से यूज कर रही है तो ऐसे में आपको

(श्री संयम लोढ़ा)

सोचना चाहिए कि अशोक गहलोत ने ये निर्णय कितना मजबूत हृदय रखते हुए लिए होंगे कि मैं अपने पैसे से 100 से बढ़ाकर 125 दिन करूंगा, अपने पैसे से शहरी रोजगार दूंगा। आपको आगे बढ़कर भारत सरकार को और देश के प्रधान मंत्री से मिलकर कहना चाहिए कि आप इनकी जिम्मेदारी अपने माथे लीजिये और जो निर्णय अशोक गहलोत ने किया है, वह पूरे देश के अन्दर आप लागू करिये।

माननीय सभापति महोदय, एक बड़ा चिन्ता का विषय था। अनेकानेक कारणों से देश में बिजली की स्थिति को लेकर हर प्रदेश अपने तरीके से काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि जब देश की सरकार 'वन नेशन वन टैक्स' की थ्योरी पर चल रही है, 'वन नेशन वन राशन कार्ड' की थ्योरी पर चल रही है और बिजली के क्षेत्र में आप लगातार स्टेट गवर्नमेंट को डिक्टेट कर रहे हैं। आप अगर राजकोषीय घाटे की लिमिट भी बढ़ा रहे हैं तो साथ में यह राइडर भी लगा रहे हैं कि आपको इतना पैसा ऊर्जा क्षेत्र पर खर्च करना पड़ेगा तो आप यह जिम्मेदारी साथ में क्यों नहीं उठाते कि पूरे देश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को एक राहत मिले? हर स्टेट में इस बात की पाबन्दी होनी चाहिए कि आप कितना पैसा उस प्रति यूनिट का रखेंगे। आज दिल्ली में आप की सरकार हर घरेलू कनेक्शन में 200 यूनिट मुफ्त दे रही है। ऐसे वक्त में इन कठिन परिस्थितियों के बीच में जब हमारी बिजली कम्पनियां एक विषम हालत का सामना कर रही है तो राजस्थान के लोगों के हक में अशोक गहलोत आकर खड़े हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, 100 यूनिट में से 50 यूनिट बिजली मुफ्त देने का उन्होंने निर्णय किया है। इसके साथ ही 150 यूनिट का जो उपभोग है उसमें प्रति यूनिट 3 रुपये अनुदान देने का निर्णय लिया, 150 से 300 यूनिट में 2 रुपये अनुदान देने का निर्णय लिया और 300 से ज्यादा के भी जो कंज़्यूमर हैं उनको इसमें राहत प्रदान की जायेगी। माननीय सभापति महोदय, इससे पहले हर किसान को 1000 रुपये प्रति महीने के अनुदान का डायरेक्ट बैनेफिट ट्रांसफर उन्होंने किया। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के साढ़े पांच लाख किसान ऐसे हैं जिनका इस डायरेक्ट बैनेफिट ट्रांसफर से जीरो बिल हो गया है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 16 लाख कनेक्शन हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको जब बोलने का मौका मिले तब यह बताना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पिछली सरकार के बिजली मंत्री हैं, टिप्पणी करने का अधिकार है। मुझसे ज्यादा ज्ञान है क्योंकि ये उस विभाग के मंत्री रहे हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, क्या ये बता सकेंगे कि उनके कार्यकाल में साढ़े पांच लाख किसानों का बिल जीरो हुआ था? जब वे बोलें तब इसका जरूर उत्तर दें। माननीय सभापति महोदय, आज तो राजस्थान के कोने-कोने में बैठा हुआ किसान एक राहत अनुभव कर रहा है। अभी जल संसाधन मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में एक कार्यक्रम में थे तो मैंने मन से किसानों ने पूछा और पूरा पण्डाल करतल ध्वनि से जिस रूप में अशोक गहलोत के प्रति कृतज्ञ था, वह देखने लायक था।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा और सभापति महोदय, मुझे याद आता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में एआईसीसी के मैम्बर के रूप में 2008 में मैंने दिल्ली में भाषण दिया था और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे, सोनिया गांधी जी बैठी हुई थीं। तब मैंने उनसे कैंसर को लेकर, हार्ट के इलाज को लेकर विनती की थी क्योंकि मैं कैंसर पीड़ित की डैथ पर वहां शोक व्यक्त करने गया तो मुझे पता चला कि उसके इलाज में उसके परिवार को कितना पैसा ब्याज पर लेना पड़ा। वह जान भी चली गयी, पैसा भी चला गया और वह परिवार तबाह हो गया। उस घटना से मैं प्रेरित हुआ कि मैं यह बात जो लोग शासन में निर्णय करने वाले हैं उनके सामने रखूं और मुझे इस बात की हृदय से खुशी है कि हिन्दुस्तान में सबसे पहले अशोक गहलोत साहब ने एक साधारण आदमी की तकलीफ को समझा। आपको याद होगा, जिस समय निःशुल्क दवा योजना लेकर आये तो हमारे प्रतिपक्ष के लोग किस तरीके की अफवाह फैलाया करते थे, किस तरीके का दुष्प्रचार उसके बारे में करते थे, लेकिन सत्य तो सत्य है सभापति महोदय। जब वे शासन में आये तो उनको भी वही मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना को जारी रखना पड़ा। उसके बाद निःशुल्क दवा योजना के बाद ये भामाशाह योजना लेकर आये थे। राजस्थान के इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई कार्ड बने और उस पर मुख्य मंत्री अपना फोटो छाप दें। कोई कार्ड आपने ऐसा देखा नहीं होगा जिसमें किसी राजनैतिक पार्टी का निशान उस पर चस्पा कर दिया जाये और इस तरीके से साढ़े तीन सौ से चार सौ करोड़ रुपया तत्कालीन सरकार ने राजस्थान के नागरिकों का बरबाद किया और इस मौजूदा सरकार को आकर नई योजना को लाना पड़ा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, माननीय सभापति महोदय, कोई भी

(श्री संयम लोढ़ा)

योजना हो, उसमें कमियां हो सकती हैं और उन कमियों को ठीक करने का दायित्व शासन का है, लेकिन हम इससे इन्कार नहीं कर सकते कि इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आने के बाद राजस्थान में 7 लाख 41 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया और 930 करोड़ रुपये की उनको कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त हुई। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि अब उस योजना में अशोक गहलोत साहब ने राशि बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपये कर दी। हम में से कई लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ा कि पेशेंट चला गया हास्पिटल में और उसके पास चिरंजीवी कार्ड नहीं है। उसके इलाज की कहां से व्यवस्था करें, कई बार सीनियर ब्यूरोक्रेट ने हमको सहयोग किया और आउट आफ द वे जाकर उनके इलाज की व्यवस्था की, लेकिन इस बार अशोक गहलोत साहब ने निर्णय किया कि अगर चिरंजीवी कार्ड किसी के पास नहीं है तो जिला कलेक्टर अथोराइज होंगे, उसका इलाज करवाने के लिए। इससे ज्यादा बेहतर बात कोई हो नहीं सकती।

माननीय सभापति महोदय, और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि इस बार उन्होंने पूरे राजस्थान में ओपीडी और आईपीडी पूरी तरह से नि:शुल्क कर दी है। माननीय सभापति महोदय, जिसके लिए मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। चिरंजीवी योजना के साथ-साथ उन्होंने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी दी है, जिसमें 5 लाख रुपये का कवर पीड़ित को दिया है और इसी तरीके से आप और हम सभी लोग, पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग, जिन परिवारों में भी शोक व्यक्त करने जाते हैं, 10 में से तीन मौतें मानकर चलिये कैंसर से होती हैं। अशोक गहलोत साहब ने हर जिले के अन्दर कैंसर डाइग्नोस्टिक वैन इस बजट में उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। इसके माध्यम से तुरन्त उन लोगों की बीमारी का हम पता कर सकें, वरना थर्ड स्टेज आ जाती है, फोर्थ स्टेज आ जाती है, जब जाकर के पूरी तरह से लाचार हो जाता है, तब जाकर पता चलता है कि यह कैंसर पीड़ित है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हर सीएचसी पर डायलिसिस की जो सुविधा प्रदान करने का आपने निर्णय किया है, यह बहुत ही श्रेष्ठ निर्णय है। अभी जिला स्तर पर भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, दूसरे जिलों के अस्पतालों में अनेक मरीजों को जाना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। मैं पहली बार इस सदन में जब चुनकर आया तो मुख्य मंत्री महोदय अशोक गहलोत ने हर विधान सभा क्षेत्र में दो-दो सीनियर सैकण्डरी

(श्री संयम लोढ़ा)

स्कूल दी थीं और मैंने दो सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करवा दीं। इसके बाद भी मुझ पर इलाके का दबाव था कि और सीनियर सैकण्डरी होनी चाहिए, कोई रास्ता नहीं था। शिक्षा मंत्री उस समय शान्ती धारीवाल साहब होते थे। मैंने उनके लिए उद्‌घाटन का कार्यक्रम बनाया और उनको मैं मोहब्बत नगर में लेकर गया, कार्यक्रम बहुत बढ़िया था, मंत्री जी प्रसन्न हो गये। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक ही निवेदन आपको करना चाहता हूं कि आप एक सीनियर सैकण्डरी यहां पर कर दें और उन्होंने अनाउंस की और उसके बाद में क्योंकि मंत्री की घोषणा की हुई थी वह सीनियर सैकण्डरी हुई। सभापति महोदय, आज पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर पहली बार यह क्रान्तिकारी निर्णय हुआ है कि एक साथ 3 हजार 920 स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल के रूप में क्रमोन्नत करने का निर्णय किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, सक्षम मां-बाप अपने बच्चों को दूर-दराज के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजने में समर्थ हैं, पर एक साधारण आदमी अपने मन में यह इच्छा रखते हुए भी कि उसके बच्चे भी कुछ काबिल बन जायें, बड़े बन जायें, अफसर बन जायें, मुंसिफ बन जायें, कुछ और बन जायें। वे उनको पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था नहीं कर पाते थे, पेट पालना ही मुश्किल होता था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा गहलोत साहब के साथ-साथ राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा जी को भी, अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आये और कितना पापुलर कान्सेप्ट है।

माननीय सभापति महोदय, एक समय था सरकारी स्कूल में बच्चे एडमिशन लेने से कतराते थे। आज वे परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि आपको लाटरी निकालकर के एडमिशन देना पड़ रहा है। यह अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान के अन्दर आपका यह प्रयोग किस रूप में कामयाब हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना, 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के टीचर लगाना, एक नयी सोच, नया संकल्प, जो आनेवाले वक्त में राजस्थान की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। हर जिले में सावित्री बाई फुले वाचनालय, धीरे-धीरे अध्ययन की प्रवृत्ति कम हो रही है। इसके माध्यम से हर सामान्य नागरिक को एक पढ़ने की जगह प्राप्त होगी।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, दिल्ली में हमारे प्रतिभावान छात्र-छात्राएं जाती हैं। हमारे नौजवान जाते हैं, कम समय के लिए भी जाते हैं, उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी, जहां वे रुककर के, रहकर के अपने भविष्य को संवारने का काम कर सकें। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि दिल्ली के उदयपुर हाउस में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल बनाएंगे, जिसमें ढाई सौ कमरे होंगे और पांच सौ लड़के-लड़कियां वहां रुक सकेंगे। इस पर 300 करोड़ रुपये खर्च करने का उन्होंने निर्णय लिया।

माननीय सभापति महोदय, रीट को लेकर इस सदन में बहुत चर्चा हुई, अनेक तरह की बातें रखी गईं, जिसका सरकार की ओर से धारीवाल साहब ने बखूबी जवाब दिया है। 62 हजार पदों के लिए जुलाई में एग्जाम होगा और उसके साथ-साथ एसओजी में एन्टी चीटिंग सेल बनाया गया है। जिस एसओजी ने राजस्थान के अन्दर पहली बार ये जो भी चीटिंग हुई, पेपर लीक हुए, उस मुक़दमे को खोलने के अन्दर पहली बार राजस्थान के अन्दर इतिहास बनाया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहा कि राजस्थान की एसओजी ने शानदार काम किया है। जो लोग लेकर वहां गये थे, वहां उस पर सवाल उठाने के लिए, उनको कहा कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, एसओजी ठीक काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, कहां तो देश की हुकूमत में आये लोगों ने यह वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 7 साल हो गये, 14 करोड़ मिल जानी चाहिए थी। जब हमारे पढ़े-लिखे नौजवानों ने मांगी तो क्या कहा, पकौड़े तलो। राजस्थान की सरकार ने इन 3 साल में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दे दीं।

माननीय सभापति महोदय, सवा लाख नौकरियां प्रोसेस के अन्दर हैं और अशोक गहलोत साहब ने इस बजट में ऐलान किया है कि इनके अलावा 01 लाख अतिरिक्त पदों पर वे और नौकरियां देंगे। राजस्थान का बेरोजगार हजारों की तादाद में अशोक गहलोत के सरकारी निवास पर पहुंचकर पिछले 7 दिन से एक उत्सव का माहौल बनाया हुआ है, आभार प्रदर्शन के लिए जो फिजां बनी वहां पर माननीय सभापति महोदय, मैंने भी अपने सार्वजनिक जीवन में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए

(श्री संयम लोढ़ा)

जो विकास फण्ड पहले 100 करोड़ का होता था, इस बजट में उन्होंने उसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने का तय किया है।

माननीय सभापति महोदय, इन्दिरा रसोई में किस गुणवत्ता का खाना मिलता है, किस कामयाब तरीके से इन्दिरा रसोई चल रही है। 358 जगह पर इन्दिरा रसोई चलती थी और उसकी कामयाबी को देखते हुए अशोक गहलोत साहब ने एक हजार स्थानों पर इन्दिरा रसोई खोलने का फैसला किया है।

माननीय सभापति महोदय, दिव्यांग स्कूल बढ़ाकर 2 से 5 हजार कर दी। कालीबाई भील और देवनारायण में, जो 13 हजार का स्कूटी का प्रोविजन था, उसको बढ़ाकर के 20 हजार कर दिया।

अब इन्दिरा गांधी मातृत्व प्रोत्साहन योजना। इसमें आपने दूसरी संतान पर पूरे राजस्थान में 6 हजार रुपये देने का निर्णय किया है। दो, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन चिकित्सा मंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं कि यह दूसरी सन्तान पर प्रोत्साहन देने का कौन-सा तरीका है। आप राजस्थान की आबादी को कहां ले जाना चाहते हो? बड़ी मुश्किल से तो हम 2. समथिंग पर आकर के अटके हैं। अगर आप इस तरह से सन्तानों के जन्म पर प्रोत्साहन देने लगेंगे तो राजस्थान की जनसंख्या और अधिक बढ़ जायेगी। यह जो आपने पहले चार जिलों में किया था, अब पूरे राजस्थान में आप यह इन्दिरा गांधी मातृत्व प्रोत्साहन योजना का जो कर रहे हो, साढ़े तीन लाख महिलाओं को और पैसा दोगे कि दूसरी सन्तान पैदा की है, इसलिए यह चैक पकड़ो। आप विचार करना इस पर कि क्या आपका निर्णय यह जनसंख्या नीति के विपरीत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत साहब को, पालनहार में भी 6 साल के बच्चों के लिए, जो अब तक हम 500 रुपये दे रहे थे। उसको बढ़ाकर 1500 रुपये किये और 6 साल से बड़े बच्चे के लिए जो 1 हजार रुपया दे रहे थे, उसका बढ़ाकर 2 हजार रुपया किया। इससे उन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, उसके परिवार का मनोबल बढ़ेगा और उनको एक आर्थिक सुरक्षा का कवच प्राप्त होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि कृषि बजट भी अलग से मुख्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है। 2021-22 के जो रिवाइज एस्टीमेट थे, उनकी तुलना में इस बार 2022-23 के अन्दर 11.68 परसेंट ज्यादा बजट प्रोविजन राजस्थान के इस बजट में किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, खेल, कला 2021-22 के रिवाइज

(श्री संयम लोढ़ा)

एस्टीमेट की तुलना में 44 हजार 821 करोड़ के विपरीत 49 हजार 627 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है, जो पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट से 11%

(समय: 13.00 बजे)

ज्यादा है। ग्रामीण विकास में 2021-22 के रिवाइज्ड एस्टिमेट में 22,672 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया था। इस साल के बजट एस्टिमेट में बढ़ा करके 28,179 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 24% ज्यादा है। चिकित्सा में 2021-22 के रिवाइज्ड एस्टिमेट में 17,078 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जो इस बार बढ़ा करके 20,111 करोड़ रुपये किया है, जो 18% ज्यादा है। समाज कल्याण में 14,899 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसको बढ़ाकर 15,222 करोड़ रुपये किया गया। पुलिस का जैसा मैंने अभिभाषण पर ध्यान आकृष्ट किया था। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को कि 7,600 करोड़ रुपये का 2021-22 में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट में प्रावधान था, उसको बढ़ा करके 8,189 करोड़ रुपये किया। इसी तरीके से ऊर्जा में 24,828 करोड़ का जो प्रावधान था 2021-22 की आर.ई. में, उसको बढ़ा करके 26,750 करोड़ रुपये किया है। सड़क एवं पुल में 8,077 करोड़ का जो प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 9,267 करोड़ रुपये किया जो पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट से 15% ज्यादा है। इसके साथ ही नगरीय विकास में 11,044 करोड़ रुपये का जो प्रावधान था, उसमें कटौती हुई है। शान्ती धारीवाल साहब को देखना चाहिए कि सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री हैं, सबसे सशक्त मंत्री हैं, उनका बजट कैसे घट रहा है। वह 21% घटा है तो उस पर उनको खास ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, रेवेन्यू रिसीट्स के लिहाज से भी जो अनुमान लगाया है, 2021-22 का अनुमान था 1,89,431 करोड़ रुपये और इस बार अनुमान किया है 2,14,977 करोड़ रुपये। वह भी पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट की तुलना में ज्यादा है। स्टेट की ओन टैक्स रेवेन्यू 2021-22 की 82,218 करोड़ रुपये रिवाइज्ड एस्टिमेट में अनुमानित की है, उसको भी बढ़ाकर बजट एस्टिमेट इस साल में 98,294 करोड़ रुपये किया है, जो 19% की बढ़ोतरी है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तीन दिन पूर्व इस विधान सभा में प्रतिपक्ष के उप नेता ने एक आरोप लगाया कि जो जालीपा लिग्नाइट खनन है उसके अन्दर जो कंपनी से वसूली की जानी थी उस

(श्री संयम लोढ़ा)

वसूली को रोक करके कांग्रेस की सरकार ने पांच करोड़ रुपये लेकर के उस वसूली को रोक दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता इसका जवाब दे दें क्योंकि उनके उप नेता ने सदन में तथ्यहीन बात कही है। जब आप सरकार में मंत्री होते थे वसुन्धरा की सरकार में 2002 से 2008 के बीच में, 13 नवम्बर, 2006 को भारत सरकार ने कपूरड़ी व जालीपा ब्लाक को लिग्नाइट के लिए आरएसएमएम के पक्ष में आबंटन किया और फिर यह तय हुआ कि या तो आरएसएमएम इसको चलायेगा या जोइंट वेंचर से चलायेंगे और संयुक्त उपक्रम बना बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड, आरएसएमएम की हिस्सेदारी 51% और राजवेस्ट की हिस्सेदारी 49% और ऊर्जा विभाग ने राजवेस्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट 29 मई, 2006 को हस्ताक्षरित किया, तब अशोक गहलोत मुख्य मंत्री थे या मुख्य मंत्री आप थे या सरकार बीजेपी की थी कि सरकार कांग्रेस की थी?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हो, चाहे एग्रीमेंट के हस्ताक्षर हो, चाहे भारत सरकार के द्वारा आरएसएमएम के पक्ष में जारी करना हो, यह सभी घटनाएं तब हुई जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आपको टोकना नहीं चाहता।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप टोकिये भी मत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप यह बतायें कि 2019 में एजी ने जो पैरा बनाया, एजी ने डिमाण्ड निकाली वह किसका समय था? आप बचाना चाहते हो, धन्ना सेठों को बचाने की वकालत कर रहे हो आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मि. डिप्टी लीडर, कमजोर आदमी चिल्लाते हैं। बैठ जाइये आप। आपको मैं पूरी बात निवेदन करूंगा। मैंने आपको शान्ति से सुना है आपकी आंखों में आंखें डालकर। आपको शान्ति से सुना है मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप हाउस का उपयोग धन्ना सेठों को बचाने के लिए कर रहे हो। एजी की रिपोर्ट है 2019 की, उसमें साफ लिखा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय उप नेता महोदय। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, प्लीज सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं एक-एक सारे पत्र टेबल करूंगा। यह कोई तथ्यहीन बात नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह आपस में वार्ता के लिए मैंने नहीं कहा है। प्लीज आप अपनी बात कहें। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिए। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अकारण उत्तेजना पैदा नहीं करें। प्लीज विराजिए आप। प्लीज आप अपनी बात चालू रखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं एक-एक डाक्युमेंट टेबल करूंगा। माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर में कपूरड़ी व जालीपा के पट्टे आरएसएमएम के पक्ष में जारी हुए थे, जिसमें कपूरड़ी का पट्टा 12 अक्टूबर, 2011 को हुआ और जिस जालीपा का प्रश्न उठाया गया, इस सदन में जिस एजी की रिपोर्ट का हवाला किया गया वह 25 मई, 2015 को उसका अनुबन्ध हुआ था और 25 मई, 2015 में राजस्थान में किसकी सरकार थी? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको कि इसके बाद में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, प्लीज विराजिए आप। अकारण उत्तेजना पैदा मत करिये। प्लीज विराजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: प्लीज माननीय सदस्य, विराजिये। क्या मंशा है आप लोगों की? मैं अलाउ नहीं करूंगा इस तरह से कि आप आपस में एक-दूसरे से वाद-विवाद करें। मैं अलाउ नहीं करूंगा। आसन से जिसका नाम पुकारा गया सिर्फ उसका अंकित होगा, बीच में किसी का अंकित नहीं होगा और माननीय सदस्य जो बैठे-बैठे बोल रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ लिख लीजिये, नये आये हो, नहीं बोलेंगे तो कुछ कम नहीं हो जायेगा आपका। समय की अपनी सीमा है, बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है। आप इस तरह से बीच में अपनी चुहलबाजी करके जो माननीय सदस्य बोलने के लिए यहां पर

(श्री सभापति)

बैठे रहते हैं शाम को सात बजे तक, आप उनका समय जाया करते हैं। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार से जब इसकी अनुमति प्राप्त नहीं हुई तो तीन बार राजस्थान सरकार की ओर से पत्र लिखे गये। 12 जून, 2014, 5 अगस्त, 2014 और 24 अप्रैल, 2015 और इसके बाद भी भारत सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई तो तत्कालीन राजस्थान सरकार ने पट्टा हस्तान्तरण की संविदा का पंजीयन कर लिया और 2015 में सरकार राजस्थान में वसुन्धरा राजे की थी। माननीय सभापति महोदय, यह सारी चीजें भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई और उसके बाद 18 मई, 2016 को भारत सरकार ने उसको शून्य घोषित कर दिया, तब किसकी सरकार थी? दोनों ही स्थानों पर माननीय सभापति महोदय, बीजेपी की सरकार थी और जिस आडिट पैरा का जिक्र कर रहे हैं 2,436 करोड़ का, वह 2016 का पैरा है, इस सरकार के कार्यकाल का नहीं था। सरकार में मंत्री बने हुए थे, तब आप क्या कर रहे थे? और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जितने चीफ सैक्रेटरी रहे सी.के. मैथ्यु हों, सी.एस. राजन हों, सबके आन रिकार्ड भारत सरकार को लिखे गये पत्र मौजूद हैं, सरकारें किसी की भी रही हों।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन में वहां से कोयला प्राप्त हो रहा है और जितनी भी प्रक्रियाएं की गयीं, स्टेट के इन्ट्रेस्ट में की गयीं और जो एजी ने पैरा बनाया है उसका जवाब देने की प्रक्रिया को माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हूं माननीय कटारिया जी के साथ में। मुझे भी पता है। कोई इसको रद्द नहीं किया है। जब तक भारत सरकार निर्णय नहीं कर देती, तब तक स्थगित किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह पांच करोड़ रुपये के चंदे की बात कही कांग्रेस को। कौन से साल में दिया, 2016 में और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फिर बीच में बोल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: वो सक्षम हैं अपनी बात सम्भालने के लिए, आप विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सुनिये, भारतीय जनता पार्टी को 2010-11 में चंदा मिला 14 करोड़ रुपये, 2011-12 में मिला 33 करोड़ रुपये, 2012-13 में मिला 83 करोड़ रुपये, 2013-14 में मिला 170 करोड़ रुपये, 2014-15 में मिला 437 करोड़ रुपये, 2016-17 में मिला 532 करोड़ रुपये, 2017-18 में मिला 437 करोड़ रुपये, 2018-19 में मिला 742 करोड़ रुपया और 2019-20 में मिला 785 करोड़ रुपया। क्या आपकी वहां नोट छापने की फैक्ट्री लग गई है, क्या मशीन लग गई है? माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस को क्या चंदा मिला, बीजेपी की तुलना में 2019-20 में 785 करोड़ की तुलना में 139 करोड़ रुपये। 2018-19 में 742 करोड़ की तुलना में 148 करोड़ रुपये। माननीय सभापति महोदय, यह जो सारे आरोप लगाये गये हैं, सब पूरी तरह से मिथ्या हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। यह जितना भी काम किया है वह भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने किया है और स्टेट आज भी अगर उस अनुबंध के साथ खड़ा है तो राज्य की जनता के हित में खड़ा है कि वहां से 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन संयंत्र को कोयला प्राप्त हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, सनसनी पैदा करना अलग विषय है, पर कई बार वह सनसनी खुद पर ही आकर गिर जाती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि सेंट्रल टैक्स में राज्यों का 41 परसेंट शेयर होगा, लेकिन क्या प्रतिपक्ष के नेता जब उत्तर देंगे तब इसका जवाब देंगे कि राजस्थान को 2021-22 में क्या टोटल रेवेन्यू का 41 परसेंट मिला है? आज अगर आप उसकी तुलना करेंगे, हिस्सा निकालेंगे तो राजस्थान को 41 परसेंट के बजाय मात्र 30 से 33 परसेंट तक सेंट्रल रेवेन्यू में हिस्सा मिलता है और यह परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुईं? यह परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न हुईं कि आपने सैस और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को उस दायरे से बाहर रख दिया। राजस्थान सरकार बार-बार पत्र लिखकर आपसे मांग करती है, भारत सरकार को कहती है कि यह जितनी भी रेवेन्यू हो रही है, उसको आप उस कोष में डालिये जिससे राज्य की जनता के माध्यम से जो आपको टैक्स प्राप्त हो रहा है, उसका हिस्सा राज्य की जनता को प्राप्त हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि खाली 2021-22 में राजस्थान को 11 हजार करोड़ रुपये कम मिले हैं। प्रतिपक्ष के नेता इस बारे में भी पहल करें। उनका लम्बा सार्वजनिक जीवन है। हम

(श्री संयम लोढ़ा)

उनका बहुत आदर और सम्मान करते हैं कि यह जो राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को ठीक करें। बिना पैसे तो कोई सरकार काम नहीं कर सकती।

माननीय सभापति महोदय, यह कहा गया था कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति इतने साल तक, पांच साल तक केन्द्र सरकार करेगी। जो क्षतिपूर्ति का पैसा स्टेट को मिलना चाहिये था, वह मिला नहीं। अब आपने क्या किया, उसकी जगह राज्यों को बाध्य किया है कि क्षतिपूर्ति की जगह हम आपको लोन देते हैं और इस तरीके से राज्यों को ऋण के दलदल में धकेला जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो स्टेट की रेवेन्यू में कमी हो रही है, दूसरी तरफ ऋण भार बढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, कोई भी स्टेट कैसे सरवाइव करेगा। आप खड़े होकर कल कहेंगे राजस्व घाटा बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? आप स्टेट को कमजोर कर रहे हैं, हर दृष्टि से कमजोर कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि 2020-21 में जीएसटी का जो क्षतिपूर्ति अनुदान 4604 करोड़ रुपये राजस्थान को मिलना था, उसकी जगह भारत सरकार ने बैक टू बैक लोन दिया। 2021-22 के भी क्षतिपूर्ति अनुदान की जगह 7268 करोड़ रुपये का बैक टू बैक लोन दिया है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति में 2015-16 से हर साल 14 परसेंट वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाकर निर्णय हुआ था, लेकिन सेंटर बजट में क्या प्रावधान किये हैं? माननीय सभापति महोदय, सेंटर बजट में कोई प्रावधान नहीं किये हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, खुद मुख्य मंत्री जी इस सदन में अनेक बार कह चुके हैं कि जो पेयजल योजनाएं पहले भारत सरकार की थीं, कृषि योजनाएं थीं वह 90:10 के रेशो पर थीं। आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में आप वह रेशो घटाकर 50:50 पर ले आये। इतना ही नहीं, पहले जो सेंटर का पैसा पीडी अकाउंट में रहता था, अब केन्द्र सरकार ने निर्णय कर दिया हमारा पैसा इस बैंक के खाते में आयेगा और आप भी अपना पैसा इस खाते में डाल दो। माननीय सभापति महोदय, स्टेट में जैसे जुगाड़ होता है वैसे होता है और जुगाड़ की व्यवस्था करके धीरे-धीरे इन योजनाओं को गति देने का काम करते हैं। इस तरीके से यह राजनीतिक विषय नहीं है। आप भी मंत्री रहे हैं, आपमें से अनेक लोग मंत्री रहे हैं। आप भी यही सब करते रहे हैं। अब यह निर्णय होगा, उसका स्टेट को किस रूप में नुकसान उठाना पड़ेगा,

(श्री संयम लोढ़ा)

वह आपको सोचना है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा राजस्व घाटा कम करने के लिये केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुदान देना तय हुआ। 2021-22 में 9878 करोड़ मिला। 2022-23 में राजस्थान को राजस्व घाटा कम करने के लिये 4862 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान मिलना चाहिये था, लेकिन इस साल के केन्द्रीय बजट में उसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री किसान निधि में 2021-22 में जो 126808 करोड़ का रिवाइज्ड एस्टीमेट था, उससे भी 4 परसेंट कम उपयोग किया गया। जब प्रतिपक्ष के नेता खड़े हों तो जरूर जवाब देना, 2021-22 में पीएम किसान निधि की दूसरी किश्त 11 करोड़ 20 लाख लोगों को मिली, लेकिन तीसरी किश्त 10 करोड़ 70 लाख लोगों को मिली। 50 लाख किसान कौनसे कारण से उस किश्त से वंचित किये गये? माननीय सभापति महोदय, जो टीनेंट फार्मर किसी जमीन पर खेती करते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। कभी 28 परसेंट होते थे, आज बढ़कर वह 51 परसेंट हो गये लेकिन उसको पीएम किसान सम्मान निधि का कोई फायदा नहीं मिलता। पार्लियामेंट की कमेटी ने जो लिखा है वह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं -

"The Standing Committee (2020) noted that tenant farmers, who are a significant part of landless farmers in many states, do not receive the income support benefits. It recommended the government to examine this issue in coordination with states so that landless farmers can also receive benefits under the scheme."

माननीय सभापति महोदय, उस गरीब आदमी को जिसके जिम्मे सारी खेती होती है, सिर्फ वह लैंड का ऑनर नहीं है, इस कारण से उसको कोई पैसा नहीं मिलता। आपने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। लैंड होल्डर की आमदनी तो आप दोगुनी नहीं कर पाये, उसकी भी नहीं कर पाये। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, वह मजदूर जो खेत में काम करता है, उसकी कमाई बढ़ाने की दिशा में भी कोई एफर्ट नहीं हुआ है। यह ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोग्राम जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम था, 2021-22 में बजट प्रावधान किया 3712 करोड़ का बजट एस्टीमेट है और 2021-22 का रिवाइज्ड एस्टीमेट 2000 करोड़ रुपये है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने क्या लिखा, मैं पढ़कर सुना देता हूं -

(श्री संयम लोढ़ा)

"The Standing Committee on Agriculture (2021) recommended that the guidelines of the scheme should be changed to ensure that the states are provided funds for their upcoming projects in the agriculture sector."

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा, 2021-22 में जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था, उसकी तुलना में 3 परसेंट कम प्रावधान किया है, मात्र 15500 करोड़ रुपये किया है।

माननीय सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ एग्रीकल्चर का हमारे विकास में योगदान 51 परसेंट था। हम लगातार यह दावा करते हैं कि हमने कृषि को बढ़ावा देने के लिये किया, लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ आपके माध्यम से निवेदन करना पड़ रहा है कि आज 2020-21 का जो फिगर है, कृषि का योगदान घटकर 16 परसेंट रह गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इर्रिगेशन 2019-20 में आपने 11 लाख 7 हैक्टेयर को कवर किया। 2020-21 में घटकर 9 लाख 40 हजार हैक्टेयर रह गया और 2021-22 में माननीय सभापति महोदय, माइक्रो इर्रिगेशन में मात्र 2 लाख 70 हजार हैक्टेयर भूमि को कवर किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं कर रहा हूं। 2019-20 में माइक्रो इर्रिगेशन के लिये जो आपने बजट प्रोविजन रखा वह 3500 करोड़ था और खर्चा 2,700 करोड़ का किया, 23 परसेंट कम। 2020-21 में 4000 करोड़ का प्रोविजन था, खर्चा किया 2,562 करोड़ रुपये, 36 परसेंट कम। 2021-22 में 4 हजार करोड़ का प्रोविजन था, वह घटकर 2 हजार करोड़ रह गया, मतलब 50 प्रतिशत कम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चाहे भारत सरकार हो या चाहे राज्य सरकार हो, दोनों कर्ज से घिरी हुई हैं। दोनों तरफ यही हालत है। अगर मैं आपको भारत सरकार के आंकड़े बताऊं तो आउटस्टेण्डिंग लायबिलिटीज 2016-17 में 48 प्रतिशत थी, आज 2022-23 में बढ़कर 60 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। 43 परसेंट पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है।

इसके अलावा साधारण आदमी का स्तर ऊंचा उठाने का बड़ा दावा करते हैं, लेकिन भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि आपने इस साल के

(श्री संयम लोढ़ा)

बजट में फूड सब्सिडी में 28 परसेंट की कटौती की है। 2021-22 का आपका जो रिवाइज एस्टीमेट था, वह 3 लाख 4 हजार 454 करोड़ रुपये था। माननीय सभापति महोदय, इस बार के केन्द्रीय बजट में उसको घटाकर 2 लाख 70 हजार 684 करोड़ रुपये कर दिया। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास में भी 2021-22 में 1 लाख 55 हजार 43 करोड़ रुपये का प्रोविजन था, उसमें 10.9 प्रतिशत की कटौती की गयी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट में समाप्त करता हूं। दो-तीन फिगर और रख देता हूं। केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी में 2020-21 में 1 लाख 41 हजार 735 करोड़ का प्रोविजन था, वह घटकर 1 लाख 7 हजार 715 करोड़ हो गया, यानी 24 परसेंट की कमी हो गयी। मैं और भी बहुत-सी बातें रख सकता था, लेकिन आपने आदेश के अनुसार दो मिनट में समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता का लगातार स्टेटमेंट पढ़ता रहा और सुनता रहा हूं। इस सरकार का मंत्रिमण्डल विस्तार हुआ नहीं कि यह सरकार गिरी। बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति हुई नहीं कि यह सरकार गिरी। लो, मंत्रिमण्डल विस्तार भी हो गया, बोर्ड चेयरमैन की नियुक्तियां भी हो गयीं, राजनीतिक नियुक्तियां भी हो गयीं। आपके सपने तो धरे रह गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरे मित्र, आपके सपनों का क्या हुआ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे सपने यही हैं। मैं इस सदन में खड़ा हूं, आपके आशीर्वाद से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नौ सलाहकार हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह तो आपको भी पता है कि अशोक जी गहलोत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस्तीफा दो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आर्डर तो हो, तब इस्तीफा दूं।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह पूरे देश के जनमानस में बस गया है। देश के कोने-

(श्री संयम लोढ़ा)

कोने तक इसकी गूंज पहुंची है। खाली गूंज ही नहीं पहुंची है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भी इस पर बयान देना पड़ा और देश के प्रधान मंत्री की भी चिन्ता की लकीरें बढ़ गयी हैं। मैं आपके माध्यम से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो साहसिक निर्णय किया है, पूरे हिन्दुस्तान की आम अवाम तक आवाज पहुंचाइये, जिससे आने वाले वक्त में 2024 के अन्दर देश से इस नाकारा, भ्रष्ट और जनविरोधी सरकार को उखाड़कर फेंका जा सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 2022-23 का बजट जो राजस्थान की आम जनता के लिए पेश किया गया है, ऐसा लगता है कि सरकार के पास जेब में तो एक रुपया है और विभिन्न योजनाओं के तहत वह हजारों रुपये खर्च करना चाहती है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कर्ज पर कर्ज लेकर राजस्थान के आम व्यक्ति को हजारों के कर्ज में छोड़कर जाना चाहती है। 2018 में जब हमारी सरकार गयी तो राजस्थान पर 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसमें उदय योजना के 62 हजार करोड़ रुपये शामिल थे, जो कि सरकार ने अपने खाते में लिये, उसको शामिल करते हुए 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था। जब यह 2023 का बजट खतम होगा तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के आम व्यक्ति पर साढ़े छह लाख करोड़ का कर्ज होगा। 58 हजार करोड़ का कर्जा तो आज डिस्काम पर है, 33 हजार करोड़ डिस्काम से उत्पादन और रिन्युएबल एनर्जी और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी बिजली पैदा कर रहे हैं, वे डिस्काम से मांग रहे हैं। मतलब डिस्काम पर 90 हजार करोड़ का कर्ज है। यह तो वह बात हुई कि उधार में घी लाओ और पीते जाओ और घर को बेचते जाओ। (व्यवधान) हमने तो जो किया है, वह आपने तीन साल में कर दिया है।

श्री सभापति: बीच में इन्टरवीन नहीं है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आपने जो तीन साल में कर दिया है, उसके लिए आने वाले समय में आपको जनता बतायेगी। सरकार वाहवाही लूटना चाहती है, पर इस सरकार की हकीकत क्या है? मैं भी पांचवीं बार विधायक हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं। गांव में बड़ा होकर यहां तक पहुंचा हूं। हकीकत में

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। यह हालत हो गयी है कि मंत्री जो कि हमारे जिले के प्रभारी हैं, उनके आठ-नौ महीने में दर्शन होते हैं। मुख्य मंत्री स्वयं दो साल बाद घर से बाहर निकले हैं तो आप समझ सकते हैं कि निचले स्तर पर सरकार कैसे चल रही है? मुख्य मंत्री जी का जनता से सम्पर्क हुए दो साल हो गये हैं। कोविड एक बहुत बड़ा बहाना था, मंत्रियों के लिए भी एक बहुत बड़ा बहाना था। आप कभी अपने प्रभार क्षेत्र में नहीं जाते हो। जनता की क्या तकलीफ है? हकीकत यह है कि चार-चार पटवार सर्कल पर एक पटवारी है। आपकी चार-चार ग्राम पंचायतों पर एक ग्राम विकास अधिकारी है। 'प्रशासन -गांवों-के-संग' की आपने बहुत वाहवाही लूटी, जबकि हकीकत यह है कि यह 'प्रशासन-गांवों-के-संग' अल्टीमेट फैलियर था। आपके तहसीलदार स्ट्राइक पर थे, आपके पटवारी स्ट्राइक पर थे। आपका आर.आई. स्ट्राइक पर था। पटवारी ने स्ट्राइक की कि मैं पास के पटवार सर्कल पर काम नहीं करूंगा। यह हालत थी कि ग्राम सेवक भी हड़ताल पर चले गये। आधा टाइम हड़ताल में बीत गया। लोगों ने अपना विश्वास खो दिया।

लगभग सभी कैम्पों पर मुझे जाने का मौका मिला, क्योंकि हम तो फ्री थे। हम तो कैम्प में जाएं और लोगों के दर्द सुनें। दर्द सुनने के बाद यह हुआ कि लोगों का कैम्पों में जाना बन्द हो गया। कैम्पों में क्या हुआ, प्रशासन ने यह तय कर लिया कि इसको कैसे फुलफिल करें। तीन-चार तो बंटवारे कर लिये, दो-तीन पालनहार बना दिये, पेंशन बना दी। पंचायत ने मेहनत करके नई आबादी के लिए जो प्रस्ताव तैयार किये थे, नये खेल के मैदान के लिए, नये गोचर के लिए या और किसी के लिए या फिर अतिक्रमण हटवाने के लिए, वह पुलिन्दा बंधा हुआ पड़ा है। आज उस पंचायत के सरपंच ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं।

"प्रशासन-शहरों-के-संग" - ऐसा लगता था कि हर गरीब को पट्टा मिल जायेगा। 269 पट्टे दिये, मामूली पट्टे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन नगरपालिकाएं हैं। एक-एक नगरपालिका में स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती और 269 के मात्र 200 पट्टे नगरपालिका में लोगों को मिले हैं। आपकी नगरपालिका में लोग चक्कर काट रहे हैं। 1999 की पूर्व की कालोनियां थीं, आपने उसको कर लिया था, उसके पट्टे अभी तक जारी नहीं हुए। आज लोग ठगा-सा महसूस कर रहे हैं।

हैल्थ की बात करें, तो मेरे पूरे क्षेत्र में एएनएम और जीएनएम की 50 परसेंट पोस्टें खाली मिलेंगी। डाक्टर्स की पोस्टें आपको खाली मिलेंगी। मैं

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, जिसमें आम आदमी तीन लाख तक का इलाज करा सकता था। एनएफएस से जुड़ा हुआ आदमी इलाज करवा सकता था। आपने उसको चिरंजीवी योजना किया। आपने उसको 5 लाख कर दिया। आपने उसको 10 लाख कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी, आपने 10 लाख कर दिया, परन्तु असत्य वाहवाही लेने से कुछ नहीं है। अधिकांश मेडिकल कालेज और प्राइवेट हास्पिटल्स आज भी चिरंजीवी योजना से जुड़े नहीं हैं। आज भी लोग जाते हैं मेडिकल कालेजों में, सोचते हैं कि 5 लाख का कैशलेस है, यह मैं हकीकत कह रहा हूं, गरीब आदमी को कहते हैं कि मैं कोई चिरंजीवी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। उसको जेब से पैसे खर्च करके या घर गिरवी रखकर या गहने बेचकर अपना इलाज करवाना पड़ता है। उसको इलाज चिरंजीवी योजना में प्राइवेट मेडिकल कालेज में, आज दिन तक, क्यों पूछा मैंने कि सरकार भामाशाह में तो हमको आई.सी.यू.बैड पर 500 रुपये देती है और हमारी कोस्ट पड़ती है 4500.

सभापति महोदय, आप आर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं कि आज 200 विधायक हम यहां बैठे हैं। अगर हमारे में से किसी का आर्गन फेल हो जाए या हमारे परिवार में किसी का आर्गन फेल हो जाए, मैं तो किडनी की बात कर रहा हूं, राजस्थान में कौनसा व्यक्ति इस विधान सभा में होगा जो अपने आर्गन को ट्रांसप्लांट राजस्थान में कराएगा। ले-देकर गुजरात और बाम्बे दौड़ते हैं क्योंकि वहां डाक्टर्स की स्पेशिलिटी है। उन्होंने इस काम को सीखा है। उन्होंने बाहर जाकर बहुत नजदीक से देखा है। मेरे वहां छोटे बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ी। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, जहां 30 हजार से कम उसकी आय है, उसका गरीब आदमी का 6-6.5 लाख का खर्चा आता है, उसको मात्र 90 हजार रुपये दिये। 90 हजार रुपये देकर गुजरात में किडनी ट्रांसप्लांट की उस बच्ची की। उसकी मां ने उस बच्ची को किडनी दी। मैंने बहुत नजदीक से देखा है। उसको हमने कई व्यापारिक संगठनों से मदद करके भेजा है। ऐसे कई उदाहरण हैं।

आज मैं पूछता हूं कैंसर, किस स्थिति से कैंसर आज हमारे प्रदेश में बढ़ रहा है? इस दो साल के कार्यकाल में, इस कोविड में जो मेरे क्षेत्र में इतना कैंसर नहीं था, मुझे आज देखने को मिल रहा है कि हर गांव में 25-30 केस आपको कैंसर पीड़ित मिलेंगे। आज हमारे पास कोई स्पेशलाइज डाक्टर नहीं है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आज लोग गुजरात दौड़ते हैं, महाराष्ट्र दौड़ते हैं। स्पेशलाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं है। आप जब तक अपने डाक्टर्स को, प्रोफेसर्स को बाहर नहीं भेजेंगे और नई टैक्नोलोजी को जब तक आप स्थापित नहीं करेंगे, तब तक राजस्थान की चिरंजीवी योजना खाली नाम की रहेगी। उस गरीब आदमी को यहां इलाज करके मरना है, उसको जीना नहीं है, उसको मरना है, यह मैं आपको आज कहकर जा रहा हूं। जब तक आप अपने डाक्टर्स की स्पेशलिटी, आप उनको उच्च तकनीकी नहीं पहुंचाएंगे, विदेश नहीं भेजेंगे, नई तकनीक क्या चल रही है, तब तक राजस्थान में इलाज कराने कोई नहीं आएगा। ठीक है हम चिरंजीवी योजना की बात करते हैं। आज हालात है कि गांव में आम आदमी को नर्स नहीं है, कम्पाउंडर नहीं है और आप बात कर रहे हैं हम सब सीएचसी पर लगाने जा रहे हैं डायलिसिस मशीन को।

आज खाद्य सुरक्षा की बात करें। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि मैं इस साल 10 लाख खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाऊंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको बहुत देर से मालूम चला, लेकिन मालूम तो चला कि इस कोविड के कारण से आम जनता की काफी स्थिति खराब हो गयी। स्थिति इतनी खराब हो गयी कि जो आदमी 20 हजार-25 हजार रुपये कमा रहा था, उसको आपकी खाद्य सामग्री की जरूरत नहीं थी, परंतु आज वह बेरोजगार हो गया है। उस बेरोजगारी के कारण वह नरेगा में जा रहा है। हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बड़ा गर्व कर रहे थे कि आपके समय में तो इतने ही खर्च हुए। 21 हजार करोड़ ही खर्च हुए पांच साल में। हमने 26 हजार करोड़ रुपये खर्च किये। नरेगा में वह आदमी जाता है जिसके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, जब जाकर वह नरेगा में जाता है। जो अच्छा कमाने वाला आदमी है, वह नहीं जाता है। कोविड से पहले आम आदमी के पास रोजगार था, कहीं भी कमाता था, 20-25 हजार रुपये कमा लेता था। आज उसको बेरोजगारी के कारण मजबूरी में नरेगा में जाना पड़ रहा है। इस नरेगा में जाकर वह आदमी आज अपने बच्चों को पाल रहा है। उसको खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की आवश्यकता थी। जब फूड सिक्योरिटी बिल आया तो यह तो आन गोइंग प्रोसेस था। किसी का नाम भी जुड़ सकता है, किसी का नाम भी कट सकता है। आपने दो साल तक उसका नाम, आपने नेट बंद कर दिया। जो व्यक्ति अपना नाम जुड़वाना चाहता है, वह विधवा मैंने देखी है जिसके छोटे-छोटे बच्चे, वह काम करने नहीं जा सकती थी। चार बच्चों को वह पाले या

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

वह विधवा नरेगा में जाए। वह अपना नाम जुड़वाना चाहती थी, परंतु दो साल तक वह विधवा घूमती रही कि मेरा नाम जुड़वाओ, परंतु कोई सुनने वाला नहीं था। आज जब तीन साल खतम होने आए और चौथा बजट आपका पेश हुआ तब आपको महसूस होता है उस विधवा का दर्द। अब जाकर आप ये 10 लाख, जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये एक आन गोइंग प्रोसेस था, फूड सिक्योरिटी बिल है, इस बिल के साथ आपने गलत काम किया है। आप इसको रोक नहीं सकते। अगर मेरे जैसे व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है तो नाम कटवाते और उस गरीब आदमी का नाम जोड़ते और सुनिश्चित होता कि उसको गेहूं मिलना चाहिए था। आपने कैसे रोक दिया? दो साल तक आपने नेट बंद कर दी। यह आपने आम जनता के साथ खिलवाड़ किया है।

सभापति महोदय, फसल बीमा योजना, मेरे क्षेत्र में 2020-21 में लगभग 700 एम.एम. बरसात हुई। मेरे पूरी खरीफ की फसल खराब हो गयी। इस साल पूरे पश्चिमी राजस्थान में, आप सबको मालूम है कि बरसात नहीं हुई। पर आज दिन तक किसानों ने जो फसल का बीमा दिया है, आज दिन तक उनको अनुदान भी नहीं मिला और आज दिन तक उनको फसल बीमा की राशि भी नहीं मिली। ऐसा लगता है कि सरकार और बीमा कंपनी दोनों एक हैं ताकि जनता को उसका फायदा नहीं मिले। दोनों एक होकर, आज मैं पाली जिले की आपको कहना चाहता हूं, पूरे बाली तहसील को 2020-21 में किसानों को मात्र 4 लाख रुपये का फसल बीमा मिला है। आप सोच सकते हैं, जहां फसल की पूरी बर्बादी हो गयी। इतनी अधिक बरसात हुई कि किसान को उसको काटने की जरूरत महसूस नहीं हुई।

आप कह रहे हैं कि आपने कृषि बजट दिया है। कृषि बजट में आपने क्या किया है? वो की वो योजनाएं, जो ड्रिप और स्प्रिंकलर, फार्म पौण्ड, जो भी पहले चल रही थीं, वो की वो योजनाएं हैं। आपने किसानों को किसान सम्मान निधि जैसे पैसे दिए क्या? उसको मजबूत करने के लिए खेती के लिए पैसे दिये क्या? आज पूरी रबी फसल में पूरे राजस्थान में किसान चिल्लाता रहा कि डी.ए.पी. नहीं है, यूरिया नहीं है। आपने ध्यान ही नहीं दिया। किसान अपनी फसल बो नहीं सकता इस रबी की फसल में क्योंकि पूरे राजस्थान में आपने डी.ए.पी. और यूरिया की सप्लाई नहीं दी। कलेक्टर से बात करें, उच्चाधिकारी से बात करें कि नहीं हो तो वह खाद ले लो। वो खाद ले लो, वो खाद मिल रहा है, किसान को चाहिए डी.ए.पी., किसान को चाहिए एन.एस.पी.

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

और आप कह रहे हैं कि वह खाद ले लो। कभी उस आदमी ने उस खाद का यूज नहीं किया। उसको आप मजबूरी में खाद दे रहे हैं। यूरिया की कमी, इससे आम किसान को कितना नुकसान हुआ है? सरकार इसकी भरपाई करने के लिए तैयार है क्या? आज पूरे रबी की फसल में पूरे राजस्थान में किसानों को यूरिया का और डी.ए.पी. का शोर्टेज रहा और सरकार को मालूम था कि इस समय आवश्यकता है, परन्तु सरकार दे नहीं सकी।

दूसरी बात, आप अभी कह रहे हैं कि हम पूरे राजस्थान में 22 जनवरी तक जितने भी कनेक्शन हैं दे देंगे। आपने फर्स्ट बजट में 50 हजार कनेक्शन दिये, सैकण्ड बजट में 40 हजार कनेक्शन दिये, थर्ड बजट में वापस आपने 40 हजार दिये, आपके कनेक्शन हो गये 2 लाख 40 हजार। ये जितने भी कनेक्शन हुए हैं, ये आउट आफ प्रायोरिटी कनेक्शन हुए हैं। लोगों ने मजबूरी में, आप कनेक्शन नहीं देना चाह रहे थे, 9 साल का गेप हो गया। जो 2012 का कनेक्शन हम छोड़कर गये थे, आप 2012 खतम नहीं कर सके। आप तीन साल में खतम नहीं कर सके। आज आपने छेड़ दिया कि 3 लाख 48 हजार कनेक्शन जो पेंडिंग हैं, उसको हम पूर्ण करेंगे। आपने यह तय कर लिया क्या कि कहां-कहां जी.एस.एस. बनाएंगे? कहां 132 बनाएंगे? कहां लोड फेक्टर बढ़ेगा, कहां फीडर सेपरेशन करना है। सबसे बड़ी बात है कि केन्द्र सरकार डिस्काम की स्ट्रेंथनिंग करना चाहती है। उसके फीडर सेपरेशन का प्रोग्राम लाना चाहती है। पोस्ट पेड, प्रीपेड मीटर लगाना चाहती है। आपके जी.एस.एस. बनाना चाहती है। आपके अभी तक डी.आर.सी. की बैठक नहीं हुई। चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक होती, कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। जहां आप केन्द्र सरकार को यह कहेंगे कि हम इस लोसेस को 15 परसेंट तक लेकर आएंगे। 28 हजार करोड़ का प्रस्ताव, डी.पी.आर. बनाकर आपने केन्द्र सरकार को भेजी। केन्द्र सरकार 28 हजार करोड़ इस डिस्कॉम को देना चाहती है, परन्तु आपने डी.आर.सी. की बैठक चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में की नहीं। कैबिनेट की बैठक बुलाई नहीं। इसके बाद आप कह रहे हैं कि हम साढ़े तीन हजार करोड़ फीडर सेपरेशन में खर्च करेंगे। यह सब केन्द्र सरकार का, मतलब 60 परसेंट तो आपको एड है, 30 परसेंट पी.एफ.सी. आपको फायनेंस कर रहा है और 10 परसेंट मात्र आपको सरकार को लगाना है।

सभापति महोदय, एक एग्रीकल्चर कनेक्शन पर 2 लाख रुपये का खर्चा है। जब 4 लाख कनेक्शन राजस्थान में आप करने जा रहे हैं, बिना

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

प्लानिंग, आज जिस किसान ने डेढ़ साल पहले जो डिमांड भरा है, उसको आज दिन तक कनेक्शन नहीं दे पाए। उसके कभी तो पोल नहीं है, कभी इंसुलेटर नहीं है, कभी केबल नहीं है। आज डेढ़ साल से डिमांड लेकर वह किसान घूम रहा है। उसको तो आप कनेक्शन दे नहीं सके और अभी आप कह रहे हैं, बूंद-बूंद के तहत जहां उस किसान ने पूरा पैसा जमा किया, पूरी लाइन का पैसा जमा किया, डेढ़ साल तक उस किसान को आप कनेक्शन नहीं दे पाए और सरकार वादा कर रही है कि हम दो साल में 4 लाख कनेक्शन किसान को देंगे। आपके पास क्या मैनेजमेंट है? अभी आपके पास, सबसे बड़ी बात है कि आपने कोल का पैसा कभी दिया ही नहीं। टाइम पर नहीं दिया, हमेशा कोल का शोर्टेज रहा। हमेशा एमआईएफ की गाइडलाइन रहती है, जहां बिजली, थर्मल पावर है, वहां एक महीना कोल का स्टोर रहना चाहिये। आपने पैसा नहीं दिया, आपके पास कोल आया नहीं। आपके पास अडानी से कोल आना चाहिये, आपके जो मेजर सुपर क्रिटिकल प्लांट्स हैं, उसके पैसे भी नहीं पहुंचे, कोल नहीं था। तब जाकर आपको 17-18 रुपये में बिजली खरीदनी पड़ी। मैं समझता हूं कि आम जनता की खरी कमाई का पैसा, आपने बिना प्लानिंग के कारण 17 रुपये में बिजली खरीदी और डिस्कॉम को हज़ारों के घाटे में उतारा।

मेरा सरकार से निवेदन है सरकार को गहराई से, निचले स्तर पर काम कर रहे हैं। आज वर्चुअल इनॉग्रेशन होते हैं। सीएम साहब बैठकर, एक दिन में पूरे ज़िले के इनॉग्रेशन कर रहे हैं। हमारे मंत्री भी वर्चुअल इनॉग्रेशन कर रहे हैं। वर्चुअल इनॉग्रेशन से, जनता के बीच जाने में बहुत फर्क आयेगा। आप जब जनता के बीच जाकर खड़े होओगे, आपको जब उनकी चार समस्यायें सुननी पडेगी, आपको उनकी चार बातें सुननी पड़ेगी। आपको जब हकीकत पता लगेगी, जब आप खुद जाकर वहां उद्घाटन करोगे, शिलान्यास करोगे, यहां बैठे-बैठे आप वर्चुअल कर रहे हो। जनता बहुत पीड़ित है।

मैं आपको आज विश्वास से कहता हूं, जिस दिन आप 20 सीट लेकर आये थे, आने वाले 2023 में, यह 2013 का जो बजट था, यह इसी तरह का बजट था। आपने कुछ नहीं छोड़ा था, पर आपकी सीटें मात्र 21 आई थीं। मैं आपको आज कहकर जा रहा हूं, हम जनता के बीच में रहते हैं, अगर आप वापस यहां 21 पर नहीं आओ, तो मैं आपको यहीं बैठा हुआ मिलूंगा। अगर 21 सीट पर नहीं आओ। जनता का दर्द है, जनता की पीड़ा है, आपने उसको अभी तक समझा नहीं है। आपने खाली वर्चुअल रैली, वर्चुअल मीटिंग, कर-

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

करके टाइम पास किया है। वर्चुअल रैली, वर्चुअल मीटिंग आपको हकीकत बता देगी कि आपका धरातल कहां है।

मेरा आपसे अनुरोध है। मैं, मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें आपको बताना चाहूंगा। एडीएम कोर्ट। बाली विधान सभा क्षेत्र में, ज़िले में दो एडीएम कोर्ट, एक तो सीलिंग कोर्ट है, एक एडीएम कोर्ट है। सीलिंग के केसेज जब खोले थे भैरोंसिंह जी ने, जब 1993, 1998 में 900 केस थे, आज मात्र 50 केस हैं। आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आयेगा। सीलिंग एडीएम कोर्ट को खतम करके बाली में एक एडीएम खुल जाता है तो..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करे।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मेरे देसूरी में और रानी, पूरे ब्लाक में, दोनों नजदीकी ब्लाक में, एक भी महाविद्यालय नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा, देसूरी में भी एक महाविद्यालय खोला जाये। जब आप जोजावर में कन्या महाविद्यालय खोल सकते हो तो देसूरी और रानी तो बहुत बड़ा ब्लॉक है, उसमें महाविद्यालय खोलने की बहुत आवश्यकता है। बाली में वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय अभी तक नहीं है, इसलिये बाली महाविद्यालय में शुरू की जाये।

पूरे देसूरी ब्लाक में एक भी उप-तहसील नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि सादड़ी और नागौन में एक उप-तहसील खोली जाये। आपने उप जिला अस्पताल की घोषणा की। हमारे पास उप जिला अस्पताल की स्वीकृति भी आ गयी। आज दिन तक उप जिला अस्पताल में न तो कोई पीएमओ लगा है, न एक एक्स्ट्रा डाक्टर लगा है। न अभी तक उसकी जमीन के बारे में कोई, कि नया हास्पिटल बनाया जायेगा। न उसकी कोई फाइनेंशियल सैंक्शन आई है। हास्पिटल की सैंक्शन तो आ गयी, उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन भी आ गयी, पर आज दिन तक आपने पीएमओ लगाया ही नहीं, डाक्टर लगाया नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): दूसरा, मेरा अनुरोध है। मैं सामाजिक न्याय मंत्रीजी से बात कहना चाहता हूं। जब आप अनाथ, पालनहार बच्चों को 1500-2500 रुपये आप देते हो, तो विधवाओं के बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, पालनहार से जो मिलता है...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने पालनहार योजना 2003 में प्रारम्भ की थी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 2004 से उनको मात्र हजार रुपये मिल रहे हैं।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उनके भी 1500 रुपये बढ़ाये जायें। मैं आपसे यह निवेदन करने आया हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण 2022-23 पर बोलने मौका दिया, धन्यवाद। सभापति महोदय, हमें गर्व है कि माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमने यह तीसरा वर्ष पूरा किया है। कोरोना काल आया, गम्भीर बीमारी आई, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद हम जनता से जो वादे करके सत्ता में आये थे, इन तीन वर्षों में 75 प्रतिशत वादे पूरे करने का काम किया।

बजट भाषण के 123 पेज माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जब पढ़े, विपक्ष के सामने ऐसा कोई एक शब्द या खण्ड नहीं था, जिसका वह विरोध कर सके। निरोगी राजस्थान का संकल्प लेते हुए, माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्वास्थ्य के ऊपर हमेशा से गम्भीर रहे, हर व्यक्ति को लाभ पहुंचे, उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, उस पर योजनाएं दीं। मैं कहना चाहूंगी, उसमें से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पिछले दो वर्षों में, कोरोना काल के अन्दर, बहुत सारे हमें ऐसे नागरिक मिले, जो प्राइवेट हास्पिटल में महंगा इलाज कराने के लिये मजबूर थे। गहने बेचने पर मजबूर हुए। 10-10, 15-15 लाख रुपये तक का बिल बना, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिये। वह अपनी व्यथा किसे सुनायें। इस बात को सोचते हुए समझते हुए, गम्भीरता से लेते हुए, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया, जिसमें गम्भीर बीमारियों को भी जोड़ा गया है, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को सदन की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूं।

सभापति महोदय, दूर ग्रामीण भूमि में हम जब जाते हैं, बिजली की समस्या काफी गम्भीर रहती है। गरीबी के कारण काफी परिवार वंचित हैं, कनेक्शन नहीं ले पाते थे। आज एक और सौगात उन परिवारों को देने का

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

काम किया। जो 100 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, उनको 50 यूनिट फ्री में दी जाये, यह कोई छोटी बात नहीं है। जब बच्चा शाम के समय पढ़ाई करता है, तो उसको बिजली चाहिये। घर के छोटे-मोटे कामों के लिये बिजली चाहिये। गरीब ताकता रहता था। पड़ोसी के घर जाकर, बच्चा पढ़ने का काम करता था। इसी के साथ-साथ 150 तक यूनिट के लिये 3 रुपये प्रति यूनिट, जो अनुदान राशि दी गयी, 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपये तक की अनुदान राशि, यह काफी बड़ा बदलाव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण में हमें दिया, उससे उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है।

सभापति महोदय, 2022 जा रहा है। 2022 में हम यह देखना चाहते थे, केन्द्र सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगुनी कर देंगे। यह तो भला हो कि चुनाव आ गये, नहीं तो पता नहीं कितने और किसानों को दिल्ली के उस बोर्डर पर शहादत देनी पड़ती, जो दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए थे, उन तीनों काले कानून के विरोध में।

मैं किसानों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि केन्द्र में शासित सत्ता है, उसके घमण्ड को चूर-चूर करने का काम किया। दूसरी तरफ मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान की तर्ज पर किसान बजट...

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में कोरम का अभाव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन के अन्दर कोरम का अभाव है। आप घंटी बजाइये, आप सत्तारूढ़ दल का व्यवहार देखिये। माननीय सदस्या अपनी बात कह रही हैं...

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह तो हम लोग बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने तो जानकर भेजा है।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): व्यवधान पैदा कर रहे हो, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय। प्लीज सहयोग कीजिये। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, यह बिना मतलब का व्यवधान पैदा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप कोरम की घंटी बजाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह क्या बात हुई (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमने तो भेजा है। हमने तो जानकर भेजा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। प्लीज सहयोग करें। विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ताकि पता लगे, सत्तारूढ़ दल कितना गम्भीर है।

श्री सभापति: विराजिये। भूखे भजन न होवे गोपाला। अभी सब अपनी...(व्यवधान) क्षुधा पूर्ति करने गये हैं। आप भी विराजिये। प्लीज विराजिये।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा वादा केन्द्र की सरकार करके आई थी कि 2022 के अन्दर...

श्री सभापति: आप बीच-बीच में, लोगों को जगाने का काम करते हो।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): हम किसानों की आय को दुगुनी कर देंगे, लेकिन आज 2022 के अन्दर कहीं पर भी, जब उन्होंने अपना बजट पेश किया, तो किसानों की आय पर जिक्र नहीं था। यह तीनों काले कानून को, अच्छा बताने वाले लोग,...(व्यवधान)

श्री सभापति: सब खाना खाने ... (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): एक दिन उन्हें झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): मैं आपसे कहना चाह रही थी, समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान की तर्ज पर किसान बजट, माननीय अशोक

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

गहलोत जी ने पेश किया। यह लाइन कोई लाइन नहीं है। यह इस प्रदेश के किसानों के लिये खुशहाली का रास्ता खोलती है। केन्द्र की सरकार को कहना चाहूंगी कि इस लाइन को मद्देनजर रखते हुए क्या आप किसानों के बारे में विचार रखते हैं। जो वादे आपने करके केन्द्र में सत्ता हासिल की थी, उन किसानों के साथ आपने दुराचार किया, उनको सड़कों पर आने के लिये बाध्य किया। किसानों के ऊपर से गाड़ियां चलायी गयीं, उनकी हत्या की गयी। ऐसे मंत्रियों को सत्ता में रखा गया और दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या रहती थी सर्द काल के अन्दर बिजली की, दिन में बिजली उपलब्ध करवाकर यह एक बहुत बड़ा उपकार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किया। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, वहां पर बहुत कम सिंचित क्षेत्र है, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा शिकायतें मिलती थीं कि बार-बार उन्हें लाइनें बदलने में दिक्कत आती है, बिजली के कट लग जाते हैं, ज्यादा ठंड की वजह से उन्हें प्राब्लम होती थी और आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 33 के 33 जिलों में उस तरीके की उपलब्धता देने की जो बात कही है, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, खेल मेरा विषय रहा है, मैं खेल से जुड़ी रही हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2021-22 की बजट घोषणा के अन्दर ओलम्पिक एवं पैरालंपिक में मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ रुपये गोल्ड मैडल के लिए, दो करोड़ रुपये सिल्वर मैडल के लिए और 1 करोड़ रुपये कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए जो राशि रखी थी, मैं आज गर्व के साथ यह कह सकती हूं कि जब हमारा पैरा एथलीट टोक्यो ओलम्पिक के अन्दर अवनी लखेरा, देवेन्द्र झाझड़िया, कृष्णा नागर और हमारे एक और एथलीट सुन्दर गुर्जर जो कि मैडल जीत कर लाये। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का सदन के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करती हूं कि आपकी वजह से वे खिलाड़ी किसी न किसी वजह से अपने आपको मजबूर महसूस करते थे, उन्हें आज आपने करोड़पति बनाने का काम किया। उनके भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित रखने के लिए राज्य में आपने उनको नौकरी दी और साथ ही, माननीय सभापति महोदय, कई बार मजबूरी हो जाती थी एथलीट की वह दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरियां करता था, पर आज पे-प्रोटेक्शन के माध्यम से मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी राजस्थान सरकार अपने स्टेट के अन्दर नौकरियां दे रही है, यह कोई छोटी बात नहीं है।

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में खेल का आयोजन होता है, 26 लाख के करीब हमारे खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उससे एक माहौल बदलेगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जब बजट घोषणा के अन्दर पारम्परिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम की घोषणा हुई। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की घोषणा हुई राजस्थान हाई परफोरमेंस सेंटर, जोधपुर के लिए भी आपने 10 करोड़ रुपये की घोषणा की। यह जयपुर में बनकर तैयार हो चुका है, ठीक वैसे ही यह है। ठीक वैसे ही सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जयपुर और उदयपुर के अन्दर देने की घोषणा की है।

राजगढ़ में कबड्डी अकादमी और श्रीगंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी देने का काम किया। खेल छात्रावास भी दिये। इस तरीके से पैरालम्पिक अकादमियों के लिए 20-20 करोड़ रुपये की जो घोषणा की है, यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे खेल को बढ़ावा मिलेगा और आज जब कभी भी ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स होते हैं तो हम हरियाणा की तरफ देखते हैं और यह जो बदलाव दिये हैं, यह कोई छोटे बदलाव नहीं है। दो प्रतिशत कोटा सरकारी नौकरियों में रखना, सीधे तौर पर डीवाई.एस.पी. की भर्ती, ए.सी.एफ. की भर्ती, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इस तरीके से जब खिलाड़ियों को नौकरियां दी जाने लगी हैं तो आज राजस्थान का खिलाड़ी दूसरे प्रदेश की तरफ नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश के खिलाड़ी राजस्थान की तरफ देखने लगे हैं। इसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का, वह कम है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के लिए विशेष तौर से, क्योंकि संयम लोढ़ाजी ने बहुत विस्तार से बातें रखी हैं। रीटाजी अभी यहां पर नहीं हैं, एक कविता के माध्यम से इतना सुन्दर विवरण उन्होंने विपक्ष की भावनाओं का रखा था, लेकिन मैं सड़कों के ऊपर यह कहना चाहूंगी कि जो मेरे सामने बैठे विपक्ष के साथी हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 200 के 200 विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर पिछले बजट में भी पांच करोड़ रुपये की सड़कें हमें दी हैं और इस बार दस करोड़ की सड़कें हमें दी हैं।

देखिये, ग्राम का वासी जो पंचायतों से जुड़ा हुआ नहीं है वह पंचायत से जुड़ना चाहता है। मिसिंग लिंक्स भी काफी हैं और साथ ही मैं यहां पर एक

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

मांग जरूर रखना चाहूंगी कि कई बार कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिनका विधान सभा क्षेत्र दूसरा लगता है और ब्लाक दूसरा लगता है। इस कारण से उन गांवों को, उन पंचायतों को वंचित रखा जाता है। आज मेरी एक मांग यह जरूरी रहेगी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि यह मेरी काफी पुरानी सड़क है, वैसे तो यह राजगढ़ से निकलती है पर खुड़ी गांव से लेकर वाया चनाना, घनाऊ, कांजण बिरमी और बायां से होते हुए यह भादरा की तरफ जाती है, जिसकी हमेशा से अनदेखी हुई है। माननीय सभापति महोदय, ऐसे में मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि इन चीजों की तरफ हमें ध्यान देते हुए थोड़ी और हम सड़कों की मांग रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक समाज प्रदेश में मिरासी समुदाय जो है, जिसमें मिरासी, ढाढी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा राणा एवं भिश्ती समुदाय के उत्थान के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इससे मिरासी समाज में खुशी की लहर है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि यह समाज यह भी चाहता है कि इनके भी समाज के बोर्ड का गठन किया जाये और यह ऐसी जाति है जिसके ऊपर विशेष तौर पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और उनके उत्थान की जरूरत है तो मैं यह उम्मीद करती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब बजट की रिप्लाई करेंगे तो उसमें यह जरूर विशेष तौर से इसके ऊपर ध्यान देंगे।

माननीय सभापति महोदय, रोजगार एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है पूरे देश के लिए। भाजपा जब केन्द्र की सत्ता में आयी थी तो दो करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा करके आयी थी, लेकिन गत वर्ष के अन्दर न हमने बेरोजगारी के ऊपर उनके शब्द सुने, न महंगाई के ऊपर सुने और न स्वास्थ्य के ऊपर सुने। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोले, नौकरियां दीं और जब रीट की परीक्षा की बात आती है तो जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, उनकी तरफ से बार-बार तख्तियां उछाली जा रही थीं सी.बी.आई., सी.बी.आई. करके तो मैं उनको यह कहना चाहती हूं कि यूपी. में जो हो रहा था या हरियाणा में जो हो रहा था, उसके लिए भी आपने सी.बी.आई. की जांच की मांग की थी क्या? दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इनकी बोलती बंद करने का काम किया। जुलाई में फिर से हम भर्ती करके, अपने युवाओं को रोजगार प्रदान करना चाहते हैं और उन रिक्तियों को बढ़ाने का भी

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

काम किया है, 32 हजार से 62 हजार करने का काम किया है, यह कोई छोटी बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण के बाद जब हम वापस अपने घर को लौट रहे थे तो मैंने यह देखा कि बाहर हमारे मीडिया के साथी रहते हैं, वहां पर विपक्ष के साथी काफी कुछ बोलते हैं, लेकिन उस दिन खाली था क्योंकि यह 123 पेज का जो बजट भाषण पढ़ा गया था, उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिसका विरोध किया जा सके।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): साहब, समाप्त करती हूं। कोरोना काल की दुहाई दी गयी और सरकार के ऊपर अलग से भार न पड़े उसके लिए फोन लौटाने की बात कही गयी है। यह बहुत अच्छी बात है। माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष बजट भाषण के दौरान आईपैड भी दिये गये थे वह वापस नहीं हुए, उस समय भी कोरोना काल था।

माननीय सभापति महोदय, एक छोटी सी चीज को लेकर इतनी बड़ी बात बनाने की बात की गयी। अगर वित्तीय भार को कम करना चाहते थे तो सारे सदन ने, जब सरकार ने यह फ्लैट दिये थे तो उन फ्लैट्स की कीमत काफी थी, मेरे ख्याल से वह वापस करने चाहिए थे। अगर वित्तीय भार आपको लगता था कि वित्तीय भार है तो यह जनता के सामने आप क्या पेश करना चाहते थे, यह मेरी समझ से परे था। अगर वास्तविकता में आप जनता के हितैषी हैं तो वह चीज तो आपको जरूर सोचनी चाहिए थी, वह फ्लैट्स हमें वापस करने चाहिए थे। (व्यवधान) लौटा रहे हैं क्या? यह तो अच्छी बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ मांगें रखना चाहती हूं। सिधमुख उप तहसील काफी वर्षों तक रही, जिसको तहसील का दर्जा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2021-22 की घोषणा में की थी। दूरदराज का वह गांव है जिससे काफी दूरी का सामना वहां के स्टूडेंट्स को और वहां के लोगों को करना पड़ता है। कालेज की व्यवस्था वहां पर नहीं है तो वहां पर मैं कालेज और सी.एच.सी. की मांग करती हूं। पीएच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की मांग रखती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से दो मेजर रेलवे लाइन निकलती है। इलेक्ट्रिक होने के बाद से किसानों के जो खसरे हैं, खेत हैं,

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

वह दोनों तरफ होने की वजह से उन्हें लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें से मैंने सिधमुख के अन्दर, किरतान के अन्दर और भोजाण के अन्दर अण्डर पास की मांग माननीय मुख्य मंत्री महोदय से रखी है।

(समय: 14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर हैडक्वार्टर राजगढ़ के अन्दर दो कालेज हैं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारे पास कोई कालेज नहीं है। अगर हमारे स्टूडेण्ट को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना पड़े तो 65 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। राजगढ़ के अन्दर को-एड कालेज है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्रमोन्नत किया जाय।

साथ ही, सभापति महोदय, बिजली की मांग को देखते हुए कालरी व ताम्बाखेड़ी के अन्दर जीएसएस की घोषणा हो, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूं।

सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान की सरकार ने जो बजट पेश किया है, सरकार के पास में 1 रुपया है और 4 रुपये का बजट पेश कर दिया आप लोगों ने। यह मुख्य मंत्रीजी कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और पैसा आ जायेगा और इस बजट की पूर्ति कर देंगे। नई घोषणाएं जो की हैं, उनमें जाऊं, उससे पहले सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मेरे मित्र यहां पर पर नहीं बैठे हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे लगातार फॉलो करते हैं कि मेरी एक्टिविटीज क्या हैं। जब मैं मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गया बजट के बाद में तो मेरा अभूतपूर्व स्वागत उन्होंने देखा, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, सदन के अन्दर उन्होंने जिक्र भी किया। वह स्वागत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभिनेश महर्षि, जिनके लिए हजारों लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान वाले झण्डों को लहराते हुए भारतीय जनता पार्टी जिन्दाबाद और अभिनेश महर्षि जिन्दाबाद और देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी की जिन्दाबाद करते हुए किया था लेकिन उन्होंने मुझे यह भी कहा था, हजारों लोग यह बात कहने के लिए आये थे कि हमने राजस्थान की सबसे

(श्री अभिनेश महर्षि)

बड़ी पंचायत में आपको हमारे हक और अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए भेजा है और वह अधिकार की लड़ाई मजबूती से आपने लड़ी है। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनन्दन करते हैं लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को बता देना, जब बजट की बहस करो तब। उन्होंने घोषणा की थी। उसके अन्दर उनको बताना, मेरे विधान सभा में आने के बाद में पहले बजट की बात करूं, परिवर्तित बजट 2019-20 के अन्दर 10 जुलाई, 2019 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन के अन्दर रखा था, मुझे दुःख के साथ बात कहनी पड़ रही है, पृष्ठ 42 पर बिन्दु संख्या 178, सभापति महोदय, इसमें लिखा था कि राजकीय हवाई पट्टियां 24 घंटे काम में ली जा सकें, इसके लिए चूरू जिले में पड़िहारा सहित अन्य हवाई पट्टियों का अपग्रेडेशन करवाया जायेगा। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें, तब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह आपने वर्ष 2019-20 के अन्दर 10 जुलाई, 2019 को घोषणा की, उसका आज दिन तक, चौथा वर्ष आ गया है, मूर्त रूप नहीं लिया है। एक कंकड़ भी वहां हवाई पट्टी पर नहीं लगाया गया है।

सभापति महोदय, उसके बाद में मैं उसी बजट की बात करूं, पेज नम्बर 9 बिन्दु संख्या 31, प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित की जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, कहां गईं वह नन्दीशालाएं? जब आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि हम गाय की बात करते हैं, आपने कहा था कि हम पशुधन, गाय और नन्दीशाला खोल कर उनकी तकलीफ को दूर करेंगे। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी जवाब के अन्दर इस बात की घोषणा करें कि कितनी नन्दीशालाएं राजस्थान के अन्दर उन्होंने खोल दीं। 2019-20 के अन्दर 10 जुलाई, 2019 की मैं बात कर रहा हूं। उसी के अन्दर पेज संख्या 10 बिन्दु संख्या 39, समस्त ग्राम पंचायतों को एक नया विकास पथ उपलब्ध कराएंगे और मुझे याद है माननीय मुख्य मंत्री महोदय का वह भाषण, जिसके अन्दर हाथों को लहराते हुए उन्होंने कहा था कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने गांवों को जो खराब करने का काम किया था, हम फेरोकवर लगायेंगे, वॉल टू वॉल सड़कें बनाएंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्दर बनाएंगे। मुझे दुःख के साथ में कहना पड़ रहा है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की बात करूं तो डेढ़ किलोमीटर सड़क की बात करने वाली यह राजस्थान की सरकार एक किलोमीटर के ऊपर सीमित हो गयी और उसके बाद टांय-टांय फिस्स। एक ईंट नहीं लगी उसके बाद में। मेरे यहां 40 गांव पंचायतों

(श्री अभिनेश महर्षि)

के अन्दर 40 बनने थे। आज एक बना है सिर्फ चार के अन्दर। यह राजस्थान सरकार का नमूना है जो पहले बजट की घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं कर सकी। वह आज इतनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं करके वाहवाही लूटने के लिए लगी हुई है।

सभापति महोदय, अभी 5 करोड़ के बजट की बात कर रहे थे नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर। जिन नगरपालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड है या जहां भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, वहां पर किसी भी व्यक्ति को इन्वाल्व किए बिना सरकारी अधिकारियों ने अपने हिसाब से उनकी योजना बना ली और जो 5 करोड़ रुपये के प्रस्ताव हमारे से लिए गये थे, वह भी आज धरातल पर नहीं आये हैं, मूर्त रूप नहीं ले पाये हैं। यह राजस्थान की सरकार का नमूना है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर जो 10 करोड़ रुपये सड़कों का प्रावधान किया है, उसके बारे में कहने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि 5 करोड़ रुपये की जो घोषणा की थी, उनके ऊपर तो सड़कें बनवाने का काम कर दो और एक ठेकेदार को 5 करोड़ रुपये का ठेका दे दिया और उसके बाद उन्होंने आज दिन तक भी, जनता त्राहिमाम कर रही है, एक भी कंकरी उन सड़कों पर लगी नहीं है। यह राजस्थान सरकार का नमूना है।

सभापति महोदय, उसी बजट में सरकार ने घोषणा की थी जनता क्लीनिक की। पुराने बजट की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद की घोषणाएं तो सारी अधूरी हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सर, दो मिनट में कैसे समाप्त होगा? अभी तीन मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: आपके सचेतक महोदय ने मुझे जो लिस्ट दी है, मैं उसके हिसाब से आपको कह रहा हूं। आपको 7 मिनट अलाट किए हैं। आपके सचेतक महोदय ने अलाट किए हैं। आप 6 मिनट बोल चुके। आपने 2 बजकर 01 मिनट पर शुरू किया था, आप 2 बजकर 08 मिनट में समाप्त करेंगे। प्लीज, सहयोग करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आपने जो समय लिया है मेरा, यह तो दे देंगे सभापति महोदय?

श्री सभापति: हां, हां, यह दूंगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद। एक आधा मिनट तो और दे दो सचेतक महोदय।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय ने मुझे आगाह कर दिया कि आप सरकार के खिलाफ मत बोलो तो मैं तो यही कहता हूं कि सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की हैं उनको मूर्त रूप में नहीं उतार पाये हैं।

सभापति महोदय, आपकी बात को मानते हुए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग माननीय मुख्य मंत्री महोदय को करना चाहता हूं क्योंकि जनता ने जन प्रतिनिधि चुनकर भेजा है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनकी बात करूं।

छापर देवाणी मार्ग सड़क निर्माण का नवीनीकरण, यह बन्द पड़ी हुई सड़क है। इसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री महोदय, डीपीआर बनवा कर एक ओवर एलीवेटेड रोड बनवाने का काम करें और तब तक के लिए वह जो दूसरी साइड लाइन की रोड है, उसके ऊपर निर्माण करवाने की कृपा करें।

किसानों का सम्पूर्ण कर्जामाफी, बेरोजगार युवकों को भत्ता, ये सब बातें तो रह गई। राजलदेसर को नई तहसील बनाने की मैं मांग करता हूं। ढाणियों में रहने वाले लोगों को दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत रोशनी दी जाती थी, वह रोशनी छीनने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। नाम अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। कोई दूसरा नाम ले दो लेकिन गरीब को ढाणियों के अन्दर लाइट का काम तो कर दो माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

संविदा मशीन विद मैन, कम्प्यूटर आपरेटर्स अपनी मांग को लेकर शहीद स्मारक के ऊपर बैठे हैं। 4 हजार 41 संविदाकर्मी हैं, उनको नियमित करने के लिए। क्लीनिक अभिलेख सहायक का क्लीनिक रिकार्ड असिस्टेंट सीआरए के पद पर समायोजित करने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें टेबल भी करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में धातरी, बछरारा, घुमान्दा, पायली, भावनदेसर, गुसांईसर, राजियासर मीठा, चक राजियासर, जिनरासर, नूवां के प्राथमिक विद्यालय और गांव खारिया, कनिराम गौरीसर, बड़ावर, सुलखनियां

(श्री अभिनेश महर्षि)

सहित माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मांग की गई है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

बहुत सारे ट्यूबवैल बन्द पड़े हैं। उनको ठीक करवाने की कृपा करें। टाड़ा, सांवतियां, रिणवां की ढाणी, रामपुर, परसनेऊ, तौलियासर, नीमड़ी, प्रेमनगर, विदावतान लोणा, कुसुमदेसर, कनवारी, जिनरासर, भोजासर, अणखोल्या, चारणवासी आदि में आपूर्ति पाइन्ट कम, जलापूर्ति नहीं हो रही है तो पेयजल आपूर्ति हेतु पीएसक्यू स्टैण्ड बढ़ाने की कृपा करें।

विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण अंचल की ढाणियां पूर्व योजना के अन्दर सर्वे से वंचित रह गई थीं। उनका सर्वे करवाकर उनको भी उसके अन्दर शामिल किया जाय।

सभापति महोदय, एक मांग जो सबसे बड़ी मांग है, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी, जिन्होंने देश के संविधान को लिखा। हमारा यह सदन भी संविधान को बनाने का काम करता है। इसके अन्दर नये कानून कायदे भी बनते हैं इसलिए राजस्थान की विधान सभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी की आदमकद मूर्ति लगाने की मैं मांग करता हूं। यहां मूर्ति लगनी चाहिए।

सभापति महोदय, न्याय, कानून व्यवस्था की बात करें तो मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक छोटे से उदाहरण के साथ मेरी बात को समाप्त कर दूंगा। चोरियां बहुत हो रही हैं। कानून व्यवस्था ठप हो गई है। ये सब बातें तो ठीक हैं। रूखासर गांव के एक दलित युवक को दबंग लोग मार-मार कर, पीट-पीट कर, अधमरा करके, मरा हुआ छोड़कर, फैंककर चले गये। आज तक राजस्थान की पुलिस ने जो असली मुल्जिम और अपराधी हैं, उन अपराधियों के ऊपर हाथ नहीं डाला है। मैं राजस्थान की सरकार और मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि वे तुरन्त प्रभाव से ऐसे दबंगों का इलाज करें और समाज के अन्दर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको प्रश्रय देने का काम करें।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गोपाल लाल मीना।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, राजलदेसर को नई तहसील बनायी जाये, यह भी मैं कह चुका हूं। बाकी सारी चीजें, माननीय सभापति महोदय, मैं टेबल कर दूंगा, क्योंकि समय कम दिया गया है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री, आदरणीय अशोक जी गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 में की गयी घोषणाओं के लिये हार्दिक आभार एवं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बजट में राजस्थान के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा। इस वर्ष के बजट में सम्पूर्ण राजस्थान के सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को, खास तौर से एस.सी., एस.टी., ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के लिये जो बजट के वित्तीय प्रावधान बढ़ाये गये हैं, उससे इस वर्ग के सभी लोगों को फायदा मिलेगा।

मैं सबसे पहले इस बजट प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं तथा इस वित्तीय वर्ष के बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में भानपुर कलां के पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। नीमला का पशु चिकित्सालय भी क्रमोन्नत किया गया। ग्राम पंचायत कोलीवाड़ा में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोला गया। बिरासना में 33 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत किया गया।

मैं सबसे पहले मेरी तरफ से और जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि वे हर बजट के अन्दर विकास की नई दिशा को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र में कोई न कोई अच्छा काम हमारे स्वीकृत करते हैं, इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा बहुमुखी प्रतिभा का धनी दूसरा और कोई नहीं देखा, जो हर समय गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित महिला और एस.टी., एस.सी., आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान व कल्याण की सोच रखता हो।

आज कोरोना की वजह से पूरे देश में आर्थिक स्थिति कमजोर है, राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले एक ही बात कही कि राजस्थान का कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने जो प्रबन्धन किये हैं, उनकी प्रशंसा न केवल देश के बल्कि पूरे संसार के कई देशों में हुई है। हमारे भीलवाड़ा एवं रामगंज मॉडल की प्रशंसा देश के प्रधान मंत्रीजी ने भी की है। इसके लिये भी हम उनके आभारी हैं।

इस कोरोना के समय आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने लगातार वी.सी. के द्वारा चाहे पक्ष के एम.एल.ए. हों, चाहे एम.पी. हों, चाहे विपक्ष के एम.एल.ए.,

(श्री गोपाल लाल मीना)

एम.पी. हों, सबसे बात करके और जहां भी कोई समस्या आयी, उनसे लगातार वी.सी. करते रहे और कोरोना का प्रबन्धन करते रहे।

शिक्षा के क्षेत्र में भी नई क्रान्ति लाने का काम आदरणीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोतजी ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की सभी 3,820 सैकण्डरी विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत किया है। ग्राम पंचायत मुख्यालय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के लिये फैसला किया गया। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। इससे सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना देखते थे, आज उन लोगों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका आदरणीय अशोक गहलोत जी की वजह से मिल रहा है और वह एक पूरे प्रदेश में हर ग्रामीण क्षेत्र में, जिन लोगों की सोच थी कि हमारा बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े, उनका सपना अब पूरा होने जा रहा है। इसके लिये राजस्थान सरकार ने 10 हजार अंग्रेजी शिक्षकों की स्कूलों में भर्ती लेने की घोषणा की है। यह भी एक ऐतिहासिक फैसला है।

सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या रहती है, वह समस्या आने-जाने की परिवहन की व्यवस्था है। इसके लिये गत बजट में पांच करोड़ रुपये हर विधान सभा क्षेत्र में दिये थे, उसको बढ़ाकर दस करोड़ रुपये किया गया है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या रहती है, उस समस्या का समाधान होगा।

मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किये हैं, चाहे खेल में किये हैं। खेलों में पैरालम्पिक खिलाड़ियों के लिये 25-25 बीघा जमीन देने की जो घोषणा की है। यह उन खिलाड़ियों के लिये बजट में जो प्रावधान किया है, उससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

भाजपा सरकार के द्वारा 01 जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त हुए कार्मिकों के लिये पेंशन बन्द कर दी गयी थी। इन पेंशनधारियों एवं उनके परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का जो निर्णय लिया है, वह न केवल स्वागत योग्य है, बल्कि ऐतिहासिक भी है। इससे समस्त सरकारी कर्मचारी, जिनको भविष्य में इसका लाभ मिलेगा, पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ राजकीय

(श्री गोपाल लाल मीना)

सेवाएं करेंगे, जिसका सामान्यजन को भी लाभ मिलेगा। यह जो घोषणा की आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने, यह केवल राजस्थान के कर्मचारी ही नहीं, पूरे देश के कर्मचारियों के लिये एक मॉडल बनकर तैयार हुआ है और इससे पूरे देश के मुख्य मंत्रियों, चाहे देश के प्रधान मंत्री हों, वे सोचने के लिये मजबूर होंगे कि कर्मचारियों को, जब बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी जब पेंशन नहीं होती है तो उनके साथ में क्या गुजरती है, यह बात सोचने वाला केवल देश में राजस्थान का मुख्य मंत्री है, जिन्होंने यह घोषणा की और इस घोषणा के साथ में जिस प्रकार प्रदेश के कोने-कोने में, जहां भी कर्मचारी हैं, उस कर्मचारी का परिवार है, वे खुशी से झूम उठे।

यहां पर शुरुआत में जब बजट पर हमारे सदन के उप-नेता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि बजट में लोगों को बुला-बुलाकर लेकर आ रहे थे। पहले बजट को मोबाइल पर नहीं देखते थे, टी.वी. पर नहीं देखते थे और एक ही बात सामने आती थी कि यह इलैक्ट्रिक सामान महंगा हुआ, यह सस्ता हुआ, लेकिन आज जो बजट आ रहा है और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने इन तीन सालों में जो बजट पेश किया है, वह हर वर्ग के लिये बजट पेश किया गया है। चाहे युवा हो, नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, हर वर्ग के लिये उन्होंने बजट में कुछ-न-कुछ अच्छा काम करके दिखाया है, जिससे अब जो कर्मचारी हैं, कांग्रेस सरकार के समय 2800 ग्रेड-पे वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त पदोन्नति के लिये दिये गये ग्रेड-पे फायदे के आदेश को पिछली भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया था।

(समय: 14.10 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): अभी दस मिनट नहीं हुए।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त कर दें आप।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): कर्मचारियों की कटौती वापस लेने से ढाई लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचा है।

सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की मांगें भी करना चाहूंगा। उसके साथ ही किसानों की बात जरूर करना चाहूंगा क्योंकि पहली बार आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों का बजट पेश किया है। भूमि अधिग्रहण बिल और 3 काले कानूनों को केन्द्र सरकार ने थोपने का काम किया। राजस्थान के मुख्य मंत्री

(श्री गोपाल लाल मीना)

जी ने किसानों के फायदे के लिये सोचा, उसके लिये कृषि बजट अलग रखा गया है। इसको 11 मिशनों में बांटा गया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): समय को देखते हुए मैं मेरे क्षेत्र की मांग बोल दूं।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): एक मिनट। मैं अपने क्षेत्र के लिये मांग करता हूं कि बीसलपुर बांध का ओवर फ्लो पानी जमवारामगढ़ बांध में आयेगा तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): हम आपके साथ हैं।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): प्रथम चरण में ईसरदा बांध परियोजना से जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने एवं विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल उपलब्ध कराना। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने गत बजट में दौसा तक पानी लाने का कहा था, मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट में प्रथम चरण में लेकर जमवारामगढ़ को पानी दिया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत नीमला में 33 केवी जीएसएस अति आवश्यक है। वह ग्रामीण क्षेत्र है। दूर-दूर तक कोई ग्रिड नहीं है। ग्राम पंचायत रायसर को नवीन उप तहसील बनायी जाये। तहसील आन्धी में पंचायत समिति भी है। नवीन उपखण्ड, एसडीएम कार्यालय यहां होना जरूरी है। जमवारामगढ़ में जयपुर विद्युत वितरण के 3 कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय ताला, सायपुरा, डांगरवाड़ा, उप तहसील ताला को तहसील में क्रमोन्नत, तहसील आन्धी में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय, ग्राम पंचायत भानपुर कलां में नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय, तहसील आन्धी में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का कार्यालय मय पद, जमवारामगढ़ में अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का कार्यालय मय पद, जमवारामगढ़ में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय मय पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसर, ताला, चावण्डिया और खरखड़ा में...

श्री सभापति: समाप्त करें आप। माननीय सुरेन्द्र सिंह जी।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): नीमला, बूज....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आपका अंकित नहीं होगा। बैठें आप।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सुरेन्द्र सिंह जी।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आपका अंकित नहीं होगा। अब आप बैठें। माननीय सुरेन्द्र सिंह जी।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): 000

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मारवाड़ के गांधी कहलाने वाले गांधीवादी नेता ने जब 23 फरवरी को यहां बजट प्रस्तुत किया था तो उस बजट में एक बात बोली कि जन घोषणा-पत्र की 70 परसेंट और बजट घोषणाओं की 85 परसेंट घोषणाओं को धरातल पर उतार दिया गया है। यह बिलकुल असत्य बात है क्योंकि जब सरकार 2 साल में कोरोना से बाहर ही नहीं निकली तो यह धरातल की रिपोर्ट इनके पास कहां से आयी?

सभापति महोदय, इसमें आप 4 लाइनें और देखो, भाषण की शुरुआत की थी,

'ना पूछो मेरी मंजिल कहां है,
अभी तो सफर का इरादा किया है।
ना हारूंगा हौसला उम्र भर,
यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है'।

इस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा,

'मंजिल का पता नहीं है
और सफर का इरादा किया है।
सिर्फ हौंसलों की बातें करते हैं ये,
इन्हें तो यह भी याद नहीं कि क्या वादा किया है'।

सभापति महोदय, मैं, आप सबको पहला वादा याद दिलाना चाहता हूं कि 30.09.2018 को दिल्ली के आपके हाईकमान के आदेश से आप मेरे विधान सभा क्षेत्र चारभुजा की नगरी में, उदयपुर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

सब नेता इकट्ठे हुए। वहां पर एक वीडियो कोच लगी। सारे नेताओं को वीडियो कोच में बैठाया गया। सबसे आगे वाली सीट पर इनके प्रभारी अविनाश खन्ना भी थे।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): खन्ना नहीं थे। खन्ना आपके हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): पाण्डे जी। हां, उन दोनों के नाम सेम हैं। अविनाश जी पाण्डे थे। एक तरफ गहलोत साहब विराज रहे थे। एक तरफ पायलट जी विराज रहे थे। सभी मेवाड़ के नेता उसमें बैठकर चारभुजा नगरी में आये थे। आप उसी स्थान पर आये थे जहां 2013 में हमने सुराज संकल्प यात्रा प्रारम्भ की थी। वहां पर आकर आपने भाषण दिये कि वसुन्धरा मुख्य मंत्री हैं और सुरेन्द्र सिंह यहां का विधायक है। इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। इस बार हम यहां चारभुजा नाथ की नगरी में अर्जी लगाने आये हैं। 0.5 परसेंट, कुल डेढ़ लाख वोटों से आपकी जोड़-तोड़ कर सरकार बनी है। उस समय आपने यह भी वादा किया था कि हम समस्त किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ कर देंगे। वे दिन आपने दिये थे, 1 से 10 और समस्त किसानों के कर्जे माफ। यह आपने सागवाड़ा की चुनावी सभा में आपके आदरणीय नेता राहुल जी गांधी से घोषणा करवायी थी।

अभी यहां बहुत प्रचार किया गया था कि इस बार कृषि बजट अलग आ रहा है। गांवों में थोड़ा उत्साह बढ़ा। पहली बार कृषि बजट आ रहा है। हमें कुछ मिलेगा लेकिन आपने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में 11 सूत्री मिशन दिये हैं। वे सारे मिशन केन्द्र सरकार की योजनाओं से मिले हुए हैं। उसमें केन्द्र सरकार से आपको पैसा मिलेगा। किसानों को तो आस थी लेकिन 10 दिन की जगह आज एक हजार से ऊपर दिन हो गये हैं। किसान आज भी गांवों में बैठा हुआ रो रहा है कि सरकार ने 10 दिन का वादा किया था और 3 वर्ष से ऊपर हो गया। एक हजार से ज्यादा दिन हो गये हैं। आपने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है।

सभापति महोदय, यही नहीं, हमारी सरकार ने, मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने किसानों के लिये बिजली में 10 हजार रुपये तक की मदद की थी। जैसे ही आपकी सरकार आयी, आपने उसको निरस्त कर दिया। अब जब आपको लगा कि धीरे-धीरे चुनाव का टाइम आ रहा है तो वापस 10 हजार से 12

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

हजार बढ़ाकर वाहवाही लेने का काम कर रहे हो। आप केवल योजनाओं के नाम बदलते हो और उसकी नकल करने का प्रयास करते हो।

सभापति महोदय, किसानों को उम्मीद थी कि भारत के प्रधान मंत्री जी जो सालाना 6 हजार रुपये की मदद कर रहे हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, उन्होंने भी राज्य सरकार की तरफ से उसमें और जोड़ा। अच्छा होता कि आप 6 हजार रुपया राज्य सरकार के खजाने से उन किसानों के खातों में डालने का प्रयास करते। किसान अब बहुत समझदार है। आप किसान विरोधी हैं।

यहां पर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने 123 कालेज 3 साल में खोल दिये। पूर्व में आपकी सरकार ने 5 साल में 82 कालेज खोले थे। लेकिन हमारी सरकार में जो कालेज खुले, उनके लिये बजट में व्यवस्था थी। वहां कालेज की बिल्डिंग्स बन रही हैं। मुख्य मंत्री जी जब कल जवाब दें तो यह बतायें कि 123 कालेज जो आपने खोले हैं, वहां कितनी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। एक भी नहीं है। यह केवल घोषणा का बजट है।

उस दिन मैं देख रहा था। मैंने 2 घंटे 58 मिनट बहुत शान्ति से सुना। क्या मेजें थपथपाई थीं, सचेतक महोदय, इसमें हुआ यह है कि सत्ता के विधायक ने और सहयोगी विधायक ने जो पत्र दिया, मुख्य मंत्री जी ने वही पत्र देकर चीफ सैक्रेटरी को कह दिया कि टाइप कर दो और वे सब घोषणाएं हो गयीं। करना क्या है, काम तो होना है, हो जायेगा, पिछले 3 साल में कुछ नहीं किया यह 1 साल और निकल जायेगा। केवल आपने घोषणाएं की हैं। वो ये भी बता रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी तो गांवों में हर पंचायत में चरणबद्ध तरीके से गौरव पथ बनाने का निर्णय लिया था। आज मेरे वहां 57 पंचायतें हैं, 3 साल में 57 ही पंचायतों में गौरव पथ के निर्माण हुए। आज वहां पर मार्बल एरिया है, 50 से 70 टन की गाड़ियां निकलती हैं लेकिन वो 8 साल पहले के बने हुए गौरव पथ अभी तक नहीं टूटे हैं। आपने उसका भी नाम बदल दिया, ग्राम विकास पथ। लोगों ने कहा कि यह कोई और बड़ी चीज आयी है। पहले वाले सरकार से और कोई ज्यादा करके बताएंगे। मुझे कहते हुए शर्म आती है सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, कल मुख्य मंत्रीजी अपना उत्तर दें तो बता

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

दें कि उमरवास के अलावा कहीं विकास पथ बना है क्या? आपका 3 साल में एक विकास पथ और हमारी सरकार के 3 साल में 57 गौरव पथ, यह अन्तर है। जनता जान रही है, धरातल पर क्या हो रहा है। अभी आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपके सरकारी लवाजमा साथ रहता है, सरकारी पैसों से अच्छे टेंट लग रहे हैं, नरेगा के लेबर उसमें ला रहे हो, भाषण ठोक रहे हो, तालियां बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं, लेकिन वो लोग ढोल इसलिए बजा रहे हैं कि आपको रवाना करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपको नहीं पता है कि होने वाला क्या है, ये घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): भाषण तो आप ठोक रहे हो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): सुनो आप मुझको, मैं तो बहुत शान्ति से सुनता हूं आपकी बात और आप तो रीट के बारे में ज्यादा बोलो ही मत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है। आप अपनी बात एक मिनट में पूरी करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने जब वहां घोषणाएं कीं तो आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसा बड़ा काम बता दो इन तीन साल में जो दो-चार करोड़ रुपये का ही करा दिया हो। मैं सड़कों का बता सकता हूं कि आमेट से गोमती, आमेट से सरदारगढ़, आमेट के केलवा, आमेट से देवगढ़ और आमेट से चारभुजा, एक साल में डबल सड़कें बनी थीं। अब केवल एक सड़क रह गयी थी और आपकी सरकार आ गयी। आमेट से जीलवा कोसीतल, थोड़ा तो नाक बचा लो एक सड़क को भी सैंक्शन करके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात बताना चाहूंगा, पीएचईडी मंत्रीजी यहां नहीं विराज रहे हैं। चार भुजा की एक महत्वपूर्ण योजना है, बेड़च नाका योजना, मैं आपसे कोई ज्यादा डिमांड नहीं करना चाहता क्योंकि केवल घोषणा ही होगी लेकिन बेड़च नाका के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जब आये थे तो उसके एक महीने पहले इसे डीएमएफटी योजना में स्वीकृत किया गया था, दो करोड़ रुपये से ऊपर बजट था, चीफ सैक्रेटरी की कमेटी में आया। मेरे पास पत्र है, चीफ सैक्रेटरी ने इस पर सहमति दे दी थी,

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

लेकिन आचार संहिता की वजह से टेंडर प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई। आपने उस क्षेत्र के किसानों को यह तोहफा दिया कि 2018 में सरकार आते ही उसको निरस्त कर दिया, तीन साल हो गये हैं, कौनसा मुंह लेकर उस चारभुजानाथ की नगरी में आओगे? जनता आपसे जवाब पूछेगी।

माननीय सभापति महोदय, तीन-चार मेरी जो मांगें हैं मेरे क्षेत्र की, उनका मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। पहली महत्वपूर्ण मांग है, बेड़च नाका, आमेट सीएचसी को क्रमोन्नत करना, चारभुजा में कालेज खोलना, आमेट कोसीतल का जैसा मैंने अभी जिक्र किया, आमेट में महिला कालेज खोलना एवं परशुराम महादेव में रोप वे बनवाना, क्योंकि वहां मेवाड़ और मारवाड़ का संगम होता है, आप भी इससे परिचित हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कल मारवाड़ के गांधी कुछ करेंगे तो कुम्भलगढ़ का नाम भी उसमें आयेगा तो कुम्भलगढ़ और आमेट की जनता को भी गांधीजी के प्रति भी विश्वास पैदा होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे बजट 2022-23 के वाद-विवाद में बोलने का मौका दिया। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 23 फरवरी को जो बजट पेश किया, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि इन पोइंटों पर घोषणा नहीं होगी तो अपन ये कहेंगे। कई बार अपन हाउजी का खेल खेलते हैं तो दूसरों के नम्बर काटते रहते हैं और खुद के नम्बर भी कट जाते हैं और बारी नहीं आती है जीतने की तो जैसे पिछले दो साल से पूरे विश्व में भारत में और राजस्थान में कोविड-19 से जो स्थितियां उत्पन्न हुईं। फाइनेंशल रिसोर्सेज जो स्टेट के थे और स्टेट की जो नीड थी, मानव के अलावा भी हर जीव के लिए चाहे पशु हों, पक्षी हों, पेड़-पौधे हों, इंसान हों, सभी के लिए उसको बैलेंस करके जो बजट पेश किया गया, उस समय हम सब लोग बैठे हुए थे, विपक्ष के माननीय सदस्य भी सब विराजे हुए थे, जैसे-जैसे तीन घण्टे में पूरा पढ़कर सुनाया गया, समाप्ति पर लगभग इस साइड में तो वास्तविक जनता का भला चाहने वाले थे, खुशी थी और उस साइड में बजट अच्छा होते हुए भी चेहरों पर खुशी नहीं थी।

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषित होने के बाद में चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्टोनिक मीडिया हो, मैं स्वयं भी खेलों से, सामाजिक कई

(श्री रूपाराम)

गतिविधियों से पूरे राज्य में जुड़ा हुआ हूं जहां से भी बात आयी, राजस्थान के करीब 350 शहर, 4 लाख ढाणियां और करीब 50 हजार गांव, हर जगह से, चाहे किसी भी विचारधारा का, पार्टीवाइज अलग विचारधारा के भी हैं, उनके मुंह से भी यह था कि बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत ही अच्छा पेश किया। कहीं भी आज अपन जो कुछ भी करते हैं राजस्थान में रहने वाली साढ़े सात करोड़ जनता के लिए करते हैं, पशुधन के लिए करते हैं, पूरा वातावरण निर्मित करने के लिए करते हैं, कहीं भी इसकी आलोचना प्रदेश में नहीं की गयी।

माननीय सभापति महोदय, अभी यहां माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट उनके लिए घोषित किया जो उनके चहेते थे। शिक्षा विभाग में जो बजट दिया गया है, 11,441 ग्राम पंचायतें हैं, वो कोई केवल चहेतों के लिए नहीं हैं, 200 विधान सभा क्षेत्रों के पूरे क्षेत्र के अन्दर 11,441 ग्राम पंचायतें हैं और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की कि जो ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, उनमें अगर स्कूल नहीं हैं तो खोली जायेंगी। पांचवीं तक है तो आठवीं तक की जायेगी, आठवीं तक है तो बारहवीं की जायेगी तो इसमें कहां चहेतों के अलावा को भी छोड़ा है? यह चीज बेसलेस है, इसको कहना ज्यादा औचित्यपूर्ण नहीं लगता है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मनरेगा में 100 दिन की जगह 125 दिन किये तो वह एक के लिए तो किये नहीं, पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 100 दिन से 125 दिन पूरे प्रति जॉब कार्ड प्रतिवर्ष किए हैं वो सभी के लिए हैं। इसी प्रकार करीब 350 शहर हैं, अरबन सेक्टर में जो 100 दिन का किया है उसके लिए भी कोई भेदभाव नहीं किया है, सभी के लिए किया है। किसी भी डिपार्टमेंट में देखो तो पूरे राजस्थान के, पूरे वासियों के लिए, हर जीव के लिए इस बजट में प्रावधान किया है, यह अपने को मानना चाहिए। देश की आजादी के बाद में चाहे भारत पूरे में या राजस्थान में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वास्तविक रूप से डवलप हुआ है, उसके अन्दर 80 परसेंट या तो कहें कि स्थानीय सरकारें थीं, स्थानीय पार्टियां थीं या कांग्रेस थी, उनका किया हुआ है। आज माननीय विपक्ष में विराजे हुए सदस्य, मैं राजकीय नौकरी में भी रहा, पीएचईडी विभाग से था, कई लोकार्पण कराये। एक चूरू जिले का लोकार्पण था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय अशोकजी गहलोत थे, उन्होंने पांच बार पूछा, मुझे ध्यान में है कि वसुन्धराजी ने शिलान्यास किया

(श्री रूपाराम)

था उसका, मैंने कहा कि शिलान्यास कर चुके हैं, मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं थी, फाइनेंशल सैंक्शन नहीं थी, टेक्नीकल सैंक्शन नहीं थी, लैंड फाइनल नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ध्यान है, मैंने देखा तो वास्तव में शिलान्यास किया था, बगैर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, फाइनेंशल सैंक्शन और टेक्नीकल सैंक्शन। मैंने कहा कि सैंक्शन तो नहीं थी लेकिन कर दिया है, कहा कि कर दिया है तो अपन नहीं करेंगे तो जो इस प्रकार से छान-बीनकर काम करते हैं, उसमें वे लोग बुराई करते हैं, जो काम किये बगैर राजीव गांधी सेवा केन्द्र की जगह सिर्फ 'राजीव' काटकर 'अटल' करते हैं। इससे नहीं होता है। गांव वालों को सब पता है। गांव वाले यहां तक पता रखते हैं कि जब हमारे यहां फलां सरपंच था, फलां एमएलए था, तब हमारे यहां यह काम हुआ था। आज आप देखें, कई बार ऐसा हुआ, जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी या बीजेपी और जनता दल की थी और केन्द्र में कांग्रेस की थी, वह इस प्रकार से भेदभाव से काम नहीं करती थी।

आज राजस्थान में जो हिल स्टेशन जैसी परिस्थितियां हैं। डेंसिटी बहुत कम है। पानी बहुत कम है। कई विषमताएं हैं लेकिन कभी भी यहां अगर बीजेपी की और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कटौतियां नहीं कीं। आज 80:20 में पैसा मिलता है। आज हवा है, वह तो कुदरत फ्री में देती है। पानी की व्यवस्था सरकारें करती हैं। उसमें 90:10 का रेशो था। यहां 10 परसेंट देना पड़ता था और 90 परसेंट भारत सरकार देती थी। चाहे बीजेपी का राज था तो भी वहां से 90 परसेंट मिलता था। अब कांग्रेस का राज यहां आया और केन्द्र में बीजेपी का आया तो धड़ाधड़ कटौतियां शुरू कर दीं। स्टेट और रिसोर्सेज कहां से लायेगा? इस प्रकार भेदभाव की नीति माननीय अशोक जी गहलोत साहब नहीं रखते हैं। सेंटर जो कर रहा है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स सभी माननीय सदस्यों ने बताये हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि यहां विपक्ष से 25 के 25 एमपी हैं, उन्हें इन चीजों को उठाना चाहिये, क्योंकि दुबारा कोई आये न आये, जिस टाइम में अन्याय हो रहा है भारत सरकार द्वारा, उस टाइम इनके एमपीज-एमएलएज की वहां तक पहुंच है। या तो वे पहुंचाते नहीं हैं अपनी बात या उनकी चलती नहीं है वहां। नहीं पहुंचायेंगे तो वे अपनी जनता के लिये नहीं कर पायेंगे। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उसके लिये जनता हमें माफ नहीं करेगी।

मारवाड़ी में कहते हैं, ''भूटे री बात भटऊ के'', बरसात होने के बाद

(श्री रूपाराम)

भले ही आप असत्य बोलें कि बरसात नहीं हुई है, वह पक्षी अपने आप कह देगा कि बरसात अच्छी हुई है, उसकी बोली ही चेंज हो जायेगी। हम लोग अधिकारी थे, तब भी देखा है। 2008 से 2013 तक कांग्रेस का राज था। मुझसे कई कांग्रेस लीडर पूछते थे, मैं कहता था, साहब, नीचे दुकान कमजोर है। वे कहते थे, लोग खूब आते हैं, भीड़ काफी रहती है कार्यक्रमों में। मैं कहता था, साहब, भीड़ वैसे ही आती है, डेरा कमजोर है। अब की बार किसी गांव और ढाणी में राज के प्रति कोई विरोध नहीं है। यह जो बजट आया, इसके बाद जो थोड़ा-बहुत उन्नीसबीस था, वह भी एकदम क्लीयर हो गया है, इसलिये आप इसमें निश्चिंत रहें। इसका किसे नुकसान होगा, वह 2023-24 बतायेगा।

मैं इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा बजट दिया है, जो भरपेट है, धपाऊ है और लोगों को पूरा सन्तुष्ट करने वाला है, फायदेमन्द है, लेकिन मारवाड़ से मुख्य मंत्री जी आते हैं और हमारे यहां मारवाड़ में जब रोटी जिमाते हैं तो खूब जीम लो, उसके बाद में एक मनुहार करते हैं। जब मनुहार नहीं करें तो माना जाता है कि हमने सही नहीं किया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, कुछेक स्टेट लेवल के बिन्दु हैं, जिनमें थोड़ी मनुहार करने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग में 11 हजार 341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में पांचवीं स्कूल को आठवीं करने और आठवीं को सीधे बारहवीं करने की घोषणा हो गयी। कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी थीं, जहां स्कूलें थीं ही नहीं। वे हमारे रेगिस्तानी एरिया में थीं। वहां स्कूलें खोल दीं। दसवीं के जितने भी स्कूल थे, उन्हें बारहवीं में कन्वर्ट कर दिया पूरे स्टेट में। अब ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अलावा करीब 40 हजार गांव और हैं राज्य में। उनकी ढाणियां भी हैं। वहां पांचवीं और आठवीं की स्कूलें संचालित हैं। वहां बच्चों की संख्या अधिक भी है। वहां चरणबद्ध तरीके से पांचवीं से आठवीं और आठवीं से दसवीं में करने का प्रावधान, कल जो अतिरिक्त जवाब दें, उसमें लेना चाहिये। मेरे हिसाब से प्रथम चरण में 500-500 विद्यालयों का राज्य में लक्ष्य रखना चाहिये।

इसी प्रकार बालिका विद्यालय जो पूरे राज्य में चलित हैं, उन सबको अपग्रेड करने का माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया है। यह बहुत बड़ा काम है बच्चियों-महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये, लेकिन राज्य में कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जहां 100 से अधिक बच्चियां अध्ययनरत हैं। उन ग्राम पंचायत मुख्यालयों में बालिका विद्यालय चलित नहीं हैं। अभी यह जो

(श्री रूपाराम)

मोबाइल वगैरह का चला है, देश में घटनाएं घटित हो रही हैं, गांवों, विशेषकर के मारवाड़ में लोग पांचवीं के बाद अपनी बच्चियों को लड़कों के साथ भेजना नहीं चाहते तो यह अच्छा रहेगा कि जिस ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 100 या उससे अधिक बच्चियां अध्ययनरत हैं और जहां उनके लिये विद्यालय नहीं हैं, वहां अलग से मिडल स्कूल्स खोली जाएं।

आज कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए पशुधन को बचाना आवश्यक है। इससे जो खाद्य उत्पाद प्राप्त होते हैं, वे आर्गेनिक होते हैं। पशुओं में भी मानवों की तरह काफी बीमारियां बढ़ रही हैं। कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां मुख्यालय पर पशुओं के लिये उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। प्रथम चरण में जिन ग्राम पंचायतों में पशुधन की संख्या 3 हजार से अधिक हो, वहां उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने चाहिये।

ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 23 तारीख के बजट में एक घोषणा कर दी है। हमारे राज्य में 33 जिले हैं। 16 जिलों में दो ब्लाक्स में विद्यत सप्लाई की जा रही है किसानों को। शेष 17 के लिये भी उन्होंने फ़रमा दिया है, पर लोग थोड़े-से कन्फ्यूज्ड हैं तो उसमें एक क्लीयर-कट घोषणा हो जाये कि 17 जिलों में दो ब्लाक्स में दिन में विद्युत सप्लाई करने के लिये आवश्यक जीएसएस/फीडर इरेक्ट करने होंगे, उनकी स्वीकृति भी आवश्यकतानुसार जारी की जायेगी।

इसी प्रकार कई माननीय सदस्यों ने फ़रमाया, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा इस विधान सभा प्रांगण में स्थापित की जाए। इसी प्रकार कई सदस्यों ने फ़रमाया, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जातियों को मांगणियार, मिरासी, ढाढी, राणा इत्यादि नामों से जाना जाता है, इनकी कला इतनी फेमस है कि कई-कई कलाकार, जैसे अनवर खां आदि को कई उपाधियां मिली हैं और ये विश्व के 170-180 देशों में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। यह कला जीवित रहे, इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में उनके विकास हेतु एक बोर्ड का गठन हो।

इसी प्रकार राजस्थान राज्य खेलों में अभी भी थोड़ा पीछे चल रहा है हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों से। इसके लिये यहां खिलाड़ियों को भारत सरकार पहले जो सुविधा देती थी, रेल का किराया वगैरह, उसे जीरो कर दिया है। राज्य सरकार रेलवे का पूरा किराया राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वहन करे। सवाई

(श्री रूपाराम)

मान सिंह स्टेडियम में हैंडबाल खेल हेतु ग्राउंड का निर्माण हो। दस खेल प्रबंधकों और 200 खेल प्रशिक्षकों और 20 खेल अधिकारियों की भर्ती की घोषणा हो। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर का एरिया राज्य के 21 विधान सभा क्षेत्रों के बराबर है। राज्य में 200 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें आप।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): मैं चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीएचसी चेलक एवं म्यांजलार, पीएचसी खुइयाला एवं खीया की घोषणा हो। इंडोर स्टेडियम के लिये 4 करोड़ रुपये, फतेहगढ़ के लिये आईटीआई, म्यांजलार, चेलक और खुइयाला में 3 समाज कल्याण छात्रावास खुलें। हमारे नहरी क्षेत्र में किसानों का प्रोडक्शन बढ़े, इस हेतु सिंगल फेज के कनेक्शन दिये जाएं। ये चीजें मांग में सम्मिलित की जाएं। एक बार फिर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, वह लाजवाब है। उस पर पाइंट वाइज डिस्कस करें तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है।

श्री सभापति: बैठें, माननीय सदस्य।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीया दीप्ति किरण माहेश्वरी जी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आदरणीय सभापति महोदय, बजट 2022-23 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी।

सरकार के अर्थ संकल्प से जनता के प्रत्येक वर्ग को भारी निराशा है। सरकार का बजट जनता के जीवन स्तर को उन्नत बनाने, आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और सभी वर्गों के सन्तुलित विकास के लिए सरकार की नीतियों का दृष्टिकोण दिखाता है किन्तु इस सरकार के अर्थ संकल्प में न तो कोई दृष्टि है, न ही जन-कल्याण की कोई सोच झलकती है।

आदरणीय सभापति जी, मैं सत्ता पक्ष के साथियों से कहना चाहती हूं कि-

"मंजिल भी आपकी सबको पता है,
यात्रा के मार्ग और इरादों को भी जानते हैं।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

सत्ता भोग के लिए तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार,
असत्य वादों को आपके, पहचानते हैं।"

बजट भाषण में कहा गया कि वर्ष 2012-13 में पहली बार महिला आधारित बजट प्रस्तुत किया गया। समाज के किसी वर्ग के लिए अलग से बजट प्रस्तुत करने से यदि उस वर्ग का कल्याण होता हो, उसका उत्थान होता हो तो फिर प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक सेपरेट बजट बनाया जा सकता है, किन्तु ऐसा होता नहीं है। आपने महिलाओं के लिए दस वर्ष पहले अलग बजट बनाया, किन्तु आज उनकी स्थिति क्या है? राजस्थान में महिलाओं में बेरोजगारी का प्रतिशत 75 से भी अधिक है। आज राजस्थान महिला अपराधों की श्रेणी में देश में पहले स्थान पर है। 2020-21 से आज यह आंकड़ा 17 प्रतिशत बढ़ गया है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि समाचार पत्रों में बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की गम्भीर घटनाएं नहीं होती हों। सभापति महोदय, मेरे यहां पर सिर्फ पिछले दस दिनों की कटिंग है और ये न्यूजपेपर्स के दस-दस कालम हैं जिनके अन्दर सिर्फ यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ राजस्थान में दुर्व्यवहार हो रहा है।

सिर्फ इतना ही नहीं, महिला विधायक भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं हैं। जिस प्रकार से राजसमन्द में नगर परिषद् के अन्दर महिलाओं के साथ जो प्रकरण हुआ, कांग्रेस के पार्षदों ने जिस तरीके का व्यवहार किया तो जहां कांग्रेस के पार्षद ही महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं तो हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करेगी लेकिन फिर भी मैं मुख्य मंत्री जी से यह मांग रखना चाहूंगी कि वे महिला सुरक्षा के लिए अपने बजट में कुछ न कुछ घोषणा जरूर करें क्योंकि राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ महिलाएं आज यह देख रही हैं, सरकार से यह मांग रखती हैं कि वे उनकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ कदम जरूर उठायें।

इसी प्रकार की स्थिति कृषि बजट की भी है। पहले भी बजट भाषण में कृषि सम्बन्धी विषयों को और उनके लिए किये गये आबंटन को प्रमुखता से दिखाया गया है। प्रचार-प्रसार तो ऐसा किया गया के जैसे इस कृषि बजट से किसानों का कायाकल्प ही हो जायेगा। जिस प्रकार की घोषणा दस दिनों में ऋण मुक्त करने की हुई थी उसी प्रकार की घोषणा इस बजट के लिए थी,

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

लेकिन फिर भी भोले-भाले किसान यह सोच रहे थे कि कहीं न कहीं इस बजट में हमें कोई न कोई राहत जरूर मिलेगी, पर इन्कम-एक्सपेंडिचर में सरकार ने स्वयं ही वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों पर 13 हजार 811 करोड़ रुपये का टोटल एक्सपेंडिचर अनुमानित किया है। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों पर कुल 13 हजार 724 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है अर्थात् कृषि क्षेत्र पर वर्तमान वर्ष के एस्टिमेट एक्सपेंसेज से भी कम प्रावधान किया गया है। यह बजट सिर्फ दिखावे का बजट किया गया है।

भारत सरकार प्रत्येक किसान को सक्षम बनाने के लिए 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में दे रही है। राज्य सरकार भी इसमें अंशदान दे और कम से कम अपनी तरफ से 4 हजार रुपये प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में दे तो इससे किसानों का क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। किसानों की समग्र ऋण मुक्ति की जो आपकी चुनावी घोषणा तीन साल पहले की गयी थी वह भी आज तक पूरी नहीं की गयी है। मेरे राजसमन्द जिले के किसानों को जो नुकसान हुआ है, बारिश की वजह से जो मक्के की खेती का नुकसान हुआ और अति ठण्ड पड़ने की वजह से कपास की खेती का नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि उनके लिए अपने बजट में जरूर कोई न कोई प्रावधान करें ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सके।

राजसमन्द झील एक ऐतिहासिक महत्व की झील है। सभापति महोदय, यह झील मेवाड़ की ही नहीं बल्कि देश की बड़ी झीलों में से एक है। कई वर्षों से कम वर्षा होने के कारण इस झील में जल आवक क्षमता बहुत कम हो गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पूर्व कार्यकाल में यह घोषणा की थी कि राजसमन्द झील में माही नदी घाटी से वाटर डायवर्जन के द्वारा पानी लाया जायेगा। राजसमन्द झील में माही नदी घाटी या देवास परियोजना से वाटर डायवर्जन की व्यावहारिक सम्भावना है, राज्य सरकार को राजसमन्द झील को बचाने के लिए, इस क्षेत्र के किसानों की समृद्धि के लिए, पेयजल समस्या समाधान के लिए और पर्यटन विकास के लिए वाटर डायवर्जन की योजना पर शीघ्र ही निर्णय लेने की कोई न कोई आवश्यकता है।

राजस्थान में राजसमन्द सहित तीन जिलों में मेडिकल कालेजेज नहीं हैं। 21 जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा मेडिकल कालेजेज खोलने का प्रावधान

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

किया गया है और उनका काम भी चालू हो गया है। राज्य सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि बचे हुए तीन जिलों में अब जल्द से जल्द मेडिकल कालेज खोलने की कोशिश जरूर करे।

जिन बड़े शहरों में पहले से ही सुपर एक्सपर्टीज वाली मेडिकल फैसेलिटीज उपलब्ध हैं वहां के लिए आपने अरबों रुपये की योजना घोषित की है। छोटे शहर, जैसे राजसमन्द के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया गया? 300 करोड़ रुपये के छोटे से प्रावधान से राजसमन्द में मेडिकल कालेज प्रारम्भ हो सकता है और इसमें राजसमन्द के डीएमएफटी फण्ड का भी उपयोग किया जा सकता है।

आदरणीय सभापति महोदय, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। सिरोही के माननीय विधायक ने कहा था और वे धन्यवाद दे रहे थे कि सीएचसी लेवल पर डायलेसिस की सुविधा उपलब्ध हुई है। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि जिला मुख्यालय के अस्पतालों में भी 75 प्रतिशत पद रिक्त हैं, डाक्टर्स नहीं हैं, मेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो हम किस तरीके से सीएचसी लेवल पर डायलेसिस जैसा ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड करायेंगे, जब जिला मुख्यालय के अस्पतालों में ही स्टाफ की कमी है। अच्छे डाक्टर्स, अच्छा नर्सिंग स्टाफ और सारे फिजिशियंस लगाने की सख्त जरूरत है।

कोविड के दौरान कांट्रेक्ट पर नर्सिंग स्टाफ रखा गया था, उनका कार्यकाल भी 31 मार्च को खतम हो रहा है। हास्पिटल्स में नर्सिंग स्टाफ की कमी होने के कारण मैं यह मांग जरूर रखना चाहूंगी कि उनका कार्यकाल आप बढ़ाने की जरूर कोशिश करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब आप समाप्त करें। एक मिनट में अपनी सारी बात कह दें, जो भी कहना है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं कुछ पाइंट बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, राजसमन्द में रोडवेज एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि राजसमन्द बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि रोडवेज बसेज वापस से चालू की जायें और छोटे-छोटे गांव जहां पर पहले लोक परिवहन सेवा के तहत उन गांवों में रोडवेज बसेज आती थीं, वहां पर वे बसेज वापस से शुरू की जायें।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

एजुकेशन पर जरूर बोलना चाहूंगी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आपने कर तो दिये हैं लेकिन उन बच्चों का क्या जो एट्थ स्टैंडर्ड तक हिन्दी मीडियम में पढ़े हैं? क्या आपने यह सोचा कि उनका वह ट्रांजिशन कैसे होगा? आज स्थिति यह है कि सबको आपने इंग्लिश मीडियम के लिए बोल दिया है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, लेकिन उन बच्चों का ट्रांजिशन बहुत मुश्किल है। उसकी वजह से जहां पर वे पढ़ रहे थे उनको वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है जहां पर अभी भी हिन्दी मीडियम एजुकेशन प्रोवाइड करायी जा रही है।

आपने एक मिनट के लिए कहा तो मैं बहुत शोर्ट में अपनी बात रखना चाहूंगी और यह निवेदन जरूर करूंगी कि पहली बार बजट पर बोल रही हूं तो आप एक मिनट एक्स्ट्रा देंगे तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगी। एम्प्लायमेंट पर भी मैं यह बोलना चाहूंगी कि आपने बहुत बड़ी घोषणा की कि हमने साढ़े चार हजार एमओयूज किये हैं जिनसे करीब पांच लाख लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा लेकिन उस एम्प्लायमेंट का क्या जो यहां से जा रहा है? इतनी इण्डस्ट्रीज यहां से बिजली की दरों की वजह से छोड़कर जा रही हैं, भले ही वह भिवाड़ी में सील इण्डस्ट्रीज हों या डेनिम इण्डस्ट्री भीलवाड़ा में हो। मैं उनकी ही बात नहीं करूंगी, मेरे राजसमन्द क्षेत्र की मार्बल मण्डी की आज यह स्थिति है कि छोटे गैंगसा आनर्स को अपनी मशीन बन्द करनी पड़ रही है क्योंकि वे बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहे हैं। कोविड की वजह से जो उनको नुकसान हुआ है उसके लिए मैं आशा करती हूं कि मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में इस बात को जरूर संज्ञान में लें और मार्बल इण्डस्ट्री के लिए जरूर कुछ न कुछ प्रावधान रखें।

सभापति महोदय, अन्त में मैं यही कहना चाहूंगी -

'बजट में न तो कुछ नयापन है,
न ही विकास की दिखती सोच है।
पहले चुनाव से गरीबी हटाओ इनका नारा है,
शाही परिवार से आगे न ही इनकी कोई सोच है।'

धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय रामकेश।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति जी, आपने बजट 2022-23

(श्री रामकेश)

पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, यह बजट असामान्य परिस्थितियों का बजट है। नोटबन्दी, जीएसटी और कोरोना के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतर गई और सीमित वित्तीय संसाधन, केन्द्र से प्राप्त राशि में भारी कमी और दो वर्षों

(समय: 15.00 बजे)

से कोरोना से लड़ते हुए इन विषम परिस्थितियों में बजट प्रस्तुत हुआ है। इसके उपरान्त भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुशल वित्तीय प्रबन्ध करके राजस्थान की जनता से जो वादे किये थे, उन वादों में से लगभग 85 परसेंट पूरे करने का काम किया और बजट घोषणाओं में भी लगभग 70 प्रतिशत बजट घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है।

माननीय सभापति जी, कोरोना के कारण पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में हाहाकार मच गया और विशेष रूप से राजस्थान में कोरोना से जो अर्थव्यवस्था खराब हुई, लोगों को जो पीड़ा हुई और जो मंजर हम लोगों ने देखा, उसे कभी भूल नहीं सकते हैं। जो परिजन अपने प्रियजन हमेशा जिनके साथ रहकर के जीवनयापन करते थे, वे ही परिजन, अपने लोगों को छोड़कर दूर हो गये। हमने वे परिस्थितियां देखीं। जिस प्रदेश को विकसित प्रदेश, गुजरात को विशेष रूप से मॉडल के रूप में पेश किया जाता है, गुजरात में हमारे राजस्थान के जो श्रमिक थे वे बहुत बड़ी तादाद में गुजरात में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जब कोरोना का समय आया, मिल मालिकों ने उन मजदूरों को वहां से निकाल दिया।

माननीय प्रधान मंत्री जी की अदूरदर्शिता की नीति एक साथ जो उन्होंने लॉक-डाउन का निर्णय लिया। उससे लाखों मजदूर पैदल चलकर के अपने घरों तक पहुंचे। मैंने गंगापुर में देखा कि गुजरात से निकलकर के हजारों मजदूर, जो पैदल चल रहे थे, राजस्थान की सीमा में आते ही माननीय मुख्य मंत्री जी का जो कुशल प्रबन्धन कोरोना का था, उसके तहत उनकी देखभाल हुई, उनकी सार-सम्भाल हुई और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सवाई माधोपुर जिले में और गंगापुर में जो मजदूर आये, उन मजदूरों को हमने वहां पर ठहराने का काम किया, क्वारंटाइन सेन्टर में व्यवस्थाएं कीं। सरकार के हर विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उसमें लगे हुए थे। चिकित्सा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी लगे हुए थे और शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी उस व्यवस्था में लगे हुए थे। इस तरीके से कोरोना का मैनेजमेन्ट

(श्री रामकेश)

किया। इस विषम परिस्थिति में यह बजट पेश किया है। यह जो बजट पेश किया है, कोरोना की मार से प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हुई, उसके बावजूद भी बहुत संतुलित और अच्छा बजट पेश किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा।

सभापति महोदय, इस कोरोना के समय हमने देखा, यूपीए गवर्नमेंट ने जो महात्मा गांधी नरेगा योजना, जिस पर बार-बार हमारे प्रतिपक्ष के साथी छींटाकशी करते रहते हैं, प्रधान मंत्री जी ने भी नरेगा योजना को महत्वहीन बताकर उसकी आलोचना की, लेकिन कोरोना के समय हमने देखा, इस महात्मा गांधी नरेगा योजना से ही ग्रामीण लोगों का जीवन बचा। उन मजदूरों को वहां पर मजदूरी मिली और अर्थव्यवस्था पटरी पर आयी।

मैं मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा, जो कमी महसूस हो रही थी, महात्मा गांधी नरेगा योजना, जो केवल गांवों में थी, इस बार अपने बजट में उन्होंने शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना की जो घोषणा की है, उसके लिए तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, कोरोना के समय हमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता का महत्व भी पता चला। इसी से माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कालेज बनाने की घोषणा की और चिकित्सा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक काम हो रहे हैं। सब जगह सीएचसी, पीएचसी को क्रमोन्नत किया जा रहा है।

हमारे जो विधायक साथी थे, विधायक कोष था, उस विधायक कोष को भी कोरोना के समय उसमें लगाने का काम किया। मुख्य मंत्री जी ने हमेशा चिकित्सा के क्षेत्र में नयी-नयी घोषणा करके नये आयाम स्थापित किये हैं। पिछली बार भी 2 अक्टूबर, 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना घोषित की और 2013 में भी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना उन्होंने लागू की। इसी के साथ इस बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करके राजस्थान यूनिवर्सल हैल्थ उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। चिरंजीवी योजना में बीमा राशि को 5 से बढ़ाकर के 10 लाख रुपये किया गया है। इससे भी हमारे उन गरीब परिवारों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, मजदूर लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, जो चिकित्सा के अभाव में, दवाई के अभाव में, इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ देते थे और पैसे

(श्री रामकेश)

के अभाव में बड़े हास्पिटलों में आकर के इलाज नहीं करवा पाते थे। मुख्य मंत्री जी की इस योजना से उन लोगों को बड़ा फायदा होगा। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर राजकीय चिकित्सालयों में, राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध ओपीडी और आईपीडी की सुविधाओं को भी पूर्णतया निःशुल्क करने का काम किया है।

माननीय सभापति जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट घोषणा में कई अनूठे काम करके और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़ा सम्बल प्रदान किया है। 3,820 माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक-एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है, इससे निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश के छात्रों को, किसान, मजदूरों को, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का जो सपना उनका था, उस सपने को पूरा करने का काम भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामकेश (गंगापुर): इसी के साथ अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का अलग से एक कैडर बनाया जायेगा, 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती की जायेगी। यह भी मुख्य मंत्री जी ने इसके साथ-साथ घोषणा की है।

सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के 9 हजार 600 करोड़ रुपये के काम हाथ में लिये जाने का प्रस्ताव किया है। हम लोगों ने अभी मुख्य मंत्री जी के सामने हमारी मांग प्रस्तुत की है कि चम्बल से पानी लिफ्ट करके पांचना में डाला जाये, पांचना से पानी ग्रैविटी के साथ टोडाभीम, नादौती, गंगापुर, बामनवास इन क्षेत्रों में आराम से वहां पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामकेश (गंगापुर): चम्बल वाली योजना को जल्दी से जल्दी लागू किया जाये। हमने डीपीआर बनाने के लिए मुख्य मंत्री जी को निवेदन किया है। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि निश्चित रूप से इसको लागू करें, जिससे हमारे दो-तीन जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय संजय शर्मा जी।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इस बजट में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा करते हुए जिस प्रकार से आपने अलवर शहर को शामिल किया है और साथ ही साथ अलवर शहर में जो पार्किंग की बहुत बड़ी परेशानी थी, उसको लेकर के कंपनी बाग़ में मन्नी के बड़ के पास बेसमेन्ट पार्किंग की घोषणा की है। साथ ही साथ सामान्य चिकित्सालय अलवर में सौ बैड और बढ़ाने की जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, धन्यवाद तो मैं दे रहा हूं लेकिन पिछले बजटों की स्थिति जब मैं देखता हूं तो चाहे वह 2019-20 का हो, चूंकि अलवर शहर में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है और 2019-20 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा चम्बल-अलवर पेयजल परियोजना के तहत, जिसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले के 14 कस्बों व गांवों को शामिल किया गया था, उसको लेकर के 4,718 करोड़ की पेयजल आपूर्ति की घोषणा की गयी थी।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इसी सदन में अलवर शहर को शामिल करते हुए ईसरदा बांध परियोजना की घोषणा की गयी थी, जिसमें अलवर शहर के लगभग पांच विधान सभा क्षेत्रों को पेयजल व्यवस्था से जोड़ने के लिए नयी परियोजना की घोषणा की गयी थी। वर्ष 2022-23 में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम बनाने की घोषणा भी की है लेकिन कोई भी योजना चाहे 2019-20 की हो, चाहे 2020-21 की हो, वह धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह है कि वर्ष 2021-22 में जो आपने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 बोरिंग और 40 हैण्डपम्प की घोषणा की थी, संभवत: 2022-23 में आप भूल गये, तो जब आप बजट के इस भाषण पर जो बहस हो रही है, उसका जवाब देंगे तो उसमें उसको जोड़ने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2019-20

(श्री संजय शर्मा)

में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक मोहल्ले में जनता क्लिनिक बनाने की घोषणा की थी लेकिन आज राजस्थान की जनता उस जनता क्लिनिक को ढूंढने का काम कर रही है। साथ ही साथ यदि मैं अलवर जिले की बात करूं तो 2016 में माननीय वसुन्धरा राजे जी की सरकार में मेडिकल कालेज के लिए जमीन का आबंटन कर दिया गया था लेकिन किन्हीं कारणों से वह मेडिकल कालेज अमलीजामा नहीं पहन पाया। 2019-20 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में मेडिकल कालेज बनाने की घोषणा की थी। साथ ही साथ केन्द्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% इस मेडिकल कालेज में लगेगा और 2020-21 में केन्द्र सरकार द्वारा 347 करोड़ रुपये भी राजस्थान सरकार को स्वीकृत कर दिये गये थे लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि उस मेडिकल कालेज का शिलान्यास, भूमि पूजन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वह घोषणा भी केवल कागजों के अन्दर तक ही सीमित है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसी सदन में घोषणा की थी कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायक की अनुशंसा पर सीएचसी को मॉडल सीएचसी बनायी जायेगी। मॉडल सीएचसी बनाने के आदेश तो जारी हो गये लेकिन जो सुविधायें मॉडल सीएचसी में मिलनी चाहिए वह एक भी सुविधा आज तक उस मॉडल सीएचसी में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इसी सदन में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विकास पथ बनाने की घोषणा की गयी थी। अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में तीन ग्राम पंचायतें हैं। एक विकास पथ बन चुका है। दो के प्रस्ताव ले लिए लेकिन उनके क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासी आज उस विकास पथ को ढूंढ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पांच करोड़ की लागत के नॉन पेचेबल या मिसिंग लिंक सड़कों के कार्ययोजना घोषित की गयी थी जिसकी घोषणा भी हो गई, प्रस्ताव भी चले गये लेकिन उनके काम अभी तक शुरू नहीं हुए। साथ ही साथ नगर परिषद् और नगरपालिका क्षेत्रों में 20 और 10 किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा की गयी थी लेकिन बाद में सरकार ने अपने आदेश में परिवर्तन करते हुए नगर परिषद् क्षेत्र में 6 करोड़ और नगरपालिका क्षेत्र में 4 करोड़ की सड़कें बनाने की घोषणा की लेकिन वह योजना भी अभी तक अमलीजामा नहीं पहन पायी है।

(श्री संजय शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इसी सदन में अलवर शहर की शालीमार योजना में सीवर लाइन डालने का काम, वैशाली नगर से एमआईए तक चार लेन सड़क व नाला निर्माण कार्य का काम, इसी सदन में घोषणा की गयी थी लेकिन वह योजना आज तक अमलीजामा नहीं पहन पायी है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशाला बनाने की घोषणा की गयी थी लेकिन वह घोषणा भी अभी तक अमलीजामा नहीं पहन पायी है। इसी के साथ-साथ गुरुनानक देव की 550वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में पांच जिलों में गुरुनानक जयन्ती पार्क बनाने की घोषणा की गयी थी, अलवर शहर भी उसमें शामिल था लेकिन वह पार्क भी आज अलवर शहर की जनता को कहीं दिखायी नहीं दे रहा है।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ चाहे वर्ष 2020-21 का बजट हो, 2019-20 का बजट हो, 2021-22 का बजट हो और 2022-23 का बजट हो, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की बात कही गयी है। उन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना तो बहुत दूर की बात है, केवल रीको द्वारा वहां एक बोर्ड लगाया गया है। मेरा इस सदन में आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि जिन क्षेत्रों में उद्योग चल रहे हैं उनमें एक ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि किसान की जमीन तो ले ली जाती है लेकिन उस उद्योग में काम करने के लिए उस किसान के बेटे को घुसने की अनुमति नहीं होती। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उद्योग लगाइये, विकास कीजिये लेकिन उस उद्योग में राजस्थान के 75 प्रतिशत का आरक्षण आप फिक्स कीजिये, उस किसान के बेटे को उस उद्योग में रोजगार मिले, इस बात की चिन्ता, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था और अलवर नगर परिषद् ने एक प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज रखा है कि अलवर नगर परिषद् को नगर निगम के रूप में क्रमोन्नत किया जाए। साथ ही साथ जो अलवर शहर का

(श्री संजय शर्मा)

सामान्य चिकित्सालय है उसमें जो हमारा शिशु वार्ड है उसको शिशु चिकित्सालय का दर्जा देने की मांग बहुत पुरानी है। अलवर शहर में जो शहरी चिकित्सालय नम्बर-1 जगन्नाथ जी महाराज की जो डिस्पेन्सरी है, साथ ही साथ राजकीय चिकित्सालय नम्बर-4, शिवाजी पार्क की जो डिस्पेन्सरी है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करने के आदेश के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा।

साथ ही साथ चूंकि अलवर में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं अलवर जिला राजस्थान के मानचित्र पर अपराध के अग्रणी जिलों में से एक आ रहा है, अलवर शहर भी इससे अछूता नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अखैपुरा जो पुलिस चौकी है उसको थाने के रूप में स्थापित करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी करें।

साथ ही साथ जो अलवर शहर का सीवरेज से जो क्षेत्र वंचित रह गया है, बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां नगर विकास न्यास द्वारा कृषि भूमि पर पट्टे तो दे दिये गये हैं लेकिन सीवरेज की सुविधा से वह अछूता है, तो आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सीवरेज के लिए बजट का आबंटन करें। साथ ही साथ सीवरेज डलने के बाद, अमृत जलम योजना की लाइन डलने के बाद जो सड़कें हमारी टूट गयी हैं, उसके लिए भी विशेष बजट देने का माननीय मुख्य मंत्री से मैं आग्रह करूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): सभापति महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रत्येक धार्मिक स्थल को जोड़ने के लिए विशेष रूप से जो ट्राइबल क्षेत्र में है, साथ ही साथ जो हमारे पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको जोड़ने के लिए एक लग्जरी बस चलाने का काम किया था। हमारे चौमूं से आने वाले विधायक ने भी माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया था कि सामोद में जो हनुमान जी का मन्दिर है वहां तक बस चलायी जाए वरना हनुमान जी की गदा से कोई नहीं बच सकता। माननीय सभापति महोदय, अलवर में भी भानगढ़ को लेकर के माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी और भानगढ़ में एक किंवदन्ती है कि वहां श्राप के कारण वह पूरा गांव, वह पूरी सल्तनत तबाह हो गयी थी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो पूर्व में की गई घोषणा है, उसको धरातल पर लायें और

(श्री संजय शर्मा)

जो लग्जरी बस चलाने की आपने घोषणा की थी उसको जल्दी से चला दें वरना श्राप के कारण कहीं ऐसा नहीं हो कि 2023 के जब चुनाव आयें तो राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को निपटाकर 21 से भी कम सीट पर लाकर छोड़ दे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें अब। समाप्त करें आप।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री चेतन सिंह चौधरी।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, सन् 1857 में अमरीका में एक पत्रिका चालू की गई थी उसका नाम था एटलांटिक मंथली। 1959 में उसमें एक लेख लिखा गया था और उस लेख में एक कथन था कि किसी भी सरकार की सफलता इस बात से तय होती है कि उस देश में उस सरकार ने चावल और गेहूं के दाम क्या तय कर रखे हैं। अगर इसी मापदंड को मानकर चलें तो मैं बहुत गम्भीरता से यह बोल सकता हूं कि राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, एक सफल सरकार है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने 23 तारीख को जो यह बजट पेश किया, इस बजट में उन तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया जो सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि उनकी सरकार उनकी जरूरतों के लिये ऐसी नीति बनाये, ऐसे निर्णय लें जो कि गरीब, किसान, मजदूर व्यक्ति के परिवार मे खुशहाली लेकर आये और आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं सुधार हो। निश्चित तौर पर यह जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किया गया, उसने इन सभी वर्गों को सम्बल देने का काम किया।

हमारी सरकार ने पहल करते हुए पहली दफा कृषि बजट पेश किया और इसके पीछे मात्र सोच यही रही कि हम कुछ ऐसा करें जिससे जो आखिरी छोर पर किसान बैठा है, जो गरीब किसान बैठा है, उसके जीवन में बेहतरी सुनिश्चित हो सके। पिछले बजट में कृषि कल्याण कोष के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये की राशि तय की गई थी और इस बार इस योजना को वृहद् रूप देते हुए 5,000 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई। इससे खेती व संबंधित क्षेत्रों में योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सकेगा, ऐसा मेरा मानना है।

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

सभापति महोदय, संचय नाम की योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 2,700 करोड़ रुपये तय किये। विपक्ष के साथी लगातार यह बोल रहे हैं, यह क्रियान्वित नहीं हो रहा है, यह क्रियान्वित नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने इसी संचय योजना में पूरे के पूरे भारत के लिये 2,000 करोड़ रुपया तय कर रखा है और हमारी राजस्थान की सरकार ने सिर्फ राजस्थान के लिये 2,700 करोड़ रुपया तय कर रखा है। पिछले साल केन्द्र सरकार ने 4,000 करोड़ रुपया तय किया था और उस 4,000 को कम करके 2,000 कर दिया, यानी 50 फीसदी की आपने कटौती की है। यह बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार की संचय में आबंटित राशि केन्द्र सरकार से ज्यादा है। आप यह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि राजस्थान की सरकार की किसानों को लेकर सोच और समझ किस तरीके की है। हमारी प्राथमिकता किसान का भला है।

सभापति महोदय, बात यहीं खतम नहीं हो रही है। हमारे प्रधान मंत्री जी यह बोलते हैं कि किसान की उन्नति खेती करके किस ढंग से सुनिश्चित हो, यह हमें देखना है। यह वही केन्द्र की सरकार है जिसने फर्टीलाइजर सब्सिडी 25 प्रतिशत कम कर दी। डीएपी समय पर आयात नहीं की, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और यह बोलते हैं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसान की तरक्की हो। और तो और आपने घोषणा कर दी कि केन्द्र की सरकार 14,500 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे। आपने सिर्फ 10,500 करोड़ किसानों को जो राशि दी जा सकती है, उतना ही आपने तय किया, उतनी ही राशि आबंटित की। 4 करोड़ किसान अभी भी मात्र 6,000 रुपये के लिये इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कब मोदी जी वह 6,000 रुपये हमें दे दें। इसके लिये केन्द्र सरकार का जो पिछली बार का 67,500 करोड़ का बजट था, उसमें एक फीसदी बढ़ोतरी की है और 68,000 करोड़ किया गया जबकि सच्चाई यह है 40 परसेंट बजट की बढ़ोतरी करते तब आप 14,500 करोड़ किसानों को 6,000 दे सकते थे। यानी कि किसान की कहीं सोच नहीं है, कहीं दिमाग में नहीं है और हमारे सामने जो मित्र बैठे हैं, वह यह बोल रहे हैं कुछ हुआ नहीं। मैं आपको जानकारी दूं इन सवा तीन सालों में पौने दो साल कोरोना में गये। हालात बद से बदतर होते चले गये। उसके बाद भी हमारी सरकार ने जो बजट दिया वह एक ऐसा बजट था जिसने गरीब और किसान वर्ग की भलाई का काम किया। हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी जब

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब 6 अप्रैल, 2014 का उनका यह कथन I quote, 'हमारे किसानों को सही दाम क्यों नहीं मिले। किसान भीख नहीं मांग रहा है, वह मेहनत करता है। उसको अच्छा दाम मिलना चाहिये।' यह 6 अप्रैल, 2014 का प्रधान मंत्री जी का कथन था। प्रधान मंत्री बनने के बाद उल्टा हो गया। हमारी केन्द्र की सरकार ने एमएसपी खरीद के लिये 2 लाख 42 हजार करोड़ रुपये रखे थे। इस बार उसमें कटौती करके 2 लाख 37 हजार करोड़ कर दिये और वह यह बोलते थे कि किसान भीख नहीं मांग रहा है, उसका अधिकार है, वह मेहनत करता है। फिर आपने एमएसपी खरीद के पैसे कम क्यों किये? आप किसान को उसके उत्पादन पर उचित मूल्य देने की नीयत रखते ही नहीं हैं और जो एमएसपी खरीद का बजट है, उसका 90 प्रतिशत सिर्फ गेहूं और धान खरीदने में चला जाता है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां मूंग की अच्छी फसल होती है। किसान मंडियों के चक्कर लगाता रहता है। अपने ट्रैक्टर लेकर जाता है, अपनी ट्रोली लेकर जाता है कि मूंग खरीदा जाय लेकिन मूंग खरीदा कहां से जायेगा, आपको पैसा ही आबंटित नहीं किया जा रहा है और उसके बाद बोला यह जाता है, इधर के कुछ साथी बोल रहे थे कि मूंग खरीदा नहीं गया। खरीदा कहां से जायेगा, मोदी जी ने एमएसपी घटा दी और उसका भी 90 प्रतिशत सिर्फ गेहूं और धान पर रखा है।

गांवों में बसे गरीब व्यक्ति को मनरेगा के तहत रोजगार मिला, बिलकुल सत्यता है। अभी हमारे साथी रामकेश जी बोल रहे थे कि जो कोरोना के दौरान हालात पैदा हुए उन हालात में मनरेगा ने रोजगार दिलाने के लिये बड़ी भारी मदद की। दिल्ली की सरकार ने उस मनरेगा का 98 हजार करोड़ रुपये का जो बजट था, उसको कम करके 73 हजार करोड़ रुपये कर दिये, यानी कि उसमें भी 25 प्रतिशत की कटौती। यह सारी बातें मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि यह वहम, यह मुगालफत खतम हो जानी चाहिये कि जो दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं या भाजपा की सरकार है, वही किसान और गरीब का भला करना चाह रही है। वही हमारी सरकार है जिसने मनरेगा में रोजगार के दिवस बढ़ाकर 100 के बजाय 125 कर दिये और उन्होंने 98 हजार करोड़ के बजट को घटाकर 73 हजार करोड़ कर दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसमें गरीब को बसेरा मिले, गरीब को छत मिले। अपने बच्चों के साथ कम से कम वह महफूज रह सके। इस सोच के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना बनायी गई थी लेकिन

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

राजस्थान के नाम क्लेरिकल मिस्टेक से कहीं न कहीं दर्ज हुए या नहीं दर्ज हुए और यह जानकारी दी गई कि यह सिर्फ त्रुटि है, क्लेरिकल मिस्टेक है। उसके बाद भी वह नाम दिल्ली ने जोड़ने से मना कर दिये क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। अगर यही सोच रही कि वोटों के लिये हम गरीब आदमी को पीछे धकेल दें तो हमारी राजनीति सही दिशा में नहीं जा रही है। बड़ी भारी गड़बड़ है, बड़ी भारी गलतफहमी में लोग जी रहे हैं और मैं आपको जानकारी दूं कि इसी प्रधानमंत्री आवास योजना का राजस्थान में 56 लाख मकान का टार्गेट था, उसमें से सिर्फ 47 परसेंट टार्गेट अचीव किया गया है।

राजस्थान पर आते हैं, पशुपालन खेती का एक अभिन्न अंग है। किसान के लिये खेती और पशुपालन दोनों एक साथ चलने वाले धंधे हैं। सभापति महोदय, जो ऋण गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पर दिया जाता है, उसमें गाय के लिये 75 हजार, भैंस के लिये 75 हजार लेकिन एक भेड़ और एक बकरी के लिये क्रमश: 6 हजार और 5 हजार माना जाता है। मैं यह मानता हूं कि इसमें बड़ा भारी फर्क है। बकरी को यदि किसान मार्केट में खरीदने के लिए जाये तो अच्छी नस्ल की बकरी की कीमत 25 हजार रुपये होगी और भेड़ की 20 हजार रुपये और किसान को सिर्फ 5 हजार और 6 हजार रुपये का ऋण दिया जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): दो मिनट का समय दीजिये, कभी-कभार तो बोलते हैं। जब किसान को बीमा का क्लेम मिलता है तो वह भी 5 हजार और 6 हजार का मिलता है। मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि यह जो कीमतों की विसंगति है, उसे सरकार दूर करे। जो कृषि ऋण दिया जाता है, उसमें सरकार 5 प्रतिशत का अनुदान है, उसको आप संशोधित करके परमानेंट कर दें। हर बार हम विधायकों को लिखकर देना पड़ता है कि इस बार अनुदान बढ़ायें, इस बार अनुदान दिया जाये, तो इसको स्थायी कर दिया जाये।

एक ऐसी समस्या जो हमारे किसानों के सामने लगातार आ रही है, सभापति महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है, वह है फसल बीमा और उसका निस्तारण। फसल के खराबे के बाद जो क्लेम का निस्तारण होना है, वह बहुत जटिल है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अन्दर यह जो प्रक्रिया अपनायी जाती है, जैसे क्लेम फाइल करना, गिरदावरी बनाना, रिपोर्ट टाइम पर आना, सैटेलाइट द्वारा फसल के नुकसान का आकलन आदि, ये सारी प्रक्रिया सिर्फ

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

इसलिये की जाती है ताकि किसान को क्लेम नहीं मिले। इसका कहीं न कहीं सरलीकरण होना चाहिये। यह बहुत ही जरूरी है। यह इतना पेचीदा ढांचा तैयार कर दिया गया है कि किसान को समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना है? राजस्थान में सरकारी कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन योजना फिर से चालू की गयी है। इससे बहुत भारी जोश है, उत्सव है और उत्सव का माहौल है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): एक मिनट, मैं अपनी मांग रख देता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में आप कोई अपनी अन्तिम मांग रख दें। टाइम आपके सचेतक महोदय ने दिया है, मेरा समय नहीं है। यह उन्होंने दिया है।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): मेरी मुख्य मंत्री जी से मांग है कि डीडवाना शहर में गंदे पानी की निकासी हेतु पांच करोड़ रुपये, दौलतपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुनखुना पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत तथा दुधोली व कोलिया में 33 केवी जीएसएस बने, इसकी मैं मांग करता हूं। जितनी घोषणाएं इस बजट में की गयी हैं, उनमें सबसे उमदा कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में 2 हजार अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें हैं, उन स्कूलों को क्रमोन्नत करना। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। 23 फरवरी, 2022 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन के अन्दर बजट प्रस्तुत किया और अगले ही दिन यानी 24 फरवरी, 2022 से इस बजट पर वाद-विवाद चालू हुआ। सबसे पहले हमारी पार्टी के उप नेता और मेरे पिता के सहयोगी और मेरे चाचा आदरणीय श्री राजेन्द्र राठौड़ साहब ने अपना वक्तव्य रखा और जिस तरीके से उन्होंने इस बजट की धज्जियां उड़ायीं तो सत्तारूढ़ साथी जो कि आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, सभी को चिन्ता हुई और बजट भाषण पर वाद-विवाद छोड़कर वे केन्द्र की सरकार पर पहुंचे और केन्द्र की नीतियों पर पहुंचे तो उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि 2024 में देश के प्रधान मंत्री

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

नरेन्द्र मोदी जी 2019 से कहीं अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापस आ रहे हैं। आप 2023 की चिन्ता करें। कहीं ऐसा न हो कि 2013 में आप 21 पर आये थे और आने वाले समय में 2023 में घटकर आप 7-8 पर न पहुंच जायें।

माननीय सभापति महोदय, अगर इस बजट की बात करूं तो पैरा नम्बर-7 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार का जो चिकित्सा बीमा है उसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया है। माननीय सभापति महोदय, अन्य जिलों की बात छोड़कर जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले में जितने भी बड़े अस्पताल हैं जैसे कि फोर्टिस, मैक्स, ईएचसीसी, शैल्बी, सीके बिड़ला, टोंगिया, नारायणा, मनिपाल, मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनके काउन्टर पर फोन करके जानकारी चाही कि क्या आपने अपने यहां पर चिरंजीवी बीमा योजना लागू की है? प्रत्येक अस्पताल ने इस योजना को लागू करने की बात पर मना कर दिया कि हमारे यहां पर ऐसी कोई भी योजना लागू नहीं है। अगर यह हाल प्रदेश की राजधानी के बड़े अस्पतालों का है तो अन्य पिछड़े जिलों के अस्पतालों का हाल जान सकते हैं। वहां पर जो गरीब लोग रह रहे हैं, उनका इलाज कैसे होगा, यह आप जान सकते हैं। जब चिरंजीवी योजना को अस्पताल लागू ही नहीं कर रहे हैं तो इस योजना को लागू करने का क्या औचित्य है? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसके सफल क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय नोडल एजेंसी बनायी जाये और साथ ही इसको सभी अस्पतालों में लागू करने के लिए सभी अस्पतालों को बाध्य करना चाहिये। अगर कोई अस्पताल इसे लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही का प्रावधान भी लागू करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, पैरा-40 में माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि "Opportunities are not offered. They must be wrested and worked for. And this calls for perseverance and courage." और उन्होंने इसका मतलब भी बजट भाषण के अन्दर बताया 'अवसर प्रदान नहीं होते, उन्हें हासिल करना पड़ता है, उसके लिए काम करना चाहिये और इसके लिए आवश्यकता है दृढ़ता और साहस की', पर मेरा मानना है कि आज प्रदेश का युवा इसका मतलब निकालता है कि सरकार आपको कोई अवसर प्रदान नहीं कर सकती है, युवाओं को हासिल करने के लिए इसका रास्ता खुद खोजना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि प्रदेश का युवा सड़कों के ऊपर है।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं, सब में कोई न कोई पेपर आउट हुआ है या फिर अन्य कोई अनियमिततायें पायी गयी हैं। उसके लिए युवा रोड पर संघर्ष कर रहा है।

अगर देश की बात करें तो राजस्थान देश का ऐसा प्रदेश है जहां पर हर दूसरा ग्रेजुएट व्यक्ति बेरोजगार है और राजस्थान इसके अन्दर देश में पहले स्थान पर आया है। यह हाल राजस्थान की प्रदेश सरकार का है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान से लगते हुए राज्यों में जो उद्योग स्थापित हैं वहां पर वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए 75 प्रतिशत तक का प्रावधान किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री जी बजट का रिप्लाई में राजस्थान में स्थानीय उद्योगों के अन्दर 75 प्रतिशत नहीं तो कम से कम 50 प्रतिशत का बाउंडेशन तय करें ताकि स्थानीय युवाओं को वहां पर रोजगार मिल सके और आराम से वे अपनी जिन्दगी बसर कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने 32 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर दो गांव रायपुर और रालोट हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही केन्द्र सरकार के द्वारा भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जो दिल्ली-मुंबई कोरिडोर बन रहा है और भारत माला प्रोजेक्ट के तहत ही जयपुर से पनियाला मोड़ होकर चंडीगढ़ को जो रोड जा रहा है, उसको जोड़ने के लिए एक रोड की घोषणा की गयी है, जल्दी ही उस पर काम चालू हो जायेगा, ये दोनों गांव उसी लिंक रोड पर पड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो 32 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की है, आप जब बजट पर अपना रिप्लाई दें तो रायपुर और रालोट में 50 हैक्टेयर भूमि सरकार की है, जिससे आपको अवाप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आप वहां पर एक औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा जरूर करें।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने पैरा 87-88 के अन्दर कुल 60 परियोजनाओं के लिए करीब 24 हजार करोड़ के कार्य प्रारम्भ करने की बात कही है। मैंने पूर्व में भी माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था और मांग की थी और मैंने व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी मांग की थी। यहां पर अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, मैंने उनसे भी आग्रह

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

किया था कि आप आज सरकार के अन्दर मंत्री हैं तो आप मुख्य मंत्री जी को कहकर जो ईसरदा बांध परियोजना है, उस योजना के तहत मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र को जोड़ा जाये, जिससे मेरे क्षेत्र में जो पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, वह आने वाले समय में दूर हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किया है। कृषि बजट पर चर्चा करूं। उन्होंने एक वादा किया था कि हम छह घंटे थ्री-फेज बिजली किसानों को देंगे। आज छह घंटे तो बहुत दूर की बात है, तीन-चार घंटे लगातार बिजली भी उनको नहीं मिल पा रही है। समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहे हैं। अब एग्जाम आने वाले हैं, किसान का बच्चा परेशान है, वह समय पर पढ़ नहीं पाता है। जिस तरह के हालात आज गांवों में सरकार ने कर रखे हैं, किसान वहां पर त्राहि-त्राहि कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पैरा 119 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उप तहसीलों की घोषणा की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अंदर मुण्डावर तहसील के अन्दर 41 पटवार मण्डल आते हैं और एक उप तहसील बनाने के लिए 15 पटवार मण्डलों की आवश्यकता होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर सोडावास और ततारपुर दो बड़े कस्बे हैं, उनको उप तहसील का दर्जा दिया जाना चाहिए। पैरा 120 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र नीमराना को नगरपालिका बनाने की घोषणा की, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और साथ ही मांग भी करता हूं कि नीमराना से अलग दो बड़े कस्बे मुण्डावर और शाहजहांपुर मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में आते हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी जब बजट पर रिप्लाई करें तो शाहजहांपुर और मुण्डावर को नगरपालिका बनाने की घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, सरकार सड़कों का राज्य के आधारभूत संरचना और विकास में विशेष योगदान बताती है। अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो एक आन्दोलन की वजह से नेशनल हाईवे-48 बन्द था। मेरे यहां की उसके करीब-करीब लगती हुई सारी सड़कें टूट गयी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा जब सड़क ही राज्य की आधारभूत संरचना है तो मेरे यहां पर जो सड़कें लगती हैं, जैसे शाहजहांपुर से दादिया की ओर 200 फीट से कुतनिया कांकर होते हुए हरियाणा बोर्डर की ओर, नेशनल

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

हाईवे 48 से सकतपुरा-मानगर-रामसिंहपुरा होते हुए हरियाणा बोर्डर, शाहजहांपुर दादिया रोड से गादली की ढाणी होते हुए मानका तक, माजरी से नीमराना-माजरी रोड से सिलारपुर नागौडी होते हुए 200 फीट तक, नेशनल हाईवे-48 से जुनायजाखुर्द सिरयानी होते हुए 200 फीट तक, नीमराना-जापानीज जोन से इंडस्ट्रीयल एरिया से जाट बहरोड़ शाहजहांपुर रोड तक, नेशनल हाईवे-48 से शाहजहांपुर-श्याम मंदिर तक, ये सभी सड़कें ऐसी हैं जो आवागमन के लिए बहुत आवश्यक हैं। बहुत सारी सड़कें इनमें ऐसी हैं जो हरियाणा बोर्डर को जोड़ती हैं। आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा जब आप बजट के अन्दर रिप्लाई करें तो कम से कम एक अलग प्रावधान बनाकर, जो हाईवे बन्द होने की वजह से सड़कें टूटीं, उनका एक अलग से प्रावधान बनाकर आप इन्हें जोड़ने का काम जरूर करें।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इस बजट के अन्दर कहा कि हमने करीब एक लाख तो सरकारी भर्तियां कर दी हैं, सवा लाख आने वाले समय में हो जाएंगी और आने वाले समय में एक लाख अन्य भर्तियों की बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्पेशल इंटीग्रेशन यूनिट फार क्राइम अगैन्स्ट वुमैन की संरचना की, इसी आधार पर एंटी चीटिंग सैल, जो कि चीटिंग की रोकथाम करेगा, इसके गठन की बात की है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि जब उन्होंने एंटी यूनिट फार वुमैन बनाया, उनके ऊपर अत्याचार के लिए एक यूनिट बनायी, इसके गठन के बाद आज महिलाओं पर अत्याचार लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ऐसे एंटी चीटिंग सैल का क्या फायदा जो एस.ओ.जी. के अधीन आयेगा? वह सरकार को जाकर क्वेश्चन नहीं कर सकती। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि परीक्षा-वरीक्षा आप बंद करो, सीधे एक भर्ती काउंटर खोल दो, इस हाथ दे-उस हाथ ले, लीक-वीक का भी झंझट खतम हो जाए, जिससे आज प्रदेश का युवा सरकार से संघर्ष न करे, कम से कम एक रास्ता तो उसे मिल जाएगा कि इतना पैसा लगेगा और भर्ती मिल जाएगी तो उस पैसे का जुगाड़ कर वह तथाकथित व्यक्ति को दे देगा और आने वाले समय में नौकरी भी उसको मिल पाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आपने मुझे बोलने का मौका

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, पहली बार आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। वह भी एक ऐसे मौके पर जब मुझे गर्व हो रहा है कि इतने शानदार बजट पर मुझे आज बोलने का सदन में मौका मिला।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि न केवल शानदार बजट ही दिया बल्कि सुजानगढ़ का भी इस बजट में उन्होंने ध्यान रखा, उसके लिए भी मेरी तरफ से उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। पिछले बजट में भी सुजानगढ़ के लिए बहुत सी घोषणाएं हुईं। विपक्ष के कुछ साथी कह रहे थे कि घोषणाएं हो रही हैं, धरातल पर नहीं आ रही हैं परंतु सुजानगढ़ के लिए जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं, सब धरातल पर हैं, सब पर काम चल रहा है। या तो वह पूरी हो गई हैं या पूरी होने के कगार पर हैं। इस तरह से जो भी योजनाएं हैं, सारी पूरी होने जा रही हैं। दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के विधायकों ने जो लिख दिया, चीफ सैक्रेटरी से वह लिखवा लिया, उसको सदन में पढ़ दिया। क्या सबने यह लिखा कि पूरे 200 विधान सभा क्षेत्रों में स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाए? क्या सबने यह लिखा कि सबको समान रूप से सड़कों का वितरण किया जाए? नहीं, मुख्य मंत्री जी ने सबका एक साथ समान रूप से सभी विधान सभाओं पर ध्यान दिया है। सुजानगढ़ पर हमेशा मुख्य मंत्री जी का स्नेह रहा है। इस बार भी उन्होंने चाहे पशु चिकित्सालय हो, चाहे सांडवा में कन्या महाविद्यालय हो, सौगात दी है। पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय सुजानगढ़ में पहले से था, बीदासर में एक और कार्यालय खोलकर कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिया है।

सभापति महोदय, फिर भी एक बहुत बड़ी मांग क्षेत्र की है, जिससे मैं मुख्य मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा। बहुत-से माननीय सदस्यों ने मांग रखी कि उनके क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए जिला बनाया जाए। आजादी के बाद जिले बहुत-से बने भी हैं। आज 33 जिले हो गये हैं। शायद हमारा क्षेत्र एक ऐसा अभागा रहा कि उस समय की परिस्थितियों में जो कभी जिला हुआ करता था, उसका अस्तित्व पुनर्गठन में खतम हो गया। परिस्थितियां उस

(श्री मनोज कुमार)

समय शायद दूसरी होंगी क्योंकि रियासतों का पुनर्गठन हो रहा था और राजस्थान का बहुत लम्बे समय तक चला। 1956 में जाकर पूरे राजस्थान का पूर्ण गठन हो पाया। 1952 का चुनाव हुआ, उस समय तो अजमेर जैसी रियासतों का अलग से चुनाव हुआ। उसी पुनर्गठन में सुजानगढ़ जिले का अस्तित्व खतम किया गया। कुछ उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि सुजानगढ़ में तीन बड़ी रियासतों की सीमा लगती थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, उस वजह से पेचीदगियों की वजह से उसका जिला समाप्त हुआ। मुख्य मंत्री जी से मैं मांग करता हूं जब भी नये जिलों की बात आए सुजानगढ़ का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए क्योंकि ये नया जिला नहीं बन रहा है बल्कि उसका जो पुराना स्वरूप है वह आप लौटा रहे हैं।

दूसरा, मैं मांग करूंगा कि आज छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में आपने ड्रेनेज परियोजनाएं स्वीकृत की हैं लेकिन सुजानगढ़ जो आज डेढ़ लाख की आबादी का शहर है, वर्षों से नगर परिषद् जहां चल रही है और सबसे बड़ी बात उसकी जो बसावट है, वह एक कटोरीनुमा बसावट है, जिसका पानी बाहर नहीं जा सकता, ढाल की वजह से बीच में आता है, उस वजह से जो छोटी तलाइयां हैं या गिनाणी जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, वहां पानी इकट्ठा होता है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ड्रेनेज परियोजना कम से कम, जब आपका बजट रिप्लाई आए उसमें सुजानगढ़ शहर के लिए ड्रेनेज परियोजना जरूर स्वीकृत कर दें ताकि इतने बड़े शहर की जो बरसात की दिक्कत है, उसको दूर किया जा सके।

सभापति महोदय, मेरी विधान सभा की बात नहीं है, परंतु वहीं से जुड़ी हुई बात है। आचार्य महाश्रमण जी आ रहे हैं छापर कस्बे में। चातुर्मास है और वहां एक छोटा-सा तीन किलोमीटर का टुकड़ा जो छापर कस्बे को जोड़ता है, सुजानगढ़ तहसील का वह भाग है, विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ लगता है। वह तीन किलोमीटर का एक भाग जो बचा हुआ है क्योंकि जो रोड थी, फोरेस्ट में आने की वजह से उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। इसकी जगह जो दूसरा एक वैकल्पिक रास्ता है, उस रास्ते का चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण कर दें क्योंकि पूरा हिन्दुस्तान उस समय यहां इकट्ठा होगा, पूरा जैन समाज इकट्ठा होगा, उस सड़क की मरम्मत आप कल के रिप्लाई में जरूर शामिल करने का प्रयत्न करें।

दूसरा, मेरा हास्पिटल जो सुजानगढ़ शहर का है, वह बहुत पहले बना

(श्री मनोज कुमार)

था भामाशाहों के सहयोग से। आज वह शहर के भीतर आ गया। पार्किंग बहुत बड़ी समस्या हो गई आज के समय में। जब बना था वाहन नहीं चलते थे। एम्बुलेंस को भी जाने में दिक्कत होती है और वहां खड़े होने में भी बहुत दिक्कत है। 150 बैड का हास्पिटल है। इसमें और बैड लगाने के लिए जगह नहीं है क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है। पी.डब्ल्यू.डी. ने कह दिया कि इसके ऊपर और बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती। इस उप जिला अस्पताल को शहर से बाहर ले जाने की घोषणा करावें जिससे कि पार्किंग की सुविधा हो, एम्बुलेंस को जाने में वहां सहायता मिले और सबसे बड़ा रोगियों को सहायता मिल सके।

एक छोटी-सी मांग है कि सांडवा में जहां 33 केवी जी.एस.एस. है या तो उसको क्रमोन्नत किया जाए या एडिशनल ट्रांसफार्मर रखा जाए जिससे किसानों को बिजली उपलब्धता में जो परेशानी हो रही है, उससे निजात मिल सके क्योंकि कृषि कनेक्शन आपने दे दिये। आपने बहुत बड़ी घोषणा भी की है कि जो पेंडेंसी है उसको भी खतम किया जायेगा और कृषि कनेक्शन दिये जाएंगे। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब एक एडिशनल ट्रांसफार्मर लगायें या इसको क्रमोन्नत किया जाए।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 करोड़ रुपये की हर विधान सभा क्षेत्र के लिए घोषणा की है, जिसमें 3 करोड़ रुपये मिसिंग लिंक के दिये हैं। मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि इस 3 करोड़ की सीमा को बढ़ाया जाए या सम्बन्धित क्षेत्र पर छोड़ दिया जाए कि वहां मिसिंग लिंक बनानी है या रिपेयर-मेंटीनेंस में लेना है या पेचेबल में लेना है क्योंकि हर विधान सभा क्षेत्र की परिस्थितियां अलग होती हैं, कहां किसको क्या जरूरत है, इसलिए ये जो बैरियर लगाया है, इस बैरियर को हटा दिया जाए और 10 करोड़ रुपये जो हैं, इसको खुला छोड़ दिया जाए ताकि विधान सभा क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से वह अपने लिये काम में ले सके।

एक मुद्दा जो मैंने देखा कि किसी ने भी नहीं उठाया, माननीय मुख्य मंत्री जी सब कुछ दे रहे हैं। मैं एक चीज उनसे वापस लेने की मांग करता हूं कि जो ये जगह-जगह शराब की दुकानें खुल रही हैं, उन दुकानों को वापस लिया जाए। 01 अप्रैल से पूरे प्रदेश में क्यों न आप शराबबन्दी की घोषणा कर दें। आपने हमेशा आगे बढ़कर एक से एक चीज की घोषणा की है, चाहे दवा वितरण का काम हो, चाहे लॉकडाउन के समय कोरोना में राहत देने का, आपने

(श्री मनोज कुमार)

हर जगह पहल की। आपको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। एक गांधी का ये भी आप काम कर दें कि पूरे प्रदेश में शराबबन्दी लागू कर दें। मुझे पता है राजस्व का नुकसान होगा, बजट में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। फिर भी अगर यह हो जाता है, तो आप इसे लागू ..

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री पब्बाराम विश्नोई।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहली बार बोल रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह पहली बार बोल रहे हैं।

श्री सभापति: एक मिनट और बोल लीजिये। पब्बाराम जी बैठिये, एक मिनट। एक मिनट बोलें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): धन्यवाद। मुख्य मंत्री जी जो योजना लाये हैं, उनको पूरा करने की कोशिश की है। किसी ने नहीं सोचा था कि दवा योजना ऐसी सफल हो सकती है। उसके बाद जांच योजना लाये, वह सफल हो सकती है। यह मुख्य मंत्री जी का विजन था, इन योजनाओं को न केवल सफल बनाया, बल्कि आज पूरा देश उसको मॉडल मान रहा है और देख रहा है कि इन योजनाओं को कैसे किया जाये। आपकी शराबबंदी योजना को भी लागू करके पूरे हिन्दुस्तान को दिखायें ताकि पूरा हिन्दुस्तान देखे और घोषणा करे। पूरे हिन्दुस्तान में यह लागू हो सके, इसलिये मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं।

आपने व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी है। पूरे बजट में राहत देने का काम किया है। इसमें रोजगार का है, विकास का है। बहुत सारी बातें हैं समय कम है, इसलिये मैं कह नहीं पा रहा हूं। व्यापारी वर्ग की बात किसी ने नहीं उठाई, मैं कहना चाहता हूं कि दो लाख रुपये का ईवे बिल आपने माफ किया है, कि दो लाख रुपये तक ई-वे बिल की जरूरत नहीं। व्यापारियों के लिये बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि छोटी-छोटी चीजों के लिये उन्हें ई-वे बिल कटाना पड़ता था, उसे भेजना पड़ता था। 2 लाख की सीमा बढ़ाई है, उसके लिये आज हम लोग, पूरा व्यापारी वर्ग..

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री पब्बाराम विश्नोई।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): धन्यवाद।

श्री पब्बाराम (फलौदी): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद। बजट के बारे में क्या कहा जाये। मेरे विपक्ष के साथियों ने सारी बातें बताई हैं कि किस प्रकार से जन घोषणा पत्र के वादे आपने अधूरे छोड़े, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसी प्रकार से जो तीन बजट आये हैं, उन बजटों की घोषणाओं का भी, धरातल पर आपने कितना किया है, यह सारी बात खंगाल कर छोड़ दी है।

(समय: 15.50 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

लगता है, गहलोत सरकार इस बात पर चल रही है कि बार-बार किसी बात को, कोई बात 100 बार असत्य बोल दी जाये, तो वह सत्य-सी लगने लग जाती है। इसी आधार पर लगातार घोषणाओं पर घोषणाओं का अम्बार लगाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यों-ज्यों 2023 नजदीक आ रहा है, लोगों को भुलावे में डालने के लिये लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं।

मुख्य मंत्री महोदय, विद्यालय क्रमोन्नत के साथ शिक्षकों की भी जरूरत होती है। आज तक तीन साल के अन्दर आप शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाये, फिर यह विद्यालय कैसे चलेंगे? न पिछली घोषणाएं जमीन पर उतर पाई हैं, नई योजनाएं करके, जनता को बहलाने का आप असफल प्रयास कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जन घोषणा के वादे और पूर्व में की गयी घोषणाओं को पहले पूरी करें, तब जाकर जनता विश्वास करेगी। आप लोग बार-बार घोषणाओं से जनता को इस प्रकार से नहीं ठग पाओगे।

यदि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय आपको देने ही हैं तो नये विद्यालय बनाओ, हिन्दी माध्यम के विद्यालयों को कन्वर्ट मत करो। हमारे वहां पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, दूर-दूर तक विद्यालय नहीं मिलते, 10-15 किलोमीटर में एक गांव है और वहां 5 हजार का है, हिन्दी को अगर अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उन हिन्दी माध्यम के सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं वाले बच्चों के साथ बड़ा अन्याय होगा। दर-दर भटकने के लिये मजबूर होंगे। 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि आप नया विद्यालय खोल दें। प्राइमरी विद्यालय की बिल्डिंग खाली पड़ी है, वहां पर खोलें, वहां पर शिक्षक लगायें।

स्कूलों में मास्टर नहीं हैं। अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। मेडीकल कर्मियों की कमी है। पंचायतों से लेकर तहसीलों, एसडीएम कार्यालय,

(श्री पब्बाराम)

नगरपालिकाओं, कर्मचारियों की कमी है। सरकारी काम के लिये दर-दर भटकते नागरिक हैं। अब इन असत्य घोषणाओं के बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। क्या बतायें, हर तरफ लूट मची है। भ्रष्टाचार चरम पर है। दरिन्दों के हाथों इज्जत लुटवाती, कराहती बेटियां हैं। चीत्कार करते नन्हें मासूम, माफियाओं की दादागीरी। कब तक असत्य घोषणाओं से यह कांग्रेस सरकार मन बहलाएगी? अन्त में, पिछली घोषणाओं के अम्बार के नीचे दबी सरकार नई-नई घोषणाएं कर जनता को भुलावे में डालने का असफल प्रयास कर रही है। मुख्य मंत्री महोदय, यदि आपको युवाओं को कुछ काम ही देना है, उनको नौकरियां ही देनी हैं तो यह भर्तियां समय पर करवा दो, वह भी बगैर चीटिंग के, आपसे यह निवेदन है।

अभी-अभी सुजानगढ़ से आने वाले मेरे साथी ने अपना दर्द छलकाया। वो दर्द ही हमारा है। पिछले 30-40 महीने पहले तक फलौदी को जिला बनाने की मांग की जा रही थी, अनशन भी हुए, पूर्व एमएलए लालजी थानवी के द्वारा परन्तु वह अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाया। 1956 के अन्दर, राजस्थान के एकीकरण के बाद कुल 28 ज़िले थे, 7 ज़िले भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बने, कुल मिलाकर 33 ज़िले। क्या आपने कसम खा रखी है कि आपके मुंह से कोई भी ज़िले की घोषणा नहीं होगी? क्या इस कसम को तोड़ने का प्रयास इस बजट सत्र में मुख्य मंत्री जी कर पाएंगे? अगर कर पाए तो हमारे ज़िले फलौदी को भी जिला बनायें। आपके ही एक विधायक मदन प्रजापत जी ने एक भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी है कि वह जूता नहीं पहनेंगे जब तक जिला घोषित नहीं कर देते। कम से कम उनको जूता तो पहनवा दो। नंदीशालाओं की, सारी बातें आपको बता दीं।

कृषि बजट, क्यों भुलावे में डाल रहे हो? लोगों को इन्तजार था, कृषि बजट में किसान सम्मान निधि की तरह कोई घोषणा होगी, जिसमें 500, 1 हजार, 2 हजार, 4 हजार, अपनी औकात के मुताबिक कुछ तो किसानों को देते। अभी-अभी हमारे लाहोटी जी ने बताया, 10 रुपये कम बजट जारी किया कृषि बजट में। यह कृषि बजट की हालत है। हमारे कोलायत विकदरत माइनर में पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है। सरकार द्वारा इन दोनों माइनरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाये।

इसी प्रकार, कृषि यन्त्रों पर मिलने वाला अनुदान है, वह फाइलों का टारगेट भी आप बढ़ाइये। प्रधानमंत्री फसल बीमा 2018-19, बीमा की राशि

(श्री पब्बाराम)

स्वीकृत होने के बाद भी गांव नारायणपुरा, चाखू, लूणा इत्यादि में नहीं मिली है, कृपया इसका भी संज्ञान लें।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपके माध्यम से निवेदन है, 191 किलोमीटर लम्बा औसियां से बीकानेर तक का एक राज मार्ग घोषित हुआ है, 136 मार्ग। उसमें बाकी पूरे मार्ग का दोहरीकरण और सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है, अभी घोषणा हुई है, परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्दर 31 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उस सड़क को सिर्फ सिंगल रखा गया है। माननीय मंत्री महोदय, आपका स्वयं का जिला है, उसके अन्दर से जाते हैं, सिंगल होता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक-दो बात करके मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। यह अवश्य करें। 7 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, कृपया मिसिंग लिंक की ज्यादा मांग है, इसको दे दें या विधायक के ऊपर डाल दें।

हमारे फलौदी के हास्पिटल को जिला हास्पिटल घोषित किया गया, परन्तु कोई भी सुविधा नहीं है। न डाक्टर लगाये गये हैं, न अन्य सुविधायें दी गयी हैं, न वहां पर ट्रोमा सेन्टर है।

इसी प्रकार से बिजली हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी है। जो बिजली कनेक्शन से वंचित रह गये थे, उनको घरेलू कनेक्शन देने का भाग्य श्री योजना के अन्दर आप कृपा करेंगे, मैं ऐसी आपसे मांग करता हूं।

सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में लगभग 80 ट्यूबवैल बन्द पड़े हैं। जेजेवाई के, सारे के सारे पंचायतों के ऊपर डाल दिये। पंचायतों के पास फण्ड नहीं है, वह उसको ठीक नहीं करते। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि 80 पेयजल योजनाएं बन्द पड़ी हैं। कब जल जीवन मिशन का पानी आयेगा, वह कब पानी पीयेंगे? एक-दो मेरी बात है, समय की परिधि है। मेरी नगरपालिका फलौदी लगभग... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(समय: 16.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम (फलौदी): एक दो मेरी बात है क्योंकि समय की परिधि है। मेरी नगरपालिका फलौदी लगभग, एक बात रखकर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप समय से एक्सीड कर गये, प्लीज वाइंड-अप।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात रखता हूं कि यह 106 साल पुरानी है, जोधपुर और फलौदी नगरपालिका का गजट नोटिफिकेशन एक ही दिन हुआ था, एक ही आर्डर के अन्दर हुआ था। जोधपुर तो इतना विकसित हो गया और मेरा शहर फलौदी आज सीवरेज के लिए भी तरस रहा है। आप स्थानीय हैं, मुख्य मंत्री हमारे जिले के रहने वाले होने के नाते क्या फलौदी आपसे कुछ अपेक्षा नहीं कर सकती? मेरा आपसे निवेदन है कि फलौदी के अन्दर सीवरेज की व्यवस्था की जाये और पिछले चार दिन पहले एक दलित युवक राहुल देवड़ा, जिसकी जघन्य हत्या की गयी। एन.डी.आर.एफ. की टीम झील के अन्दर जाकर खंगालती रही लेकिन वह नहीं मिला। तीसरे दिन जाकर उसकी लाश किसी ने वहां पर डाल दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बजट पर बोल रहे हैं, माननीय सदस्य। प्लीज आपका हो गया, थैंक यू।

श्री पब्बाराम (फलौदी): कृपया उसको भी न्याय दिलायें और उनको वित्तीय सहायता भी दें। न्याय दें, चाहे उसके एक नौकरी भी दें। धन्यवाद, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: स्टेटमेंट, माननीय मंत्री महोदय।

शासकीय वक्तव्य

यूक्रेन में फंसे राजस्थानी छात्रों व नागरिकों की सुरक्षित वापसी के प्रयास

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पिछले महीने की 24 तारीख से रूस द्वारा यूक्रेन पर जो आक्रमण किया गया है, यह एक बहुत ही चिन्ताजनक विषय है सभी के लिए। पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए एक यह गम्भीर मैटर है जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस युद्ध के कारण यूक्रेन में रह रहे राजस्थान के नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं को बहुत ही खतरा है और बच्चे बहुत ही डरे हुए और भयभीत हैं। वहां उनसे जब भी बात करते हैं तो वे बहुत डरे हुए हैं और वे यही बात कहते हैं कि प्लीज, हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकाला जाये।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

यूक्रेन से सुरक्षित उन बच्चों और नागरिकों को वापस लाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। यूक्रेन में खरकीव, कीव और सूमी एवं अन्य स्थानों पर टोटल मिलाकर हजार के लगभग अपने यहां के नागरिक और छात्र-छात्राएं हैं जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। युद्ध के चलते यूक्रेन सरकार ने 24.02.2022 को यूक्रेन के सभी हवाई अड्डे बन्द कर दिये हैं, हवाई यात्राएं बन्द कर दी गयी हैं। हवाई यात्रा और हवाई अड्डे बन्द होने के बाद जो संकट की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद से ज्यादा एक भयानक सा माहौल वहां पर क्रिएट हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए नागरिक एवं छात्र-छात्राओं को सुरक्षित लाने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार यूक्रेन में फंसे राजस्थानवासियों को सुरक्षित वापस घर लाने के लिए अभी राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया क्योंकि राजस्थान फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें कि ऑल इण्डिया और आल वर्ल्ड के जो राजस्थानी प्रवासी हैं उनसे उनका लिंक-अप है, एक ग्रुप बना हुआ है तो उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है। विदेश मंत्रालय और यूक्रेन में भारत के दूतावास के साथ लगातार वे सम्पर्क में है, जिससे कि राजस्थानवासी सुरक्षित अपने प्रदेश में आ सके।

यूक्रेन बोर्डर के आस-पास जो रह रहे हैं, जो अपने राजस्थान के अप्रवासी हैं, उनसे भी सम्पर्क किया गया। कल भी मेरे सामने ही बात हुई तो वे लोग भी बहुत सहायता कर रहे हैं। अपनी गाड़ियों से, जिस तरीके से भी सुविधा की जा सके, लगातार सम्पर्क करके यूक्रेन में फंसे हुए राजस्थानी नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं को समस्या नहीं आये, उनको सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है कि वीजा ट्रांजिट प्रक्रिया जो है उसमें थोड़ा समय लगता है जिससे कि उन बच्चों और नागरिकों को सुविधा देने में थोड़ा समय लग जाता है तो कई बार उनसे सम्पर्क भी बीच-बीच में टूट जाता है।

चाहे पड़ोसी जो देश हैं, जैसे हंगरी, रोमानिया, स्लोवाक गणराज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश हैं उनसे विदेश मंत्रालय सम्पर्क करे और जो उड़ानों की संख्या है वह बढ़ाई जाये जिससे कि उनको आने में सुविधा रहे और वीजा ट्रांजिट में टाइम नहीं लगे, ऐसी अपनी प्रक्रिया भारत सरकार की तरफ से कुछ न कुछ होनी चाहिए।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार सभी छात्र-छात्राओं का जो भी वहां से आने तक, चाहे फ्लाइट का खर्चा हो, चाहे उनके बोर्डिंग का, लोजिंग का, किसी भी तरीके का जो खर्चा होगा, वह राजस्थान सरकार वहन करेगी और उन बच्चों के लिए प्रशासन द्वारा, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रधान मंत्रीजी और विदेश मंत्री महोदय को भी पत्र लिखा है जिसमें वहां के जो स्थानीय लोग हैं यूक्रेन के वे उन बच्चों के साथ या भारतीय जो भी नागरिक है, उनके साथ वे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा कि अपन सोशल मीडिया में देख रहे हैं तो इस तरीके के भी अगर अपन वहां की एम्बेसी में बात करें जिससे कि उन्हें सुविधा रहे कि उनको परेशान नहीं किया जाये। कई जगह पर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई, आप यहां से जाइये, निकलिये तो इस तरीके की जो गोलीबारी वहां पर हो रही है तो कई बच्चे यह कह रहे हैं कि हम बंकर में रह रहे हैं। उनको खाने-पीने की भी सुविधा किसी तरीके की नहीं है।

भारत सरकार से अतिशीघ्र निकासी के लिए जो पड़ोसी देश हैं, उनसे सम्पर्क करके जिससे कि वहां पर रह रहे नागरिक और छात्र-छात्राएं अपने सुरक्षित आ सकें। मुख्य सचिव एवं प्रमुख आयुक्त महोदय नई दिल्ली मंत्रालय, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार से लगातार सम्पर्क में हैं। 23 और 24 फरवरी, 2022 को जैसे अपने 34 छात्र तीन फ्लाइट से दिल्ली और जयपुर पहुंचे और 25 छात्र नई दिल्ली के थे, 9 जयपुर के थे। 26 फरवरी, 2022 को 8 छात्र मुम्बई, 27 फरवरी, 2022 को 70 यात्री टोटल पहुंचे चार फ्लाइट से और अभी तक जो पहचान की गयी है कि हजार के लगभग, अपने एक हजार आठ का और भी लगभग बढ़ते जायेंगे कि कितने अपने राजस्थानी वहां पर फंसे हुए हैं। आज सुबह तक जो सुबह की फ्लाइट वहां पर उतरी है उसमें 207 तक अपनी गिनती पहुंच गयी है तो यह इस तरह से अपना वहां से आवागमन जो हो रहा है, उसमें राजस्थान के प्रवासी अभी तक कुल इतने हैं।

राजस्थान सरकार की तरफ से हैल्प लाइन नम्बर जारी किया गया है, फोन नम्बर भी है, ई-मेल आई.डी. भी है, मोबाइल ग्रुप भी बना दिया गया है। राजस्थान के सभी बच्चों को वहां पर, कल हमारी भी बात हुई थी तो वे सारे एक ग्रुप से जुड़ जायें, जो यहां पर आ गये वे भी और जो वहां पर फंसे हुए हैं वे भी और जिनसे सम्पर्क नहीं हो पा रहा है कइयों से तो उनसे भी सम्पर्क

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

करने का प्रयास किया जा रहा है एक ग्रुप बनाकर कि आपको उस जगह पर पहुंचना है।

जो कल बच्चे आये थे, हैल्प लाइन नम्बर्स के जरिए उनको भी जोड़ा गया है। कई बच्चों से मेरी स्वयं की भी बात हुई थी। राजस्थानी जो यूक्रेन से आ रहे हैं, उनको रहने की राजस्थान हाउस और चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, मुम्बई और सभी जगह राजस्थान के निवासियों के लिए, छात्र-छात्राएं, नागरिकों के लिए भी रहने की पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित की गयी है।

यूक्रेन से लौटने वाले राजस्थान के जो छात्र-छात्राएं हैं, उनके लिए इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, मुम्बई एयरपोर्ट, जयपुर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैल्प डेस्क नम्बर भी वहां पर स्थापित किया गया है जिससे कि जो आये उसको किसी तरीके का कष्ट नहीं हो। नई दिल्ली, मुम्बई और जयपुर में रहने और ठहरने, खाने एवं घरों तक उनको पहुंचाने की, जैसे कल आये तो उनको धौलपुर पहुंचाना हो या चाहे सीकर वालों के उनके दादाजी आ गये थे तो वे एकदम से इतने भावुक हो गये, वे सरकार की बहुत ही सराहना कर रहे थे कि ऐसा हमने सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे इतनी सुविधा से आसानीपूर्वक अपने घर तक पहुंच जायेंगे। बच्चों से हमने कल बात की तो स्वयं बच्चे भी यह कह रहे थे कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री महोदय ने जो हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था की कि टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम गाड़ी के लिए व्यवस्था और बिलकुल उनसे टच में रहे। इतनी बार तो हमारे घर वालों ने भी बात नहीं की जितनी बार हमारे से सरकार के प्रतिनिधियों ने फोन पर बात की और हमारे से सम्पर्क किया। मेल टू मेल और मोबाइल पर बात की तो यह हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारा जो डर वहां पर था, वह डर यहां पर आकर खतम हो गया। अब हम औरों को भी कह रहे हैं, जो और बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं कि आप वहां से आयेंगे तो आपको फ्री आफ कोस्ट लाया जायेगा और घर तक पहुंचाया जायेगा, रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। यह गलत बात है। आप सीनियर हो और बोल रहे हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य द्वारा वी.सी. के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर्स से बात भी हुई

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

है। प्रमुख आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली एवं आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन धीरज श्रीवास्तव द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किये गये हैं। सभी जिला सम्भागीय आयुक्तों को निर्देश दिये गये हैं कि जिला स्तर पर कण्ट्रोल रूम स्थापित किये जायें यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से लगातार प्रशासन सम्पर्क में रहें और सूचना आदान-प्रदान करते रहें सम्पर्क में आकर कि आपका बच्चा यहां तक पहुंचा है या यहां पर है, इस स्टेज पर है, अब आ जायेगा या पहुंच जायेगा, प्रशासन लगातार सम्पर्क बनाये रखें।

गृह विभाग के सम्बन्ध में भी पोर्टल पर सूचनाएं दी गईं हैं और निर्देशित किया गया है। उनसे भी लगातार हमारा सम्पर्क हो रहा है। मंत्रालय और यूक्रेन में भारत दूतावास से सम्बन्धित अधिकारी और आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन की तरफ से एक ई-मेल भी भेजा गया है यूक्रेन के नागरिकों एवं छात्रों को। जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनसे भी दूतावास पर कहा गया कि आप इस तरीके का व्यवहार नहीं करें। राजस्थान के प्रवासियों को आप सुरक्षित पहुंचाएं। 01.03.2022 को माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा यूक्रेन से पोलैण्ड आये राजस्थानियों से वीसी के माध्यम से वहां के हालात की भी जानकारी ली और बात भी की गयी कि आपको किसी तरीके की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है और सभी सकुशलता से वापस लौटें, इसके लिए हरसम्भव राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है।

यह घटना बहुत ही चिन्ताजनक है और सभी बच्चों को लाने की जिम्मेदारी के बारे में अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एयरफोर्स के जरिये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कल से आना शुरू हो जायेंगे। लगभग 500 से 800 तक बच्चे आ जायेंगे। यह भी सराहनीय है और इसमें एक साथ मिलकर हमको वायुयान के द्वारा ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के ही नहीं, पूरे देशवासियों को लाने का एक प्रोसीजर अपनाना चाहिए जो सराहनीय है। राजस्थान फाउण्डेशन ने राजस्थानवासियों के लिए जो ग्रुप बना रखा है उससे देश-विदेश से सम्पर्क करके जो सुविधाएं वे अवेलेबल करवा रहे हैं, वह भी सराहनीय हैं। राजस्थान के किसी भी प्राणी को कभी भी किसी तरीके का संकट आता है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय संवेदनशील हैं, एक अभिभावक की तरह से पक्ष हो, विपक्ष हो, तत्परता से मदद के लिए आगे रहते हैं।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार हर सम्भव प्रयासरत

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन से आने वालों को या वहां रहने वालों से लगातार सम्पर्क में रहें और सुविधाजनक तरीके से वह अपने घरों तक पहुंच जायें। सरकार का ऐसा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्रजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने स्थगन प्रस्ताव का जो जवाब दिया है, इससे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली या मुम्बई पहुंचने के बाद में सरकार पूरा खर्चा खाने-पीने की व्यवस्था करके उसको घर तक पहुंचाया जा रहा है। मैंने यह स्थगन 24 को लगाया था और 25 को आपने 2 तारीख को स्टेटमेंट दिलाने की बात कही। मेरे क्षेत्र से भी काफी लोग हैं, उनके लगातार फोन आ रहे थे और मुझे यह बताया गया था कि अभी फ्लाइट्स की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और चूंकि सेना अन्दर आ गयी है इसलिए फ्लाइट्स भी बन्द हो गयी है तथा बोर्डर पर पहुंचना भी हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया है।

जैसाकि सोशल मीडिया तथा मीडिया में देखते हैं, कल मैं आज तक देख रहा था, राकेश पंवार मीडियाकर्मी जो आज तक का है, उसने बताया कि पोलैण्ड या हंगरी की तरफ घुस रहे हैं तो वहां 45-50 किलोमीटर की लाइन है तथा ट्रैफिक जाम है। वहां से बच्चे उतरकर पैदल यात्रा करके बोर्डर तक पहुंचते हैं। उनको बोर्डर से घुसना भी आसान नहीं है। मुझे बताया कि उन्होंने चार दिन में एक दो बिस्कुट खाये होंगे। उनको पानी भी नहीं मिला। ऐसी स्थिति है कि वे बहुत डरे हुए हैं हताहत हैं। मैंने सरकार को इसलिए ध्यान दिलाया कि उस दिन आर्मी ने अन्दर प्रवेश कर लिया था। मैं चाह रहा था कि सरकार उसी दिन हैल्पलाइन खोले। अध्यक्ष महोदय, अभी भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार यह सोचे कि हम जयपुर में हैल्पलाइन खोलें और आपके साथ सभी कोर्डिनेट हों, मैं यह चाहूंगा कि उपखण्ड स्तर पर, जिला स्तर पर कलेक्टर के मार्फत अभिभावक को सूची वहां दे कि उनका बच्चा कहां है। आज भी कई ऐसे बच्चे हैं, हो सकता है कि वह बोर्डर पर आ गया है, कीव जैसे कई शहर हैं जिनको आर्मी ने घेर लिया है, उनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कल एक लड़के की डैथ हो गई क्योंकि वह राशन लेने गया था। राशन लेते वक्त उसकी डैथ हो गयी। उसके ऊपर गोला बारूद फूट गया और उसकी डैथ हो गयी तो आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो शहर को खाली नहीं कर पाये क्योंकि आर्मी ने उस शहर को

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

घेर लिया है। वह निकल नहीं पा रहे हैं। आपको माइन्यूटली सर्वे करवाना पड़ेगा। आप उपखण्ड स्तर पर, जिला स्तर पर माइन्यूटली सर्वे करायें कि हजार, बारह सौ बच्चे, जितने भी हैं, उनके अभिभावक वहां जाकर बतायें, बच्चे के फोन नम्बर दें और वहां का जिला कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट से कोर्डिनेट करके एम्बेसी तक उसकी बात को पहुंचाये, फोरेन सैक्रेटरी तक उसकी बात को पहुंचाये, फोरेन मिनिस्टिर तक उसकी बात को पहुंचाये ताकि उनको आसपास के देशों में लाकर फिर हम यहां ला सकते हैं। आज हालत यह है कि वे भूखे हैं। आज वे तनाव की स्थिति में हैं। वे बंकरों में ठहर रहे हैं। बंकरों में रहते हुए 72 घंटे, 96 घंटे हो गये। खाने-पीने की उनके पास व्यवस्था नहीं है। हालत यह है कि 48 घंटे में केवल एक बार खाना मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि जैसा बताया गया कि हजार-ग्यारह सौ छात्र-छात्राएं हैं, आप माइन्यूटली इसकी तह तक जाएं। एसडीएम और जिला कलेक्टर से सम्पर्क करें। उनके नम्बर और एड्रेस दें जो अभी तक बाहर नहीं निकल सके हैं और बोर्डर तक नहीं पहुंच सके हैं, उनकी स्थिति और भी ज्यादा गम्भीर है जो शहरों में बंकरों में बैठे हैं। बोर्डर पर आ गये हैं वह तो आज नहीं तो कल हमारे देश में आ जायेंगे परन्तु आज जो शहर में बैठे हैं और शहर को आर्मी ने पूरा कैप्चर कर लिया है, उनकी स्थिति क्या हो रही होगी, यह बताना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही संवेदनशील विषय पर सदन यह चर्चा कर रहा है। जब यह चर्चा प्रारम्भ हो रही थी, उससे पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक बच्चे ने मुझसे बात की और जब मैंने उससे कहा कि हम सब लोग, चाहे बच्चे चूरू के हों, तारानगर के हों, सारा सदन और सदन के माध्यम से सारा राजस्थान इस संकट की घड़ी में आपके साथ है। मैं समझता हूं बहुत से लोग इस पूरी चर्चा को देख रहे होंगे। मंत्रीजी ने ठीक कहा कि 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अध्यक्ष महोदय, अब तो वेक्यूम बम का इस्तेमाल होना चालू हो गया यानी बम फूटे उसके साथ ही आदमी पूरा भाप बन जाए। मैं समझता हूं जिस प्रकार से कल कीव और खरकीव पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है और जिस विद्यार्थी नवीन की आपने बात की, गवर्नर हाउस के सामने खाना बंट रहा था, खाना लेने गया और मिसाइल का शिकार हो गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, चिन्ता तब और बढ़ गई जब मैं सम्पादकीय पढ़ रहा था, नाटो देशों के बीच में समझौते का जो प्रोटोकाल हुआ है, उसके आर्टिकल 5 में यह लिखा गया कि अगर कोई भी देश दूसरे देश के नागरिकों को हताहत करेगा तो नाटो में सम्मिलित देश के नागरिक हथियार उठायेंगे। अध्यक्ष महोदय, चिन्ता छोटी नहीं है। हम विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। मैं समझता हूं कि अब तक तीन एडवाइजरी जारी हुई। पहली एडवाइजरी हमारे दूतावास ने 15 फरवरी को जारी की और उसके माध्यम से अपने बच्चों को कहा कि वहां की स्थिति तनावपूर्ण है, आप यूक्रेन छोडें और दूसरे लोगों को कि आप यूक्रेन में घरों में रहें। दूसरी एडवाइजरी 26 फरवरी को जारी हुई। उसमें कहा कि आप यूक्रेन से निकलें पर सीमा पर जो भारतीय अधिकारी तैनात हैं, उनके कोर्डिनेशन से निकलें वरना आपको बड़ी तकलीफ होगी। उसमें भारत सरकार ने जो आपरेशन गंगा चलाया, उसमें उन्होंने यह भी कहा कि रोमानिया, पोलैण्ड, हंगरी आदि देशों से हम आपको रेस्क्यू कर रहे हैं। कल 01 मार्च को मंत्री महोदय, जो एडवाइजरी जारी हुई है, उसमें सीधा कहा कि तत्काल ही आप कीव छोडें। इसके साथ ही भारत सरकार ने कहा कि हम ग्लोब मास्टर प्लेन, जिसका आपने जिक्र किया, वह भेजेंगे। मैं इस बात को लम्बी नहीं कहूंगा लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए आज भारत सरकार के चार मंत्री पड़ौसी मुल्क के अन्दर डेरा जमाये हुए हैं।

मंत्री महोदय, आपने ठीक कहा। मैं भी वह आंकड़ा देख रहा था। राजस्थान के 1008 विद्यार्थी हैं और आपने कहा 207 विद्यार्थी राजस्थान के अन्दर वापस लौट आये। आप इन बच्चों पर अपने बच्चे का चेहरा लगाकर देखो। अगर मेरा बच्चा, आपका बच्चा होता तो रात को नींद नहीं आती। हम सबको समग्र चिन्ता करनी है, आलोचना, समालोचना की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपकी सदारत में हम सब लोग एक हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी, वह 22 तारीख को एक्टिव हुए। उन्होंने 22 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम से बात की बच्चों से, 27 तारीख को गवर्नमेंट आफ इण्डिया से बात की। धीरज श्रीवास्तव को नोडल आफिसर बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पत्रिका के संवाददाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने देखा होगा फोटो सहित बच्चों से बात करता हुआ वह संवाददाता, कितना सुकून मिला। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक बच्चा था, उसके अभिभावकों ने टेलीफोन किया कि मेरे बेटे की फोटो खींची है तो मेरा बेटा वहां सुरक्षित है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कल आपका चेहरा देख रहा था, जब आप विधान सभा से बच्चों से वी.सी. से बात कर रहे थे। मैं उप-सचेतक महोदय, आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हम सब लोगों ने यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हैं, उन बच्चों से अपना बच्चा समझकर बात की और मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो तीन यूनिवर्सिटी हैं- कीव यूनिवर्सिटी, इवानो फ्रेंकिव्स्क यूनिवर्सिटी, टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में अपने जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा एक निवेदन है, मैं बात को लम्बी नहीं कहूंगा।

अभी बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात और महाराष्ट्र, दोनों के ग्रुप आफ मिनिस्टर्स दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली में लगातार वह भारतीय दूतावास से विदेश मंत्रालय से सम्पर्क में हैं। वह ग्रुप आफ मिनिस्टर्स कोई न कोई एक-एक बच्चों से बात करें, इसका बन्दोबस्त कर रहे हैं। हम यहां से नहीं, आप सरकार को कहें कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स आपको जरूरत पड़े, इधर हमारे यहां से किसी को इशारा कर देना, हम आपके साथ, आपके असिस्टेंट के रूप में, आपका नेतृत्व करने नहीं, भारत सरकार है। भारत सरकार में हमारे प्रतिपक्ष के नेता को भी कह सकते हैं वह, हम सब मिलकर कोशिश करें, इसलिए आप एक ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बनाकर दिल्ली में जायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा यह कहना चाहता हूं कि वे बच्चे, जो वहां पढ़ रहे थे, वापस आने की स्थिति में नहीं हैं। वे बच्चे चाहे मेडिकल के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों, उन बच्चों को यहां पढ़ने के लिये अपने यहां मेडिकल और इंजीनियरिंग में स्पेशल सीट क्रिएट करवाएं। वह बच्चा गरीब का बच्चा है, वह लुट गया इसलिए स्पेशल पैकेज उनको दो फाइनेंस का, वह वापस नहीं जाएगा। इसलिए यह सारी व्यवस्था करें और अन्त में, मैं यह कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति बैठा है, हम चाहते हैं, समग्र रूप से यह बात जाये कि राजस्थान का यह सर्वोच्च सदन आज सारी चीजों को छोड़कर, वे बच्चे सकुशल आयें, इस पर चिन्तित हैं और मैं फिर कह रहा हूं, प्रतिपक्ष के नेताजी हमारे विधायक दल से बात की है, हम सब लोग आपके साथ कदम-से-कदम मिलाकर, जो आप चाहते हो, भारत सरकार से बात करनी हो, वहां हम जाने को तैयार हैं। आप और कोई हैल्प हमसे लेना चाहें, उसके लिये तैयार हैं और सब लोग मिलकर चिन्ता करें। मुझे इतना ही निवेदन करना था। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपका इस बात के लिये बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने एक ऐसे संवेदनशील विषय पर, जिससे सम्पूर्ण राजस्थान और देश अपने नागरिकों और बच्चों को सुरक्षित लाने के लिये चिन्तित है। मैं सोचता हूं कि कई बार हम अपने दिमाग में जयपुर अलग है और दिल्ली अलग है, इस पुट में जब बात बोलते हैं तो मन को बहुत ही दुःख होता है। यह समस्या न राजस्थान की है, न दिल्ली की, बल्कि हम सबकी है। ये बच्चे किसी के भी हो सकते हैं। हमारे भारत के नागरिकों को लाने का दायित्व हम सब लोगों का सामूहिक रूप से है। एक तो यह दिमाग में जो एक डण्डा लगाकर कि यह मैंने किया, यह मैंने किया, इसके बनिस्पत हम सबने किया, अगर इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं सोचता हूं इसमें और ज्यादा अपन सफल होंगे।

यूक्रेन के बारे में जो समस्या थी, वह पहली एडवाइजरी 15 फरवरी को केन्द्र सरकार ने जारी कर दी और कहा कि आप तुरन्त लौट आओ। मैं सोचता हूं उसके बाद तो 24 फरवरी से तो युद्ध ही शुरू हो गया और उसकी पोजीशन कुछ अलग प्रकार से हो गयी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार ने इसके बारे में कोई चिन्ता नहीं की, क्योंकि आपके मंत्रीजी का भाषण सुनकर लगा कि दिल्ली और दिल्ली सरकार का कहीं नाम भी नहीं लेना, यह हमारे मन की कमजोरी लगती है। मैं सोचता हूं कि ऐसे विषय पर कभी भी न तो पार्टी लाइन आनी चाहिए, न सरकारी लाइन आनी चाहिए। यह हम सब मिलकर एक काम करते हैं, इस बारे में हमको विचार करना चाहिए।

मेरा आपसे आग्रह है कि हमको भी राजस्थान की कोई टीम दिल्ली में बिठानी चाहिए, जो इन सब बच्चों को यहां से भी जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उससे कांटेक्ट में रहें, उन बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहें। हम सब लोग भी आपस में बातचीत कर सकें तो मैं सोचता हूं 10 बच्चों से बातचीत करने से भी सैंकड़ों बच्चों के पेरेंट्स को मैसेज पहुंचेगा कि राजस्थान के फलां-फलां जिम्मेदार व्यक्ति ने मेरे सुख-दुःख के बारे में मुझसे बात की, तो मैं सोचता हूं बहुत अच्छा रहेगा।

वैसे केन्द्र सरकार ने चार मंत्रियों को पहले से ही वहां भेज रखा है। आपने देखा होगा रोमानिया, पौलेण्ड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में हमारे मंत्री वहां हैं। सिंहजी वहां हैं, पुरी जी वहां हैं, उनको पहले से ही केन्द्र सरकार ने वहां डेप्युट कर दिया लेकिन जो बच्चे निकलकर बोर्डर तक आ गये, उनको तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फिर भी हमारी जो फ्लाइट अभी आ रही है, आपरेशन गंगा जो शुरू हुआ, उसमें बच्चों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सेना के भी हमारे कई प्लेन बहुत सारे बच्चों को सुरक्षित निकालकर ला रहे हैं। मैं सोचता हूं कि एक हजार किलोमीटर की लम्बी जगह पार करके बोर्डर तक पहुंचना कई बार उनको बहुत बड़ा संकट दे रहा है। इसके बारे में जो कुछ भी व्यवस्था केन्द्र सरकार और हम मिलकर, हमारे लोग भी वहां हैं, हममें से कई लोगों का कांटेक्ट भी हुआ है। मैं सोचता हूं, अभी 18 फरवरी के दिन केन्द्र के विदेश मंत्रीजी ने जो पूरी सूची जारी की है, उसमें वह सारे कांटेक्ट नम्बर दिये हैं कि अगर हंगरी में कांटेक्ट करना हो तो हमारा कांटेक्ट नम्बर क्या है, कौन उसको फोलो-अप करेगा? रोमानिया का कौन करेगा, पौलेण्ड का कौन करेगा, चेकोस्लोवाकिया का कौन करेगा? इसमें सबके नम्बर दे रखे हैं, यह मैं टेबल पर रख दूंगा। यह उन्होंने सारी व्यवस्था की है। सारे फोन नम्बर कि कौन कहां-कहां उपलब्ध हैं और उन्होंने गाइड लाइन में यह भी कहा। फिर भी अगर आप हमारे साथ कोई विशेष जानकारी साझा करना चाहें तो कृपया नीचे दिये गये विवरण के अनुसार सीधे मेरे कार्यालय से सम्पर्क करें। इन्होंने लिखा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हर पूछताछ और सूचना का संज्ञान ले रहे हैं। सभी पूछताछ के बारे में सम्बन्धित स्थान पर उपस्थित विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। फिर भी आपको कहीं लगता है कि कहीं कोई कमी-खामी है, तो भी हम उनको कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार अपनी-अपनी बाउण्ड्री में हैं, ऐसा है कि जो काम केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि वहां जाकर ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह पत्र विदेश मंत्री का है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, यह विदेश मंत्री का पत्र है, जिसमें उन्होंने सारे कांटेक्ट नम्बर दिये हैं। अभी एक-एक का नम्बर बताने की जरूरत नहीं है। मैं हाउस में टेबल पर रख दूंगा ताकि इसकी कापी हम सब लोग लेकर और निश्चित रूप से इन पर भी सम्पर्क करने की कोशिश करें तो हम इस दिये नम्बर पर सम्पर्क कर सकेंगे। मैं सोचता हूं कि हमारे एक हजार बच्चे हैं या जनता है, सबको ही लाना इस समय आवश्यक हो गया। अब आज की तारीख में वह वहां रहने की मानसिकता में नहीं हैं, न ही वहां रह सकते हैं। अब कौन कैसे आये, केवल एक ही जगह जो परेशानी आ रही है, वह सबसे ज्यादा, क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा दबाव है, वह राजधानी कीव पर है और वहां जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है और हमारे बच्चे जो खारकीव, जो स्थान है, वहां पर भी हमारे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने गये हैं। सुमी में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिये गये हुए हैं। उन बच्चों को निकालने के लिये भारत ने रूस के दूतावास से सम्पर्क करके हमारा आदमी वहां बिठा रखा है, जो रूस की बोर्डर है, वह 100 किलोमीटर पर ही है, उस बोर्डर से भी हमारे बच्चों को निकालकर लाया जा सके, उन्होंने रूस सरकार से भी इस बारे में बात करके व्यवस्था कर रखी है। हमारे व्यक्ति वहां मौजूद हैं। हमें भी किसी के बारे में कुछ जानकारी मिले तो विदेश मंत्रालय से कांटेक्ट करके उन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन बतायें, कहां हैं, क्या है, वह हर प्रकार से मदद करेंगे।

मैं सोचता हूं इस संवेदनशील विषय पर पक्ष-विपक्ष नहीं है, पार्टी नहीं है, यहां हम सब लोग एक हैं और भारत के हर नागरिक को, जिसमें राजस्थान के नागरिक भी हैं, उनको सुरक्षित बचा लाने के लिये हम सब लोग, जहां-जहां, जिस प्रकार से भी उसके परिवार को मदद करने की स्थिति में हमें उस व्यवहार से करना चाहिए और मैं सोचता हूं, आपने जिस मंच से इस चर्चा को रखा है, उसका यही है कि उन सब माता-पिता को, उन परिवारों को यह संदेश जाये कि हमारे पीड़ा के साथ, राजस्थान के सारे के सारे जन-प्रतिनिधि भी एक राय होकर हमारे बच्चों को सुरक्षित यहां लाने के प्रयत्न में अपनी भागीदारी पूरे मन से निभा रहे हैं, तो मैं सोचता हूं हम स्वयं भी संतुष्ट होंगे और राजस्थान की जनता को भी संतुष्ट कर पाएंगे कि हम सब लोग मिलकर इस संकट के समय में अपने बच्चों और नागरिकों की मदद कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जो भावना व्यक्त की है, उस भावना में, मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं। व्यक्तिगत तौर पर हम स्वयं, राजस्थान सरकार और भारत सरकार, सभी इस मामले में चिन्तित हैं और प्रयत्न कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह युद्ध समाप्त होगा और हमारे जो बच्चे वहां पर पढ़ने के लिये गये, वे बच्चे हमारे देश में आएंगे। मैं आपकी भावना को माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराएंगे और मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर राजस्थान के सभी अभिभावकों को यह विश्वास दिला सकेंगे कि राजस्थान के बच्चों को सुरक्षित लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार मैं पुन: आप सबकी भावना से राजस्थान के सभी अभिभावकों से इस महा सदन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि पूरा सदन एक है सब चिन्तित हैं और सबके बच्चे अपने बच्चे हैं और हम आशा करते हैं कि वह सब बच्चे राजस्थान में आएं, ऐसी मैं आप सबकी भावनाओं को राजस्थान सरकार को अवगत कराऊंगा।

चर्चा समाप्त हुई। श्री सुदर्शन रावत।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान के जन नायक मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने 2 साल के इस कठिन दौर में भी इतना शानदार बजट दिया, विशेष तौर से कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए पिछले 70 सालों के वन आफ दी बेस्ट बजट दिया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। 121 पेज का यह बजट, 3 घंटे का लम्बा भाषण था लेकिन राजस्थान की सरकार का एक कमिटमेंट था। यह भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी का विजन दर्शाता है। उनका अनुभव इस भाषण के अन्दर था। इस बजट को बनाने में जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी का पोलिटिकल एक्सपीरियंस काम आया, 13 साल तक मुख्य मंत्री के तौर पर जो उनका अनुभव था, वह इस बजट में दिखाई दे रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। चाहे युवाओं की बात है, चाहे महिलाओं की बात है, चाहे रोजगार की बात है, ग्रामीण हो या शहरी हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम चीजों को इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने शामिल किया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस कारण भी धन्यवाद दूंगा कि इस बार कृषि बजट का एक नवाचार राजस्थान में शुरू किया गया। जहां दिल्ली में केन्द्रीय सरकार रेलवे बजट को केन्द्रीय बजट में मर्ज कर रही है, यहां किसानों को सम्मान देने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने अलग से एक कृषि बजट पेश किया है। उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

इस पूरे बजट में प्रमुख तौर पर जो योजनाएं माननीय मुख्य मंत्री जी ने लागू की हैं उनमें चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया। सभी के मुफ्त इलाज की बात की है। बिजली के बारे में भी हमारे विपक्ष के साथी अक्सर कहते रहते थे कि रेट्स ज्यादा हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबकी भावनाओं को, जन भावनाओं को मानते हुए इसको सब्सिडाइज्ड

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

किया है। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख रुपये तक नि:शुल्क की गयी है। एक लाख अतिरिक्त नौकरियां जारी की गयी हैं। दिव्यांग स्कूटी 2 हजार से बढ़ाकर 5 हजार की गयी हैं। एससी, एसटी विकास कोष में भी 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। दिल्ली में 250 करोड़ रुपये की लागत से एक यूथ हॉस्टल माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तावित किया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उदयपुर और कोटा को भी प्राधिकरण बनाने की इसमें घोषणा की है। तमाम घोषणाओं के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी का एक कमिटमेंट दर्शाता है कि कैसे राजस्थान को आगे लेकर जाना है। आने वाले समय में किस तरह से राजस्थान में विकास करना है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम, देवगढ़ के लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने भीम में बहुप्रतीक्षित कन्या महाविद्यालय की इसमें घोषणा की है। बर में एक उप तहसील की घोषणा की है, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। ताल्लसानी से होते हुए 40 मील तक की एक सड़क माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी है, उसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

इस बजट में सबसे अच्छी बात यह रही कि हमारे विपक्ष के साथियों के पास बोलने को कुछ नहीं रहा। मैंने अख़बार में अगले दिन देखा, सारे समाचार-पत्रों में ज्यादातर बयान जो प्रतिपक्ष के थे, उनके अन्दर दम नहीं था। राजनीति आधारित बजट कहा। किसी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास जनता को देने के लिये कुछ नहीं है। किसी ने कहा कि चुनावी रंग में रंगा हुआ बजट है। कुल मिलाकर विपक्ष के पास कहने के लिये कुछ बात नहीं थी। माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट इतना दमदार रहा कि इस कोरोना की परिस्थिति में उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतना शानदार बजट आयेगा। इस बजट ने विपक्ष को भी चारों खाने चित कर दिया।

मैं, हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता राजेन्द्र जी राठौड़ का अक्सर भाषण देखा करता हूं। आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं। ज्ञानवान हैं और सारी तैयारी करके आते हैं, लेकिन इस बार आपकी स्पीच में दम नहीं था। अब की बार आपकी स्पीच इसलिए दमदार नहीं थी क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट दमदार था। अन्दरखाने आप भी यह बात समझ रहे थे कि इतना शानदार बजट मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है तो इसकी गलती कहां से

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

निकालें। तमाम विपक्ष के साथी इस बात के लिये बजट के चारों तरफ घूमते दिखायी दिये कि इस बजट के अन्दर घुसे कहां से, कमी निकालें कहां से। मुख्य मंत्री जी ने इतना शानदार बजट पेश किया कि आप सब लोगों को कोई पाइण्ट नहीं मिला।

मैं, आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको यही उम्मीद है कि बजट लागू नहीं होगा। अगर बजट लागू नहीं करना होता तो आखिरी साल में बजट घोषणा करने की परम्परा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में भी लागू करने की मंशा से ही बजट की घोषणाएं की थीं। इस बजट में भी यही मंशा रही है। 2021-22 का बजट जहां तक मेरी जानकारी है, 70-80 प्रतिशत तक लागू हो चुका है। हम सब बजट में अपनी विधान सभा क्षेत्र की घोषणाओं को इसको जानते हैं। उसी तरह मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022-23 का बजट भी पूरा लागू होगा।

जहां तक बजट लागू होने की बात है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये 1,032 करोड़ रुपये की चम्बल की घोषणा की थी। एफएस जारी हो गयी, टीएस जारी हो गयी और आज टेण्डर अण्डर प्रोसेस है। बर में थाना खोलने की बात की थी। थाना स्टार्ट हो गया। भीम में साइंस सब्जेक्ट कालेज में दिया था। कालेज में साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट है और आज 160 बच्चे अध्ययनरत हैं। दिवेर में उप तहसील के लिये कहा था। जमीन अलाट हो गयी। स्वीकृति जारी हो गयी। भीम में आईटीआई बोला था। जमीन अलाट हो गयी। एफएस इश्युड हो गयी और अब पीडब्ल्यूडी के द्वारा काम चालू किया जाना है। मिसिंग लिंक्स में जो 5 करोड़ की सड़कों की बात हुई थी, वह मेरे ख्याल से तमाम सदन के सदस्यों के यहां चालू हो चुकी हैं।

(समय: 16.40 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, यह बजट लागू करना माननीय मुख्य मंत्री जी का पहला प्रोरोगेटिव है। यह किसी भी सूरत में पूरा लागू होगा। हमारे विपक्ष के साथी यही सोच रहे हैं कि बजट लागू नहीं होगा और उसकी हमें आलोचना करने को मिलेगी, लेकिन मुख्य मंत्री की जो इच्छा है, उसके लिए कमिटमेंट के साथ हम कह सकते हैं कि 2023 में इस बजट को लागू करेंगे और राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से, माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में दुबारा राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार बनायेंगे।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

मानमनीय मुख्य मंत्री के साथ हम इसलिए भी हैं कि इस बजट में हर विधान सभा क्षेत्र के लिये कुछ न कुछ घोषणा हुई है। यह बजट पूरी तरह से निर्वाचन क्षेत्र स्पेसिफिक नहीं होकर, पैन राजस्थान के लिये इस बजट में कुछ न कुछ बोला गया है। आप देखें कि पूरे राजस्थान के लिये इस बजट में घोषणाएं हुई हैं। मेरे हिसाब से इस बजट में किसी भी विधान सभा क्षेत्र को बाकी नहीं रखा है। 10 करोड़ की मिसिंग लिंक्स सड़कें सारे विधान सभा क्षेत्रों में लागू होंगी। 3,820 सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स सैकण्डरी से बनेंगी। यह भी तमाम विधान सभा क्षेत्रों में लागू होंगी। 2 हजार इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यह भी तमाम विधान सभा क्षेत्रों में होंगी। तकरीबन 2,350 बालिका विद्यालय क्रमोन्नत होंगे। यह भी सभी विधान सभा क्षेत्रों में लागू होंगी। कुल मिलाकर बजट पूरे राजस्थान के आम-अवाम को दिमाग में रखकर बनाया गया है।

जहां तक बजट इम्प्लीमेंटेशन की बात है, हम तो निश्चित रूप से करना चाहते हैं। जैसा मैंने मेरे इलाके का बजट इम्प्लीमेंटेशन बताया, पूरे राजस्थान का बजट बताया। पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आखिरी बजट आया था, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित एक मांग देवगढ़ के अंदर आईटीआई खोलने की आयी थी। 2018 के बजट में दिया। आईटीआई वालों ने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन किसी तरह की कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई। आज आईटीआई कहीं पर बनी हुई नहीं है।

जहां तक राजसमन्द जिले की बात है, मुख्य तौर पर जल योजना की बात आती है। पिछले बजटों में, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 2018-19 में 450 करोड़ की योजना की बात की गयी। इसमें कुछ नहीं हुआ। उसके पहले 2016-17 में देवास योजना के अन्दर 1,064 करोड़ की लागत से राजसमन्द जिले के लिये पानी लाने की बात की गयी थी। उसके लिये न तो एएस जारी हुई, न टीएस जारी हुई, न एफएस जारी हुई। किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। पूरी तरह से बजट भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आप लोगों ने लागू नहीं किया। इस कारण आपको लगता है कि यह बजट लागू नहीं होगा।

मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अध्यक्ष जी के कहने पर, आप और हम सब लोगों ने पिछली बार अनुरोध किया था, एमएलए लैड को 5 करोड़ करने की मांग रखी थी, उसी सदन के अन्दर, फ्लोर आफ दी हाउस माननीय मुख्य मंत्री जी ने आप और हमारे

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

सबके कहने से एमएलए लैड को बढ़ाकर के 5 करोड़ रुपये किया। गांधीवादी मुख्य मंत्री ही इस तरह की बात कर सकता है। अशोक गहलोत जैसे मुख्य मंत्री ही इस तरह की बात कर सकते थे कि फ्लोर आफ दी हाउस यह घोषणा हुई।

दूसरी तरफ, दिल्ली की सरकार ने, केन्द्र सरकार ने कोरोना के समय एमपी लैड पर रोक लगायी। आज एमपी लैड से किसी तरह के काम नहीं हो पाये। हम देख रहे हैं कि एमपीज का काम इलाके में पूरी तरह से अटका हुआ है।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने मिसिंग लिंक्स सड़कें तो दे दीं, लेकिन जो एमपीज राजस्थान में मिसिंग हैं, उनको ढूंढने के लिये कोई न कोई योजना बनानी पड़ेगी। सारे एमपीज लापता हैं, नदारद हैं। किसी तरह के काम करने की उनकी कोई मंशा नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले 8 सालों से दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार है, उसमें 4-5 मंत्री आज की तारीख में हैं। पिछले शासन में भी 4 मंत्री रहे। 8-8, 9-9 मंत्री होने के बावजूद इन 8 सालों में राजस्थान को कुछ विशेष नहीं मिला। वहीं अगर पिछले 10 सालों के कांग्रेस राज की बात करें तो चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे एम्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे डीएफसीसी हो, चाहे ट्रेन्स हों, चाहे मेमो कोच हों, तमाम घोषणाएं हमारी सरकार के समय हुईं। आज इस पूरे इलाके में कोई भी काम करना है तो हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आज दिल्ली में पार्लियामेंट में हमारे 25-25 एमपी बैठे हैं, किसी तरह की कोई मांग राजस्थान की नहीं उठायी जाती। राजस्थान की किसी मेजर मांग के बारे में वहां दिल्ली में कोई बात नहीं की जाती। वो एक तरह से दिल्ली का जो तानाशाही शासन है उससे डर कर चुपचाप बैठे हैं, न तो अपनी आम-ओ-अवाम की आवाज पहुंचा रहे हैं न अपनी जनता की आवाज दिल्ली की सरकार तक पहुंचा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मनरेगा के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। मनरेगा के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय की जो सोच रही, उसके अन्दर जो 100 दिनों की योजना थी उन्होंने उसको 125 दिन करने की मंशा जतायी। इससे राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मदद मिलेगी। 750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

इसके लिए की गयी है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसको बड़ा दिल रखते हुए इसको किया है जबकि दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार, जब से प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में बनी है, 2014 से ही इस मनरेगा को बार-बार कोस रही है। हमेशा माननीय प्रधान मंत्रीजी कहते रहते हैं कि यह कांग्रेस की योजना है, इसका क्या करें। आज दिल्ली की सरकार ने इसके साथ अपनी मंशा जतायी है, 98 हजार करोड़ रुपये का बजट था पिछले साल, जिसको घटाकर 73 हजार करोड़ रुपये कर दिया, 25 परसेंट की इसमें कटौती की है। इसके अलावा 12 हजार करोड़ के करीब अभी पुराना ड्यूज बाकी है जिसमें मैटेरियल कम्पोनेंट का भी है, मैट और लैब का भी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब ये घटायेंगे तो कुल मिलाकर 60 हजार करोड़ रुपया बाकी रह जायेगा और उससे लोग मनरेगा का विकास करना चाहेंगे देश के अन्दर, किस तरह से होगा जहां लाख, डेढ़ लाख करोड़ रुपये का बजट कैप होना चाहिए था, उसकी बजाय 60 हजार करोड़ रुपये के इस बजट कैप से किस तरह से काम होगा, यह आपके सामने है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मनरेगा जो रोजगार गारंटी योजना थी, वो आप्शनल योजना बन जाये और लोगों को इसके कारण गांवों में तकलीफें नहीं उठानी पड़े।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शहरी रोजगार को दृष्टिगत रखते हुए 100 दिनों की एक योजना दी है जिसमें 800 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। देश में चार-पांच दूसरे राज्यों में भी ये योजना चल रही है परन्तु उन सब राज्यों में 100-150 करोड़ रुपयों से ज्यादा का बजट नहीं है। राजस्थान की सरकार ने इसमें 800 करोड़ रुपये का बजट रखा है। पिछले सात-आठ सालों में केन्द्र की सरकार ने कभी भी इस मनरेगा के बजट को नहीं बढ़ाया, घटाने की बात तो हुई है इस साल लेकिन या तो बराबर रखा है या एक-दो परसेंट ऊपर नीचे रखा। पिछले चार-पांच महीने से तो पूरा राजस्थान परेशान है, हमारा जो मैट कम्पोनेंट है, कारीगर कम्पोनेंट है वह मैटेरियल कम्पोनेंट के साथ अटैच किया हुआ है, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। चार-पांच महीने से राजस्थान के हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि ये पेमेंट हो।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जब इस मनरेगा के डेटा को देखा तो इसमें पाया कि 2017 में भी यह तकरीबन-तकरीबन साल में आठ दस बार इसमें पेमेंट हुआ। 2018 में भी इतना ही हुआ, 2019 में भी इतना ही पेमेंट

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

हुआ, 2020-21 में थोड़ा कम और 2021-22 में हद हो गयी है, पूरे साल में सिर्फ तीन मर्तबा पेमेंट हो रहा है। आज दिनांक तक तीन बार पेमेंट हुआ। किस तरीके से हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सर्वाइव करेगी जब इस तरह से पेमेंट होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे एमपीज को दिशा की मीटिंग के लिए जिलों में प्रधान मंत्रीजी ने भेजा है। दिशा की मीटिंग में जाते हैं हमारे तमाम एमपीज साहिबान और दिशा की मीटिंग में किसकी समीक्षा होती है, राजस्थान सरकार की योजनाओं की, चलो उन योजनाओं की समीक्षा आप करो लेकिन जब आप समीक्षा करते हो तो सेंटर की स्कीम्स के बारे में आपको पता नहीं लगता कि मनरेगा का पेमेंट नहीं हो रहा है? क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी की पूरी मंशा के बावजूद हमारे सभी तमाम एमपीज अगर जाकर बोलें इस बात को तो निश्चित तौर पर यह डिले नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक भर्तियों की बात है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक लाख भर्तियों का ऐलान किया है और करीब सवा लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। अनएम्प्लायमेंट के बारे में क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, दिल्ली की सरकार का अनएम्प्लायमेंट को लेकर बिलकुल भी फोकस नहीं है। आज की तारीख में देश की अनएम्प्लायमेंट रेट 8 परसेंट है, जिसको सुधारने की जरूरत है। तीन ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करने वाले प्रधान मंत्री जब तक इन युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, जब तक इन युवाओं के लिए रोजगार नहीं होगा तब तक तीन ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी?

माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसे इलाके से आता हूं जहां पर फौज में सभी लोग जाते हैं। 10 हजार फौजी फैमिलीज का हमारा विधान सभा क्षेत्र भीम-देवगढ़ है। तमाम नौजवानों की इच्छा है कि वो फौज में जायें लेकिन पिछले डेढ़-दो साल से जिस तरह से कोरोना के नाम पर सेना की भर्ती रोकी हुई है, ये भी बहुत दुखद है। इसके लिए भी माननीय प्रधान मंत्रीजी को, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पत्र लिखा और उसमें दो वर्ष की छूट देने के लिए भी कहा है। जैसे 2015-16 में 127 भर्तियां हुई और ये घटती-घटती 92 हो गयीं 2019-20 में, इन भर्तियों को वापस चालू किया जाये क्योंकि कोरोना के नाम पर आप इन भर्तियों को तो रोक रहे हो लेकिन चुनाव कराये जा रहे हो। देश का नौजवान समझता है और यूपी के चुनाव में इसके लिए सबक सिखा

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

देगा कि किस तरह से आप भर्तियों को रोककर आप चुनाव में जाना चाहते हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार में तकरीबन पौने नौ लाख वैकेंसीज पेंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में, उनमें से साठ-सत्तर हजार की वैकेंसीज निकाली है लेकिन आठ लाख वैकेंसीज अभी भी पेंडिंग है। दो करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करने वाली केन्द्र की सरकार अब पूरे तरीके से इस मामले में फेल हो चुकी है और इस बार साठ लाख नौकरियों का कहा है, वो ऑर्गनाइज्ड या अनआर्गनाइज्ड, किस सेक्टर में है, इसको आपको क्लीयर करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष और सब हम यूक्रेन के मामले में बात कर रहे थे। युवाओं से सम्बन्धित मामला है, हम सब इस बात के लिए एकजुट हैं कि इस मामले में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है पर जिस तरह से अमेरिका की एम्बेसी ने दिसम्बर के एंड में, जनवरी के फर्स्ट वीक में एडवाइजरी जारी की, डिप्लोमैटिक तौर पर अगर हम भी 15 फरवरी के पहले एडवाइजरी जारी करते तो शायद इसमें हम लोगों को जल्दी ला सकते थे, उसमें हम लोग कामयाब होते।

माननीय सभापति महोदय, पेंशन के लिए जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने योजना दी है, उससे पूरे राजस्थान के कर्मचारी खुश हैं लेकिन पेंशन की टेंशन हमारे विपक्ष के साथियों को है, क्योंकि ये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उनकी बहुत पुरानी लम्बित मांग को पूरा किया है। 2004 से वापस जो कर्मचारी उसके बाद लगे हैं उनको सबको पेंशन देने की जो मंशा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने रखी है वह पूरे देश में एक मॉडल बन गया है।

माननीय सभापति महोदय, वेतन कटौती को लेकर भी मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार में वेतन कटौती की गयी, इस सरकार ने उसको बहाल किया है। 20 प्रतिशत मानदेय भी बढ़ाया है हमारे संविदाकर्मियों का। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी तक यह संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि हमारे जो संविदाकर्मी हैं उनके बारे में भी हमारी सरकार निर्णय करे और उनको भी किसी न किसी तरह से नियमितीकरण करने का सरकार फैसला ले।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन में भी केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार में राजस्थान से जल शक्ति मंत्री हैं पर राजस्थान को कोई प्रिफरेंस नहीं है, वो राजस्थान को रिप्रजेंट जरूर करते हैं लेकिन राजस्थान के लिए करते कुछ नहीं हैं। दिल्ली में जाकर मंत्री बनते हैं राजस्थान के कोटे से पर राजस्थान के लिए कुछ नहीं करते हैं। आज राजस्थान सबसे बड़ा भू भाग है, रेगिस्तानी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है, उसके बावजूद राजस्थान के आदमी के लिए जल शक्ति मंत्रालय से कुछ नहीं किया गया है। मैं मांग करना चाहूंगा कि तमाम एमपी जो वहां चुप बैठे हैं वो वहां आवाज उठायें बात उठाये और राजस्थान का रेशो 90:10 कराया जाये। जब पीएमजीएसवाई में हम 60:40 पर काम कर सकते हैं, मनरेगा में हम 75:25 पर काम कर सकते हैं, पीएम आवास में 60:40 पर काम कर सकते हैं तो क्यों आप जल जीवन मिशन में 50-50 करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि 40 लाख करोड़ रुपये का दिल्ली की सरकार का बजट है और 3 लाख करोड़ रुपये का राजस्थान की सरकार का बजट और 50:50 की बात और चाहते हो कि 2024 तक हम किसी भी सूरत में इस जल जीवन मिशन को लागू करें, यह सम्भव नहीं है। इन कागजी बातों से ऊपर उठकर हम किसी भी सूरत में प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत कुछ दिया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं परन्तु कुछ मांगें ऐसी हैं जो 15 सालों के शासन काल में नहीं होने के कारण मैं उठाना चाहूंगा।

देवगढ़ और भीम में एक एडीजे कोर्ट दोनों जगहों में से किसी एक जगह खोला जाये क्योंकि हमारे 100 किलोमीटर से अधिक दूर राजसमन्द एडीजे कोर्ट है। 50 बैड का एमसीएच विंग भी खोला जाये। जिला सैनिक कार्यालय अभी उदयपुर में है, उसको राजसमन्द में खोला जाये। देवगढ़ में साइन्स सब्जेक्ट की व्यवस्था की जाये। सभी सदस्यों की मांग के अनुसार पीएचसी और सीएचसी की संख्या बढायें, साइंस सब्जेक्ट की व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, दो लाइन कहकर अपनी बात पूरी करूंगा,

पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है,

पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है,

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग,
पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है।

धन्यवाद, जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया गया।

श्री गोविन्द प्रसाद (अनुपस्थित)। श्री शंकर सिंह रावत।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने बजट भाषण 2022-23 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट भाषण किया है, इसमें इस प्रकार की घोषणाएं हुई हैं, मैं सोचता हूं, ये अगर पूरी हो जाएं तो राजस्थान का काया-कल्प हो जायेगा, लेकिन ये घोषणाएं घोषणाएं ही रह जाती हैं। अभी तो इनके 2019 के घोषणा पत्र में नये जिले बनाने का जो लिखा गया है, मैं समझता हूं, राजस्थान में एक भी जिले का आजादी के बाद कांग्रेस ने मुहूर्त नहीं किया है। मेरी मांग रहेगी कि कहीं न कहीं खाता खोलकर एकाध जिला बनाने की कोई घोषणा करें। आपके सदस्य नंगे पांव चल रहे हैं। उन्हें तो जूता पहनाने का कार्य कर दें। हमारे ब्यावर का नम्बर न आये तो कोई बात नहीं। दूसरों का तो आ जाये। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस के कोई सदस्य यदि जूते खोलकर विधान सभा में आ रहे हैं, उनके कहीं कांटे लग जायेंगे। आपके घोषणा पत्र में जो है, आप उसकी क्रियान्विति करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है।

(श्री शंकर सिंह रावत)

आपने सड़कों के बजट के लिये बात कही है। बजट में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, उनमें ब्यावर ने ऐसा कौन-सा गुनाह किया है कि एक भी सड़क की घोषणा ब्यावर में नहीं की गयी? जिस प्रकार विधायक कोटे से हर विधायक को पांच करोड़ की सड़कों का प्रावधान हुआ है, उसमें भी अभी शुरू हो रही हैं। सालभर हो गया। एक भी सड़क कहीं बनी नहीं है। अब बनना चालू हुई हैं। अब उनके टेंडर हो रहे हैं। अभी जो दस करोड़ की हुई वह कब हो जायेगी? उसका उद्‌घाटन शायद माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के आने के बाद में ही हो पायेगा, ऐसा लग रहा है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार पांच से दस करोड़ की घोषणा हुई है, उसमें भी तीन करोड़ ही मिसिंग सड़कों के लिये दिये गये हैं। मेरा सुझाव है कि दस करोड़ को ही मिसिंग सड़कों में दिया जाये तो कम से कम उस क्षेत्र में कुछ काम होगा। जिस प्रकार ब्यावर शहर है, उसमें आस-पास के एरिया में काफी बस्तियां बस चुकी हैं और कालोनियां कट चुकी हैं, उन कालोनियों में सारी कच्ची सड़कें हैं। आप अगर सबको मिसिंग सड़कें देंगे तो वहां भी कम से कम कच्ची से पक्की सड़कें मिल जायेंगी, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

वन क्षेत्र में सरूपा गांव को आजादी के बाद आज तक न तो सड़क मिली है और न बिजली मिली है। 150 वर्षों से बसा हुआ यह गांव है। इससे उनके सम्बन्ध भी नहीं हो पाते हैं कि इतनी दूर अपनी बच्चियों को कौन दे। मेरा अनुरोध है कि वहां बिजली के लिये कहीं न कहीं व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिये।

जिस प्रकार एक सड़क की घोषणा हुई है पूरे बजट में, तीन साल में ब्यावर के लिये एक भी चीज की किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई, इस बार जो घोषणा हुई है, वह कन्या महाविद्‌यालय की हुई है, मैं उसके लिये धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, बजट के पेज नं. 30 पर ब्यावर-रामगढ़-विजयनगर-गुलाबपुरा सड़क (मसूदा), यह 7 किलोमीटर सड़क ब्यावर एरिया में पड़ती है। आपने बैन लगा दिया है, सात किलोमीटर की वह सड़क नहीं बनेगी, क्योंकि वह ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में है। लोग उपदेश दे रहे हैं या लचीले भाषण देकर सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी है, किसी पर हम भाजपा-कांग्रेस का ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं, मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सड़क पर सिर्फ मसूदा का एरिया

(श्री शंकर सिंह रावत)

ही पक्का होगा, ब्यावर का नहीं होगा। ऐसा पाप का काम किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया होगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मेरा माननीय सभापति महोदय से निवेदन है कि जब माननीय मुख्य मंत्री अपना रिप्लाई दें तो उसमें थोड़ा क्लीयर करें। ब्यावर को जिला बनाने के लिये जो घोषणा पत्र में इन्होंने दिया है, मैं समझता हूं, गांधीवादी सरकार का कोई वचन, वैसे मुख्य मंत्री जी जो कहते हैं, वह करते हैं। सबने कहा है तो मैं भी पूरी आस लगाकर समझता हूं कि इनके बजट घोषणा पत्र में ब्यावर को नया जिला बनाने का लिखा है तो ब्यावर का भी नम्बर आयेगा।

सभापति महोदय, डीएमएफटी योजना में जो बजट आबंटित होता है, अजमेर की मैं बात करता हूं, वहां पिछले तीन साल का डीएमएफटी का बजट सिर्फ एक विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में गया है 44.11 करोड़ और ब्यावर में एक रुपये का भी बजट नहीं। यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसे काफी माननीय सदस्य आये हैं, जिन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है कि डीएमएफटी के द्वारा कलेक्टर अपनी मर्जी से जिसे चाहें, उसे दे रहे हैं और बाकी को नहीं दे रहे हैं। यह बन्दरबांट बन्द होनी चाहिये, ऐसा मेरा निवेदन है।

बीसलपुर प्रोजेक्ट के लिये जनता जल मिशन में घर-घर कनेक्शन के लिये वन विभाग के एरिया में हमारे टाटगढ़ में जाने वाले पानी की लाइन बन्द पड़ी है, उसके लिये भी वन विभाग को निर्देश देकर पानी चालू होना चाहिये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, मैं मेरी मांग तो रख लूं। मैं अपने एरिया की मांग रख लेता हूं। सरूपा देवल, फतेहपुर (I), रावली, सेजरिया, टीलाखेड़ा, रामपुरा दूदा, मालीपुरा, इन स्कूलों को अभी तक क्रमोन्नत नहीं किया गया है, इसलिये मेरा निवेदन है, इन्हें भी क्रमोन्नत किया जाये।

सिरोही से आने वाले भाई ने आरोप लगाये थे, आरोप तो मैं लगाता हूं कि आपके कांग्रेस के सदस्य ने 86 बीघा 9 बिस्वा जमीन पटवारी के द्वारा सादे पेपर पर, सम्बन्धित तत्कालीन तहसीलदार ने हस्ताक्षर किये सादे पेपर

(श्री शंकर सिंह रावत)
पर बिना रजिस्ट्री कराये, कि जाओ इसका नामान्तरकरण उसके नाम पर खोल दो। नामान्तरकरण उसमें खुला है और मैं बता रहा हूं, प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 28.11.2001 को तहसीलदार ने मार्किंग की, उसका नामान्तरकरण 2002 में 1328 नम्बर पर खुला है। उस समय भाजपा की नहीं, कांग्रेस की सरकार थी। गांधीवादी मुख्य मंत्री महोदय ईमानदार हैं। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं उनकी सरकार पर आरोप लगा रहा हूं। इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे और नामान्तरकरण निरस्त करने की घोषणा करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, आज बजट 2022-23 पर बोलने का जो अवसर आपने दिया, उसके लिये धन्यवाद। राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय का यह चौथा बजट था। हर बजट को उन्होंने ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की। इस बजट के साथ उन्होंने पहला कृषि बजट राजस्थान को दिया। इससे पहले एक पेपरलेस बजट दिया। 2013 में उन्होंने एक जेंडर बजट भी दिया। इस सरकार में यह चौथा बजट पेश किया गया। उन्होंने इस बजट में कोविड काल में इस राज्य की जनता को कुछ न कुछ देने की कोशिश की, लेकिन हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो आवश्यक डिमांड थी, जैसे कि गुजरात से सटा हुआ आता है तो वहां पर सीमलवाड़ा में जो सामुदायिक

(समय: 17.00 बजे)

स्वास्थ्य केन्द्र था उसको उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की लम्बे समय से डिमांड चल रही है चाहे उधर की सरकार रही हो या इधर की सरकार रही हो, पर यह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि उनकी जो रिप्लाई आये उसमें सीमलवाड़ा को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन से 125 दिन करने की जो घोषणा की है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। साथ ही नगर निगम, नगर परिषद् और नगरपालिकाओं में शहरी रोजगार योजना लागू की है वह कहीं न कहीं राहत प्रदान करेगी। लेकिन बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो नरेगा में मेट लगे हुए हैं उन मेट का छह माह से भुगतान नहीं हुआ है और ऊपर से यह डायरेक्शन हुए हैं कि उनको अटेंडेंस ऑनलाइन लेनी है, जो लेबर आयी है उसका फोटो खींचना है। अब यह समझ में नहीं आता कि जिस मेट को 200-300 रुपये का भुगतान हो रहा है और

(श्री राजकुमार रोत)

वह भी छह माह से नहीं मिला है तो उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल कहां से होगा और कैसे वह फोटो खींचेगा। अभी कई जगह यह स्थिति बनी हुई है कि कई मेट मस्टररोल लेने के लिए भी मना कर रहे हैं और सरपंच तथा वहां का विकास अधिकारी उनको जैसे-तैसे मना रहा है कि मस्टररोल लिया जाये। अब देखा जाए तो एक तरह से तो यह ठीक किया गया है, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में मेट इतने सक्षम नहीं हैं कि एंड्रॉयड फोन रखें और एंड्रॉयड फोन से उपस्थिति दें।

माननीय सभापति महोदय, अभी संविदाकर्मियों, पैराटीचर को लेकर अच्छा किया उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन पंचायती राज में जो लम्बे समय से जेटीए लगे हुए हैं वे कोविड काल में भी लोगों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए, लोगों को रोजगार प्रदान देने के लिए रात-दिन दौड़े हैं, पर इनको जो भुगतान किया जा रहा है वह कहीं न कहीं बहुत कम है। वर्तमान राज्य सरकार ने और पिछली सरकारों ने भी कई बार आश्वासन दिया था। उनके लिए कमेटी बनी थी उस कमेटी ने छत्तीसगढ़ और बिहार का सर्वे किया था और जेटीए के आन्दोलन के समय उन्होंने सरकार से समझौता किया था। उस समझौते के अनुसार वह सर्वे रिपोर्ट आ गयी है तो जिस तरह से बिहार और यू.पी. में जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत यहां पर भी जेटीए को राहत प्रदान की जाये और उनकी वृद्धि की जाये।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय में घरेलू उपभोक्ता जो 100 यूनिट बिजली खर्च करता है उसके लिए 50 यूनिट बिजली फ्री की गयी है और साथ ही जो 150 यूनिट तक बिजली का उपभोग करता है उसके लिए 3 रुपये तक का अनुदान पर-यूनिट पर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, विद्युत विभाग को देखा जाए तो कई योजनाएं लागू हुई हैं। अभी वर्तमान में कुसुम योजना चल रही है, लेकिन योजना धरातल पर नहीं जा पाती है जिससे जो गरीब व्यक्ति है वह गरीब व्यक्ति उस योजना का लाभ लेने के लिए दर-दर भटकता है। हमारा जो चौरासी विधान सभा क्षेत्र है वहां पर कुसुम योजना लागू हुई है उसके बावजूद भी हमारी जानकारी में एक भी कृषि कनेक्शन कुसुम योजना से नहीं जोड़ा गया है।

माननीय सभापति महोदय, हम राज्य लेवल पर कोई भी कानून बनाते हैं, किसी भी विभाग की कोई योजना लागू करते हैं तो समान रूप से लागू करते हैं। बिजली विभाग का देखा जाए तो हमारी भौगोलिक स्थिति है

(श्री राजकुमार रोत)

उसमें वह पूरा पहाड़ी और जंगल का इलाका है जिसमें बारिश होती है तो पता नहीं चलता है कि कहां पर तार टूटा है। अब उपभोक्ता की कमी है, लेकिन वहां पर कई ऐसी जगह हैं जहां 33 केवी जीएसएस की विशेष आवश्यकता है जैसे कि पालसासरपुर, रेटा, पगारा में 33 केवी जीएसएस खोलने की अति आवश्यकता है और हम चाहेंगे कि इस बजट में यह प्रावधान हो। माननीय सभापति महोदय, जोत्री और चिखली में ए.ईएन. ऑफिस और धम्भोला में एक्स.ईएन. आफिस के लिए भी लम्बे समय से डिमांड चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग को देखा जाए तो सरकार की कई योजनाएं रही हैं चाहे इधर की सरकार रही हो या उधर की सरकार रही हो, लेकिन योजनाएं नीचे तक ठेठ गरीब परिवार है उस परिवार तक नहीं पहुंच पाती हैं। पिछली बार चिरंजीवी योजना थी, इस चिरंजीवी योजना का लाभ अब 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। नि:शुल्क दवा योजना है, नि:शुल्क जांच योजना है, लेकिन इन योजनाओं को धरातल तक, गरीब आदमी तक पहुंचाने का काम अधिकारी, कर्मचारी वर्ग करता है। हमारे डूंगरपुर जिले में सीएमएचओ की लड़ाई है वह लम्बे समय से चल रही है। एक सी.एम. की कुर्सी के लिए नहीं लड़ते हैं, उतना सीएमएचओ की कुर्सी के लिए डूंगरपुर जिले में लड़ा जा रहा है। मैं आपको बता दूंगा तो आप सोचकर विचार करोगे कि हमारे विधायक कोटे से कोरोना काल में मार्च माह में हमने एम्बुलेंस दी थी, हमारे डूंगरपुर जिले के सभी विधायकों ने एम्बुलेंस दी थी लेकिन आज एक साल होने को आ गया पर वह एम्बुलेंस एज इट इज वहां पर खड़ी हुई है और उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

इसी तरह से हमारे डूंगरपुर जिले के सीएमएचओ हर तीसरे दिन बदलते हैं। अभी जो तत्कालीन सीएमएचओ लगे हुए हैं उनको पता नहीं सीएमएचओ की कुर्सी से इतना कैसे लगाव हो गया है वह समझ में नहीं आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि 2008 में वहां पर वे संविदा पर डाक्टर लगे हुए थे तब जननी सुरक्षा राशि का गबन किया था। वहां महिला की डिलीवरी उसके घर पर हुई थी लेकिन उन्होंने संस्थागत प्रसव बताकर उसका पैसा उठा लिया था। 2008 से यह जांच चल रही है। उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर नीरज के. पवन थे और उन्होंने एफआईआर का कहा और उसके बाद विभाग ने इनकी सेवा समाप्ति कर दी थी। 2008 से वह सीएमएचओ कोर्ट में गये हुए हैं और अभी तक वह कोर्ट

(श्री राजकुमार रोत)

केस चल रहा है। इसके बावजूद वहां पर बीसीएमएचओ लगे हुए हैं। इस कोर्ट केस की जो डेट आयी है, 2008 से यह कोर्ट केस चल रहा है और गवर्नमेंट के जो वकील हैं, एपीपी हैं उन्होंने आज तक पैरवी नहीं की है और उसकी सुनवाई की डेट आज ही 02 मार्च, 2022 है, आज उसकी हियरिंग थी। 2008 से आज 14 साल हो गये पर कोर्ट का डिसीजन अभी तक नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कई बार हटाया पर वे स्टे लेकर वापस लग जाते हैं। मैं इसलिए यह बात इस बजट पर बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की योजना है वह योजना धरातल पर नहीं पहुंच पा रही है और वह इसलिए नहीं पहुंच पा रही है कि ऐसे अधिकारी जो कुर्सी से चिपके हुए हैं उनको मलाई से मतलब है गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है चाहे हम कितनी भी बड़ी योजना चला दें। जैसे चिरंजीवी योजना है जिसमें 5 लाख से 10 लाख कर दिये, लेकिन ऐसे अधिकारी बैठने से ये योजनाएं वैसी की वैसी हो रही हैं और आम जनता को किसी प्रकार का कोई बैनेफिट नहीं हो पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मैं बताना नहीं चाहूंगा कि कोविड काल में जो कफन होता है उसमें भी कमीशन की उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। यह सरकार की बदनामी है इसलिए ऐसे लोगों को तत्काल हटाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बावड़ी और पालसासरपुर में पीएचसी की डिमांड चल रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 50 पीएचसी खोलने और 50 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पीएचसी में क्रमोन्नत करने की जो बात कही है, उसमें हम चाहेंगे कि पाल सासरपुर और बावड़ी को पीएचसी दी जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी रिटायर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करके बुढ़ापे में एक सहारा दिया है, लेकिन इस राज्य के बेरोजगार भी सरकार से आशा लगाये हुए बैठे हैं। सरकार ने अभी विद्या सम्बल योजना चलायी थी जिसमें कई बेरोजगारों को आशा जगी थी कि हमें इसमें कहीं न हीं रोजगार मिलेगा, हमारा घर-गुजारा चलेगा और हम स्कूल में जाकर अध्ययन करायेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी एक आदेश आया है कि रिटायर्ड कर्मचारी को ही इसमें लिया जायेगा। यह कहीं न कहीं युवा बेरोजगारों के साथ अन्याय है, इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि विद्या सम्बल जो योजना है उस योजना में रिटायर्ड कर्मचारियों को छोड़कर जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों को लिया जाये क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए तो सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है, इसलिए युवाओं को भी कहीं न कहीं देने का कष्ट करें।

(श्री राजकुमार रोत)

माननीय सभापति महोदय, आज शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए इस बजट में घोषणा हुई है लेकिन इससे पूर्व 2019 में 98 पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है जो कोर्ट में अटकी हुई है तो सरकार उसमें जल्दी करके उसका समाधान किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए गांवों में, पहाड़ियों में छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए मां-बाड़ी योजना चलायी गयी थी। वह मां-बाड़ी कहीं न कहीं सार्थक रही है, लेकिन इसमें जो कार्मिक लगे हुए हैं, उसमें जो समन्वयक लगे हुए हैं उनका जो मानदेय है, उनकी जो डिमांड है उसके लिए सरकार अलग से कैडर बनाकर उनकी डिमांड पूरी करे। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने लास्ट में जाते-जाते एक बड़ा सा बेरोजगारों पर अपने वोट बैंक का दांव खेला। जो शिक्षाकर्मी लगे थे, जो बेरोजगार थे उनको पंचायत सहायक के रूप में....

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। दस मिनट से ज्यादा बोल लिये आप। अब समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): दस मिनट का ही समय हुआ है। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने जितने जो बेरोजगार थे और शिक्षाकर्मी जो लगे थे उनको पंचायत सहायक के रूप में लगाया। उसके लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की, उनका भुगतान कहां से होगा यह भी क्लियर नहीं हुआ और कहीं न कहीं उनको लाकर पंचायतों पर थोप दिया गया। आज पंचायत सहायकों की यह स्थिति बनी हुई है कि उनके भुगतान में भी किसी प्रकार कोई वृद्धि अभी नहीं हुई इसलिए हमारी मांग है कि उनका भी पैराटीचर की तरह स्थायीकरण किया जाये क्योंकि आज वे लोग लगे हुए हैं और उनको पंचायत से 6-7 महीने में पेमेन्ट हो पाता है तो उनके लिए घर का गुजारा चलाना काफी मुश्किल है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य और देश में देखा जाये बेरोजगारी काफी बढ़ रही है। अभी वर्तमान में रीट में भी काफी धांधली हुई। हर बार पेपर लीक होता है, कोई भी भर्ती हो, किसी की भी सरकार हो, इधर-उधर आरोप लगाने से नहीं, लेकिन यह बीमारी कहां है, यह समस्या कहां है, उसको ढूंढने की जरूरत है।

इसमें हमारी जो मांग है, उदयपुर सम्भाग मतलब अनुसूचित क्षेत्र के

(श्री राजकुमार रोत)

लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होती है। हर भर्ती 1 से लेकर 9 तक तो उनका सेन्टर सीकर, भरतपुर इतना दूर दिया जाता है तो एक गरीब परिवार का व्यक्ति इतने दूर नहीं आ सकता है। हमारा निवेदन है कि उदयपुर सम्भाग और अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के जो अभ्यर्थी हैं, उनका सेन्टर कहीं न कहीं उदयपुर सम्भाग के अन्दर जो जिले हैं, उनमें दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आरक्षण को लेकर, क्योंकि भर्तियां होती हैं, भर्तियां करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गयी है। अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण की इतनी विसंगतियां हैं। उस विसंगति की वजह से कई घटना होती हैं। 2013 में तत्कालीन सरकार के समय अधिसूचना जारी हुई और उस अधिसूचना के अनुसार ये भर्तियां हो रही हैं। 2016 में बीजेपी सरकार ने कुछ संशोधन किया। इसी का परिणाम काकर डूंगरी घटना हुई।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, वह भी कहीं न कहीं उसी का परिणाम रहा है।

श्री सभापति: माननीय जगसीराम कोली।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है अभी वागड़ टूरिज्म सर्किट की घोषणा हुई है। हम चाहेंगे कि उदयपुर सम्भाग के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, उन पर्यटन स्थलों को जो नाम दिया वागड़ टूरिज्म सर्किट, उसको ट्राइबल टूरिज्म सर्किट नाम देकर यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, चौरासी विधान सभा क्षेत्र में हमारे चिखली में एक न्यायालय खोलने की अति आवश्यकता है, क्योंकि यहां के लोगों को सागवाड़ा और डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 70-80 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पेयजल को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई थी। उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन साथ में सिंचाई के लिए रिस्का कीनाल, मोदरामहूड़ी, काकरीदरी एनिकट की विशेष आवश्यकता है, लम्बे समय से डिमाण्ड है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसमें पहल करें। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट लूंगा, हमारा गुजरात से सटा हुआ इलाका है।

श्री सभापति: विराजिये, आप सहयोग करें। श्री जगसी राम कोली।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): नीलकण्ठ महादेव पुलिया बनी हुई है और वह पुलिया लम्बे समय से टूटी हुई है, वहां आवागमन बन्द हो गया है, उसकी घोषणा की जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2022-23 का बजट 23 फरवरी को प्रस्तुत किया है। सभापति महोदय, इसमें मोटे तौर पर अभी समय बिलकुल सीमित कर रखा है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर, जो पिछले बजट में मंत्री जी बता रहे हैं कि बोलने दो, हम सुनना चाह रहे हैं, लेकिन पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था, जब परिवहन मंत्री जी थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर फिर गाड़ी चूक जाओगे। फिर मेरी कांस्टीट्यूएंसी करोगे। आप सीधे-सीधे उसी पर बोल लें। आप उधर मत देखिये, आप मेरी तरफ देखिये।

श्री जगसी राम (रेवदर): उस समय वोल्वो माउन्ट वाली बस है, जो आपने बन्द करवायी थी और उसको चालू करवाने के लिए आपने आश्वासन दिया था। तीन साल होने के बाद भी आपने बस चालू नहीं की, वोल्वो बस माउन्ट से जयपुर वाली तो इससे बड़ी विडम्बना आपकी सरकार के लिए, मैं समझता हूं कि कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। मैं भी पिछले लम्बे समय से 20 साल से इस विधान सभा में आ रहा हूं, लेकिन मंत्री लोग जो वादा करते हैं, उसी समय आदेश करते हैं।

ये जो बड़ी-बड़ी घोषणाएं मुख्य मंत्री जी ने की हैं, ये घोषणा तक ही हैं। हमारी सड़कों के बारे में बात करें तो रेवदर और जयसिंहपुर वाली बीच में सड़क है। वह पिछले घोषणा पत्र में भी थी और अभी वापस भी किया है। मण्डार, रानीवाड़ा, सांचौर वाली सड़क है, वह भी पिछली घोषणा में थी और दुबारा इस घोषणा पत्र में है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि जो भी आपने घोषणाएं की हैं। आज रेवदर में और आबू रोड में जो बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हैं, लेकिन काम चालू नहीं हुए हैं। इनके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखें तो हमारे अनादरा को पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्न्त किया है, मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र जो ग्रामीण

(श्री जगसी राम)

क्षेत्र से लगता हुआ एरिया है, उसके अन्दर हम देखें तो डाक्टर, कम्पाउंडर स्टाफ शहरों की ओर जाने के लिए रहते हैं और लगभग-लगभग जब भी विधान सभा के अन्दर दो मिनट का भी समय मिलता है तो हम कहते हैं कि डॉक्टर हमारे क्षेत्र में लगाओ। मण्डार कस्बा बहुत बड़ा कस्बा है, आस-पास के 25 गांव लगते हैं, एकमात्र डाक्टर था, उनको भी तीन दिन पहले हटा दिया है।

अब टीएसपी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें। अभी मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के अन्दर बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं, आबूरोड टीएसपी पूरा क्षेत्र लगता हुआ है। वहां पर आसपास के क्षेत्र के अन्दर, जो भी हमारे आदिवासी भाई आते हैं। उनको इलाज के लिये, हमने जिला अस्पताल करवाने के लिए कई बार मुख्य मंत्री जी से, मंत्री जी से भी निवेदन किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब रिप्लाई दें उस समय हमारे आबू रोड शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उसको जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाने के लिए यदि आप घोषणा करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे आबू रोड क्षेत्र सिरोही जिले में जो टीएसपी एरिया है, उनके आप शुभचिन्तक हैं।

इसी तरह से मैं चाहूंगा कि सिरोही जिले के अन्दर पिछले दो वर्षों से लगातार बारिश नहीं हो रही है, पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट के अन्दर प्रत्येक विधायक को 40 हैण्डपम्प और 10 ट्यूबवैल का जो अनाउंस किया था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जब भी सरकार जवाब दे तो यह बता दे कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 40 हैण्डपम्प और 10 ट्यूबवैल में से एक भी दिया हो तो उसका रिप्लाई आप देंगे। मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर कुछ हुआ है।

ऐसा ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देखें। इस सरकार के आने के बाद पहले स्टाफ पूरा पर्याप्त था। हर 12वीं तक स्कूल में पर्याप्त स्टाफ था, लेकिन अभी पिछले कार्यकाल में सभी अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर स्थानान्तरण करवाकर, यह कैसे किया है। मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अपने-अपने क्षेत्र में वापस यथास्थान पहुंच गये हैं तो सरकार सीमित दायरा क्यों रख रही है कि अपने-अपने क्षेत्र में ले जायें। आज राजस्थान की चिन्ता करें तो मैं समझता हूं कि सबको बराबर दायरा देते हुए सिरोही जिले को ही नहीं रेवदर हमारा क्षेत्र है, गुजरात से लगता हुआ, आबू रोड लगता हुआ है तो सारे क्षेत्रफल को देखें तो रेवदर को भी उसमें सम्मिलित करें।

(श्री जगसी राम)

इसी तरह से सड़कों को देखें तो जो गौरव पथ के नाम से और विकास पथ के नाम से, पूर्व में हमारे सभी माननीय सदस्यों ने बताया है कि विकास पथ के नाम से जो किया है, एक भी काम चालू नहीं हुआ है। हमारे मंत्री जी अभी यहां विराजमान नहीं हैं। जब उन्होंने जिले की बैठक रखवायी थी तो उनके अधिकारियों ने बताया कि काम चालू क्यों नहीं किया गया, बजट के अभाव में काम चालू नहीं हुआ है तो इसीलिए यह बजट भाषण है, बजट भाषण के अन्दर मैं कहता हूं जो भी अपने प्रदेश के लिए चिन्ता कर रहे हैं। इस चिन्ता के माध्यम से जनता तक काम कैसे धरातल तक पहुंचे, ऐसी अपन को व्यवस्था करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि टीएसपी के अन्दर हमारे यहां पर आदिवासी छात्रावास जो हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): छात्रावासों की जो स्थिति है, बड़ी दयनीय है। वहां पर कोई नये संसाधन नहीं लगाये गये हैं। उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है और छात्रावासों की जो व्यवस्था है, वहां पर बैड वगैरह की बहुत बुरी व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्र के अन्दर सरकार एक योजना लायी थी कि किसान जो सीमित काश्तकार हैं उनको कुआं गहरा करवाने के लिए फ्री व्यवस्था की गई थी। इस सरकार ने आने के बाद में उनको बन्द कर रखा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जब भी जवाब दे, उसके अन्दर उनको बताये कि टीएसपी क्षेत्र का जो भाग है, उसके अन्दर हमारे क्षेत्र के जो भी आदिवासी किसान हैं उनको सीधे-सीधे फायदा मिल सके। इसके अलावा भी सरकार के द्वारा जो कृषि यंत्र किसानों के लिए वितरित किये जाते हैं, वे मात्र कागजों में ही किये जाते हैं। सरकार उनकी जांच करवाये और जांच करवाने के उपरान्त जिन किसानों को सामान नहीं मिला है, कृषि यंत्र नहीं मिले हैं, उन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसी तरह से हर क्षेत्र के अन्दर कोई भी विभाग आप देखे लें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो एमआई टैंक हैं ये हमारे जो बांध हैं। हमारे मण्डार के पास एक सूलिवा ओर पिथापुरा के बीच में पुराना कई वर्षों से फूटा पड़ा है और एक सांगलिया, हलमतिया वाला बांध टूटा पड़ा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको जोड़कर नया चालू करें, ताकि जलस्तर ऊपर कैसे उठे और किसानों को उसका फायदा मिलेगा। मैं

(श्री जगसी राम)

आज के इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय, यही कहना चाहूंगा कि जो भी सरकार ने वादे किये हैं उनके ऊपर खरे उतरने का प्रयास करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, पांच मिनट ही हुए हैं। सभापति महोदय, खेल स्टेडियम के लिए सरकार ने कहा था कि हम प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम बनवायेंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान में किसी के भी प्रपोजल तक नहीं बने हैं, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, कांग्रेस के साथियों ने काफी सराहना की कि हमने यह किया, वह किया, लेकिन जो कहा, है वह करके बताओ। हमारे आगरा भट्टा वाली जो रोड है वह रोड आलरेडी बनी हुई है और वहां पर दुबारा सैंक्शन की है तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में 33 केवी के जीएसएस रेवदर विधान सभा क्षेत्र में एक भी अनाउंस नहीं किया है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में किसानों की मांग के अनुसार मैंने कई बार मांग कर रखी है, जिरावल क्षेत्र में 33 केवी का सब स्टेशन बने ताकि क्षेत्र के किसानों को फायदा मिल सके। यही नहीं प्रत्येक ...

श्री सभापति: समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। श्री दानिश अबरार।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस वर्ष के बजट 2022-23 के ऊपर बोलने का मौका दिया और आज के भाषण की शुरुआत मैं एक शेर के साथ करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले क्योंकि सामने वाले इस शानदार ऐतिहासिक बजट जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने पढ़ा, उसके बावजूद भी खिलाफ बोल रहे हैं इसलिये मैं शुरुआत में एक शेर कहना चाहूंगा।

'अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़े है।
यह सब धुंआ है, कोई आसमान थोड़े है।'

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसके रचयिता आप ही हैं। यह अभी-अभी रचा है आपने शेर, है न?

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): इसका रचयिता पहली बात तो मैं हूं नहीं और अगर आप ऐसा समझते हो कि मैं हूं तो यह काबिलेतारीफ बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): हमारी सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के ऊपर हमेशा गरीब वर्ग की सबसे पहले सोची है। इस गरीब वर्ग की बात को सोचते-सोचते सबसे पहले महात्मा गांधी नरेगा योजना लायी गई जिसको इस भाजपा की सरकार ने खड्ढे खोदने का काम कहा और आज उस नरेगा को बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने इस बजट में सौ दिन से बढ़ा कर एक सौ पच्चीस दिन कर दिया और गांव से आगे बढ़ते-बढ़ते उस नरेगा के काम को इस बजट में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना" भी लेकर आ गए जिसके अन्दर सौ दिन का रोजगार फिर से दिया जाएगा। गांव से चलते-चलते अब शहर तक आ गये तो गांव में तो इन बीजेपी वालों ने कह दिया था कि खड्ढे खोदने का काम है, अब यह देखा जायेगा कि जब सौ दिन तक शहर के अन्दर भी रोजगार देंगे तो अब इसको यह कौन सा काम का नाम देंगे।

इसके साथ ही गरीबों के लिए, जो एक गरीब आदमी है जिसका बिजली का बिल मात्र सौ यूनिट आता है उनको पचास यूनिट फ्री करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके बाद अगर आप सोशल सिक्योरिटी की बात को छोड़कर आदमी के स्वास्थ्य की बात करें तो यह हमारी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी 2011 के अन्दर, जिसने सबसे पहले दवा फ्री की। यह हमारी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2013 के अन्दर, जिसने जांच फ्री कर दी और अब यह हमारी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसने ओपीडी और आईपीडी को भी फ्री करने का काम किया है और फ्री जो किया तो किया, दवा फ्री, जांच फ्री, ओपीडी फ्री, आईपीडी फ्री, इसके साथ-साथ चिरंजीवी योजना लाकर बीमा योजना तक दे दी, उसको भी पांच लाख से बढ़ा कर दस लाख रुपये कर दिया। यह काम किया है हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने।

सभापति महोदय, जो हमारे सामने बैठे हैं बीजेपी के लोग, सिवाय बांटने के कभी कोई काम नहीं किया। कभी हिन्दू-मुसलमान को लड़ा दिया, जाटों को राजपूत से लड़ा दिया, मीणा को गुर्जर से लड़ा दिया और यह कहने की बात है, यह कर्मचारियों की ओल्ड पेन्शन की जगह न्यू पेन्शन स्कीम भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। यह हमारी सरकार है जिसने वापस ओपीएस लागू करने की घोषणा की और ओपीएस लागू करने के पीछे मंशा, सरकारी कर्मचारी ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सरकारी दवा काम ही नहीं करती।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): मुझे पता है आपको नहीं पचेगी मेरी बातें। आज जो बच्चा पढ़-लिखकर काबिल होता है उसको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए सरकार के अन्दर जब तक सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, उसके भविष्य की सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सरकार के कर्मचारी में नहीं आयेगा। आप उठाकर देखें 2004 के बाद की जो भर्तियां हुईं उन भर्तियों में टेलेन्टेड लोग कम आये, क्यों? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं थी और आज जब हमारी सरकार ने 2004 की भर्तियों के बाद जो भर्तियां हुईं उनके अन्दर वापस से पेन्शन स्कीम लागू कर दी। यह देखना चाहिए आपको लोग गुलाल से खेल रहे हैं, लोग स्कूलों में नाच रहे हैं, लोग गाने गा रहे हैं, लोग गीत बना रहे हैं और सभापति महोदय, इस सदन में खड़े होकर खुला चैलेंज करके मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सामने वाले साथियों को कि अगर आपके अन्दर दम है तो जब आप जवाब दें तो खुलकर कहना कि यह जो ओपीएस स्कीम हम 2004 के बाद के लिए वापस लाये हैं इसका आप लोग विरोध कर रहे हो या साथ खड़े हो? आपको मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि आप हमारे साथ खड़े हो और अगर आप में दम है तो आप यह कहकर दिखाना कि आप इसका विरोध कर रहे हो और मेरे को तो ऐसा लगता है कि यह ओपीएस की जब घोषणा हुई और होने के बाद जिस तरह का आज प्रदेश में माहौल है और उस दिन बजट की शाम को बीजेपी के चंद नेताओं का हाल कुछ ऐसा था, इसको भी एक शेर के माध्यम से बताना चाहूंगा। 'दिन ढल गया तो रात गुजारने की आस में सूरज नदी में डूब गया, हम गिलास में।' यह कुछ हाले आलम था हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों का और अब जहां तक बची बात बांटने की जो मैं बात कह रहा था, अफसोस होता है कि राजनीति, जाति बिरादरी तक तो ठीक था, अब कपड़ों को लेकर भी बांटने की बात आ गयी। इस हिन्दुस्तान के अन्दर अगर कोई महिला अपना सिर ढंक कर रहना चाहती है तो उसके अन्दर भी पूरे देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया और उसको हिजाब का नाम दे दिया। क्या सिर ढंक कर रखना किसी के लिए गुनाह है क्या? और अगर यही बांटने की बात करते हैं तो साहब, हमने तो कभी बांटने की बात में यह नहीं कहा कि जो हमारे भीनमाल से माननीय सदस्य आते हैं वो विधान सभा में चश्मा लगाकर बैठते हैं। अधिकार है, हमने तो कभी बात नहीं कही। चूरू से जो हमारे माननीय सदस्य आते हैं उनका हमेशा कुर्ते का रंग अलग, जैकेट का रंग अलग और पाजामे का रंग अलग होता है। मकराना से जो हमारे माननीय सदस्य आते हैं वो हैट लगाकर आते हैं। पाली से जो हमारे माननीय सदस्य ज्ञानचंद पारख जी हैं उनको तो मैंने हमेशा पेंट-टीशर्ट में ही देखा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बजट पर बोल लो। माननीय सदस्य, क्षेत्र पर बोल लो, फिर कहोगे कि टाइम नहीं दिया।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): मैं कहना चाहता हूं कि कपड़ों पर बांटने में आ गए बीजेपी वाले। राजनीति तक तो ठीक था, अब कपड़े तक बंटने लग गये और ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: साइलेंस।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): और अगर कपड़ों को लेकर, इस हिजाब को लेकर इतना बड़ा ताण्डव हिन्दुस्तान में रचा गया था तो मैं इसके लिए भी कहना चाहूंगा कि 'है दुनिया छोड़ने को मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं किसी भी हाल के अन्दर।' किसी हाल के अन्दर चाहे कैसा ही ताण्डव क्यों न रचते रहें और साहब, आपको बात बतायें, अभी बात चल रही थी, हमारी सरकार ने सब विधायकों को जब बजट पेश हुआ तो बजट पढ़ने के लिए मोबाइल फोन दिया। अख़बार में चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, बीजेपी के लोगों ने मोबाइल फोन वापस कर दिये। इसमें भी ढोंग और तमाशा। मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहता हूं, सवाई माधोपुर का विधायक कहता है, इस सदन में ये जो दो सौ के दो सौ बैठे हैं, हम सब लोगों ने या तो सरकार के माध्यम से फ्लैट लिये हैं और जिन लोगों ने फ्लैट नहीं लिये उन्होंने प्लाट लिये हैं। आज अगर सबने मोबाइल भी दे दिये तो लगे हाथ वो फ्लैट और प्लाट भी वापस क्यों नहीं करते आप लोग? यह मोबाइल इसलिये वापस करने का नाटक करते हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। (व्यवधान) चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): और चोर की दाढ़ी में तिनका क्या है मैं बताता हूं ...(व्यवधान) चोर की दाढ़ी में तिनका। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये आप। माननीय सदस्य, काफी वरिष्ठ हैं आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये आप। आसन पैरों पर है। अकारण उत्तेजना पैदा करने की जरूरत नहीं है। न पेंट और शर्ट की बात करनी है, बजट पर बोलेंगे आप तो बोलें नहीं तो वरना मैं नैक्स्ट को बुलाता हूं। आप पेंट-शर्ट मत लाइये यहां पर।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): साहब, आपने कहा बजट पर बोलना है, पेंट-शर्ट पर नहीं बोलना है, पेंट-शर्ट पर नहीं बोलता हूं, लेकिन मोबाइल तो बजट में ही मिला था।

श्री सभापति: छोड़िए, जिसको देना है वह देगा, नहीं देना है नहीं देगा। आप अपनी बात कहिए।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): साहब, फिर यह इतने ढोल क्यों पीटते हैं? हमने भी लिया, हमने भी फ्लैट लिये, हमने भी मोबाइल लिया, हम तो नाटक नहीं कर रहे। चोर की दाढ़ी में तिनके की बात तो कहूंगा। साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका यह था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जासूसी की आदत है, तो इनको डर था कि कहीं मोबाइल के जरिए इसमें कुछ डाल नहीं दिया हो, इसलिए मोबाइल वापस करें और चारों तरफ ढोल पीटा जा रहा है कि हमें मोबाइल नहीं लेना। खैर, मैं आपके आदेश अनुसार बजट की बात पर आता हूं।

श्री सभापति: 10 मिनट मोबाइल को ही समर्पित कर दिये आपने।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): साहब, जहां तक सवाल राजीव गांधी पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी और मदरसा पैराटीचर्स का है, यह मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, तकरीबन 15-20 साल से मुद्दा चला आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं कि चाहे उधर वाले थे या इधर वाले थे, मीठी गोलियां सबने दीं और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, इन्होंने तो पिछली बार 15-15 लाख देने की बात कही और अपने मेनिफेस्टो में इतनी मीठी-मीठी बातें करी थीं, इसको भी एक शेर के जरिए कहता हूं। जब आपका राज था तब जनता के प्रति क्या हाल था मेनिफेस्टो के जरिए, 'आप कहें तो कायनात की सारी खुशियां लाकर आपकी तरफ मोड़ दूं, ऐसा आप कहते थे। 'आप कहें तो कायनात की सारी खुशियां आपकी तरफ लाकर मोड़ दूं। और आप कहें तो चांद सूरज भी लाकर तोड़ दूं। इतना बस है मेरी जान। थोड़ा कम असत्य बोल लो।' सिर्फ वादे-वादे किये और आज मुझे खुशी है इस बात की और गर्व है इस बात का यह हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिन्होंने आज मदरसा पैराटीचर्स, राजीव गांधी पैराटीचर्स और शिक्षाकर्मियों की जो समस्या चली आ रही है, उस समस्या का समाधान निकाला है और बहुत जल्द इस पर नोटिफिकेशन भी जारी होगा।

साहब, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य राजेन्द्र राठौड साहब का भाषण उस दिन मैं ध्यान से सुन रहा था। बजट वाले दिन राठौड़ साहब ने

(श्री दानिश अबरार)

कहा था कि मैंने काफी देर रात को बजट पढ़ा। साहब, जब देर रात तक पढ़ते हैं तो कभी-कभी पढ़ते-पढ़ते झपकी लग जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की आदत है बोलो और भूल जाओ। यह बजट पढ़ते-पढ़ते उनको अहसास हुआ था बोलो और भूल जाओ। बजट के संदर्भ में कहा था जो पुराने बजट हुए हैं उनके काम अभी तक धरातल पर नहीं आये हैं। साहब, दिसम्बर, 2018 में हमारी सरकार आई। 2019 में दबाकर घोषणाएं हुईं और 2020 और 2021 दो साल पूरे कोरोना काल में गये। दिसम्बर, 2018 में आये, 2019 में घोषणाएं हुईं, 2020 और 2021 कोरोना काल में गये और अधिकांश चीजें धरातल पर हैं, नहीं हैं तो इस साल आपको अधिकांश चीजें धरातल पर दिख जायेंगी लेकिन मैं राठौड़ साहब से कहना चाहूंगा कि चाहे हम कुछ भूले या ना भूले लेकिन जब यह कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल की दूसरी लहर में जब लोग मर रहे थे, आक्सीजन के लिये तड़प रहे थे।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): साहब, मेरे को टाइम दिया गया है 10 से 15 मिनट।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): साहब, मुझे पूरे पांच मिनट चाहिये और मैं बोलूंगा। कोरोना काल में भाई, भाई को छूने से डर रहा था। मां, बेटे को छूने से डर रही थी। आदमी, आदमी को छूने से डर रहा था। आक्सीजन के लिये लोग तड़प-तड़प कर मर रहे थे। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की। पेशेंट को रिसीव करने से लेकर भर्ती करने तक, भर्ती के बाद जांच कराने तक, जांच कराने के बाद आक्सीजन देने तक और आक्सीजन देने के बाद इलाज कराने तक और फिर भी कोई बीच में हमें छोड़कर चला जाता है तो उसके पार्थिव शरीर को गांव तक पहुंचाने तक का काम किया तो वह इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोरोना काल में किया। साहब, ...(व्यवधान) आप तो कह रहे हो बोलते रहो, सभापति जी ने मेरे को टाइम गिना दिया।

श्री सभापति: शांत रहें, बोलने दें उन्हें।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): साहब, हमारी सरकार ने कृषि बजट अलग से पेश किया, बहुत पेट दुख रहा है। भारत सरकार ने तो कृषि

(श्री दानिश अबरार)

बजट को मिला दिया। आज इनका पेट इसलिए दुख रहा है क्योंकि कृषि बजट राजस्थान के किसानों के लिये है और राजस्थान के किसानों के लिये राजस्थान सरकार ने कृषि बजट अलग कर दिया। जमीन खरीदने से लेकर, उसकी तार फेंसिंग से लेकर, बीज खरीदने से लेकर, उसकी जमाबंदी के बाद उसके सारे काम करने तक, उसको ऋण लेने तक, हमारी सरकार ने सारे इंतजाम करके बजट अलग कर दिया और वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डंडे बरसाये, खैंची तारें, इसलिए आज तकलीफ है कि कृषि बजट किस प्रकार अलग हो गया।

साहब, मैं सवाई माधोपुर के संदर्भ में कहना चाहूंगा, इतिहास में और दशकों से माधोपुर में मांग चली आ रही थी। वहां हमारे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। वहां हमारी सरकार ने रोप-वे की घोषणा कर दी। एक नया अस्पताल, नया नर्सिंग कालेज, सेंटर पार्क, मुस्लिम के लिये 25 करोड़ के हॉस्टल, माधोपुर के लिये अनगिनत घोषणा कीं। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही जो रिप्लाई आयेगा, उसके लिये मैं कुछ गुजारिश और करना चाहूंगा। साहब, सवाई माधोपुर जिला एसटी बहुल जिला है, इसलिए सवाई माधोपुर में एक एसटी हॉस्टल की भी घोषणा हो और वहां चार एनीकट बनने चाहिये, ओवलवाड़ा, बेहतड, भूखा में। चकेरी और फिलसीभून में पीएचसी। सवाई माधोपुर जिला हैडक्वार्टर है, वहां पर कृषि महाविद्यालय। एग्जिस्टिंग कालेज में एमएससी खुलनी चाहिये। मलारनाडूंगर में एसडीएम कोर्ट है, हमारी तहसील है, वहां एक मुंसिफ कोर्ट की कमी बची है, मुंसिफ कोर्ट होना चाहिये। हमीर सर्किल हमारे सवाई माधोपुर में है, उस हमीर सर्किल का पूरी तरह से जीर्णोद्धार होना चाहिये। बजरिया में विद्यार्थियों के लिये पुस्तकालय, अमरूद प्रशिक्षण केन्द्र। खिरनी को उप तहसील, ऐसी तमाम और बहुत सारी बातें हैं जो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखकर दी हैं, जिनकी मैं उम्मीद करता हूं कि अपने रिप्लाई में वह यह एड करके बोलेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): साहब, खाली एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। जैसे शुरू शेर से किया था समाप्त भी शेर से कर देता हूं। राजस्थान की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो डंडे बरसते हैं और हमारी सरकार दवाई, इलाज फ्री कराकर गोली खिलाती है।

(श्री दानिश अबरार)

इसलिए एक शेर से अपनी बात समाप्त करता हूं। 'चाहे सब खो जाय' लेकिन उनको मत खोना जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया-सा लगता है।' बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने एक ग्लोबल मांग, पूरे विश्व की एक ग्लोबल मांग ओल्ड पेंशन स्कीम, जब 2004 में हिन्दुस्तान में न्यू पेंशन स्कीम आ रही थी, यूरोप के देशों में वापस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा रही थी। इस ग्लोबल मांग को पूरा करने के लिये उनका कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक आदमी के दो बच्चे पैदा करने का नारा है, यह उन्होंने तीसरा बच्चा पैदा करके दिया है, जो बुढ़ापे की लाठी बनेगा। खुद का पैदा किया हुआ बच्चा बागी हो भी सकता है, यह बच्चा बागी नहीं होगा। यह बुढ़ापे में उस कर्मचारी की सेवा करेगा जो 60 साल तक सरकार की और जनता की सेवा करता है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, इसमें कुछ लोग रह गये जैसे राजस्थान रोडवेज के और बिजली विभाग के 4-4, 5-5 हजार कर्मचारी, जिनके विकल्प पत्र भरवाने हैं। बड़ा दिल करके उनके भी विकल्प पत्र भरवाये जाएं।

मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का इस बात के लिये धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह अलग से कृषि बजट लेकर आये। मैं कृषि बजट से मेरी बात पूरी करना चाहूंगा। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने इसके लिये 11 कालम बनाये जिसमें सबसे पहले राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। सूक्ष्म सिंचाई पर खर्च करेंगे 1,705 करोड़ रुपये। मैं मांग करता हूं चौदह बिराने गांव भादरा के, चौदह नोहर के और दो तारानगर के, 36 हजार हैक्टेयर जमीन जो सिद्धमुख नहर से वंचित हो गई, जिसको साहवा लिफ्ट कैनाल से सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से जोड़ा जाय और ड्रिप सिस्टम से उनकी सिंचाई की जाय ताकि वहां के किसानों को हौसला हो। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को याद कराना चाहूंगा, जिन्होंने यह कहा है कि किसान जो खेत में पौंड बनायेगा, उसके लिये 45 हजार कृषकों को 375 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में जो खेत में डिग्गियां बना लीं, जिन्होंने बारी के इंतजार में, जिन्होंने लाटरी के इंतजार में डिग्गियां बना लीं, उन किसानों को भी इसमें शामिल किया जाय और उस किसान के खेत में

(श्री बलवान पूनियां)

बनायी हुई डिग्गी का राजस्थान की सरकार भुगतान करे। थोड़े दिन पहले राजस्थान में विधान सभा में खाद्य प्रसंस्करण को लेकर एक अधिसूचना, जिसे हमने निरस्त करने की मांग की थी, उसमें एमपी और एमएलए को किसान नहीं माना गया था। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह अधिसूचना अभी पूर्ण रूप से निरस्त नहीं हुई है। इसका हमारे अध्यक्ष जी ने आदेश किया था और पूरे सदन ने कहा था कि एमपी और एमएलए भी किसान हैं। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि कृषि बजट में आप जो-जो चीजें लेकर आये हैं, उसमें सबसे पहले आपने कर्ज का जिक्र किया। आपने जो सहकारी समितियों के कर्जे माफ किये, आपने जो राजस्थान के बैंकों के कर्ज माफ किये, मैं मांग करता हूं कि आप कामर्शियल बैंकों के लिए योजना लेकर आयें और सैटलमेंट योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसान का कर्ज माफ करे। किसान को सैटलमेंट में जो 10-20 परसेंट का कर्ज भरना पड़े, राज्य सरकार उस पैसे का भुगतान करे। फिर नये तरीके से पूरे राजस्थान की खेती को उबारने के लिए ये जो 11 कालम बनाये गये हैं, उन एक-एक कालम पर मजबूती से बात करें।

बीच में मेरी खाद्य प्रसंस्करण की बात रह गयी। सभापति महोदय, अभी तक एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसको ऋण मिला हो, क्योंकि बैंक सीधा आईटीआर मांगता है, इसलिए सरकार किसान को ऋण दिलाकर खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों को मजबूत करने का काम करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जिस तरीके से आपने ओपीएस को बहाल करके निजीकरण पर चोट की है, आप नहरी तंत्र में भी जिसमें इन्दिरा गांधी नहर, गंग कैनाल, भाखड़ा और भाखड़ा में नोहर भादरा भाखड़ा की नहरें, जो आपने 1960 बनायी थीं, उन नहरों में सन् 2000 में निजीकरण लागू किया था, उसमें मैट और बेलदार हटा दिये गये थे, जिसकी वजह से नहरों की दुर्गति हो रखी है। उन नहरों में मैट और बेलदार वापस लगाये जायें और निजीकरण पर एक और चोट की जाये।

सभापति महोदय, यह भी कहा कि नहरों के पुनरुद्धार के लिए करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। हमारे टोहाना के लिए राजस्थान की एंट्री तक करीब 27 किलोमीटर के हरियाणा के क्षेत्र में जो नहर डेमेज हुई है, उसकी वजह आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसान बार-बार पानी को लेकर मांग कर रहे हैं, पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा के सिस्टम से पानी

(श्री बलवान पूनियां)

नहीं ले पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 87 किलोमीटर के फोरचून को भी राजस्थान की सरकार इस बजट में शामिल करेगी और उसके पुनर्निर्माण की बात करेगी। हमारे जो वाटरकोर्स 2005-06 में बन गये थे, वे खराब बने, घटिया बने, वे वाटरकोर्स टूटकर खतम हो गये। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछली बार 84 करोड़ रुपये दिये, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र और नोहर विधान सभा क्षेत्र में वाटरकोर्सों का काम चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि बजट घोषणायें थोथी रह जायेंगी, वे पूरी नहीं होंगी। मैं कह रहा हूं कि मेरे यहां पर 40 खालों के निर्माण का कार्य चल रहा है और 40 खालों का कार्य भी नोहर विधान सभा क्षेत्र में चल रहा है, जो 83 करोड़ रुपये पिछली बार स्वीकृत हुए थे। अब की बार 125 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री जी और देते हैं तो जो खाले 2005-06 में बने थे वे खतम हो गये, उन खालों का दुबारा निर्माण कराया जा सकता है। आपने इन्दिरा गांधी नहर के सैकण्ड फेज के लिए यह बात की है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कृषि का अलग से बजट लेकर आये हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसी तरह से आप मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आयें। उसी पारदर्शिता से राजस्थान की सरकार एक कम्पनी बनाये और किसान से प्रीमियम ले और जिस क्षेत्र में नुकसान हो, वहां किसान को राशि का भुगतान करे। यह मेरी सदन से मांग है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरे विधान सभा क्षेत्र में और मेरे क्षेत्र में ही नहीं, राजस्थान भर में हजारों-करोड़ रुपये किसानों के बाकी हैं। सभापति महोदय, किसान से उसके पिता की डैथ होने के बाद उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र मांगते हैं। हर बैंक में जिसमें किसान की केसीसी है, वहां नोमिनी होता है, नोमिनी का नाम लिखा होता है। उस नोमिनी को फसल बीमा का आया हुआ क्लेम नहीं देते। उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र छह महीने में भी कोर्ट से नहीं आता है। सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की सरकार इस मसले का समाधान करेगी।

'शुद्ध के लिए युद्ध' की बात आयी। मैं इस बात को कृषि से इसलिए जोड़ रहा हूं, क्योंकि कृषि के बिंदुओं में है, पशुपालन को मजबूत करने का। पशुपालन से डेयरी मजबूत हुई। हनुमानगढ़ की डेयरी, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, मिलावट का धन्धा करते हैं। आज से पांच साल पहले वहां पर एक

(श्री बलवान पूनियां)

एमडी बैठा था, वह डेयरी को नोंचकर खा गया। हमने जांच बिठायी, हमने हैडलोड की गाड़ी चैक की। सभापति महोदय, 12 सौ लीटर दूध, सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था, एक महीने की जांच की। एक महीने की जांच में, जब हैडलोड की गाड़ी आती, सीसीटीवी कैमरा बन्द था। अगले दिन हैडलोड की गाड़ी में 30 लीटर दूध आया, कौनसी भैंस कूद गयी? भैंस ने दूध नहीं दिया। मिलावट का दूध था। हम लोग सरस से बहुत प्यार करते हैं। इनके शासन में और हमारे शासन में सरस को मजबूत करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को 'शुद्ध के लिये युद्ध' में हम प्राइवेट दुकान पर जाने की बजाय पहले सरकारी दफ्तर में भी जाकर देखें। सभापति महोदय, मेरे घर में बच्चों का ब्याह था, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सरस का दूध अपने परिजनों को और अपनों को खिला-पिला पाऊं, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से हैडलोड की गाड़ी में मिलावट का दूध देखा था। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूती से कदम उठायेगी।

सभापति महोदय, किसानों को लेकर अलग बजट की बात राजस्थान की सरकार ने की। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की सरकार किसानों के लिए डेयरी में, डिग्गी में, किसानों के खालों में, किसानों के बारानी क्षेत्र को नहरी करने में, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में और नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए तेजी से काम करेगी। इससे प्रदेश का किसान मजबूत होगा।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने 11 हजार करोड़ रुपये खरीद में कम किये हैं। हमारे सामने अभी सरसों और चने की फसल आयेगी। सरसों और चने की फसल के समय जब हम सरकारी खरीद में उतरेंगे तो किसान कल्याण कोष में मुख्य मंत्री महोदय ने एक हजार करोड़ से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपये करने का प्रण लिया है, उससे अनाज मण्डियों को और मजबूत करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा किसान की जो फसल पैदा होगी, उसको तौलने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने सरकारी तंत्र को मजबूत करने की बात की। मेरे विधान सभा क्षेत्र समेत पूरे राजस्थान में 3,860 स्कूल दसवीं से सीधे बारहवीं कर दिये। दसवीं से बारहवीं किये स्कूलों में छात्रों की 20 प्रतिशत संख्या भी बढ़ी है। अगर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो आप ताज्जुब करेंगे कि स्कूल क्रमोन्नत करने के बाद और माहौल बनने के बाद एक साल में 23 हजार से 39 हजार नामांकन हुए हैं। यह नामांकन की वृद्धि इसलिये हुई कि अब सरकारी स्कूलों की तरफ

(श्री बलवान पूनियां)

सरकार ने ध्यान दिया। लोगों का ध्यान भी गया है। कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हुआ है। नहीं साहब, कोरोना की वजह से तो सरकारी धन्धे चौपट हुए थे। यह ऊंचा इसलिये हुआ, क्योंकि सरकारी एल्युमिनी मीट के माध्यम से ग्रामीण स्कूलों में गये हैं। बच्चे स्कूल में इसलिये गये हैं, क्योंकि आपने भर्ती की है। बच्चे इसलिये स्कूल में गये हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल के प्रति विश्वास जगा है। आपने जो 3,860 स्कूल क्रमोन्नत करने की घोषणा की है, उसमें हर विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच एग्रीकल्चर और पांच-पांच विज्ञान विषय खोलने के लिए भी मुख्य मंत्री जी पूरक बजट में घोषणा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसमें जो लैक्चरर, जिनके जिम्मे स्कूलों को मजबूत करना है, वसुन्धरा जी के समय में वेतनमान में कटौती की गयी थी, आपके 2012-13 में वेतन बढ़ाने के बाद, तब आप स्कूल लैक्चरर को भूल गये थे, मैं उम्मीद करता हूं कि स्कूल लैक्चरर की वेतन वृद्धि भी आप वापस बहाल करने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी ध्यान देंगे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, थोड़ा-सा टाइम तो दें। पांच मिनट दे दें, मैं पांच मिनट में सारी बात कह दूंगा।

श्री सभापति: आप दस मिनट बोल चुके हैं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मुझे पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री आवास योजना में केसीसी का हर्डल आया हुआ है। सभापति महोदय, जिस किसान के पास केसीसी है उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। केसीसी की हर्डल हटाकर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा दिलाया जाये। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि दस लोगों को एनएफएसएस से जोड़ेंगे, साहब, 2020 के बाद पोर्टल बन्द है। उस पोर्टल को खुलवाकर खाद्य सुरक्षा का फायदा दिलवाने का काम करें।

सभापति महोदय, जिन बुजुर्गों के बेटे और बेटियां नौकरी में हैं उन बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, उनको पेंशन दिलायी जाये। सभापति महोदय, मैंने कभी मेरे पिता जी की मांग नहीं उठायी। मेरे पिता जी मांग करते हैं कि मुझे विधुर पेंशन दिलवा। मेरे मां नहीं है। मैं सदन में मांग करता हूं कि विधुर पेंशन भी दी जाये। वे कह रहे हैं कि एक रुपये ही दिलवा दो, हम भी रजिस्ट्रेशन में आ जायें। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि

(श्री बलवान पूनियां)

विधुर पेंशन भी शुरू की जाये। बापू बार-बार कहते हैं कि तू मेरी बात कभी नहीं करता।

सभापति महोदय, हमारे इलाके में कैंसर फैल चुका है। मेरी मां भी कैंसर से मरी थी। यह बीमारी बड़ी पीड़ादायक होती है। संयम जी सही कह रहे थे कि घर खतम हो जाता है और हम उस जीव को भी नहीं बचा पाते हैं। कितनी मेहनत, कितनी सेवा, डाक्टरों ने खूब मदद की, नवार्टिस कम्पनी का एक इंजेक्शन था, जो कि 4 हजार पर-डे के हिसाब से था, वह साढ़े चार साल लगा, लेकिन हाथ नहीं लगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जिस तरीके से हैल्थ पर ध्यान दिया है, हर जिला हैडक्वार्टर पर आपने रिसर्च सेन्टर खोलने का फैसला है, उस रिसर्च सेन्टर की वैन हर विधान सभा क्षेत्र में जाये, हर तहसील में जाये और कैम्प करें। जिस तरीके से अमरीका में कैंसर को रोकने के लिए, अमरीका में कैंसर महामारी है, वहां रोकने के लिए वे प्राइमरी स्टेज पर जांच करते हैं जिससे आदमी दस-बीस साल जी लेता है। इसलिए इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। मेरी सीएचसी पर हमने एक करोड़ रुपये सीएचसी को मजबूत करने के लिए, आदर्श सीएचसी बनाने के लिए खर्च किये हैं। हमने पहले एम.एल.ए. लैड से भी 27 लाख रुपये उसमें खर्च किये हैं। कोरोना में हमने अलग-अलग चीजें दी हैं। दानदाताओं ने भी मदद की है, इसलिए 100 बैड करने की हम मांग करते हैं।

राजस्थान पशु धन सेवा केन्द्र में जो कर्मचारी 2002-03 से लगे हुए हैं, जो मुख्य मंत्री जी के पहले कार्यकाल से लगे हुए हैं उनको नियमित करने की हम मांग करते हैं। जनता जल योजना में जो कर्मचारी लगे हैं, उनके स्थायीकरण की मांग करते हैं। मांग करते हैं कि जल जीवन मिशन में जो आप हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, आपने संकल्प लिया है कि हर घर में पानी, हर घर में ठंडा व मीठा जल जायेगा। महोदय, मैंने तो इससे आगे की बात की, पीतल वाली टूंटी लग भी गई। बहुत जगह काम तेजी से शुरू हो गया। एस आर उगनी शुरू हो गयी। ऊंची-ऊंची एस आर, ऊंची-ऊंची डिग्गियां, पाइप लाइनें बिछ रही हैं। गांव-गांव में पानी जाना शुरू हो गया है, इसलिए जनता जल जीवन मिशन में जो लोग काम में लगे हैं, उनको स्थायी नियुक्त कीजिए।

सभापति महोदय, मैं सरकार के एक फायदे की बात और करना चाहता हूं जिससे सरकार को फायदा होगा। सब लोगों को राजनीतिक

(श्री बलवान पूनियां)

नियुक्तियां दी गयीं। इधर वाले साथी कई बार डायलोग भी मारते थे कि राजनीतिक नियुक्तियां नहीं दी गयीं। सब लोगों को नियुक्ति दी गयी लेकिन राजस्थान की सरकार सिख समुदाय को भूल गयी। गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, मेरी विधान सभा क्षेत्र में सिख समुदाय के लोग हैं। उनका प्रतिनिधित्व हो।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, नि:शुल्क जांच योजना में और नि:शुल्क दवा वितरण योजना में जो कर्मचारी लगे हुए हैं जिन्होंने कोरोना में सबसे ज्यादा काम किया। इसमें जो कम्प्यूटर के संगणक लगे हुए थे, सबसे ज्यादा काम किया, इनके स्थायीकरण की और जब तक स्थायीकरण नहीं हो, तब तक इनका मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने की मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, स्टेनोग्राफर और संगणक की भर्ती जो 2018 में आयी थी, उनके पद बढ़ाने की मांग करता हूं क्योंकि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने सारी भर्तियों में पद बढ़ाए हैं। ये दो स्टेनोग्राफर की भर्तियां आठ-आठ, दस-दस साल बाद आती हैं। उसके पद बढ़ाने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, छोटी-सी बात और रह गयी। ऊंट-बछड़ों की खरीद-फरोख्त का मसला है। मेरे गोगामेड़ी में मेला चल रहा है। जो मेला सर्दियों में लगता है, उस समय ऊंट आते हैं, पूरे राजस्थान से ऊंट आते हैं। ऊंट की नस्ल खतम हो जाएगी। पता नहीं दिल्ली से कौन फोन कर रहा है? ऊंट वाले डर जाते हैं कि साहब ऊंट नहीं बेचने। ऊंटों के प्रसंस्करण के लिए, ऊंटों के संवर्द्धन के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। ऊंट खतम हो जाएंगे। नागौर का मेला खतम होने से बछड़े खतम हो गये, गाय की कीमत कम हो गयी।

श्री सभापति: विराजिए। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, एक छोटी-सी बात और रह गयी। विकलांगों, विधवाओं, वृद्धजनों की पेंशन बढ़ाने की मांग करता हूं। साथ ही जो मेरे कालेज खोले और पूरे राजस्थान में कालेज खोले, उसके लिए मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि बहुत बड़ा फैसला 123 कालेज खोलना, एक्सट्रीमली फैसला है, लेकिन इसमें स्टाफ लगाने की जरूरत है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए। श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, आपने मेरी बात रखने का मौका दिया। बाकी अभी डिमांड पर बची हुई सारी बातें रखता रहूंगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 28)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 02 मार्च, 2022 को मध्याह्न पश्चात् 3:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार दिनांक 4 मार्च 2022 से बुधवार, दिनांक 16 मार्च 2022 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च 2022	1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार एवं पारण
	2. व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 पर विचार एवं पारण।
	3. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2021-22 का उपस्थापन।
	4. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2021-22 (द्वितीय संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान, पारण एवं तत्संबंधी विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2022 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 05 मार्च 2022	बैठक नहीं होगी।
रविवार, दिनांक 06 मार्च 2022	

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सोमवार, दिनांक 07 मार्च 2022	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
मंगलवार, दिनांक 08 मार्च 2022	
बुधवार, दिनांक 09 मार्च 2022	
गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2022	
शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2022	
शनिवार, दिनांक 12 मार्च 2022	बैठक नहीं होगी।
रविवार, दिनांक 13 मार्च 2022	
सोमवार, दिनांक 14 मार्च 2022	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2022	
बुधवार, दिनांक 16 मार्च 2022	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 16 मार्च, 2022 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।)

इसके उपरांत राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित किया जायेगा।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री सुरेश मोदी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का 2022-23 का जो मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किया गया बजट है, वह बहुत ही ऐतिहासिक है और शानदार है। मैं सत्ताधारी पार्टी का सदस्य होने के नाते ऐसा नहीं कह रहा हूं, अपितु एक चार्टर्ड एकाउंटेंट होने के नाते ऐसा कह रहा हूं। बिना नया टैक्स लगाए या बढ़ाए सभी वर्गों को राहत देकर एक विकासशील बजट राजस्थान को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का सार्थक प्रयास है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना, नरेगा में रोजगार के दिवस बढ़ाना, घरेलू बिजली के बिलों में छूट, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा राशि बढ़ाना, इसका दायरा बढ़ाना, दुर्घटना बीमा योजना का लाभ देना, सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार का इलाज मुफ्त करना, सभी जिलों में मेडिकल कालेज व नर्सिंग कालेज खोलना एवं चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के अनेक अन्य उपाय करना सरकार की जनता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का परिचायक है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, बालिका शिक्षा के लिए नए स्कूल व कालेज और अन्य स्कूल-कालेज खोलकर प्रदेश के नौजवानों को उत्तम शिक्षा देने का बेहतर प्रयास इस बजट में हुआ है।

युवाओं को खेल सुविधा बेहतर करने एवं रोजगार देने के लिए भी इस बजट में पूरा ध्यान दिया गया है। कृषकों के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर अलग से कृषि बजट पेश कर 11 मिशनों के तहत कृषि क्षेत्र के बहुमुखी विकास की शुरुआत राजस्थान से की गयी है। एस सी/एस टी, दिव्यांगों, सामान्य श्रेणी के गरीब परिवारों का भी पूरा-पूरा ध्यान इस बजट में रखा गया है। सड़कों का सुधार, पेयजल की व्यवस्था, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था भी मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में की है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उपाय, उद्योगों के विकास एवं खनन उद्योग के विकास हेतु भी इस बजट में प्रभावी प्रयास किये गये हैं ताकि सरकार को राजस्व एवं जनता को रोजगार के नये अवसर मिल सकें।

सभापति महोदय, इस बजट में हर वर्ग व क्षेत्र का भरपूर ध्यान रखा गया है, जिसका विस्तृत उल्लेख मेरे से पूर्व सदस्यों ने अपने भाषणों में किया है। मैं उनको न दोहराकर मेरे क्षेत्र की समस्याएं, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, सदन में रखना चाहता हूं।

(श्री सुरेश मोदी)

सबसे पहले मैं नीम का थाना क्षेत्र की बरसों पुरानी जिला बनाने की मांग पुरजोर शब्दों में दोहराना चाहता हूं। नीम का थाना अंग्रेजी हुकूमत एवं रियासत काल से आसपास के क्षेत्र का प्रशासनिक केन्द्र रहा है एवं यहां सेशन कोर्ट तोरावाटी के नाम से चलायी जाती थी जिसके अधीन खेतड़ी से लेकर शाहपुरा और बैराठ तक का क्षेत्र आता था। नीम का थाना जिला बनाने के सभी मापदण्ड पूरा करता है। वर्तमान में जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 90 से 135 किलोमीटर की है एवं यहां पर राज्य सरकार के काफी बड़े-बडे कार्यालय भी

(समय: 18.00 बजे)

कार्यरत हैं जैसे ए.डी.एम. कार्यालय, एडीजे-2, सिविल जज, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सी. टी. ओ., आयकर अधिकारी, एडिशनल एसपी, सीओ, तीन थाने ब्लाक स्वास्थ्य अधिकारी, 2 ब्लाक शिक्षा अधिकारी, 55 पंचायतें एवं 2 पंचायत समिति, तहसील, उप तहसील, नगरपालिका, 5 सरकारी कॉलेज, ट्रांसपोर्ट इन्सपेक्टर, जिला अस्पताल, जनाना अस्पताल, अनेक सीएचसी एवं पीएचसी, खेल स्टेडियम (निर्माणाधीन), सीडीपीओ कार्यालय स्थित हैं। महोदय, यहां पर बिजली विभाग के, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के एग्जिक्युटिव इंजीनियर सहित, अनेकों असिस्टेंट इंजीनियर के कार्यालय भी स्थित हैं। नीम का थाना चारों और से सड़क मार्ग से जुड़ा है एवं हरियाणा सीमा से लगता हुआ है। पूरे क्षेत्र से रेलवे लाइन एवं फ्रेट कोरिडोर गुजरता है। इसमें फ्रेट कोरिडोर के लोडिंग, अनलोडिंग के अनेकों स्टेशन हैं। यहां पर सीमेन्ट फैक्ट्री सहित अनेक बड़े एवं छोटे उद्योग हैं एवं बहुत बड़ा खनन क्षेत्र है। उसके साथ ही खनिज आधारित उद्योग, मिनरल ग्राइन्डिंग यूनिट, क्रेशर, मार्बल, कटिंग यूनिट कार्यरत हैं। यहां पर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अलावा प्राइवेट कालेज, बीएड कालेज, आईटीआई कालेज एवं अनेकों कोचिंग संस्थान एवं वाचनालय भी हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं। यहां प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय, आयुर्वेद चिकित्सालय, कृषि मण्डी, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम भी कार्यरत हैं।

नीम का थाना धार्मिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां बालेश्वर, बागेश्वर, गणेश्वर, टपकेश्वर जैसे धार्मिक स्थान हैं एवं पाटन व गुहाला के प्राचीन क़िले हैं।

महोदय, मैं अन्य राज्यों के जिलों की स्थिति आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। हरियाणा राज्य का गठन 01 नवम्बर,

(श्री सुरेश मोदी)

1966 को हुआ, उस समय उसमें 7 ज़िले थे। केवल मात्र 7 ज़िले। आज हरियाणा में 22 ज़िले हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल 44 हजार 212 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके विपरीत राजस्थान का गठन 1 नवम्बर, 1956 को हुआ, उस समय इसमें 26 ज़िले थे। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख 42 हजार 249 स्क्वायर किलोमीटर है, इसके बावजूद आज इसमें 33 ज़िले हैं। हरियाणा से पौने आठ गुना बड़ा राज्य, उसमें ज़िले हरियाणा से मात्र 25 परसेंट ज्यादा। इसको ध्यान में रखते हुए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस बजट में नीम का थाना को जिला घोषित कर, नीम का थाना की जनता को सौगात दें।

दूसरी लेकिन अधिक बड़ी मेरे क्षेत्र की मांग कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के द्वितीय फेज का काम शुरू कराने की है। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले कई सालों से, वर्षा कम होने के कारण जल स्तर एक हजार फिट से भी नीचे चला गया है। इतनी गहराई के बाद जो पानी आता है, उसमें फ्लोराइड व टीडीएस की मात्रा बहुत अधिक होती है जिससे लोगों के शरीर में, जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियां फैल रही हैं। पुराने बोरिंग फेल हो गये हैं। हैण्डपम्प नकारा हो गये हैं। जल जीवन मिशन में खोदी जा रही बोरिंग भी या तो सूखी जा रही हैं या पानी कम आ रहा है, जिससे इस योजना में भी मेरे क्षेत्र में पानी की कमी रहने की सम्भावना है।

नलकूप एक हजार गहराई से भी ज्यादा होने के कारण उनमें डिस्चार्ज कम व गुणवत्ता खराब पाई जायेगी। विद्युत भार भी बढ़ेगा अन्यथा आने वाले समय में पेयजल का दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण जनता को यहां से पलायन करना पड़ेगा। यह समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही नहीं, सीकर ज़िले की 5 और विधान सभा क्षेत्रों की है, 2 झुन्झुनूं ज़िले के विधान सभा क्षेत्रों की है। अत: इस समस्या की गम्भीरता को समझते हुए, अतिशीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय बैठे हैं, इनके विधान सभा क्षेत्र में भी यही स्थिति है।

जल जीवन मिशन में सीकर ज़िले के 8 विधान सभा क्षेत्रों में नलकूप निर्माण हेतु, साइट सलेक्शन हेतु, एक ही कनिष्ठ भू-वैज्ञानिक पदस्थापित है। अत: कार्य समय पर पूरा करने के लिये एक पद और सृजित किये जाने की महती आवश्यकता है। ऐसे हालात में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के द्वितीय फेज का कार्य किया जाकर ही हो

(श्री सुरेश मोदी)

सकता है। महोदय, गहलोत जी के पिछले कार्यकाल में प्रथम चरण का कार्य पूरा किया गया था। द्वितीय चरण को स्वीकृत किया गया था, जल का बंटवारा दोनों चरणों के लिये स्वीकृत किया गया था। 2021-22 के बजट में मुख्य मंत्री जी ने, द्वितीय चरण के कार्य स्वीकृति 7,500 करोड़ की करके कार्य चालू करवाने का संकल्प भी दोहराया था। अब एक साल बाद नीम का थाना क्षेत्र की जनता यशस्वी मुख्य मंत्री जी की ओर निहार रही है कि इस बजट में इस योजना के लिये बजट देकर कार्य शुरू करवाये। अधिक देरी होने से जो पानी द्वितीय फेज के लिये स्वीकृत है, उसका मिलना मुश्किल हो जायेगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): साहब, दो मिनट और दीजिये। अत: कुम्भाराम लिफ्ट योजना को अवश्य बजट दिया जाकर, धरातल पर इसका काम शुरू करवाने की कृपा करें।

महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है एवं पथरीला भी है। यहां पर सड़कों की बहुत कमी है। आपने सड़कों के लिये बजट में प्रावधान किया है, लेकिन मेरे क्षेत्र में कुल मिलाकर मैंने 60 सड़कों की, लगभग 140 करोड़ रुपये की मांग की है, अत: उसमें जितना सम्भव हो और देने की कृपा करें।

पीएचसी व नये स्वास्थ्य केन्द्र के लिये, आपने क्षेत्र में नई सीएचसी खोलने की घोषणा की है, जो काफी कम है। मेरे क्षेत्र में मुझे 3 सीएचसी सिरोही, चला एवं हसामपुर में आवश्यकता है। 6 पीएचसी कोटड़ा, पुरानाबास, बिहार, दरीबा आदि स्थानों पर आवश्यकता है। अत: निवेदन है कि इनकी भी घोषणा करें। मेरे क्षेत्र में पाटन बड़ा सम्भाग है। यहां पर प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टि से पीएचईडी का सहायक अभियन्ता कार्यालय होना बहुत आवश्यक है। इसे खोलने का कष्ट करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): साहब, एक मिनट और। मेरे क्षेत्र में मावण्डा खुर्द में नई पुलिस चौकी एवं डाबला में नये पुलिस थाने की आवश्यकता है, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की सुविधा मिलेगी। अत: इसकी भी घोषणा करें।

(श्री सुरेश मोदी)

मेरे क्षेत्र में कई पंचायतों का सहायक अभियन्ता विद्युत का कार्यालय कांवट में लगता है, जो बहुत दूर पड़ता है। मैंने इस कार्यालय को अथवा नया कार्यालय चला में खोले जाने का प्रस्ताव किया है। कृपया उसे एवं एक नया कार्यालय जीलो में और खोला जाये। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा बजट दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि...

श्री सभापति: श्रीमती शोभा चौहान।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): साहब, एक मिनट और। कई रेवेन्यू गांव ऐसे हैं, जो पंचायत मुख्यालय से दूर हैं एवं वहां भी उच्च प्राथमिक को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जाना आवश्यक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हेमराजपुरा, छापर, खातियों की ढाणी, नई कोठी, जोडली, सालावाली में इस तरह क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा में प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय ढाणी बावतान को उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत करने का कष्ट करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): इसी प्रकार नये विद्यालय, औद्योगिक क्षेत्र नगरपालिका एवं ढाणी राज़ी आगरी में खोलने की आवश्यकता है। पिछली सरकार ने जो स्कूल बन्द किये थे, उनमें से कुछ को वापस चालू किये जाने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: अब डिमाण्ड पर बोलना। प्लीज सहयोग करें, समाप्त करें। श्रीमती शोभा चौहान।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): धन्यवाद।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): आदरणीय सभापति महोदय जी, आपने सदन में मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 226 बिन्दुओं का बजट पेश किया, वह सरकार के मायने में समृद्ध व खुशहाल राजस्थान की सोच वाला बजट है। जिस तरह का बजट पेश किया गया, सरकार ने मानस बना लिया है कि आगामी 20 साल तक सत्ता में नहीं आयेंगे। मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूं कि हम भी आपको नहीं आने देंगे।

(श्रीमती शोभा चौहान)

महोदय जी, जनता तो प्यास से मर रही है। पाली ज़िले में अभी यह भयानक स्थिति है। जरा सोचिये, भीषण गर्मी में क्या हाल होगा। जवाई बांध में निर्भरता हटाने हेतु दातीवाड़ा फीडर से, इस सरकार ने 2021 के बजट में घोषणा की थी, लेकिन धरातल पर काम जीरो है। इस योजना से सोजत की 15 पंचायतें, जो अभी गंदा, बदबूदार, खारा पानी पीने के सहारे, इस योजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र की जनता हिमालय का पानी पी सकेगी, लेकिन यह सरकार तो हवाई बातें करती है। हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया, जबकि मूर्तरूप में कुछ भी नजर नहीं आता है। जनता को जल तो शुद्ध पिलाओ, यह बीड़ा भी मोदी सरकार ने उठाया है। घर-घर पानी पहुंचाने का काम, आप लोग नहीं कर सकते हो तो जन सेवा में सहयोग करें। क्या आपने अपने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि जनता प्यासी मरे तो मरने दो, शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराना है?

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार राजस्थान में सुशासन स्थापित करने में कितनी सफल रही है, यह अन्दाजा तो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आये दिन महिला उत्पीड़न, दलित अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। आज राज्य में बहिन/बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं लेकिन आप यह दावा करते हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा हेतु यह किया जा रहा है, वह किया जा रहा है और आपके खोखले दावों के चलते महिलाएं आये दिन हादसों का शिकार होती जा रही हैं। तैयार रहिये कि समय आने पर राजस्थान की महिलाएं अपनी शक्ति का परिचय देंगी।

माननीय सभापति महोदय, प्रति वर्ष बजट को बढ़ाकर पेश किया जाता है। मैं इसलिए कह रही हूं कि विगत बजट में जो घोषणाएं की गयी थीं उन पर कितना अमल हो पाया है, यह पूरा राजस्थान जानता है। उनमें वे एक भी बड़ी घोषणा पूरी नहीं कर पाये हैं। चाहे वह नन्दीशाला की हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की हो अथवा किसानों के कर्ज माफी की घोषणा हो। किसानों की कर्ज माफी तो दूर, यह सरकार किसानों के घरों की नीलामी में लगी हुई है। चुनावों से पहले आपके नेता राहुलजी ने किसानों का कर्जा एक से दस दिवस के भीतर माफ करने का असत्य पुलिंदा पकड़वाया था। उसी असत्य दिलासा से किसान अपने को आज तक ठगा-सा महसूस कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यही हाल इस बजट का भी होने वाला है। प्रत्येक किसान का दो लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने के बजाय सरकार किसानों के घरों को कुर्की करने में लगी हुई है वहीं दूसरी ओर इसी बजट में

(श्रीमती शोभा चौहान)

अलग से कृषि बजट का जो झुनझुना पकड़ा दिया, इससे किसानों को ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है।

सरकार की कार्य मंशा तो इससे जाहिर होती है कि किसानों के लिए दुर्घटना एवं जीवन बीमा के लिए भी अभी तक कम्पनियों से एम.ओ.यू. नहीं कर पाये हैं। भगवान न करे यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार इस योजना के लाभ से वंचित रह जायेगा, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? माननीय सभापति महोदय, जनता इनके काम का तरीका देख रही है। किसान व्यथित, ठगा-सा है, इनकी करतूतों को आगामी समय में ब्याज सहित लौटायेगा।

सोजत में किसानों को फसल बीमा का क्लेम नहीं दिया जा रहा है। इन किसानों का क्या दोष है? आपने तो वसुन्धराजी के सरकार की जनोपयोगी योजनाएं अपना खेत आपका काम योजना और गरीब पशुपालकों हेतु चलाई गयी कैटल फीड जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को समाप्त कर दिया। पशुपालकों की उन्नति इस सरकार से देखी नहीं गयी इसलिए इन योजनाओं को बन्द कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इस बार बजट में सोजत का जिक्र तक नहीं किया गया है। खैर, कोई बात नहीं है लेकिन आपने जो ट्रोमा सेंटर की घोषणा विगत बजट सत्र में की थी इसके लिए अभी तक नींव का पत्थर भी नहीं लग पाया है। ब्यावर से पाली के मध्य आपातकालीन चिकित्सा सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार को कई बार अवगत कराया है कि हमने ट्रोमा सेंटर हेतु विभाग को जमीन सुपुर्द कर दी लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

इनकी बजट घोषणाओं का भी अमल नहीं हो रहा है तो दूसरे विकास कार्य तो कोसों दूर हैं। मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि आपको परेशानी भा.ज.पा. विधायक से हो सकती है लेकिन जनता से थोड़े ही है। आप चिकित्सा सुविधा की डींग हांकते हैं पर सरकारी चिकित्सालयों में डाक्टर्स, नर्स और अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह है कि आप सरकारी चिकित्सालयों का ढांचा सुधारें। यूं बजट में असत्य घोषणाओं के पुलिंदे नहीं बनायें और सोजत में ट्रोमा सेंटर का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायें।

माननीय सभापति महोदय, ई-श्रमिक कार्ड योजना में वसुन्धराजी के सरकार के समय कार्डधारी की बेटी की शादी पर 55 हजार रुपये की सरकारी

(श्रीमती शोभा चौहान)

सहायता प्रदान की जाती थी। इस सरकार ने कितनी बेटियों को यह राशि प्रदान की है? पूरे प्रदेश में एक भी बेटी को इस सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी?

माननीय सभापति महोदय, मगरा विकास बोर्ड द्वारा मगरा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के विकास हेतु वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती थी लेकिन डींग हांकने वाली सरकार ने तीन वर्षों में मगरा क्षेत्र के विकास हेतु एक धेला भी नहीं दिया जबकि मगरा क्षेत्र में गरीब तबके के पशुपालक किसान निवास करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करती हूं कि मेहरबानी करके मगरा विकास हेतु कार्य प्रारम्भ करें मगरा क्षेत्र के लोगों को राजनीति में मत बांटिये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): किसी सरकार ने अगर काम किया है तो बी.जे.पी. सरकार में मगरा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के काम हुए हैं। आप कम से कम इनके लिए थोड़ा सा करके दिखाइये।

माननीय सभापति महोदय, यह विचार आता है कि इन्होंने सोजत विधान सभा क्षेत्र के लिए बजट को दरकिनार कर दिया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि सोजत जनविहीन है क्या? आपने सोजत के लिए एक भी काम नहीं जोड़ा और सोजत क्षेत्र में शहर के अन्दर सीवरेज की व्यवस्था भी नहीं है। इस सरकार द्वारा विगत बजट में प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक किलोमीटर विकास पथ के निर्माण की घोषणा की थी। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि पूरे प्रदेश में कितनी दूरी पर विकास पथ का निर्माण करवाया गया है? मैं सदन को यह बताना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पचास ग्राम पंचायतों में एक भी पथ का निर्माण नहीं हुआ है। पथ तो दूर की बात, ग्रेवल सड़क भी नहीं है। क्या यह इनका खुशहाल और समग्र राजस्थान का मॉडल है? यदि इनका ऐसा मानना है तो मैं पुरजोर शब्दों से ऐसे बजट की निंदा करती हूं। फिर से मैं यह बात दोहरा कर अपनी वाणी को विराम देती हूं कि यह बजट असत्य घोषणाओं का पुलिंदा मात्र है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हीराराम।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सौंफ की विशिष्ट मण्डी की घोषणा की। यह मण्डी राजस्थान में दूसरे नम्बर की मण्डी है इसलिए यहां किसानों को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पीपाड़ के लिए 597 लाख रुपये पानी के पाइप सारे चेंज करने के लिए दिये, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं और कापरड़ा में नया थाना खोलने की भी घोषणा की है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटनारहित सड़क के रूप में बर-बिलाड़ा (जोधपुर) एन.एच. 25 के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में प्रत्येक विधायक को सड़क के लिए पांच करोड़ रुपये दिये गये थे और इस बार उसको बढ़ाकर दस करोड़ रुपये कर दिये हैं। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार। यह सारे ही विधायकों के लिए है, कोई भेदभाव की बात नहीं है, सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब ही ऐसा कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में शारीरिक शिक्षा विद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन तथा खेल विभाग के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, राजस्थान हाई परफोरमेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेब्लिटेशन सेंटर की स्थापना, इन दोनों हेतु 25 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

महिलाओं के लिए पृथक से चिह्नित कर W-Hub में मुख्य मंत्री वर्क फ्रोम होम जोब वर्क योजना प्रारम्भ की, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

(श्री हीराराम)

माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने इस ऐतिहासिक बजट में एस.सी., एस.टी. विकास कोष की राशि 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये की घोषणा की, इससे अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

शहरी क्षेत्रों एवं बड़े कस्बों में जरूरतमंद मजदूरों के लिए इन्दिरा रसोई योजना की संख्या 358 से बढ़ाकर एक हजार किये जाने की घोषणा की, जिससे मजदूरी करने वाले लोग, सड़कों पर रहने वाले लोग और गरीब तबके को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में भी स्कूटियों की संख्या दो हजार से बढ़ाकर पांच हजार करने की घोषणा की, उसमें दिव्यांगों को बहुत फायदा मिलेगा।

राजस्थान में अजमेर, उदयपुर इस प्रकार की कई सिटीज को पहले बी.जे.पी. के राज में स्मार्ट सिटी की घोषणा कर दी थी लेकिन जोधपुर के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया। सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जोधपुर सम्भाग को स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित करके बहुत बड़ी लोगों को राहत देने की घोषणा की, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री का बहुत-बहुत आभार।

सैनिक कल्याण भवन हेतु 20 करोड़ रुपये की घोषणा भी की है। सबसे एक बड़ा तोहफा जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिया, उसके लिए कर्मचारी आज भी नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं और खुशी का माहौल पूरे घर-घर में है, जिसमें 01 जनवरी, 2004 और उसके पश्चात् जो नियुक्ति की है, इन समस्त कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना जो लागू की है उसके लिए बहुत-बहुत आभार। आज करीबन सप्ताह भर हो गया मुख्य मंत्रीजी के वहां लोगों का जमावड़ा बधाई देने के लिए लगा हुआ है।

समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान का सपना साकार करने के लिए प्रदेश का पहला ऐतिहासिक कृषि बजट में आधुनिक खेती से कृषकों की आय एवं आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना प्रारम्भ करने की जो घोषणा की, उससे किसानों में बहुत खुशी है और खुशी का माहौल है।

राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन

(श्री हीराराम)

तारबन्दी में जो पहले समूह के रूप में तारबन्दी दी जाती थी, समूह में तीन लोग होते थे, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उनको हटाकर इन्डिविजुअल तारबन्दी का कर दिया है। उसके लिए किसानों में खुशी का माहौल है।

सभापति महोदय, ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना में भी किसानों को राहत मिली है। उसके लिए भी किसान खुशहाल हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करते हैं।

दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए पिछली भाजपा सरकार आयी, उस समय उनके मुख्य मंत्रीजी ने 2 रुपये प्रति लीटर दिए हुए थे। भाजपा सरकार ने घोषणा की थी कि हम 2 रुपये के 4 रुपये कर देंगे लेकिन उन्होंने वह 2 रुपये भी बन्द कर दिये और जब वापस अशोक गहलोतजी की सरकार आयी तो 2 रुपये के 5 रुपये कर दिये। इससे किसानों को बहुत राहत मिली। किसान हर्षोल्लास के साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट कर रहे हैं। इससे काफी किसानों को राहत मिली है।

सभापति महोदय, मैं कुछ मांगें मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए करना चाहता हूं। ग्राम पंचायत जालेली फौजदार में प्रशासन गांवों के संग कार्यक्रम में मुख्य मंत्रीजी की मौजूदगी में ग्रामीणों ने मांग रखी थी कि दातीवाड़ा प्रोजेक्ट की मेन पानी की पाइपलाइन जो माणकलाव से आ रही है, इस पाइपलाइन के बीच में ग्राम देवलिया पड़ता है, यहां से जालेली फौजदार तक बड़ी पाइपलाइन जोड़कर जालेली फौजदार में पानी का बड़ा हौद बनाने की स्वीकृति प्रदान करावें। उसमें कुल 16 गांव जालेली फौजदार, जालेली आहीचा, कानावास का पाना, बासनी, निकुबा, आनन्द नगर, काकेलाव, पीथावास, रुडकली, जालेली चम्पावता, फिटकासनी, जम्भेश्वर नगर (काकेलाव), जाटीयावास, डोलिया, खंगार, बापूनगर, रसीदा फिटकासनी को मीठा पानी देने की स्कीम बनाकर पीएचईडी के अधिकारियों ने माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय में भेज दी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन गांवों को पानी पिला कर राहत दें।

सभापति महोदय, नगरपालिका बिलाड़ा में खारा पानी आ रहा है और खारा पानी पिलाया जाता है जबकि हाल ही में बिलाड़ा के बाद में सोजत पड़ती है, उसकी स्कीम मीठा पानी पिलाने की कर दी गयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बिलाड़ा में मीठा पानी पिलायें ताकि लोगों में बीमारी नहीं हो।

(श्री हीराराम)

नगरपालिका बिलाड़ा में सीवर लाइन बिछाने का कार्य इस बजट में शामिल करावें। नगरपालिका पीपाड़ शहर में सीवर लाइन बिछाने का कार्य बजट में शामिल करावें।

पीपाड़ शहर में सीडीपीओ कार्यालय की स्वीकृति प्रदान करावें। सीडीपीओ कार्यालय यहां से भोपालगढ़ चला गया। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि पीपाड़ शहर में यह खोलने की कृपा करें।

सभापति महोदय, हमारे 11 गांव जो उदलियावास, पिचियाक, जसवन्तपुरा, बड़ी कल्ला, बीजासनी, जेलवा, खारिया मीठापुर, बिजवाड़िया, हर्ष और बरना, ये गांव बिलाड़ा की सीमा में चले गये हैं। इनको नगरपालिका बिलाड़ा पेरीफेरी में ले लिया गया है तो मैं निवेदन करूंगा कि ये जो रेवेन्यू ग्राम हैं, इन गांवों में जो भी इनकम होती है, वह नगरपालिका लेती है इसलिए इन राजस्व ग्रामों का विकास नहीं हो सकता। ये गांव अपने आप में विकास कर सकें, मेरा आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन गांवों को बिलाड़ा नगरपालिका की सीमा से बाहर निकालें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): सभापति महोदय, डांगियावास, बुचकला व कुकण्डा में पीएचसी खोलने व डांगियावास में उप तहसील खोलने की कृपा करावें।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): भावी, भटीण्डा, बिसलपुर, खेजला में सीएचसी खोलने की मांग करता हूं। फिटकासनी में महिला कालेज खोलने की मांग करता हूं। बोरून्दा में आदर्श सीएचसी चालू करने व थाना बनाने का बजट अलाट करने की मांग करता हूं। कापरड़ा में उप तहसील बनाने व पीएचसी बनाने की मांग करता हूं। बिलाड़ा में एग्रीकल्चर कालेज खोलने की मांग करता हूं। वहां पर 80 बीघा जमीन एग्रीकल्चर की पड़ी हुई है। पलासनी में असामाजिक तत्वों का हमेशा बोलबाला रहता है इसलिए पुलिस चौकी खोलने की मांग करता हूं। जैतिवास में 33 केवी जीएसएस खोलने की मांग करता हूं। लाम्बा पंचायत में स्टेडियम बनवाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट

(श्री जोराराम कुमावत)

भाषण 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्य मंत्रीजी ने तीन घंटे का बजट भाषण दिया, 23 तारीख को प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से बजट सरकार का आईना होता है और बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने खूब घोषणाएं कीं तथा खूब वाहवाही लूटी लेकिन जब तक वह धरातल पर घोषणाएं नहीं उतरेंगी तब तक जनता का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। सड़कों की घोषणा इस बजट में बहुत कम हुई है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में पाली से डेंडा कूरना, पादरड़ा होते हुए गुढ़ा प्रताप सिंह सड़क बिलकुल क्षतिग्रस्त है। मनिहारी से डेरी सड़क बिलकुल क्षतिग्रस्त है। बाली, पिण्डवाड़ा स्टेट हाईवे से जवाई बांध, सुमेरपुर, तखतगढ़ रोड, जहां पर ट्रैफिक खूब ज्यादा है, को स्टेट हाईवे घोषित करने का श्रम करें। तखतगढ़ से कोसीलाव, खीमाड़ा, खांगड़ी, विरानी ढाणी, रानी रोड तक सड़क एमडीआर में निर्माण करवाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 से जवाली होते हुए स्टेट हाईवे 67 तक सड़क को चौड़ी करके एमडीआर घोषित करवाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, सुमेरपुर बहुत बड़ी व्यावसायिक मण्डी है। पाली, जालौर और सिरोही के लोग सुमेरपुर में आते हैं। वहां का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उसको क्रमोन्नत करके जिला अस्पताल बनाने की आवश्यकता है। सिंदरू, रूपावास, दुजाना उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता है। साण्डेराव में नेशनल हाईवे पर ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत कराने की आवश्यकता है। पाली और सिरोही के बीच की कुल दूरी 130 किलोमीटर है और 130 किलोमीटर के बीच में कहीं भी ट्रोमा सेन्टर नहीं है। साण्डेराव नेशनल हाईवे पर ट्रोमा सेन्टर हो जाए तो दुर्घटना में लोगों को मदद मिलेगी।

खौड़ व मनिहारी के ज्यादातर क्षेत्रों में क्राइम ज्यादा होते हैं तो वहां की पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करके नया थाना खुलवाने की आवश्यकता है। साण्डेराव को उप तहसील करवाने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत मुख्यालय सिन्दरू और बांकली में आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत कराने की आवश्यकता है। गुढा पन्दला और डेंडा में 33 केवी जीएसएस स्वीकृत कराने की आवश्यकता है। खांगड़ी से बांगड़ी के बीच नदी पर और पावा से भासुन्दा के बीच नदी पर बरसात के मौसम में करीब 3-3 महीने तक रास्ते बन्द रहते हैं तो वहां पुल बनवाने की आवश्यकता है।

(श्री जोराराम कुमावत)

सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र सुमेरपुर और तखतगढ़ में गवांई तालाब बहुत बड़ा तालाब है, उसका सौन्दर्यीकरण करवाने की आवश्यकता है। सिन्दरू गांव पर आरडी 61,500 से सिन्दरू बांध तक कच्चा फीडर बना हुआ है, वहां पर नहर का पानी डैम के अन्दर डालते हैं तो किसानों के खेतों की कटाई होती है इसलिए उसे पक्का करवाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, इसमें कई पहलू छोड़ दिये गये हैं। पैरा संख्या 25 में राज्य के 3,820 सैकण्डरी स्कूल्स को क्रमोन्नत किया, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन, सभापति महोदयजी, एक-एक ग्राम पंचायत में चार-चार, पांच-पांच गांव होते हैं और पांच गांवों में वहां माध्यमिक स्कूलें नहीं हैं, वहां उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। वहां की जो छात्राएं हैं, उनको हैडक्वार्टर तक पांच-सात किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है तो यदि इस बजट में उन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय करने की घोषणा होती, तो निश्चित रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलने में मदद मिलती।

माननीय सभापति महोदयजी, इस बजट में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, दीपक, ईंटें, घरेलू सामान बनाने वाले कुटीर व घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये इस बजट में राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है। राज्य सरकार का ध्यान इनकी तरफ गया ही नहीं है। मिट्टी की मूर्तियां, बर्तन, दीपक, ईंटे और घरेलू सामान जब कारीगर बनाते हैं तो कई बार बरसात आ जाती है। सारा सामान गीला होकर गल जाता है। किसानों को जिस तरह से फसल बीमा करवाने का जो प्रावधान है और उनको राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा देने का जो प्रावधान है, उसी तरह से ऐसे कुटीर उद्योगों और घरेलू सामान बनाने वालों के लिये भी प्रावधान किया जाये तो निश्चित रूप से इन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने में मदद मिलती।

इस बजट में असंगठित मजदूर, मण्डी और बाजारों में हम्माली करने वाले हम्मालों को सरकार की किसी योजना का फायदा नहीं मिलता। मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन हम्मालों के लिये अलग से हम्माल मजदूर बोर्ड बनाकर इन्हें राहत देने का सरकार काम करे तो निश्चित रूप से इनका जीवन स्तर भी सुधरने में मदद मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था हमेशा

(श्री जोराराम कुमावत)

खराब रहती है और करीब-करीब पंचायतों के पास में बजट भी नहीं होता, जिससे वह सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। मुख्य मंत्रीजी ने अभी जैसे 100 दिन से 125 दिन नरेगा में किये हैं, तो यदि मुख्य मंत्रीजी ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिये नरेगा में प्रावधान करवा दे और सफाईकर्मियों को उसमें लगाने की व्यवस्था करवा दे तो निश्चित रूप से इन पंचायतों को भी फायदा होता।

संविदाकर्मियों को परमानेंट करने के लिये सरकार ने पहले भी घोषणा कर रखी है, लेकिन इस बजट में संविदाकर्मियों को परमानेंट करने का कोई प्रावधान नहीं रखा है। यदि उनका प्रावधान रखे तो निश्चित रूप से उनको भी राहत मिलेगी। आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय बढ़ाने के लिये भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

माननीय सभापति महोदयजी, सुमेरपुर-पाली जिले में लगातार अकाल पड़ रहा है और इस बार भयंकर अकाल है। जवाई बांध में बिलकुल पानी नहीं है। आज की तारीख में 500 एम.सी.एफटी. पानी बचा है और वह सिर्फ 15 दिन चलेगा। पिछले हर सत्र में बार-बार मैं और मेरे साथी विधायक मांग करते आये हैं कि जवाई बांध वर्षा आधारित बांध है, इस बांध में जब बरसात आती है तो ही पानी आता है, नहीं तो खाली रहता है। इस बांध से कई योजनाएं, जैसे सरकार ने पानी ले-जाने की बना रखी है। जवाई क्लस्टर प्रथम, सैकण्ड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से पूरे जिले को पानी देने की योजनाएं बना रखी हैं। हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं कि जवाई पुनर्भरण योजना वसुन्धरा जी ने उस समय बनायी थी, उसके लिये छह करोड़ की बजट घोषणा भी की थी, लेकिन वह योजना सरकार बदलते ही ठण्डे बस्ते में डाल दी थी। अब हमारी लगातार मांग के ऊपर सरकार ने बजट घोषणा तो की है, लेकिन वह भी आधी-अधूरी की है। तीन हजार करोड़ की घोषणा की है, पूरी घोषणा नहीं की है, तो मैं सरकार से मांग करूंगा आपके मार्फत, कि वह पूरी बजट घोषणा करे और तीन हजार की घोषणा की है, इसे भी जल्दी से जल्दी लागू करे, नहीं तो पूरे पाली जिले और आस-पास के क्षेत्रों में भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। पानी पीने के लिये भी नहीं मिलेगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि ये घोषणाएं, जो भी सुमेरपुर क्षेत्र में की हैं, जवाई पुनर्भरण की घोषणा है, तहसील बनाने की घोषणा है तख्तगढ़ को, कई और भी छोटी-मोटी घोषणाएं

(श्री जोराराम कुमावत)

हैं, यह घोषणाएं जल्दी से जल्दी पूरी करें। इसका कारण है कि पहले भी वर्ष 2019-20 और 2021-22 में जो घोषणा सरकार ने की थी..(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती रमीला खड़िया।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट, अभी तो बोलना ही शुरू किया है। सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, वे घोषणाएं भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। जनता पूछ रही है कि वह घोषणाएं कब पूरी होंगी? सरकार ने घोषणा की थी गौरव-पथ की तर्ज पर हर ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाने की, वह घोषणा पूरी नहीं हुई है। प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर नन्दीशाला बनाने की घोषणा की थी, वह घोषणा भी पूरी नहीं हुई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र खोलने की, वह घोषणा भी पूरी नहीं हुई है। प्रमुख देवस्थानों को डामर सड़क से जोड़ने की घोषणा की थी, वह घोषणा भी पूरी नहीं हुई है।

श्री सभापति: विराजिए। सहयोग करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): ग्राम पंचायत मुख्यालय से डामर सड़क से नहीं जुड़े गांवों को जोड़ने की घोषणा की थी, वह घोषणा भी पूरी नहीं हुई है। तख्तगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोला, लेकिन अभी तक उसके लिये जमीन आबंटित नहीं हुई है। सुमेरपुर में डी.टी.ओ. आफिस खोला, लेकिन अभी तक उसकी जमीन आबंटित नहीं हुई है।

श्री सभापति: सहयोग करें माननीय सदस्य।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सुमेरपुर में कोलीवाड़ा में..., माननीय सभापति महोदयजी, पांच मिनट तो दो।

श्री सभापति: सहयोग करें। विराजिए आप। श्रीमती रमीला खड़िया। अंकित नहीं हो।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट 2022-2023 के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की जनता, जो बहुत शानदार बजट दिया, उसके ऊपर बहुत धन्यवाद देती है कि सभी वर्गों के ऊपर ध्यान दिया। मैं धन्यवाद देती हूं कि जिस तरह से आज हमारे राजस्थान

(श्रीमती रमीला खड़िया)

के मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट के ऊपर सभी वर्गों का ध्यान उन्होंने रखा और आज राजस्थान ही नहीं, पूरा देश हमारे गांधीवादी जो नेता हैं, उनकी तस्वीरें लगाकर ऐसा लग रहा है कि दीपावली-होली मना रहे हैं और गुलाल उड़ा रहे हैं। आज तक कभी कोई सरकार आयी होगी, गयी होगी, पर जैसे सभी वर्गों का ध्यान रखा और जो बजट पेश किया, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी, पर रेडियो के मार्फत, टी.वी. के मार्फत और मोबाइलों में जो चला, वह आज की तारीख में दिख रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय दिया। हम जैसे ही सदन से आठ बजे निकले तो रात तक मोबाइल की घंटियां बजती रहीं और लोग बधाइयां देते रहे। हजारों की संख्या में बालिकाओं ने रैलियां निकाली और पटाखे फोड़े और खुशियां मनायीं। 2018-19 में मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ को कालेज मिला। आज वहां पर एक हजार बालक-बालिकाएं पढ़ रही हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर लगता हुआ है। वह बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जो कन्या महाविद्यालय दिया, तो आज हमारे कुशलगढ़ की बालिकाएं जितनी खुशियां मना रही हैं, उसके लिये मैं कैसे उनको धन्यवाद दूं।

आज हमारे नरेगा का ले लो, तो नरेगा में नगरपालिका आज तक शहरी क्षेत्र को कभी फायदा मिलता नहीं था तो उनके लिये भी इन्होंने 100 दिन कर दिये। आज शहरी क्षेत्र के भी लोग हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जो हमारे गांव के लोग थे, उनका 100 दिन था, उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। जिस तरह से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है, इस बजट के ऊपर जितना कहें, उतना कम है।

इसी तरह से हमारे सिंचाई के क्षेत्र में ले लो, तो हमारे कुशलगढ़, बागीदौरा और सज्जनगढ़ को जो बजट दिया है। मैं सिंचाई के लिये धन्यवाद देती हूं। वास्तव में मेरा एरिया सूखा क्षेत्र है। वहां घाटा क्षेत्र में पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है। वहां टैंकरों के माध्यम से पानी पिलाया जाता है। समय पर उन टैंकरों का भुगतान नहीं होने के कारण वह नये टेण्डर नहीं डालते हैं। इससे जनता बहुत परेशान होती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अच्छा बजट दिया लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करती हूं कि मेरा एरिया सूखा क्षेत्र है। इसको पेयजल स्रोत से जोड़ा जाये। हमारा कोई कोना सूखा न रहे। मेरे क्षेत्र में हाथियादली है, वहां

(श्रीमती रमीला खड़िया)

ऐसी कोई घटना घट गयी थी। मैं 10-15 दिन पहले वहां गयी तो वहां मात्र एक ही हैण्डपम्प चलता है। बच्चे पानी को ट्यूब में भरकर लाते हैं। मैं वहां एक स्कूल में बैठी थी। वहां बहुत समय हो गया था, पानी को टीचर ने भरकर रखा था। उस पानी को हमने पीया। टीचर्स ने कहा कि हम बहुत परेशान हैं। बच्चों को भी पानी पीने के लिए इधर-उधर दौड़ना पड़ता है। वह वन विभाग का एरिया है। उस एरिये को वन विभाग से एनओसी दी जाये और छोटे-छोटे एनिकट बनाये जायें। वहां के जानवर भी प्यासे मर रहे हैं।

मेरे एरिये में जो कुशलगढ़, घाटा एरिया है। जिस जगह सिंचाई का पानी नहीं पहुंच सकता, लिफ्ट के द्वारा उस जगह पानी पहुंचाया जाये और मेरे कुशलगढ़ क्षेत्र को जोड़ा जाये।

सड़कों के लिये जो 5 करोड़ रुपये थे, उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 करोड़ किये, उसके लिये उनका धन्यवाद करती हूं लेकिन जो छोटी-छोटी रोड रह गई हैं, आजादी के बाद कभी वरसिंह भाई जीते थे, नहीं तो वहां कांग्रेस का विधायक कभी जीता नहीं है।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मैं कभी बोलती नहीं हूं। मैं आज पहली बार खड़ी हुई हूं। मुझे थोड़ासा समय दें बोलने का।

श्री सभापति: आपका लिखा हुआ है, आप टेबल कर दें। जो भी आप 2 मिनट में बोल सकें, उतना बोलें और बाकी टेबल कर दें।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): आप 2 मिनट तो दें। अभी तो 3 मिनट ही हुई है।

श्री सभापति: आप 2 मिनट बोलिये। जो बच जाये वह टेबल कर देना।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): इस तरह से छोटी-छोटी सड़के हैं, जो रह गयी हैं। अन्धेश्वर से इटाला का 5 किलोमीटर रोड है। छोटी सरवा से गानवन जाने वाला 7 किलोमीटर रोड है। टिमेड़ा से घाटा गढली और केला पानी को जोड़ने वाला 7 किलोमीटर रोड है। इस रोड की मैं मांग करती हूं। ये छोटे-छोटे काम हैं।

हमारा पहाड़ी एरिया है। वहां आये दिन चोरी होती रहती है। आपने पेपर में भी देखा होगा। वहां एमपी की सीमा पड़ती है। छोटी सरवा में चौकी खोलने की मांग करती हूं। टिमेड़ा में भी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 4 चोर

(श्रीमती रमीला खड़िया)

थे, उनमें से 3 भाग गये और एक को पकड़ने के बाद भी पुलिस उसमें कार्यवाही नहीं कर रही है। टिमेड़ा बड़ा में भी एक चौकी खोली जाये।

हमारे कसारवड़ी में चौकी पहले से थी। सीएम साहब ने बजट में चौकी की वापस घोषणा की है। चौकी नहीं, उसको थाना बनाया जाये। वह बिलकुल गुजरात के बोर्डर पर है। सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बच गया हो तो आप टेबल कर दें। कुछ बच गया हो तो आप टेबल पर रख दें। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, आज संसदीय लोकतन्त्र के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो यह सरकार का बजट है, इस पर चर्चा में भाग लेने का मौका मिला। सदन में वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में जो बजट घोषणाएं हुई, जो आज तक अधर में लटकी हुई हैं, उनकी ओर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, पैरा 31, आपने पहले बजट में प्रत्येक पंचायत समिति में नन्दीशालाएं स्थापित करने की घोषणा की। सरकार ने सदन में भी अपने जवाब में स्वीकार किया कि अभी तक घोषणा पूरी नहीं हुई है।

एक लाख से अधिक वाहन वाले फिजिकल रेलवे फाटकों पर रेलवे मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2019-20 में 2 आरओबी और 32 आरयूबी बनाये जाने की सरकारी घोषणा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है।

सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में समस्त ग्राम पंचायतों में विकास पथ 10 हजार किलोमीटर लम्बाई के सड़क, नाली सहित बनाने की घोषणा की। विकास पथ राज्य की कितनी पंचायतों में बने हैं, यह भी हम सबको पता है।

सभापति महोदय, जब सरकार ने कृषि के लिये अलग से बजट पेश करने की घोषणा की तब किसानों को आस लगी। कृषि कनेक्शनों हेतु पिछले बजट में पृथक फीडर बनाने हेतु 5,200 करोड़ की योजना थी, उसमें से अभी तक एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं हुई है।

राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्सृजन संरचना परियोजना द्वारा 22,831 हैक्टेयर क्षेत्र में कृषि योग्य 207 करोड़ का जो प्रावधान किया, पाकिस्तान जा

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

रहे पानी को रोकने के लिये, उसमें भी कहीं योजना दिखाई नहीं दे रही है। 200 करोड़ रुपये की लागत से सौर ऊर्जा चालित टैंक सहित ट्यूबवैल्स का कार्य आज भी अधर में है।

मुख्य मंत्री जी ने पैरा 77 में मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ के ऋण ब्याज अनुदान दिया होता तो आज उद्यमी आर्थिक संकट में नहीं होते। वर्ष 2019-20 में 50 करोड़ व अगले 5 वर्षों में 250 करोड़ का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन इसमें से कितनी राशि खर्च हुई इसका उल्लेख करें।

पैरा 81 में, राजस्थान एम-सेंड नीति, 2019 कागजों से बाहर नहीं निकली है।

मौहल्ला और गली में जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की थी, उसके लिये आज तक भी कोई बजट आबंटित नहीं हुआ है। प्रत्येक गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी सुविधाओं के लिये मास्टर प्लान सिर्फ कागजों में ही बनकर तैयार हुआ है। धरातल पर नहीं हुआ है।

राजस्व कानूनों में जो संशोधन कर निस्तारण प्रक्रिया को इस तरह सरलीकृत किया कि आज तक लाखों प्रकरण राजस्व न्यायालय में लम्बित पड़े हुए हैं।

इसी बजट में 2022-23 के पैरा 23 में आपने प्रदेशवासियों को मिलावट रहित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध खाद्य पदार्थ सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित शुद्ध के लिये युद्ध अभियान को मूर्त रूप देने के लिये 10 नयी मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स संचालित किये जाने का प्रस्ताव दिया है जबकि धरातल पर कुछ होना नहीं है। मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये फास्ट ट्रेक कोर्ट जैसी घोषणाओं पर अमल होता तो आज प्रत्येक नागरिक को शुद्ध भोजन पहुंचाने की जो सरकार की प्रतिबद्धता है, वह पूरी होती। मिलावटखोरों में ऐसा कोई भय नहीं है कि सरकार कोई कार्यवाही कर रही है।

राज्य के सभी किसानों को 3 वर्ष में दिन के 2 ब्लाक्स में कृषि हेतु विद्युत उपलब्ध कराने पर 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, जिसमें 220 केवी के नये 6 जीएसएस और 132 केवी के 30 नये जीएसएस और 33 केवी के 287 नये सब स्टेशंस बनाना निर्धारित था। अगर इन घोषणाओं पर खर्च होता तो आज किसानों को विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

18 करोड़ की लागत से अजमेर, जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय क्या बनकर तैयार हो गया है? अगर हां, तो कितने विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत हैं? बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के अन्तर्गत भी बीसलपुर, माही, जवाई, जाखम, सोम, कमला, अम्बा, छापरवाड़ा प्रदेश के सभी बड़े बांधों में 18 बांधों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण का कार्य 503 करोड़ रुपये से करवाये जाने की घोषणा भी अभी बन्द है।

पैरा 10 में 2021-22 में 3,500 करोड़ की लागत से यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज की घोषणा बजट 2022-23 के पैरा संख्या 7 में मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के अन्तर्गत चिकित्सा बीमा के क्लेम को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने एवं चिरंजीवी कार्ड नहीं होने पर जिला कलेक्टर के माध्यम से नि:शुल्क इलाज कराने की घोषणा सरकार ने कर दी लेकिन निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के नाम पर लूट खसौट है और उस पर कोई सख्त कदम उठाने के बारे में कुछ भी प्रावधान नहीं है।

जिला कलेक्टर किन मरीजों का इलाज करायेंगे, यह इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि इन मरीजों को हम निराश्रित मानते हैं।

राज्य के सभी 7 सम्भागीय मुख्यालयों पर पब्लिक हैल्थ कालेज की घोषणा का क्या हुआ? घोषणा को जमीनी स्तर पर कब उतारेंगे?

राजस्थान के औद्योगिक परिवेश को बढ़ावा देने के लिए जो उद्योग नीति आयी है और राजस्थान में निवेश के लिए अभी सरकार ने भी अभियान चलाया है, इस निवेश में हमारे नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में कालेसरा में एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए घोषणा सरकार ने अपने बजट में की है। सरकार ने कहीं पर भी इसको मूर्त रूप देने के लिए जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

पिछले वर्षों में सड़कों की घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कीं, उनमें चाहे मांगलियावास से पीसांगन होते हुए रियां बड़ी वाली रोड हो, चाहे ब्यावर से पीसांगन वाली रोड हो, इन पर कहीं पर भी धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। 5 करोड़ का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने नोन पेचेबल रोडों के लिए किया है। उसमें कहीं पर भी गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है और न ही इसमें कोई गारंटी पीरियड, सुनिश्चित अवधि का उल्लेख है कि इतने वर्ष तक यह रोड खराब नहीं होगी और हो गयी तो इसको ठेकेदार सही करेगा। जहां पर भी रोड बन रही हैं, ग्रामीणों की शिकायतें

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

आती हैं, इसमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाये क्योंकि उन सड़कों पर चलते हैं तो यह महसूस होता है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ऐसी स्थिति नहीं आये और अपने जो नोन पेचेबल सड़कें बनें और जहां पर फिजिबिलिटी के आधार पर सीसी रोडों की आवश्यकता हो तो उन नोन पेचेबल सडकों में सीसी रोडों का भी प्रावधान हो। साथ में जहां पर आवश्यकता हो वहां पर सौ मीटर, दो सौ मीटर सीसी रोड की स्वीकृति भी मिले।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग में भी कई घोषणाएं हुई हैं। हमारे जेठाणा रामसर सहित प्रदेश में कई ऐसे विद्यालय हैं, जहां पर छात्राओं के स्कूल हैं। उन स्कूलों को बन्द करके अंग्रेजी माध्यम से खोलने से छात्राओं के नामांकन में कमी आयी है और कई जगह स्कूल शिक्षा से छात्राओं के वंचित होने का काम भी हुआ है। सरकार छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है लेकिन कहीं पर भी इसको अमली जामा पहनाने के लिए धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शिवपुरा स्कूल जो हमारे करनोज पंचायत में है, इसको क्रमोन्नत किया जाए। डीएमएफटी फंड के माध्यम से जहां पर शिक्षा विभाग की जर्जर इमारतें हैं वहां पर नई इमारतें बनाने का प्रावधान है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाये क्योंकि कई स्कूलें ऐसी हैं जहां पर छात्र बैठते हैं लेकिन बरसात के मौसम में उन स्कूल भवनों के ढहने का खतरा होता है तो इसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी कोआर्डिनेट करके कोई बड़ा हादसा नहीं हो, इससे बचाव के लिए इसका सर्वे करवायें पूरे प्रदेश में और जिन स्कूलों में नई इमारतों की जरूरत हो वहां नई इमारतें बनायी जायें।

माननीय सभापति महोदय, टीचर्स भी स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। अभी स्कूलें तो क्रमोन्नत हो रही हैं पर विषय विशेषज्ञ, हमारे लैक्चरर्स हैं उनकी नियुक्तियां नहीं हो पायेंगी तो इस वजह से भी छात्रों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ेगा।

पीसांगन में जो उप खण्ड मुख्यालय हमारे नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में है इसमें कालेज खोला जाये जिससे आम जनता और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले आम निवासियों को लाभ मिल सके। मिसिंग लिंक्स योजना में भी सड़कें बनी हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे श्रीनगर अजमेर रोड को भी चौड़ा किया जाये। पीएमजीएसवाई में और जो सड़कें बनी हैं उनकी तर्ज पर हमारे नोन पेचेबल और मिसिंग लिंक्स बन रही हैं, उनकी गुणवत्ता भी बराबर बनी रहे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): मैं आपका ध्यान खेलकूद की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश में भी हमारे प्रतिभाएं हैं और छात्र छात्राओं को भी और मौका मिलेगा तो ओलम्पिक में हों या चाहे नेशनल में हों, मैडल लेकर आयें। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ठोस नीति लेकर आये और उनको जहां-जहां पर भी भत्तों की जरूरत हो, सहयोग की जरूरत हो वह सहयोग प्रदान किया जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): जल जीवन मिशन में जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच की जाये। जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है उसकी राज्य स्तरीय कमेटी जांच करे। ट्यूबवैल जो पिछली घोषणाओं के अनुरूप जो नहीं लगे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी लगवाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, जो कृषि बजट अलग से पेश किया गया है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री हाकम अली।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप टेबल कर दीजिये, आप नये सदस्य हैं। समय की सीमा है। मैंने आपको कह दिया है कि आप टेबल कर दें। जो भी कुछ बच गया हो आप यहां वह टेबल कर दें।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): एक-दो लाइन हैं। मैं कहना चाहूंगा कि नसीराबाद में जो चिकित्सालय है उसको ट्रोमा सेंटर का दर्जा दिया जाये।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): 000

श्री सभापति: श्री हाकम अली।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाकर साढ़े सात बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया गया।

श्री हाकम अली।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आय व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत राज्य के प्रत्येक वर्ग के लिए हितकारी बजट की मैं बड़ी सराहना करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे द्वारा चिंतन शिविर में घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई विद्युत दरों में अनुदान देकर आम जन को राहत प्रदान करने का सुझाव माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दिया था, जिस पर सकारात्मक विचार कर मेरे सुझाव को आम जन की इच्छा मानकर लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी से प्रस्तुत बजट में 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली एवं 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान व 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने पर 2 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान एवं इससे अधिक यूनिट के उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार अनुदान का लाभ मिलेगा। इससे आम जन बहुत प्रसन्न है और सरकार की बहुत सराहना कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में निवास

(श्री हाकम अली खां)

करने वाले परिवारों को मांगे जाने पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इससे शहरों में निवास कर रहे मजदूरों को कम से कम 100 दिवस के रोजगार की गारंटी मिलने से इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसी क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उपलब्ध सौ दिवस के रोजगार को राज्य सरकार ने अपने खर्चे पर बढ़ाकर 125 दिवस किए जाने की घोषणा करने से ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। इससे इन परिवारों को सम्बल मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, राज्य कर्मचारी 30-35 वर्षों तक राजकीय कार्य कर जन सेवा के उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक की वृद्धावस्था में सार-सम्भाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उनको पेंशन उपलब्ध कराती रही है परन्तु 1 जनवरी, 2004 के बाद सरकार में भर्ती कार्मिकों के लिए एनपीएस योजना लागू की गयी थी जिसमें अंशदायी पेंशन का ही प्रावधान है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कर्मचारी सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान तभी दे सकता है जब वह कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसका ध्यान रखते हुए, राज्य कर्मचारियों के हित में इसका ध्यान रखते हुए प्रस्तुत बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया इससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। इस घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। राज्य कर्मचारी बजट की घोषणा होते ही खुशियां मनाने लगे। कर्मचारियों ने जगह-जगह आतिशबाजी कर व मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया और सरकार व माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पेंशन रूपी उपहार देने के लिए आभार व्यक्त किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अलग हटकर एक समस्या से सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले यूक्रेन संकट पर चर्चा हो रही थी, उसी तर्ज पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खाड़ी देशों में मजदूरी कर जीवनयापन करने वाले प्रदेश के मजदूरों एवं उनके परिवार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सहित प्रदेश भर से बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग अपने परिवार की रोजी-रोटी चलाने के लिए खाड़ी देशों में जाता है। हमारे शेखावाटी अंचल के मजदूरों की आय का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में मजदूरी करने से आता है। माननीय

(श्री हाकम अली खां)

सभापति महोदय, वर्तमान में बेरोजगारी की मार झेल रहे शिक्षित युवा वर्ग भी रोजगार के लिए विदेश में जा रहा है, वे वहां जाकर कठोर परिश्रम करते हैं, इससे होने वाली आय से प्रदेश के साथ ही भारत देश भी सशक्त होता आ रहा है। कई युवा शिक्षित होने के बाद भी रोजगार नहीं मिलने के कारण दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। ये मजदूर जब विदेश जाते हैं तो वीजा के लिए ट्रेवल एजेंटों, दलालों के झांसे में आ जाते हैं, कुछ ट्रेवल एजेंटों द्वारा मजदूर वर्ग की बेरोजगारी का फायदा उठाया जाता है। ये एजेंट मजदूरों से

(समय: 19.00 बजे)

असत्य वादे करते हैं तथा अधिक वेतन तथा अच्छी नौकरी का झांसा देकर हजारों-लाखों रुपये ऐंठते हैं। विदेशों में कठोर परिश्रम कर प्रदेश के साथ ही देश को मजबूत करने वाले इस मजदूर वर्ग के साथ अनहोनी की सम्भावना बनी रहती है। सभापति महोदय, कई बार मजदूर विदेश जाने के कुछ समय में ही हृदयाघात होने व अन्य किसी गम्भीर बीमारी से अथवा किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो जाने से काल का ग्रास बन जाते हैं, तो इनकी पार्थिव देह को निवास स्थान तक लाने में बहुत धनराशि खर्च होती है तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन मजदूरों के परिवार जमा-पूंजी के अभाव में यह खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। कई परिवार अपने परिजन का पार्थिव देह विदेश से लाने के लिए अपनी जमीन या अन्य सम्पदा बेचते हैं, जिससे इन परिवारों का वर्तमान एवं भविष्य अंधकारमय हो जाता है। सभापति महोदय, मैं खुद खाड़ी देशों में रहा हूं। वहां मैंने मजदूरी की है तथा इन मजदूरों की पीड़ा को मैंने देखा व समझा है। वहां किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाने पर इन मजदूरों व इनके परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कई देशों में इन परिवारों को भारतीय समुदाय कल्याण निधि (ICWF) से सहायता मिल जाती है, परन्तु जानकारी के अभाव में अधिकतर वंचित रह जाते हैं। वहीं, कई खाड़ी देशों में हिन्दू रीति-रिवाज से पार्थिव देह के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं होने के कारण हिन्दू भाइयों की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में उन मजदूरों की समस्या को देखते हुए केरल और तमिलनाडु की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी जो मजदूर मजदूरी के लिए विदेशों में जाते हैं, उनके एवं उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए योजना बनाकर इनके परिवारों को आर्थिक सम्बल दे। इनके साथ विदेश में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर इनकी पार्थिव देह

(श्री हाकम अली खां)

को भारत लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक बजट आबंटित कर इन परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं से अवगत कराना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा फतेहपुर के नजदीक रामगढ़, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि में कोई राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है, जिससे क्षेत्र की बालिकाओं को अध्ययन हेतु दूर जाना पड़ता है और परिवार पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। अत: मैं मुख्य मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि कन्या महाविद्यालय खोलकर उन कन्याओं की समस्या का समाधान करें। यदि कन्या महाविद्यालय खोला जाता है तो भामाशाह भूमि एवं भवन बनाकर देने को तैयार हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधीन कस्बा रामगढ़ शेखावाटी जो कि काफी पुराना शहर है तथा नगरपालिका एवं उप-खण्ड मुख्यालय है, वहां पर 30 बैड का अस्पताल काफी समय से संचालित है, जिसका भवन भामाशाहों द्वारा बनाकर दिया हुआ है। यदि इस अस्पताल को 50 बैड में क्रमोन्नत कर दिया जाये तो भामाशाह इसमें सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। अत: क्षेत्रवासियों की मांग अनुसार इस सीएचसी रामगढ़ को 30 बैड से 50 बैड में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, रामगढ़ के कर्मचारियों एवं व्यापारियों की मांग को देखते हुए रामगढ़ में उपकोषागार खोलने की भी मैं मांग करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु क्षेत्रवासियों की मांग पर मेरे विधान सभा क्षेत्र की पीएचसी बीबीपुर को सीएचसी में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करें। क्षेत्रवासियों की मांग पर फतेहपुर में एक नवीन पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, महणसर-बिसाऊ सड़क, जो कि रामगढ़ कस्बे के अन्दर से गुजरती है, उस पर आवागमन अधिक रहता है, जिसके कारण कस्बे में हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है तथा दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है। अत: मैं इस सड़क को रामगढ़ के बाईपास से बनाये जाने की मांग करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय भींचरी एवं खोटिया काफी बड़े गांव हैं तथा यहां सब-सेंटर संचालित हैं। क्षेत्रवासियों की काफी समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग थी। अत: भींचरी एवं खोटिया में पीएचसी

(श्री हाकम अली खां)

स्वीकृत करने की मैं मांग करता हूं। खोटिया गांव एनएच52 पर पड़ता है और आये दिन वहां एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसलिये उस गांव में अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है तो एक्सीडेंट होने पर घायलों को अच्छा इलाज, फर्स्ट एड मिल सकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर से एनएच-52 गुजरता है। इस पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अत: इस हाईवे को फोर लेन करने की मैं मांग करता हूं। सभापति महोदय, आखिर में आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि नीम का थाना को जिला बनाया जाये। साथ ही, मैं सीकर को सम्भाग का दर्जा दिलाने की मांग करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राजस्थान सरकार का यह जो बजट पेश हुआ है, वह दिशाहीन है। यह बजट विकास को बढ़ावा देने वाला नहीं है। आपने इस बजट के माध्यम से अनेकों घोषणाएं की हैं, परन्तु पूर्व के बजटों की घोषणाओं को ही अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस बजट में विपक्ष को नजरअंदाज किया गया है। यह सरासर हमारे क्षेत्र के साथ अन्याय है। आपने मनमर्जी की है। ऐसा नहीं करना चाहिये। जनता ने हमें भी वोट दिये हैं और हमारे क्षेत्र की जनता हमसे काफी उम्मीद भी करती है, परन्तु आपने नाइंसाफी की बात की है।

आपने पिछले बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा-सूरतगढ़ रोड, अमरपुरा के पास आरओबी की घोषणा की थी, पर अभी तक उसका कोई अता-पता नहीं है। पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर नन्दीशाला की घोषणा की गयी थी, उसका भी अता-पता नहीं है। विकास पथ की घोषणा की गयी थी, पर वह भी अभी तक नहीं बना है। वार्डों में आपने जनता अस्पताल बनाने की घोषणा की थी, उनका भी अभी तक अता-पता नहीं है।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीलीबंगा, रावतसर व गोलूवाला तीनों ही हाईवे पर स्थित हैं, जिस कारण शहर में पूरे दिन वाहनों का जमावड़ा रहता है। मैं इन तीनों कस्बों के लिये बाईपास की मांग करता हूं। किशनगढ़

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

हनुमानगढ़ मेगा हाईवे काफी सालों से री-कारपेट नहीं हुआ है। पूरे हाईवे पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, लेकिन फिर भी टोल वसूला जा रहा है। जब तक उसे पूर्णत: री-कारपेट नहीं किया जाता तब तक उस सड़क पर टोल बन्द किया जाये। ये मेगा हाईवे वाले अपनी मनमर्जी कर रहे हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी बहुत-सी सड़के हैं जिन्हें चौड़ी करना अत्यन्त आवश्यक है, जैसे- डिंगा से भागसर 26 पीबीएन सूरतगढ़ तक, रावतसर से जाखड़ावाली होते हुए सूरतगढ़ तक, चाइया से होते हुए गन्धेली लालपुरा नोहर तक, धन्नासर कैंची से होते हुए हरदासवाली थर्मल सूरतगढ़ तक, गोलूवाला से उम्मेवाला श्रीगंगानगर रोड तक, मक्कासर से भाम्भूवाली ढाणी, यालकी होते हुए पीलीबंगा-गोलूवाला रोड तक।

गांवों में जो सड़कें बरसों पहले पीडब्ल्यूडी व कृषि विपणन बोर्ड ने बनायी थीं, आज तक वे री-कारपेट नहीं हुईं। ऐसी सड़कों का सर्वे कराकर सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण आरओबी व आरयूबी हैं, जो सरकार को बनाने चाहिये, जैसे- रावतसर-पीलीबंगा हाईवे पर आरओबी, अहमदपुरा, अमरपुरा व रामपुरा रंगमहल फाटकों पर आरयूबी।

जल जीवन मिशन, जिसमें 50-50 का राज्य सरकार व केन्द्र सरकार का रेशो है, उसमें भी आपने 10 परसेंट जनता पर नाजायज लाद दिया है। आपने आबादी और गांवों को जोड़ने बात की है, परन्तु गैर आबादी चकों में लोग अपने खेतों में ढाणियां बनाकर रह रहे हैं और वे अभी भी खेत में लगने वाले सिंचाई का पानी ही पी रहे हैं, जो कि दूषित है। अत: गैर आबादी चकों को भी जेजेएम से जोड़ा जाये।

रावतसर शहर में केडब्ल्यूडी नहर के माध्यम से पानी आता है, जो कि खुले नाले के माध्यम से आता है। वहां उद्योग भी हैं तथा वहां रहने वाले जो भी श्रमिक हैं वे उस खुले नाले में कपड़े धोते हैं तथा आये दिन उसमें आवारा पशु गिर जाते हैं, जिससे पानी दूषित होता है। अत: रावतसर शहर को पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल दिया जाये।

''आपणी योजना'', जो धन्नासर में है, मुझे दु:ख इस बात का है कि जब यह योजना बनी थी तब यह कहा गया था कि सबको पानी दिया जायेगा, पर इसमें आज तक किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं हुआ है। आस-पास के गांवों में पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। जहां-जहां यह योजना है, वहां एसआर

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

बनाये जाएं। इस योजना का विस्तार किया जाये। कस्बा रावतसर में वार्ड नं. 10 में तो ये हालात हैं कि पिछले 5-6 महीनों से गटर का पानी सप्लाई हो रहा है। नयी पाइपलाइन डालना प्रस्तावित भी है, परन्तु अभी तक नहीं डाली गयी है। लोगों के साथ यह नाइंसाफी की बात है कि उन्हें गन्दा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है।

शिक्षा के लिये मैं कहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो उपखण्ड हैं, एक उप-तहसील है, परन्तु बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिये एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। सरकार ने अपनी पार्टी के विधायकों को तो रेवड़ियां बांट दीं, परन्तु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को वोट पीलीबंगा विधान सभा में भी मिलते हैं, लेकिन अब वे वोट घट जायेंगे, क्योंकि आपने पीलीबंगा के बच्चों के साथ व हमारे साथ अन्याय किया है, इसलिए मैं पीलीबंगा, रावतसर, गोलूवाला व डबली में राजकीय महाविद्यालय की मांग करता हूं।

आपने महात्मा गांधी स्कूल तो बना दिये और उनको बनाया जो अच्छे तरीके से चल रहे हैं, परन्तु मेरा आपसे निवेदन है कि जो नये स्कूल की आपने घोषणा की है उससे पहले जो पुराने स्कूल चल रहे हैं उनको सुधारें, उनमें कमरों की व्यवस्था करें, उनमें शौचालय की व्यवस्था करें। जिन स्कूलों में आज बच्चों की अच्छी भरमार है, अच्छे स्कूल चल रहे हैं उनको इंग्लिश मीडियम न बनाकर जो मिडल स्कूल हैं उनको बनायें ताकि उस क्षेत्र का, उस स्कूल का विकास हो सके और वहां पर पढ़ने वाले बच्चों पर कोई प्रभाव न पड़े। कई राजकीय स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय भी नहीं हैं।

कुछ निजी स्कूलों में आरटीई का भुगतान नहीं किया गया है और वे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

चिकित्सा के सम्बन्ध में मेरे द्वारा आदर्श सीएचसी के लिए पीलीबंगा सीएचसी की अनुशंसा की गयी थी पर सरकार द्वारा आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आदर्श सीएचसी में विधायकों ने एक करोड़ रुपये की अनुशंसा की परन्तु उनमें राजनीति की जा रही है, पैसे वहां पर नहीं दिये जा रहे हैं। पीलीबंगा सीएचसी बहुत जर्जर हालत में है। वहां कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री बलजीत यादव। विराजिये आप।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): पीलीबंगा सीएचसी, गोलूवाला सीएचसी, डबली सीएचसी के स्टाफ व बैड बढ़ाकर उनको क्रमोन्नत किया जाये। एक मिनट, सर।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिये। प्लीज, सहयोग करें, विराजें। विराजिये, माननीय सदस्य। टेबल कर दीजिये।

(माननीय सदस्य श्री धर्मेन्द्र कुमार के शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो जो कर्मचारियों/अधिकारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू की, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ, उनसे निवेदन करता हूं कि रोडवेज और बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी रह गये, उनको भी अगर सहानुभूतिपूर्वक इस स्कीम से जोड़ा जायेगा तो उनकी अतिकृपा होगी।

इसके साथ ही जो मंत्रालयिक कर्मचारी हैं उनके वेतन विसंगति की जो समस्या है, मैं समझता हूं कि उसका भी निराकरण करेंगे।

इसके साथ ही 2002 के बाद में तीसरी सन्तान जिस कर्मचारी/अधिकारी को हुई उसकी पांच भर्ती वर्ष तक पदोन्नति पर रोक लगा दी थी जिसको बाद में तीन भर्ती वर्ष कर दिया गया था। भर्ती वर्ष उसको माना जाता है जिसमें पदोन्नति के लिए सीट खाली होती है। ऐसे में जब सीट खाली नहीं होती है तो कई विभागों में 8 से 10-10 साल तक वे वर्ष भर्ती वर्ष में काउंट हो जाते हैं और जब उनकी पदोन्नति होती है तो उनका जो स्टेटस होना चाहिए वह नहीं मिलता है और वे जूनियर ही रह जाते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उनकी वरिष्ठता जो उस वक्त काउंट होनी चाहिए, वह उनको मिले। यह प्रावधान केवल राजस्थान में है, देश के किसी भी अन्य राज्य में ऐसा नहीं है और न ही केन्द्र में ऐसा है, इसलिए मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी हमारे यहां के कर्मचारियों/अधिकारियों को यह लाभ मिलना चाहिए।

चिरंजीवी योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर जो 10 लाख रुपये की, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं।

पूरे प्रदेश में कालेज खोले गये, सीएचसी, पीएचसी, हास्पिटल क्रमोन्नत किये गये, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, बजट चाहे केन्द्र का हो, चाहे किसी राज्य का हो,

(श्री बलजीत यादव)

हमेशा कोई भी सरकार हो उस सरकार का यह कहना रहता है और हमारे विपक्ष के साथियों का भी यह कहना रहता है कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं, कहां से पैसे लाओगे? सभापति महोदय, मैं उसके विपरीत कहना चाहता हूं कि बहुत पैसा है सरकार के पास, केन्द्र सरकार के पास भी, राज्य सरकार के पास भी और बहुत पैसा जुटाया जा सकता है केन्द्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी, लेकिन जो मेन कमी है वह है मैनेजमेंट की, जो कमी है, जो गड़बड़झाला है वह वितरण व्यवस्था का है, वह नीयत का है। सभापति महोदय, कोई भी सरकार चाहे कि बहुत अच्छा-सा काम स्टेट के अन्दर हो तो ज्यादा नहीं, 8 से 10 आईएएस की जरूरत है जिनके सीने में आग हो कुछ करने की, जिनमें लगन हो कुछ नया करके दिखाने की और कमी नहीं है अच्छे आईएएस की। बहुत से आनेस्ट और अच्छे आईएएस हैं, बहुत से ऑनेस्ट और बहादुर आईपीएस हैं। ऐसे ही बहुत से आनेस्ट आरएएस हैं, आरपीएस हैं लेकिन होता क्या है कि जो आनेस्ट है, जो काम करना चाहता है उसको मौका नहीं मिलता है। हमारे गांव में कहावत है कि जिसके पास जाड़ है उसके पास चने नहीं और जिसके पास चने हैं उसके पास जाड़ नहीं और इसी के कारण व्यवस्था ठप रहती है।

सभापति महोदय, कोई भी सरकारी उपक्रम हो, चाहे आपका आरटीडीसी ले लीजिये, इतनी बढ़िया-बढ़िया लोकेशन पर उनके होटल हैं लेकिन सब घाटे में हैं। प्राइवेट बसें हैं वे प्रोफिट में हैं लेकिन रोडवेज का बंटाढार। आपका पीडब्ल्यूडी है वह एक किलोमीटर डामर की सड़क बनाता है तो उसकी 40 लाख रुपये लागत लगाता है और कोई प्राइवेट आदमी बनाता है, प्रोपर्टी डीलर बनाते हैं तो वे एक किलोमीटर 14 से 15 लाख रुपये में बना देते हैं और उनसे बेहतर सड़क होती है। पानी की बोरिंग है वह गांव में साढ़े तीन लाख रुपये में हो जाती है और पीएचईडी उसको 12-13 लाख रुपये में करता है। हर विभाग में, हर जगह पर पैसे का मिस-यूज होता है, सभापति महोदय। अब इस तरह से अगर लूट होगी, इस तरह से पैसे को लुटाया जायेगा तो फिर पैसा विकास के लिए बचेगा कहां से? सभापति महोदय, गांव में आपने भी देखा होगा, मेरे साथियों ने भी देखा होगा, आपके भी आस-पास में बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि इसके बाप-दादा ने मेहनत करके इतनी बड़ी सम्पत्ति अर्जित की थी लेकिन एक घर में कपूत हो गया, एक घर में शराबी हो गया, अय्याशी हो गया तो उसने सबको बेच-बाचकर मटियामेट कर दिया और फांके

(श्री बलजीत यादव)

के ऊपर पड़ गया उसी की जिन्दगी में। सभापति महोदय, वह मिस-मैनेजमेंट और फिजूलखर्ची का नतीजा होता है। ऐसा ही सरकारी विभागों में होता है क्योंकि जो आईएएस चोरी करेगा, जो अधिकारी रिश्वत खायेगा तो जब पावरफुल नेताजी की घरवाली का जन्म दिन होगा तो वह डायमंड का सैट उसको गिफ्ट करके आ जायेगा। नेताजी का जन्म दिन होगा तो नेताजी को बड़ा गिफ्ट देकर आ जायेगा और जो गरीबड़ा होगा, जो आनेस्ट अधिकारी होगा वह अपने बच्चे पालेगा, वह किसी के हाज़िरी लगाने नहीं जायेगा इसलिए वह किसी को दिखायी नहीं देगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, 10-15 मिनट तो दें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अब। प्लीज, कृपया शान्त रहें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, कोई बात नहीं सर। सभापति महोदय, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता की बात कहना चाहता हूं और जनता सुनती है। सभापति महोदय, बलजीत यादव इस विधान सभा में बोला और उस वीडियो को एक व्यक्ति ने डाला तो तीन करोड़ लोगों ने बलजीत यादव के स्पीच को सुना। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे मेरी बात को कहने दिया जाये। यह बलजीत यादव की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं है, यह जनता की बात है और वह जनता सुनना चाहती है, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, किसान पानी के लिये तड़प रहा है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सभापति महोदय, कश्मीर से पानी पाकिस्तान चला जाता है, पंजाब की नदियों से पानी पाकिस्तान में चला जाता है, बाढ़ का पानी आता है, बाढ़ राहत के लिए अरबों-खरबों खर्च कर दिये जाते हैं। सभापति महोदय, मेरा इतना-सा निवेदन है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसान के लिए पानी की व्यवस्था करें, इन नदियों को जोड़ने का काम करें। किसान को अगर सिंचाई का पानी मिलेगा तो वह देश को उन्नत बनायेगा।

बेरोजगारी दूर नहीं होती है, जिसके घर में कोई व्यक्ति नौकरी में नहीं है, गरीब आदमी है, वह बेचारा तड़पता रहता है। हमारे यहां कहा जाता है टैक्स नहीं लगाया, बहुत अच्छा बजट। केन्द्र में कहा जाता है, टैक्स नहीं

(श्री बलजीत यादव)

लगाया बहुत अच्छा बजट। सभापति महोदय, ये कहां का न्याय है? वेलफेयर के लिए सरकार चला रहे हैं, राज चला रहे हैं। सभापति महोदय, एक आदमी पांच करोड़ की गाड़ी में घूमता है, एक व्यक्ति पांच हजार से लेकर के रोज एक लाख रुपये की दारू पी जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): दारू की एक बोतल खरीद लेता है। गरीब आदमी को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): और सीवर की लाइन से मिक्स हुआ पानी मिलता है या गन्दा पानी उसको पीने को मिलता है। सभापति महोदय, तीन-तीन सौ रुपये पानी की एक बोटल अमीर आदमी पीता है और उसके तीन-तीन दिन में पानी आता है।

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, ये कहां का न्याय है? 75 साल हो गये देश को आजाद हुए, लेकिन इसके बाद भी गरीब आदमी यूं ही रो रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): हर बार सरकार बदलता है, हर बार रोता रहता है, हर बार झांसे में आता है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, प्लीज विराजिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): 000

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला। श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 23 फरवरी को इस सरकार का चौथा बजट पेश किया है, लेकिन मेरे पास आंकड़े हैं कि पिछले तीन बजट जो इन्होंने पेश किये, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए जो कहा उसमें से कुछ भी नहीं किया। जैसे 2019-20 के बजट में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर नन्दीशाला, आज तक नहीं बनी। समस्त ग्राम पंचायतों में विकास पथ, मेरी 63 पंचायतें हैं, एक में बना है, बार-बार पीडब्ल्यूडी वालों से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि अब नहीं बनेंगी।

(श्री अशोक डोगरा)

सिंचाई के 21 जिले हैं, जिसमें बूंदी शामिल है, 515 करोड़ रुपये के काम, एक भी नहीं हुआ। गली-मोहल्ले में जनता क्लिनिक नहीं बना, उसके अगले साल के बजट में 2020-21 में, सिंचाई के लिए दिन में पानी मिलेगा, हमारे यहां आज भी रात में ही मिल रहा है। प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क नहीं बना, राजस्थान में 9 जिले जिनमें बूंदी शामिल है, एक टाउन हाल की, टाउन हाल की अभी तक जमीन की ही चर्चा नहीं है। ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार, शहीद स्मारक कोई चर्चा नहीं और उसके बाद पिछले बजट में बूंदी, सिलोर, निमाणा, कडदा, भोपदपुरा रोड 132 करोड, इसके न तो टेण्डर हुए न कोई चर्चा है, कुछ भी नहीं है।

फिर तीन घन्टे मुख्य मंत्री जी ने इतना लम्बा-चौड़ा बजट दिया है और न पहले के हुए हैं न इसके होंगे। बजट उसी साल के लिए आता, जिस साल में वे काम होने होते हैं। उसमें से कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हो, डीजल, पेट्रोल पर वैट इतना ज्यादा है कि राजस्थान में डीजल, पेट्रोल सबसे महंगा है। लेबर डिपार्टमेन्ट की जो भी योजनाएं थीं, किसी गरीब आदमी की बच्ची 18 साल की हो जाती है तो उसको शादी के लिए 55 हजार रुपये मिलते, वे सब स्कीमें आपने बन्द कर दी हैं।

आपने इस बार कहा कि जन घोषणा पत्र हमारी प्राथमिकता है। कृषि बजट आपने दिया, 10 दिन पहले से ही अखबारों में एड आने लगे कि राजस्थान में पहली बार कृषि बजट अलग से आ रहा है, तो लोगों ने उम्मीद की कि जो 10 दिन में कर्ज माफ होने थे, वे अब होंगे या जो प्रधान मंत्री जी की किसान सम्मान निधि में 6 हजार रुपये मिलते हैं तो इस सरकार की तरफ से भी मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं, सबको निराशा मिली है। जगह-जगह शराब के ठेके आपने खोल दिये।

अब आपने 3 करोड़ रुपये नयी सड़कों के लिए दिये हैं। उनमें चार, साढ़े चार किलोमीटर सड़कें भी नहीं बनेंगी। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि ये 10 करोड़ पूरे के पूरे नयी सड़कों के लिए रहने दें, ताकि दस-बारह किलोमीटर की सड़कें बन सकें और कुछ विकास हो सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कर लेता हूं, क्योंकि आप समय कम देंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच-सात प्रोब्लम है। एक तो चार साल पहले एक नयी कृषि मण्डी बनी थी, वहां शिफ्ट हो गयी थी। वहां प्लेटफार्म पर्याप्त

(श्री अशोक डोगरा)

नहीं है और सीजन में सवा लाख से डेढ़ लाख बोरी माल आता है। माल सारा बिक जाता है, लेकिन तुलकर उठने में दिक्कत आती है, अगले दिन फिर मण्डी बन्द करनी पड़ती है। किसान माल लेकर आ जाते हैं, वे परेशान होते हैं, मण्डी बन्द हो जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि दो बड़े प्लेटफार्म और बना दिये जायें, जिसकी वजह से एक दिन एक में शिफ्ट हो जायेगा, दूसरे दिन दूसरे पर माल खाली हो जायेगा, किसानों को परेशानी नहीं होगी और मण्डी भी बराबर चलेगी।

दूसरा, एक गरडदा बांध, लतारिया बांध है। 2010 में पहली बार इसको भरने लगे तो आधा बांध भरते ही टूट गया था, तब से पड़ा है। फिर, हमने काफी प्रयास किये, उसके बाद 2017 में इसके निर्माण के लिए पहले 72.87 करोड़ की स्वीकृति आयी, जो पुन: बाद में सर्वे में 123.9 करोड़ की हो गयी और अब सर्वे में 152.85 करोड़ रुपये इसका बजट बना है। जो केबिनेट कमेटी के पास सैंक्शन हेतु पेण्डिंग है तो इसकी सैंक्शन जल्दी आ जाये, 130 करोड़ से ज्यादा अभी तक लग चुके हैं। 9,161 हैक्टेयर भूमि पर तो सिंचाई होगी और करीब 200 गांवों का वाटर लेवल बढ़ेगा। इसी से 198 गांव और 108 ढाणियों की पेयजल योजना भी है, इसी बांध से, वह तभी हो पायेगी जब यह बांध पूरा होगा तो मेरा सरकार से निवेदन है कि गरडदा बांध को प्राथमिकता से पूरा कराये।

एक, हमारे यहां बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर अभयारण्य स्वीकृत हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन एक-दो दिन में होने वाला है। इसमें सात गांव खाली होंगे। अब वे खाली होंगे तो सरकार उनको 15 लाख रुपये पर परिवार देना चाह रही है, जो कि बहुत कम है। मेरी सरकार से मांग है कि कम से कम 25 लाख रुपये प्रति परिवार दिया जाये और इन गांव वालों को बसाने के लिए खटकड़ पंचायत की बहुत चरागाह भूमि पड़ी है जिसको आबादी में परिवर्तित कर बसाया जाये। गांवों के विस्थापन से पूर्व इनके रहने हेतु बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये। इन गांवों के जो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं, उनको पैसा अलग से दिया जायें। इसी अभयारण्य में ही एक टाइगर हिल और एक मांधाता बालाजी का मन्दिर आता है, जहां के लिए रास्ता नहीं है तो मांधाता बालाजी के मन्दिर के लिये सुख महल की तरफ से सीढ़ियां बनायी जायें। उसके रास्ते में लाइट लगा दी जाये और मन्दिर में बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है, वह भी करवायी जाये।

(श्री अशोक डोगरा)

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की 14 पंचायतें हैं। वह माइनिंग एरिया कहलाता है, बरड़ क्षेत्र कहलाता है, डाबी एरिया है। वहां सेण्ड स्टोन की माइनिंग होती है। इसमें वन भूमि भी है और राजस्व की भूमि भी है। इन दिनों वहां वैध से ज्यादा अवैध माइनिंग सत्ता पक्ष के नेताओं की शह और मदद से हो रही है। इससे क्षेत्र की माला की मुड़या, प्राणा, गणेशपुरा, लाम्बा खो, बड़पू, फाटीसल्या, बड़पू पठारी, काली घाटी, बागलिया, कमरपुरा, खड़ी, पीलिया, राजपुरा में पड़ने वाले वन विभाग में खनन क्षेत्र मुख्य हैं। इन अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। माननीय खनिज मंत्री जी का इनको पूरा आशीर्वाद है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): यहां एक ही काम हो रहा है और वह है पैसा दो और खान चलाओ। रायल्टी ठेकेदार बिना रसीद के रायल्टी वसूलता है। यहां पर वैध खननकर्ताओं पर अण्डर लोड का प्रेशर है और अवैध खननकर्ताओं पर ओवर लोड की पूरी छूट है, उनको नियमों में पूरी छूट प्राप्त है। वन क्षेत्र में रात भर अवैध खनन होता है, जिससे जंगली जानवर गांवों में आ जाते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, उनकी गाय और बछड़ों को उठाकर ले जाते हैं। इस पूरे अवैध माइनिंग की वजह से राजकीय राजस्व की बड़ी हानि हो रही है और वैध खननकर्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। इसको तत्काल बन्द कराया जाये।

मेरे बूंदी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लालपुरा और बागदा के बीच में एक नदी है, जिस पर पुलिया नहीं है, सैकड़ों काश्तकार 25-30 किलोमीटर का चक्कर काटकर कृषि उपज मण्डी में आते हैं जिससे उनको काफी परेशानी होती है। यदि बागदा और लालपुरा के बीच में एक पुलिया बन जाती है तो 6-7 किलोमीटर में ही किसान अपनी जिन्स को लेकर मण्डी पहुंच जायेगा, नहीं तो ये किसान कोटा मण्डी में चले जाते हैं, बूंदी मण्डी का भी नुकसान होता है। इसी तरह कुरेल नदी पर हनुतिया और जैतसल के बीच में एक पुलिया बनायी जाती है, तो यहां के निवासियों को जिला मुख्यालय आने में 80 किलोमीटर की जो दूरी तय करनी पड़ती है वह मात्र 40 किलोमीटर रह जायेगी।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री मदन प्रजापत।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): एक मिनट सर। इसके निर्माण से जिला

(श्री अशोक डोगरा)

मुख्यालय, खटकड, जैता, रेहाणा, खियाबदा, न्यूत्या से जैतसल, बुलकासा, कापरेण सभी गांव जुड़ जायेंगे और काफी फायदा होगा और एक लास्ट कह दूं मेरे विधान सभा क्षेत्र की सिलोर, नमाणा, गड़दा सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जाये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घन्टा बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय आधा घन्टा बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घन्टा बढ़ाया गया। श्री मदन प्रजापत।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार और माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने जो राजस्थान का बजट पेश किया, इस विधान सभा में 8 बजट मैंने खुद देखे और गत बजट में भी प्रतिपक्ष की तरफ से बातें थीं कि सुनामी बजट है, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, धरातल पर कैसे आयेगा और आज यह बजट देखकर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह साबित कर दिया लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री ने कि भूतो न भविष्यति, न ऐसा शानदार बजट कभी पेश हुआ और न हर मुख्य मंत्री कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह आम मुख्य मंत्री नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि ऊपर वाले ने एक फ़रिश्ते के रूप में एक गरीब की सेवा करने के लिए मुख्य मंत्री के रूप में माननीय अशोक गहलोत जी को भेजा है। माननीय सभापति महोदय, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाले चिन्तित हैं कि पैसा कहां से आयेगा, काम होगा या नहीं होगा, यह चिन्ता पूरा मंत्रिमंडल और लोकप्रिय मुख्य मंत्री और जिनको छत्तीस

(श्री मदन प्रजापत)

कौम की राजस्थान की जनता ने सरकार में जो भेजा है यह चिन्ता उनकी है, जवाबदारी उनकी है, आप चिन्तित क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज जो कर्मचारियों की पेंशन लागू की है यह पूरे देश में एक मॉडल के रूप में पेश किया है। पूरे हिन्दुस्तान में एक नयी बहस छिड़ी है, नयी जंग छिड़ी है और आने वाले समय में केन्द्र सरकार हो या हर स्टेट हो, इसके ऊपर मन्थन करना पड़ेगा। आज किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे पशुपालकों के लिए हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं, चाहे बिजली में अनुदान हो, दूध में अनुदान हो, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो लेकिन इतना होने के बावजूद भी प्रतिपक्ष का तो धर्म बनता है कि बोले तो भी मरना है पक्ष में नहीं बोले तो भी मजबूरी है और एक हमारे मारवाड़ में कहावत है, 'सूअर री मां गटर में मूंडों घाले और रोवा री आवाज करे।' यह हालात हैं। मैं धन्यवाद देता हूं चाहे राठौड़ साहब हो, वास्तव में इनके भाषण सुनते हैं तो तारीफ करते हैं लेकिन कई कोशिशों के बावजूद इस बार भाषण फीका था, कोई रंग नहीं था क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने जिस तरीके से जो बजट पेश किया है वास्तव में क्या तारीफ करूं, चाहे मोबाइल देने की बात हो, मैं विशेष रूप से लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि पीसीपीआईआर जोन की भारत सरकार ने भी मंजूरी दे दी और यह हिन्दुस्तान का पांचवां पीसीपीआईआर जोन है जो एक हजार करोड़ रुपये रिफाइनरी से जोधपुर के बीच में और पूरे बाड़मेर जिले में एक हजार करोड़ रुपये औद्योगिक क्षेत्र के लिए खर्च होंगे, इससे बड़ी सौगात हो ही नहीं सकती है।

माननीय सभापति महोदय, समय भी काफी हो गया है और भी बातें हैं लेकिन मुख्य बात जो गरीब के इलाज के लिए पांच से दस लाख और दुर्घटना में पांच लाख रुपये और तमाम जो किया है उसकी वास्तव में तारीफ मैं क्या करूं, पूरे राजस्थान में, पूरे हिन्दुस्तान में एक नयी बहस कि वास्तव में इतना शानदार मैनेजमेंट, शानदार बजट कोई दे सकता है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी दे सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान में कई जिलों की मांग भी उठी लेकिन विशेषकर मेरा निवेदन है कि आज मुझे दूसरी बार राजस्थान की जनता ने राजस्थान की विधान सभा में

(श्री मदन प्रजापत)

भेजा और मुझे खुशी इस बात की है कि दोनों बार सरकार बनी और मुख्य मंत्री लोकप्रिय अशोक गहलोत जी बने और आज जो मैं मांग कर रहा हूं, सत्ता पक्ष का विधायक हूं और मुख्य मंत्री जी हमारे आदर्श हैं उनकी प्रेरणा से मैं यहां पहुंचा है। आज उनके आशीर्वाद से हम यहां पहुचे हैं और मैं लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी से उम्मीद नहीं करूंगा तो दूसरों से उम्मीद मैंने न तो आज तक की है और न कर सकता हूं और वास्तविक धरातल पर देखें तो अन्तिम छोर का सिवाना का जो रामपुरा गांव है 225 किलोमीटर जिला हैडक्वार्टर से दूर है। चाहे निर्माणाधीन रिफाइनरी है, वहां से 100 किलोमीटर दूर जिला हैडक्वार्टर है और एक लाख करोड़ का प्रोजेक्ट और 100 किलोमीटर जिला दूर है और जिला अस्पताल हमारे बन गया, एडीएम आफिस बन गया, श्रम कार्यालय हो, उद्योग कार्यालय हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सब हैं, सिर्फ जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय की हमारी मांग है। बाकी सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। पीसीपीआईआर एक जोन है और रिफाइनरी हमारा बड़ा मजबूत आधार है कि 28 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया आज बाड़मेर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है और 28 हजार में मात्र 8 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया की हम मांग करते हैं कि हमारा 8 हजार वर्ग किलोमीटर..

श्री सभापति: कृपया शान्त रहें। आवाज नहीं। माननीय सदस्य, अपने-अपने स्थान पर जायें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): और सौ किलोमीटर दूरी है तो रिफाइनरी को आधार मानते हुए माननीय सभापति महोदय, कि रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्पेशल जिला घोषित किया जाता है तो मैं प्रेम से मांग कर रहा हूं, कोई अदरवाइज या उलटा नहीं लें कि मैं विरोध कर रहा हूं, मैं मेरे नेता मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का कभी विरोध नहीं कर सकता लेकिन मुझे उम्मीद है और पूरे प्रेम से उम्मीद से मांग कर रहा हूं कि मेरी भावना है, यह मांग मेरी नहीं, हमारे पूरे बाड़मेर जिले के प्रस्तावित जिले के और मुझे खुशी है कि बाड़मेर जिले के हम सात एमएलए हैं, एक बीजेपी से और 6 कांग्रेस से, सातों ही सर्वसम्मति से इस फैसले से कोई नाराज नहीं है, यह अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है और सभी ने जो आशीर्वाद दिया है, चाहे माननीय हेमाराम जी एकमात्र मंत्री जिले से हों, चाहे हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक अमीन साहब हों, चाहे मेवाराम जी हों, चाहे भाई

(श्री मदन प्रजापत)

पदमाराम जी हों, चाहे पूर्व मंत्री हरीश जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमीर सिंह जी हों, इसमें कोई असहमत नहीं है और सबकी सहमति होना यह अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। बाकी कई मांगें हैं, चाहें एससी एसटी होस्टल कल्याणपुर में हो, चाहे ए.ईएन. पानी का और बिजली का हो लेकिन हमारी मुख्य मांग जो है वह जिले की है और बाकी मांगें मैं लिखित में दे दूंगा। ज्यादा समय हो गया है लेकिन मैं प्रेम से पुन: निवेदन करता हूं क्योंकि गत बार के बजट में, अपने घोषणा पत्र में भी है और आधार भी है और कई स्टेट और कई जिलों से बाड़मेर बड़ा है इसलिये हमारी जायज मांग है और रिफाइनरी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कभी कोई हादसा, कोई अनहोनी हो जाए तो सौ किलोमीटर से प्रशासक आकर क्या देखरेख कर सकता है? सबसे बड़ा आधार है तो वह रिफाइनरी है। पीसीपीआईआर जोन एक हजार करोड़ का है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): और भी हैं। माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत पुन: हमारे लोकप्रिय, क्रान्तिकारी, गरीबों के मसीहा माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत से निवेदन करता हूं कि हमारी इस मांग को गहराई से मन्थन करते हुए इस बजट के जवाब में बालोतरा जिले की सौगात दें। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, बजट परिचर्चा पर मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में तीन साल में बजट में कोई एक भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस सरकार जनता से जो वादे करके सत्ता में आयी, उन वादों पर खरी नहीं उतरी और लगातार हमारे प्रदेश के बेरोजगार भाई हर परीक्षा में बिलकुल अपनी आत्मा से सरकार को नकार रहे हैं, वो आस लेकर बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने घोषणायें की हैं वो थोथी घोषणायें हैं। मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में एक सड़क की घोषणा की थी पिछले बजट में लेकिन वह कार्य भी अभी तक चालू नहीं हुआ और जब हमने वहां धरना-प्रदर्शन आंदोलन किया तो डीएमएफटी में वह राशि स्वीकृत की, उसके बाद कार्य चालू हुआ।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

सभापति महोदय, मैं मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख मांगों को रखना चाहता हूं। एक सड़क जो बजट में प्रस्तावित की गयी उस सड़क को कोटड़ी-अगरपुरा से लेकर कोटड़ी-पण्डेर-गन्देर सड़क बजट में प्रस्तावित की गयी है, उसको मैं कोटड़ी में जो एक हमारे सम्भाग का चारभुजानाथ का मन्दिर है वहां बाईपास इसमें सम्मिलित किया जाए। सम्माननीय, हमारे इस बजट में जो प्रस्ताव लिया गया है उस सड़क को मैं बाईपास की मांग करता हूं। हमारे जहाजपुर में पीपलून में आये दिन हमेशा जाम लगा रहता है इसमें भी एक बाईपास की मांग करता हूं मैं।

मैं मेरे जहाजपुर क्षेत्र की कुछ मांगें रखना चाहता हूं। उपखण्ड जहाजपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे-148 निकला हुआ है, आये दिन दुर्घटना होती रहती है। अभी दो घण्टे पहले एक जवान की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी राजेश सोनी की तो मैं ट्रोमा सेंटर खोलने की मांग करता हूं और साथ ही भीलवाड़ा जिला मुख्यालय की दूरी 100 किलोमीटर पड़ती है, इसलिए ब्लड बैंक की स्थापना की मांग करता हूं। हमारे जहाजपुर में लुहारीकलां के 10 हजार सैनिक देश की रक्षा में सेवा दे रहे हैं। इन सैनिक भाइयों को दूरदराज जाने के लिये 15-20 किलोमीटर सीएचसी देवली, सीएचसी जहाजपुर आना पड़ता है। अत: लुहारीकलां पीपीपी मोड से संचालित है, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को मैं सीएचसी में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। इसी तरह अम्बरगढ़ सबसेंटर को पीएचसी में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। हमारे सीएचसी खजूरी की 2019-20 के बजट में सरकार ने सीएचसी की घोषणा की थी, भवन निर्माण के लिये भूमि आबंटन कर हमने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये लेकिन अभी तक राशि स्वीकृत नहीं की गई। मुख्य मंत्री जी सिर्फ घोषणा करते हैं। मैं मांग करता हूं कि सीएचसी खजूरी के भवन निर्माण के लिये राशि आबंटन की जाय। इसी तरह हमारे क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्र विधान सभा क्षेत्र में जहां-जहां क्षतिग्रस्त हैं, उन भवनों का नया निर्माण करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जर्जर हैं, उनकी भी मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के लिये राशि स्वीकृत की जाय।

इसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिलिकोसिस के मरीजों को मृत्यु के बाद 5 लाख की आर्थिक सहायता मिलती है। उस 5 लाख राशि को बढ़ाकर 10 लाख अनुदान राशि देने की मैं मांग करता हूं। संविदा कार्मिकों, कोविड हैल्थ सहायक, पंचायत सहायक, रोजगार सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा

(श्री गोपी चन्द मीणा)

सहायक को 8-10 हजार मानदेय मिल रहा है, उनका मानदेय बढ़ाकर 25 हजार या स्थायीकरण करने की सरकार से मांग करता हूं।

जहाजपुर एक पिछड़ा क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में बजट 2019-20 में हमारे यहां कालेज खोला, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन तीन साल बाद भी, बजट घोषणा करने के बाद भी राशि आबंटन नहीं की। हमने वहां प्रयास करके डीएमएफटी से बजट स्वीकृत कराया। उसकी चारदीवारी के निर्माण की मैं मांग करता हूं। जहाजपुर में आदिवासी लोग है, जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी है तो मैं कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग भी साथ ही करता हूं। मुख्य मंत्री जी रिप्लाई दें तो इसकी घोषणा करें। कोटड़ी उप खण्ड क्षेत्र में भी नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। जहाजपुर की ग्राम पंचायत धौड़ में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की मांग करता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सरसिया तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गडबोदिया को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक किये जाने की मांग करता हूं। कोटड़ी के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आगरिया को क्रमोन्नत कर माध्यमिक किये जाने की मांग करता हूं। जहाजपुर क्षेत्र के अंतर्गत क्रमशः रोपा, पण्डेर, कुराडिया, शक्करगढ़, खजूरी, लुहारीकलां, धौड़ एवं उप खण्ड मुख्यालय कोटडी परिक्षेत्र के अंतर्गत क्रमशः सवाईपुर, रेडवास, बीरधोल तथा पारोली में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्वीकृति की मांग करता हूं। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में लोग राजकीय महाविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की आबंटन भूमि में कब्जा कर अतिक्रमण कर लेते हैं, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि चार दीवारी निर्माण के लिये या तो नरेगा में अनुमत की जाय या डीएमएफटी में आदेश जारी करें ताकि अतिक्रमण से सरकारी विद्यालय भूमि हम बचा सकें और वहां चारदीवारी निर्माण हो सके।

इसके साथ ही राजकीय महाविद्यालय जहाजपुर में भवन के चार दीवारी निर्माण की स्वीकृति की मांग करता हूं। इसी तरह जहाजपुर में शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। खेलों को बढ़ावा देने के लिये इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम की कोटड़ी और जहाजपुर उप

(श्री गोपी चन्द मीणा)

खण्ड मुख्यालय पर खेल स्टेडियम खोलने की मांग करता हूं। जनजाति क्षेत्र होने के कारण जनजाति बालिका आवासीय छात्रावास ग्राम पंचायत सरसिया, बेई, इटुन्डा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खोलने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय मंत्री महोदय आज भी कह रहे थे कि 50 हजार से ज्यादा आबादी या 50 प्रतिशत से ज्यादा है वहां एकलव्य मॉडल स्कूल की भी मांग करता हूं।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण। समाप्त करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, टेबल करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के गांधी आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा एक शानदार एवं जानदार बजट पेश किया गया। इस बजट के बाद जहां विपक्ष के साथी दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर थे, वहीं पूरे राजस्थान की जनता में एक खुशी का माहौल था। यह पहली बार देखा गया कि बजट आने के बाद राजस्थान का युवा, राजस्थान के युवा कर्मचारियों ने होली और दीवाली एक साथ मनाई। वह सड़कों पर आकर रंग गुलाल खेलते हुए, पटाखे बजाते हुए, डीजे पर नाचते हुए जय जयकार के नारे लगा रहे थे, जननायक के नारे लगा रहे थे कि ऐसा मुख्य मंत्री न राजस्थान में कभी आया, न कभी देश में आया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह दिखा दिया कि राजस्थान की आठ करोड़ जनता के लिये, राजस्थान की 36 कौम बिरादरी के लिये, राजस्थान के हर वर्ग के लिये चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह कृषक हो, इस बजट में सभी वर्गों के लिये उन्होंने ऐसे कार्य किये जिससे आज पूरा राजस्थान का युवा, राजस्थान का प्रत्येक वर्ग का नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमने 2018 में जो मतदान किया वह सही व्यक्ति के लिये किया क्योंकि अब राजस्थान के गांधी मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को बनाकर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनाई थी, आज उनको उसका हक मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में किस-किस क्षेत्र की बात करें, इस बजट के बारे में बताना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। अगर हम

(श्री अमित चाचाण)

पूरे बजट की बात करें तो शायद कई दिन लग सकते हैं। लेकिन चूंकि समय का अभाव है, मैं मुख्य बिन्दुओं पर ही अपनी बात रखना चाहता हूं। आज कर्मचारी वर्ग, राजस्थान में लाखों कर्मचारी हैं, वर्ष 2000 के बाद हमारे युवा भाई बहन कर्मचारियों में पहले निराशा थी कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा। भाजपा सरकार ने जो यह पुरानी पेंशन बंद कर दी, बुढ़ापे में किस तरह हमारा गुजारा चलेगा? लेकिन मुख्य मंत्री जी ने उनके दुःख दर्द को समझते हुए पुरानी पेंशन को बहाल किया। राजस्थान ही नहीं पूरे देश में यह उदाहरण बना और अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी कहा कि जो भाजपा ने गलती की थी, वह कांग्रेस के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने सुधारी है और आज पूरे देश में यह मांग मुखर रूप से उठने लगी है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मुख्य मंत्री जी ने गरीबों का, आमजन का, मध्यम क्लास का दर्द समझते हुए अपने हर कार्यकाल में चाहे वह नि:शुल्क मुख्यमंत्री चिरंजीवी दवा योजना हो, नि:शुल्क जांच योजना हो, हर बार उन्होंने ऐसा काम किया, क्योंकि आज किसी के घर में कोई भी बीमारी आ जाती है तो वह मध्यम क्लास का हो, चाहे वह गरीब आदमी हो, वह आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। उनके दर्द को समझते हुए मुख्य मंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया कि राजस्थान के प्रत्येक राजकीय चिकित्सालय में नि:शुल्क ओपीडी और आईपीडी होगी। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चलाई गई थी, उसका दायरा भी बढ़ाते हुए 5 लाख से 10 लाख रुपये करने का काम किया। इसके साथ ही कोकलर इम्प्लांट, बोनमैरो, ब्लड कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों को शामिल करते हुए आज पूरे राजस्थान की जनता को राहत देने का काम किया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी, जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा कि नरेगा एक सहारा थी, ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्ति जीवन यापन कर रहे थे। मुख्य मंत्री जी ने उसका दायरा बढ़ाते हुए 100 दिन के साथ 125 दिन किया, जिसका लगभग राज्य सरकार पर 750 करोड़ रुपये का भार आयेगा। इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी 100 दिवस के लिये शुरू की, जिसके तहत भी 800 करोड़ रुपये राज्य सरकार पर भार आयेगा लेकिन उन्होंने पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति को, कमजोर और गरीब व्यक्ति को राहत देने का एक सराहनीय कार्य किया है।

(श्री अमित चाचाण)

इसके साथ ही बिजली में जो गरीब आदमी पर भारी भरकम बोझ पड़ता था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक शानदार पहल करते हुए 100 यूनिट तक 50 यूनिट बिजली को मुफ्त करने का काम किया, 100 से 150 यूनिट तक तीन रुपये अनुदान, 150 से 300 यूनिट तक दो रुपये अनुदान देकर उन्होंने गरीब और मध्यम परिवार को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में तो जब से सरकार बनी है लगातार नवाचार करते आ रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीयेगा उतना दहाड़ेगा। हमें मुख्य मंत्री जी पर गर्व है कि उन्होंने ऐसी शानदार व्यवस्था की कि आज हमारे राजस्थान के युवा साथियों का राजकीय विद्यालयों की तरफ रुझान बढ़ा है और लगभग दस लाख से ज्यादा नामांकन बढ़े हैं। गरीब परिवार के बच्चों का सपना था कि वे भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में जायेंगे। मुख्य मंत्री जी ने पहले 1,250 विद्यालय खोलने की घोषणा की और इस बजट में शहर और ग्रामीण क्षेत्र में एक-एक हजार राजकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलकर गरीब बच्चे के सपने को साकार करने का जो काम किया है, उसके लिए हम मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं।

इसके साथ ही, उन्होंने समानता से देखते हुए 200 विधान सभा क्षेत्रों में, 3,820 स्कूलों को दसवीं से बारहवीं करने का जो साहसिक कार्य किया है, उसके लिए भी हम मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। मुख्य मंत्री जी ने कभी पक्ष और विपक्ष नहीं देखा, वे आठ करोड़ जनता को समानता की भावना से देखते हुए और 200 विधायकों को एक समान देखते हुए, उन्होंने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समानता के साथ कार्य करने का काम किया है, इसलिए हम मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं।

आज सड़कों की बात करें। गांव हो या शहर हो, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका सड़कों की रहती है। मुख्य मंत्री जी ने गत बजट में 5 करोड़ रुपये प्रत्येक विधायक को दिये और इस बार भी उन्होंने 10 करोड़ रुपये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए दिये। नगर निगम में 40 किलोमीटर, नगर परिषद् में 25 किलोमीटर और नगरपालिका क्षेत्र में 15 किलोमीटर की सड़कें देने की जो सौगात दी है, उसके लिए भी हम मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं।

उन्होंने पहले घोषणा की थी कि कृषि का बजट अलग से पेश किया जायेगा। किसानों को राहत देते हुए, क्योंकि मुख्य मंत्री जी जानते हैं, वे गरीब

(श्री अमित चाचाण)

को गणेश और किसान को भगवान मानते हुए अन्नदाता को भगवान मानते हैं। वे जानते हैं कि हमारा क्षेत्र और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसानों के हाथ मजबूत करने से ही देश और राज्य में विकास के नये आयाम स्थापित किये जा सकते हैं। इसलिये उन्होंने कृषि के बजट को अलग से पेश किया। मुख्य मंत्री कृषि साथी योजना में 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपये करने का काम किया है।

इसके अलावा हर एक क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी ने एक सराहनीय कार्य किया है। समय का अभाव है। सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का बताना चाहता हूं। मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओं ने तीस साल के बाद अपने स्थानीय बेटे को विधायक चुनकर भेजा। इन तीस सालों में बाहरी क्षेत्र से विधायक बनकर आते रहते थे। उन्होंने कभी नोहर विधान सभा क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा। जब अपने जाये-जन्मे और बेटे को राजस्थान की विधान सभा में भेजा और उनके बेटे ने क्षेत्र की समस्याओं के लिए उन सभी की आवाज को बुलन्द करते हुए राजस्थान की विधान सभा में रखा और मुख्य मंत्री जी को अवगत कराया तो नोहर क्षेत्र की जनता को पता चल गया कि अपना क्या होता है और पराया क्या होता है? शायद तीस वर्षों में उन्होंने बजट में कभी नोहर का नाम नहीं सुना था, लेकिन मुझे यह गर्व है कि हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने लगातार चार बजटों में नोहर विधान सभा क्षेत्र में अनेकों सौगातें दीं, जिसके लिए नोहर क्षेत्र की जनता दशकों से इन्तजार कर रही थी। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले तीन बजटों में घोषणायें नहीं, उन पर धरातल पर भी काम हुआ है। सारी घोषणाओं को धरातल पर उतारा गया। उसके लिए मैं खुद प्रयत्नशील रहा। चाहे मुझे मंत्री जी के पास जाना पड़े, चाहे किसी अधिकारी के पास जाना पड़े या फिर मुख्य मंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे मुझे दानदाताओं को प्रेरित करके उनसे पैसा लाना पड़े, सभी काम किया।

इसके साथ ही, एक बड़ी घोषणा, जिससे हमारा क्षेत्र वंचित है। नोहर-भादरा के 28 गांवों को सिंचित करने की मैं मांग करता हूं। नहर के किनारे होने के बावजूद भी वे आज तक सिंचित नहीं किये गये हैं।

इसके साथ ही राजकीय चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं। नोहर के राजकीय चिकित्सालय में ब्लड की आवश्यकता होती है तो हरियाणा से लाना पड़ता है, मैं ब्लड बैंक की

(श्री अमित चाचाण)

स्थापना की मांग करता हूं।

नोहर में सावित्री बाई फूले कन्या महाविद्यालय स्तर के छात्रावास की मैं मांग करता हूं। इसके साथ ही पल्लू तहसील जो कि अभी क्रमोन्नत की है, उसमें 70 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है तो मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय की सौगात देकर क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। एक बार फिर आपका धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा देवी।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि पहले के बजट में मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में ट्रोमा सेन्टर की घोषणा की थी, अभी तक ट्रोमा सेन्टर नहीं है। मैंने 100 बैड के अस्पताल की मांग उठायी, मैंने पहले भी दो बार मांग उठायी है, पर अभी तक 100 बैड का हास्पिटल मेड़ता सिटी में नहीं बना है। मेड़ता सिटी में जो पुराना हास्पिटल है, उसके लिए गांव वालों व शहर के लोगों की यही मांग है कि उसमें एक लेडी डाक्टर लगा दें तो महिलाओं को राहत मिलेगी। मैंने मुख्य मंत्री जी को लैटर भी दे दिया और मैं मांग भी करती हूं कि ट्रोमा सेन्टर बने तो अच्छा रहेगा। जो मेड़ता रोड है, वहां पर लोग धरने पर बैठ गये कि मेड़ता रोड नगरपालिका होना चाहिए। मैंने उनको आश्वासन देकर धरने से उठाया। मैं मुख्य मंत्री जी से यह मांग करती हूं कि मेड़ता रोड में नगरपालिका होनी चाहिए। मेड़ता रोड में जो पीएचसी है, वह सीएचसी बननी चाहिए। मोकलपुर और इन्दावड़ गांव के लिए आपने पीएचसी की घोषणा की थी, अभी तक वे पीएचसी नहीं बनी हैं तो मैं सरकार से यही मांग करती हूं कि पीएचसी जल्दी बने। आपने मेड़ता सिटी में कन्या महाविद्यालय की घोषणा की थी, अभी तक वह कन्या महाविद्यालय नहीं बनी है तो उसकी भी मैं आपसे मांग करती हूं कि कन्या महाविद्यालय बने तो कन्या अच्छी तरह पढ़ सके और आगे बढ़ सके। मेड़ता से गोटन सड़क है, वह बहुत टूटी हुई है तो मैं सरकार को कहना चाहती हूं कि आप जल्दी ही घोषणा करके उस रोड को बनवायें। जारोड़ा और लाम्बा गांव में पीएचसी की जरूरत है तो मैं आपसे और सरकार से मांग करती हूं कि जारोड़ा और लाम्बा के लिए आप पीएचसी की घोषणा करें।

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

मैं भी आपसे एक मांग करती हूं कि लाम्पोलाई गांव के लिए विद्युत के कर्मचारियों को मैं तीन साल से बोल रही हूं, पर अभी तक लाम्पोलाई गांव आज तक लाइट नहीं आयी है, वहां छोटी चिमनी जलाते हैं। मैं आपसे और सरकार से निवेदन करती हूं कि आप जल्दी ही मेरे काम करवायें। आज तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है तो मैं आपसे मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र को बजट दें और घोषणा करें। मेरे मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में गंदे पानी की नाली है और बरसात के पानी की नाली है, पानी के निकासी के लिए कुछ नहीं है तो आप बड़े नाले की घोषणा करें। मेड़ता सिटी में गटर का पानी नाली में जाता है, मैं मांग करता हूं कि मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में एक नाले की घोषणा हो जाये तो गंदे पानी की निकासी हो सकेगी। मैं मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन करती हूं आप घोषणा करके मेरा हौसला बढ़ायें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 20 मिनट बढ़ाकर 08 बजकर 20 मिनट तक किया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 20 मिनट बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय 20 मिनट बढ़ाया गया।

श्री रामलाल।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले तो आवश्यक रन पूरे कर दूं, उसके बाद बैटिंग करूं, क्योंकि समय कम है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाये उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने सभी वर्गों, सभी समाजों, सभी धर्मों और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अरनोद उपखण्ड में एक कालेज की घोषणा भचुण्डला के लिए

(श्री रामलाल मीणा)

करें। दलोट और सहाणपुरा को सीएचसी करें। खेरोड़, मौखमपुरा, पानमोड़ी, गादोला को पीएचसी करें। बोरी को, पण्डावा को, जालर, पाल को पीएचसी करें। उसके बाद गोतमेश्वर जो कि आदिवासियों के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, वह पूरे सम्भाग का तीर्थ है। वहां इतना बढ़िया काम अपने कार्यकाल में हो रहा है। सभी तरफ सड़कें बन रही हैं, वहां पर एक और सड़क का निर्माण हो जाये उसके लिए भी मैं चार करोड़ रुपये की मांग करता हूं।

मेरे क्षेत्र में एमबीसी वर्ग के लोग भी बहुत रहते हैं, इसलिए उनके लिए भी एक आवासीय विद्यालय या हॉस्टल की मांग करता हूं। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी हॉस्टल या आवासीय विद्यालय की मांग करता हूं। जिस प्रकार से मेरे यहां पर 70 पंचायतें हैं, उन सभी पंचायतों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र की मांग करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में जिस प्रकार से घोषणायें की हैं, उन घोषणाओं से यह लगने लग गया है कि विपक्ष के साथियों के साथ सांप-छछूंदर वाली बात हो गयी है, क्योंकि वे न तो बजट की बुराई कर सकते हैं और न ही प्रशंसा कर सकते हैं। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने ओपीएस लागू करके वह काम किया है, पूरे देश की सरकारों की आंखें खोल दी हैं। आज माननीय मुख्य मंत्री जी की वजह से ही सभी सरकारें सोचने को मजबूर हो गयी हैं और सभी जगह पर लागू करने की बातें हो रही

(समय: 20.00 बजे)

हैं। इन्होंने 2004 के अंदर ओ.पी.एस. को बन्द करके कर्मचारियों के साथ कपड़े उतारकर लंगोट पकड़ाने का काम किया है। आज जिस प्रकार से ओ.पी.एस. लागू होने के बाद में पूरे राजस्थान के अन्दर कर्मचारियों में खुशी है। ऐसे मुख्य मंत्री की परिकल्पना लोगों ने नहीं की होगी जो माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को भगवान मानकर कर्मचारी उनके लिए भोग चढ़ा रहे हैं, जगह-जगह आपने देखा होगा नाचते-गाते हुए। यह बात इनको हजम नहीं हो रही है इसलिए ये कह रहे हैं कि इतना खर्चा होगा, पैसा कहां से लाएंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो 19 हजार करोड़ के भार को भी नहीं देखते हुए क्षेत्र के इतने सारे कर्मचारियों के लिए सहयोग की बात की है। आज वे बुढ़ापे का सहारा बने हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ओपी.एस. लागू करके सभी कर्मचारियों के हित का काम किया है। बुढ़ापे का सहारा आप बने हैं। बुढ़ापे में उनका बेटा बनकर आप काम कर रहे हैं।

(श्री रामलाल मीणा)

मैं इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं, आपने वैसे तो पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसाकर्मी और पंचायत सहायक सभी का 20 परसेंट मानदेय तो बढ़ाया है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा टीचर्स और पंचायत सहायकों का अलग से कैडर बनाकर इनको नियमित करने की मांग भी करता हूं। जब केन्द्र में यूपी.ए. की सरकार थी तब देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए क्या किया जाए? सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने नरेगा योजना लागू करके 100 दिवस का रोजगार देना अनिवार्य किया। जैसे ही नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आयी। आते ही उन्होंने देखा कि लेबर को अगर रोजगार गारंटी मिलेगी तो अडाणी-अंबानी का क्या होगा? उन्होंने रोजगार गारंटी को खड्ढ़ा खोदने की स्कीम कहा और इसको बन्द करने की कार्यवाही की। लेकिन इनको यह पता नहीं था कि रोजगार गारंटी एक अधिनियम है, इसको बन्द नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में धीरे-धीरे हर साल के बजट में रोजगार गारंटी अधिनियम के, रोजगार गारंटी योजना के बजट को वह कम करते गये, कम करते गये। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने हर बार मजदूरों का ध्यान रखते हुए, इस बार तो कुछ नया ही उन्होंने कर दिया, 100 दिवस से बढ़ाकर राज्य सरकार के खर्चे से 125 दिवस करने का काम माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने किया है। गरीबों का, मजदूरों का हर कोई भला नहीं कर सकता है। माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने किया है।

सभापति महोदय, आज मैं इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 125 दिवस रोजगार गारंटी में पूरे राजस्थान के किये हैं। हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र के अन्दर गरीबी बहुत है, रोजगार के साधन नहीं है। गुजरात और जोधपुर पलायन करना पड़ता है। रास्ते में कई घटनाएं घटित हो जाती हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए, टी.एस.पी. क्षेत्र के लोगों के लिए स्पेशल 150 से 200 दिन कीजिए ताकि आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो काम किये हैं, आज शहर के अन्दर गरीब तबके के जो लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, उनके ऊपर ध्यान आज तक किसी का नहीं गया लेकिन माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब जो गरीबों के भगवान हैं, उन्होंने देखते ही पीड़ा को महसूस किया कि शहर के अन्दर किस प्रकार से गरीब अपना जीवन-यापन करता है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): उन्होंने तुरन्त इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू करके 100 दिवस का रोजगार शहर के अन्दर भी दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपने चिरंजीवी योजना 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की। पहले मैं बीच में सुनता था लोग कहते थे मुख्य मंत्री जी ने चिरंजीवी योजना से हमारा 5 लाख का इलाज करवा दिया, 2 लाख हमको ऊपर से और देने पड़ेंगे क्योंकि 7 लाख का बिल बना था, लेकिन इस बार तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 लाख रुपये कर दिये। यहां तक कि दुर्घटना बीमा के लिए भी एक स्कीम लागू कर दी।

बिजली के अन्दर आपने देखा ही होगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, क्योंकि पूर्व की सरकार के अन्दर बिजली तार के अन्दर नहीं आती थी, बिजली बिलों के अन्दर आती थी लेकिन आज दिन में लाइट देने का काम, प्रतापगढ़ के अन्दर सबसे पहले दिन में लाइट और इतने जी.एस.एस. नये खोले, पुराने जी.एस.एस. को डबल केपेसिटी किया। यहां तक कि किसानों को बाढ़ के अन्दर, अतिवृष्टि के अन्दर फसलें खराब हो जाती थीं तो बिजली का बिल नहीं भर पाते थे, किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करके एक हजार रुपया महीना बिजली का बिल भरने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसके बाद में घरेलू के अन्दर भी 50 यूनिट तक की बिजली फ्री कर दी और उसके बाद में कई सारी सब्सिडियां उन्होंने दी हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि बजट अलग से पेश किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जैसे छोटे-से जिले के अन्दर भी कृषि महाविद्यालय और नर्सिंग कालेज आपने दिया है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

पानी के लिए भी आपने पूरे प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सहित बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के धमोतर पंचायत समिति के सभी गांवों के घर-घर नल कनेक्शन के लिए 1,620 करोड़ रुपये आपने स्वीकृत किये। माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने 60 करोड़ रुपये की सड़कें प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में देकर रोकड़िया हनुमान जी को डबल पट्टी से आपने जोड़ा। आपने लुहारिया होते हुए नकोर होते हुए बारवरदा को डबल पट्टी से जोड़ा।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए। श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): आपने मोखमपुरा होते हुए डाबडा को डबल पट्टी से जोड़ा। बहुत-बहुत धन्यवाद साहब।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): सभापति महोदय, सरकार के बजट 2022-23 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत आभार। मैं इस सदन के सदस्य के रूप में वर्ष 2019-20 से माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण सुन रहा हूं। मुझे तो केवल एक बात समझ में आयी कि पुरानी बातों को भूलता चल, नई बातें करता चल। घोषणाओं का हिसाब बताते तो अच्छा रहता। मैं निवेदन करूंगा कि सदन के नेता जब इसका उत्तर दें तो जो पुरानी बजट घोषणाएं हैं, अब तक जमीन पर नहीं उतरीं, उनके बारे में भी विचार व्यक्त करें।

राजस्थान की वर्तमान सरकार ने दो काम प्रमुखता से किये हैं। एक तो वसुन्धरा राजे जी की सरकार की योजनाओं का नाम बदल दिया गया। भामाशाह कार्ड को जन आधार कार्ड कर दिया और अन्नपूर्णा रसोई को इंदिरा रसोई कर दी है। क्या सरकार बदलते ही नाम बदल देना, यह विकास है? माननीय मुख्य मंत्री जी की पिछली बजट घोषणाएं अधूरी रह गयीं क्योंकि इनका अधिकतर समय अपने विधायकों की सार-संभाल, मान-मनौवल व बाड़ाबन्दी में निकल गया। ऐसी स्थिति में पुराने बजट की अधूरी घोषणाओं के लिए समय नहीं मिल पाता होगा। जो घोषणा समय पर पूरी न हो, उसका अर्थ ही क्या रह जाता है? एक विद्वान ने कहा, विलम्ब से मिला हुआ न्याय भी एक प्रकार का अन्याय है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के बिन्दु संख्या 29 में प्रदेश में 100 राजकीय विद्यालयों में वृहद् मरम्मत करने की घोषणा की। मेरे विचार से यह संख्या अत्यन्त न्यून है। केवल मेरे विधान सभा में 80 से अधिक राजकीय विद्यालय हैं, जो पुराने जीर्ण-शीर्ण और जर्जर हो गये हैं। सरकार को इन भवनों के लिए समुचित राशि का प्रबन्ध करना चाहिये।

मान्यवर, राजस्थान के रोडवेज कर्मचारी, संविदा कर्मचारी व प्रदेश के बेरोजगार युवा आपके वादों को लेकर आपका इन्तजार कर रहे हैं। वे बार-बार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, रीट परीक्षा के नाम पर बेरोजगारों के साथ जो छलावा और कुठाराघात किया गया, वह दुखद है। रीट का पेपर आउट हो गया, परीक्षा को निरस्त किया गया। मैं सोशल मीडिया पर देख आश्चर्य कर रहा था कांग्रेस के लोग परीक्षा निरस्त करने पर मुख्य मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। रीट की परीक्षा को निष्पक्ष व सुचारु रूप से न करा पाने का अपराधबोध होने की जगह रीट परीक्षा निरस्त करने की बधाई दी जा रही है। इससे अधिक आत्म प्रशंसा और आत्म मुग्धता और क्या हो सकती है? युवाओं को रोजगार की मृग-मरीचिका दिखाकर आप राज में तो आ गये। युवा बार-बार परीक्षा का फार्म भरता है, फीस भरता है, कोचिंग करता है

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

और परीक्षा निरस्त हो जाती है। अब तो हालात ये हो गये हैं कि मेरे क्षेत्र में मिलने वाले लोग, बेरोजगार युवा मुझे नाथी के बाड़े का पता पूछते हैं।

राइट टू हैल्थ, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, पत्रकार बन्धुओं की सुविधाएं, जनता क्लिनिक की घोषणाएं अभी-भी अधूरी हैं। प्रस्तुत बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की उपेक्षा हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि कुछ नजरें इनायत विपक्षी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों पर रखा करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट बिन्दु संख्या 31 में प्रदेश के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। मान्यवर, बजट में घोषणा करके आप तीन साल में भवन ही नहीं बना सके, ये कन्या महाविद्यालय और कक्ष कैसे खुलेंगे? ये ईश्वर ही जानता है। खेल स्टेडियम की आपने पहले बजट में घोषणा की थी परन्तु मेरे माण्डलगढ़ और बिजौलिया उपखण्ड में कुछ भी धरातल पर नहीं हुआ है।

मेरे क्षेत्र में मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे बिजौलिया बहुत बड़ा कस्बा है, वहां विकास के लिए कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए नगरपालिका की जवाब दें तब घोषणा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजौलिया में जो नेशनल हाईवे हैं और खनन क्षेत्र है, वहां पर आपने पहले वाले 2020-21 के बजट में ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा की थी, परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

वर्तमान में सरकार द्वारा एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. वर्ग की भांति ई.डब्ल्यू.एस., आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षण संस्थानों व उच्च अध्ययन संस्थानों तथा प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों को छात्रवृत्तियां का लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्य मंत्री जी बजट भाषण का जवाब दें तब ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग की प्रतिभाओं को एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. वर्ग की भांति छात्रवृत्तियां प्रदान करने की घोषणा करें।

जिला मुख्यालय से माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र दूर है। वहां ओ.बी.सी. वर्ग के छात्र-छात्राओं को मुख्यत: पूर्ण शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि बजट भाषण में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा करें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): देवनारायण भगवान की जयन्ती माही सप्तमी को राजकीय अवकाश की घोषणा करें क्योंकि सभी देवताओं के जन्मदिन पर छुट्टी रहती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा से साठ

(श्री गोपाल लाल शर्मा)
किलोमीटर दूर होने से यहां माण्डलगढ़ में अस्थायी एडीजे कोर्ट चार साल से संचालित है, परन्तु बजट में घोषणा नहीं होने से, उस क्षेत्र के वासी निराश हैं, इसलिये एडीजे कोर्ट खोलने की घोषणा करें।

माण्डलगढ़ में परिवहन विभाग भी नहीं है। भीलवाड़ा से 100 किलोमीटर दूर होने से आम जनता को आने-जाने में परेशानी होती है, यह खोलने की भी कृपा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कें बिलकुल खराब हैं। अब तक कोई काम नहीं हुआ। बिजौलिया से शकरगढ़ रोड बिलकुल टूट चुकी है। महुवा से जलेदरी सड़क, पहले वाले बजट में घोषणा की पर अब तक कुछ नहीं हुआ। भीलवाड़ा से गेंदया सड़क, कोटली से काचूला व गवली, ककुढा घाटी, राजगढ़ होते हुए जाती है, रोड बिलकुल खराब हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में बसों के संचालन के बारे में मुख्य मंत्री जी ने पहले बजट में घोषणा की कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को रोडवेज से जोड़ेंगे, परन्तु अब तक धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है।

आपकी सरकार बार-बार केन्द्र सरकार पर आरोप लगाती है कि केन्द्र सरकार हर उपक्रम प्राइवेट को दे रहे हैं। राजस्थान सरकार बिजली कम्पनियों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है।

अंग्रेजी स्कूलों की बात तो आपने की है, परन्तु किसी क्षेत्र में अब तक स्कूल नहीं खुले हैं। स्कूल खोलने की बात आप बजट में करते हैं, परन्तु स्कूलों में अध्यापक नहीं है। मेरे यहां संस्कृत स्कूल 9 हैं, उसमें 38 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं, परन्तु 8 हैं, 2 स्कूलों में तो एक भी टीचर नहीं है। ऐसी घोषणा करने से क्या फायदा है।

मेरे क्षेत्र में बांध बहुत अधिक हैं, परन्तु उनमें जो नहरें निकलती हैं, वे बिलकुल कच्ची हैं। पूरा पानी टेल तक नहीं पहुंचता है। मुख्य मंत्री जी जवाब दें, तब नहरों को पक्का करने की घोषणा करें।

माण्डल का ऐतिहासिक किला स्थित है। उसके विकास के लिये, मुख्य मंत्री जी बजट रिप्लाई में घोषणा करें। माण्डलगढ़ शहर के बीचों बीच एक झालेश्वर तालाब है, जिसमें पूरे शहर का गंदा पानी आता है, बदबू मारता है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री कालूराम।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): दुर्गन्ध आती है। इसकी घोषणा करें।

श्री सभापति: विराजिये। श्री कालूराम।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): एक मिनट साहब। जन घोषणा पत्र में कहा था कि बिजली की दर नहीं बढ़ेगी। पिछले दरवाजे से चार्ज, सरचार्ज लगाकर जनता पर भार बढ़ाया है। जन घोषणा पत्र में कहा था कि 30 हजार स्कूल जो भाजपा सरकार ने बन्द किये, फिर खोलेंगे, अब तक कितने खोले हैं? अभी तक प्रारम्भिक शिक्षा में ही 552 और..

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): 500 विश्वविद्यालय खोले। 30 हजार स्कूलों की बात थी, उसका क्या हुआ? कांग्रेस सरकार की चुनावों में असत्य वादे, थोथे नारों की परम्परा पुरानी है।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री कालूराम।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): इस पार्टी ने गरीबी हटाओ, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे।

श्री सभापति: श्री कालूराम। अंकित नहीं होगा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): 000

श्री सभापति: श्री कालूराम।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): 000

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट का व्यक्ति हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र का नम्बर भी 197 है। सर, मुझे दो मिनट टाइम देना। ज्यादा देना थोड़ा। माननीय सभापति महोदय, 2022-23 पर बोलने का आपने मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आप यहीं विराजमान हैं। बजट में घोषणा तो बहुत सारी की गयी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 21 पद में से 6 डाक्टर लगे हुए हैं, डग ब्लाक में। भवानीमण्डी में करीब 8-10 डाक्टर्स के रिक्त पद हैं। सबसे पहले डाक्टर्स के पद भरे जायें।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में एनआरएचएम, प्रबन्धकीय, संविदा वर्ग के कर्मचारी, बीपीएम, लेखाकार, ब्लाक हैल्थ सुपरवाइजर, कम्प्यूटर आपरेटर आदि 5 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं, जो

(श्री कालूराम)

आज 22 गोदाम पर धरने पर बैठे हुए हैं। इन कर्मचारियों की मांग है कि इनको स्थायी किया जाये। मैं मांग करता हूं कि इनको भी स्थायी किया जाये। स्वास्थ्यकर्मी के लिये, संविदाकर्मी के लिये, आपने 20 परसेंट राशि बढ़ाई है, उसमें स्क्रीनिंग करने की मांग की है, तो इसमें क्या स्क्रीनिंग की जाय। उनको 7-8 हजार रुपये मिलते हैं। सभी स्वास्थ्यकर्मी, संविदाकर्मी, पंचायती राज कर्मी, जितने भी संविदाकर्मी लगे हैं, उन सबका वेतन बढ़ाया जाये। 6-7 हजार रुपये में क्या काम करेंगे? सभापति महोदय, इस पाइंट को आप बिलकुल नोट करें और इनका ध्यान रखा जाये।

डग विधान सभा क्षेत्र में एम्बुलेंस की अवस्था बहुत जर्जर हो चुकी है। मेरा विधान सभा क्षेत्र 175 किलोमीटर लम्बा जिला अस्पताल पड़ता है। एम्बुलेंस बिलकुल जर्जर अवस्था में है। अगर डग में एम्बुलेंस नहीं मिलने के बाद उन्हेल फोन किया जाता है, तो वह बताते हैं कि चार घंटे बाद एम्बुलेंस आयेगी। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। आप एम्बुलेंस की व्यवस्था जरूर करें ताकि हमारे उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके।

हमारे उन्हेल और आवल को पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये, क्योंकि ज़िले में, बहुत दूर जाने में बड़ी दिक्कत आती है। डग में 30 बैडेड अस्पताल है, मेरा विधान सभा क्षेत्र डग है, उसको 30 बैड से बढ़ाकर या तो 50 किया जाये या उसमें ट्रोमा सेन्टर खोला जाये, ताकि चोमेला या कुण्डला से दूरी से आने वाले व्यक्तियों को इसका फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जो अभी आपने लागू की है, इसका बराबर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। ढाई साल पहले जो भामाशाह योजना चल रही थी, वह ढाई या तीन साल से बन्द पड़ी थी। अभी जो योजना चालू हुई है इसका सभी अस्पतालों में, सभी मरीजों को बराबर लाभ नहीं मिल रहा है। आप इसके ऊपर थोड़ा जोर दें। सभी मरीजों को इसका लाभ मिले, ताकि सभी जनता को इसका लाभ मिल सके। यह योजना सिर्फ एक हवाई योजना है, इसमें क्रियान्विति नहीं हुई है। अभी आप, नये-नये चिकित्सा मंत्री जी पधारे हैं, तो इसमें आप जरूर ध्यान देंगे।

सड़क के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मैंने 41 सड़कों के प्रस्ताव दिये थे, उसमें से मुझे मात्र एक सड़क मिली है। उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। वह क्षेत्र छतरपुरा, गठोत, खोद, पचपाड होते हुये दूदा खेडी तक, इस बजट में आपने जोड़ी है, इसलिये मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।

(श्री कालूराम)

आपने 10 करोड़ रुपये विधायकों को दिये हैं, मैं चाहता हूं कि आप 10 करोड़ की ही मिसिंग लिंक बनायें। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत तो केन्द्र से भी पैसा आ जाता है, सड़क मरम्मत के लिये, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत तो केन्द्र सरकार से भी पैसा आ जाता है सड़क मरम्मत के लिये। बाकी मिसिंग लिंक की सबको जरूरत है। इधर वाले को भी है, उधर वाले को भी जरूरत है। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि 15 किलोमीटर कम से कम या तो सड़क बनायें या 10 करोड़ रुपये मिसिंग लिंक में दें। मेरा विधान सभा क्षेत्र एमपी सीमा से लगा हुआ है। मैंने 41 सड़कें दी थीं, इनमें से कम से कम 20 सड़कें आज मिसिंग लिंक होंगी। अगर मिसिंग लिंक एक सड़क जुड़ जाती है तो 20 किलोमीटर की कनेक्टिविटी उसमें दूर हो जाती है और उसका फायदा काफी लोगों को मिलता है।

पेज सं. 35, पैरा नं. 126, सुलिया से सुनेल पेड़ाव होते हुए स्वेज तक पिछले बजट में 2020-21 में घोषणा की थी, वह सड़क अभी तक नहीं बनी और न ही उस सड़क का काम चला। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो घोषणा की है, कम से कम उनका तो कार्य कराया जाये। जो सड़कें हैं, 2017-18 में जो सात सड़कें हमारी सरकार के टाइम पर माननीय पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने स्वीकृत की थीं, वे सभी सड़कें अभी अधूरी पड़ी हैं। कछुए की चाल से सड़कों का निर्माण चल रहा है। सात सड़कें, दो हाईब्रिज पुलिया और एक आरओबी, ये सारे काम अधूरे पड़े हैं। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री यहां विराजमान हों तो आप इन अधिकारियों को कहकर तुरंत ये कार्य पूरे करवाएं। आज पांच-पांच साल हो गये, ये कार्य अधूरे पड़े हैं। ये ठेकेदार कहते हैं कि हमें बजट नहीं मिलता। या तो ठेकेदार की कमी है या फिर आपके अधिकारियों की कमी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें और तुरंत ये सड़कें बनवाएं ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके।

विधान सभा क्षेत्र डग में पांच पेयजल परियोजनाएं चालू हैं, पहले से 6 परियोजना। उन सभी को जल जीवन मिशन के तहत आपने कन्वर्ट कर दिया। जल जीवन मिशन के तहत अभी जो काम चल रहा है, उसमें इन पुरानी लाइनों को पंक्चर कर दिया गया, तो जो पानी ग्रामीण क्षेत्रों को जाता था, वह पानी मिलना बन्द हो गया। अगर यह योजना सही तरीके से लागू नहीं की गयी तो हाहाकार मच जायेगा। क्षेत्र में मैं अभी गया था तो हर गांव

(श्री कालूराम)

में एक ही आवाज उठ रही है कि जल जीवन मिशन के तहत जो योजना चल रही है, पुरानी लाइन से फोड़कर कनेक्शन दे दिया और वह लाइन पंक्चर होने के कारण उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आपसे निवेदन है कि इसका या तो पम्प टैंक बढ़ाया जाये या जल स्रोत बढ़ाया जाये, उसके बाद आप इस योजना को चालू करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन-तीन नदियां बहकर जाती हैं चौमेला क्षेत्र में। उस क्षेत्र में एक भी बांध नहीं है, यदि सिंचाई मंत्री जी यहां विराजमान हों तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कालीसिंध नदी या चाचुनी नदी या आक्या परमार गांव या फीफाखेड़ी गांव के पास में कहीं भी एक बांध बनाया जाये, क्योंकि इसका सर्वे भी पहले हो चुका है। यदि बांध बन जायेगा तो इस क्षेत्र की जनता को इसका काफी लाभ मिलेगा।

शिक्षा में आपने सैकण्डरी स्कूल्स को सीनियर सैकण्डरी में तब्दील कर दिया। मैं आपका इसके लिये धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। बाकी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाये।

श्री सभापति: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 03 मार्च 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.20 बजे गुरुवार, दिनांक 03 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

अजमेर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बकाया मानदेय का भुगतान

141. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का मानदेय, क्रय सामग्री, भवन किराया की कितनी-कितनी राशि, कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल उपलब्ध कराते हुए नेट रिचार्ज के लिए भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त भत्ता कितने समय से बकाया चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त बकाया राशियों का भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का मानदेय, क्रय सामग्री, भवन किराया का दिसम्बर, 2021 तक कोई भुगतान बकाया नहीं है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। कार्यकर्ताओं को रियल टाइम मानिटरिंग हेतु मोबाइल डेटा रिचार्ज भत्ता 200 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। अजमेर जिले की 13 परियोजनाओं में से 11 का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। शेष 2 परियोजना जवाजा में जुलाई, 2019 से मार्च, 2020 तक 3 लाख 72 हजार 600 रुपये एवं परियोजना पुष्कर में अक्टूबर 2020 से मार्च, 2021 तक राशि रुपये 2 लाख 68 हजार 800 नेट रिचार्ज भत्ते का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

(3) जिला अजमेर में क्रम संख्या 2 में वर्णित बकाया राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगंज मण्डी में विकास पथ का निर्माण

142. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मदन दिलावर)

(1) क्या पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रारम्भ की गई गौरव पथ योजना के स्थान पर विकास पथ का निर्माण करवाये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में कितनी लम्बाई के कितने विकास पथ ग्रामवार बनाये जाने चाहिए थे? उनमें से अब तक कितने बनकर तैयार हो गये व कितने निर्माणाधीन हैं तथा कितने स्वीकृत किये गये हैं? शेष को कब तक स्वीकृत कर कार्यादेश दे दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। गौरव पथ के स्थान पर विकास पथ बनाने की घोषणा नहीं की गई है। विकास पथ वर्तमान सरकार की एक नवीन योजना है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में वर्तमान में 40 ग्राम पंचायतें हैं। बजट घोषणा 2019-20 के अनुसार अगले पांच वर्ष में समस्त ग्राम पंचायत में एक नया विकास पथ निर्माण की घोषणा की गई थी। अभी तक रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत सुकेत में विकास पथ स्वीकृत कर निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

शेष विकास पथ का निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा में आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण

143. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में अनुसूचित जाति विकास कोष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष के माध्यम से छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ रोजगारपरक कार्यों के लिए प्रति व्यक्ति सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला भीलवाड़ा के कितने-कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(2) क्या छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए उक्त योजना में उक्त जिले के कौन-कौन से आवासीय विद्यालयों में आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में वाल्मीकि कोष से कितने व्यक्तियों को रोजगारपरक कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभान्वित किया गया? पंचायतवार लाभान्वितों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में अनुसूचित जाति विकास कोष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष के माध्यम से छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ रोजगारपरक कार्यों के लिए प्रति व्यक्ति सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति विकास कोष में से अनुजा निगम को रोजगारपरक कार्यों के लिए प्रति व्यक्ति सहायता उपलब्ध कराने के लिए इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान के रूप में तथा प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना में ऋण प्राप्त करने वाले ऐसे आशार्थी जिन्हें टूलकिट/औजारों की आवश्यकता होती है, उनको प्रति व्यक्ति 5,000/- (टूलकिट/औजारों के लिए) इस कोष में से देने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राशि रुपये 3.00 करोड़ तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान के लिए राशि रुपये 7.50 करोड़ आबंटित किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में भीलवाड़ा जिले में किसी भी व्यक्ति को कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं करायी गई।

(2) भीलवाड़ा जिले में सभी वर्गों के 33 छात्रावास संचालित हैं जिनमें खेलकूद सामग्री एवं इन्टरनेट कनेक्शन के लिए 11,55,000/- की राशि मुहैया करायी गयी है तथा राजकीय अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय छात्रावास भीलवाड़ा की भवन मरम्मत हेतु राशि 5,12,000 की राशि मुहैया करायी गयी है। भीलवाड़ा जिले में संचालित छात्रावासों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

भीलवाड़ा जिले में डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय आटूण एवं देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय तेलीखेडा संचालित है, जिनमें आधुनिकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत स्मार्ट

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

इन्टरेक्टिव टीचिंग बोर्ड, शिक्षण सामग्री, खेलकूद सामग्री, वाई फाई/इन्टरनेट एवं ओपन जिम आदि कार्य हेतु आवासीय विद्यालय आटूण को 19.48 लाख एवं तेलीखेडा को 5.10 लाख की स्वीकृति जारी की गई है, जिनमें क्रय कार्यवाही प्रकियाधीन है।

(3) वाल्मीकि कोष में से भीलवाड़ा जिले में किसी भी व्यक्ति को लाभान्वित नहीं किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जैतारण में संचालित सीमेन्ट उत्पादक उद्योग

144. श्री अविनाश (जैतारण): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कितनी सीमेन्ट उत्पादक फैक्ट्रियां संचालित हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सीमेन्ट फैक्ट्रियों में कुल कितने कार्मिक कार्यरत हैं? फैक्ट्रीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सभी फैक्ट्रियों में श्रमिकों के लिए वेज बोर्ड का गठन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार श्रमिक हितों के लिए उक्त सीमेन्ट फैक्ट्रियों में वेज बोर्ड गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में 3 सीमेन्ट फैक्ट्रियां उत्पादनरत एवं संचालित हैं तथा एक इकाई मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, बलाड़ा निर्माणाधीन है, का विवरण निम्नानुसार है:-

1. मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड, बांगड़ सिटी, रास तहसील जैतारण
2. मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड, राबडियावास तहसील जैतारण
3. मैसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड निम्बोल, तहसील जैतारण

(2) उक्त सीमेन्ट फैक्ट्रियों में कुल कार्यरत कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:-

(उद्योग मंत्री)

क्र.सं.	सीमेंट फैक्ट्री का नाम	कुल नियोजन
1.	मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड, बांगड़ सिटी, रास तहसील जैतारण	5,666
2.	मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड, राबडियावास तहसील जैतारण	1,239
3.	मैसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड निम्बोल, तहसील जैतारण	1,032

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा वेज बोर्ड का गठन नहीं किया जाता है। वेज बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के समक्ष सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए वेज बोर्ड का गठन किया जाना विचाराधीन नहीं है। श्रम विभाग द्वारा 62 अनुसूचित उद्योगों के लिए वेतन का निर्धारण न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर किया जाता है जिसमें सीमेन्ट मैन्यूफेक्चरिंग फैक्ट्रियां शामिल नहीं हैं।

रेवदर के अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में विकास के कार्य

145. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के गांव व ढाणियों में अनुसूचित जनजाति का बहुल है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि टीएसपी एरिया घोषित किये जाने के अभाव के चलते उक्त विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में वर्तमान में भी पिछड़ापन है? यदि हां, तो क्यों? विगत पांच वर्षो में उक्त क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कराये गये विकास कार्यों का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों को टीएसपी क्षेत्र घोषित करते हुए अनुसूचित जन जाति के सर्वांगीण विकास का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के गांव/ढाणियों में अनुसूचित जनजाति का बहुल है। विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्रामों की अनुसूचित जनजाति की आबादी का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(2) यह सही नहीं है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने के अभाव के चलते रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बहुल के गांवों में भारी पिछड़ापन बरकरार है। विधान सभा क्षेत्र रेवदर की जनजाति बहुल वाले आबूरोड तहसील के गांवों को अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत सम्मिलित कर विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु गत पांच वर्षों में करवाये गये निर्माण कार्यो का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों को 12-02-1981 की अधिसूचना द्वारा सम्मिलित कर लिया गया था।

अनुसूचित क्षेत्र के गठन सबंधी मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले ग्रामों को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त जो ग्राम अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आते हैं, उन ग्रामों को विभाग द्वारा संचालित माडा एवं बिखरी क्षेत्र में संचालित जनजाति विकास योजनाओं मे लाभान्वित किया जाता है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मिलावटी पदार्थों की जांच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना

118. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए एक अथोरिटी बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो कब? उक्त अथोरिटी में कौन-कौन सदस्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक किस-किस जिले में प्रयोगशाला की स्थापना की जा चुकी है व उक्त में कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.06.2020 के द्वारा राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसके सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए चरणबद्ध रूप से प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की घोषणा की गई थी।

राज्य के 11 जिलों यथा- जयपुर, जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, चूरू एवं जालौर में खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित हैं, जिनमें कार्यरत कार्मिकों का संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

7 जिलों यथा- सीकर, बारां, भीलवाड़ा, बाड़मेर, धौलपुर, नागौर एवं गंगानगर में प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा सम्भाग में सिलिकोसिस बीमारी की पहचान

119. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा सम्भाग में सिलिकोसिस बीमारी की पहचान के लिए माह जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक कुल कितने कैंप आयोजित किए गए? उक्त कैंपों में स्क्रीनिंग के बाद कितने संभावित रोगी चिन्हित किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिन्हित मरीजों में से बड़ी संख्या में मरीजों को सिलिकोसिस बीमारी के लिए देय मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो कितने मरीजों को कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बड़ी संख्या में सिलिकोसिस के चयनित मरीजों का प्रमाणीकरण नहीं होने से उन्हें देय मुआवजा राशि नहीं मिली है? यदि हां, तो कितने मरीजों को? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग में सिलिकोसिस बीमारी की पहचान के लिए माह जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक 105 कैम्प आयोजित कर 1,296 संभावित रोगियों की स्क्रीनिंग कर 147 रोगी चिन्हित किये गये हैं।

(2) जी नहीं। उक्त मरीजों में से 139 मरीजों को सिलिकोसिस बीमारी के लिए देय मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष रोगियों को प्रति रोगी 3 लाख रुपये की मुआवजा राशि दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सिलिकोसिस मरीजों को मुआवजा राशि के भुगतान की कार्यवाही वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जाती है।

(3) जी नहीं। कोटा सम्भाग में उक्त अवधि में सिलिकोसिस बीमारी के किसी चयनित रोगी के प्रमाणीकरण की कार्यवाही लम्बित नहीं है।

जालसू व आमेर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस का उपयोग

120. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जालसू एवं आमेर को उन्नत श्रेणी की एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं? यदि हां, तो क्या उक्त का लाभ वाहन चालकों के अभाव में स्थानीय आमजन को नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आमजन हित में उक्त चिकित्सा केन्द्रों पर स्थायी रूप से वाहन चालक उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधायक कोष से माह मई, 2021 में सीएचसी जालसू तथा माह जुलाई, 2021 में सीएचसी आमेर में उन्नत श्रेणी की एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर में आरएमआरएस के माध्यम से अनुबन्ध पर कार्यरत वाहन चालक द्वारा उक्त एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जालसू में आरएमआरएस के माध्यम से अनुबन्ध वाहन चालक की व्यवस्था कर उक्त एम्बुलेंस का संचालन करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

इस प्रकार की एम्बुलेंसों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एम्बुलेंस प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर आवश्यक बजट के प्रावधान के लिये एनएचएम पीआईपी 2022-24 के माध्यम से भारत सरकार को अनुरोध किया गया है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर में वाहन चालक का 01 पद स्वीकृत है, जो वर्तमान में रिक्त है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जालसू में वाहन चालक का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

उक्त चिकित्सा केन्द्र पर स्थाई रूप से वाहन चालक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

इस प्रकार की एम्बुलेंसों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एम्बुलेंस प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर आवश्यक बजट के प्रावधान के लिये एनएचएम पीआईपी 2022-24 के माध्यम से भारत सरकार को अनुरोध किया गया है।

बदनोर में कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पद की स्वीकृति

121. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के उपखण्ड बदनोर में कृषि पर्यवेक्षक उद्यान का नवीन पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के उपखण्ड बदनोर में कृषि पर्यवेक्षक उद्यान के नवीन पद सृजन का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। सहायक निदेशक उद्यान, भीलवाड़ा के अधीन आसीन्द में कृषि पर्यवेक्षक उद्यान का पद सृजित है, जिसके द्वारा बदनोर में भी उद्यानिकी सेवाएं दी जा रही हैं।

माण्डलगढ़ में संचालित पशु चिकित्सालय

122. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कुल कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश पशु उपकेन्द्रों के भवन नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में कुल 23 पशु चिकित्सालय संचालित हैं, जिनका स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थायें आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में वर्तमान में 27 पशु चिकित्सा संस्थायें पंचायत/वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत उपलब्ध करवाये गये भवनों में एवं शेष 28 पशु चिकित्सा संस्थायें विभागीय भवनों में संचालित की जा रही हैं।

वर्तमान में माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, थलकलां का भवन निर्माणाधीन है।

विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार राजकीय भवन निर्माण कार्य कराया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर में जल जीवन मिशन में स्वीकृत योजनाएं

123. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जल जीवन मिशन योजना में कितनी योजनायें स्वीकृत हुई हैं व उक्त योजनाओं में कौन्कौनसे गांव सम्मिलित हैं? उक्त योजनाओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय होगी तथा किस-किस गांव में क्या-क्या निर्माण व कार्य होंगे? क्या उक्त सभी योजनाओं में कार्यादेश जारी हो गए हैं? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निश्चित समय पर उक्त योजनाओं का कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल जीवन मिशन के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के 166 आबाद राजस्व ग्रामों में घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दो वृहद् पेयजल परियोजनाओं एवं इनके अतिरिक्त अन्य जल योजनाओं की स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) सतही जल स्रोत जवाई बांध आधारित जवाई क्लस्टर प्रथम परियोजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के 43 ग्रामों सहित पाली जिले के 99 ग्रामों हेतु राशि रुपये 127.85 करोड़ तथा जवाई क्लस्टर चतुर्थ परियोजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के 11 ग्रामों सहित पाली जिले के 224 ग्रामों हेतु राशि रुपये 230.02 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमश: दिनांक 08.10.2021 एवं 11.02.2021 को जारी की जा चुकी है।

जवाई क्लस्टर चतुर्थ परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु राशि रुपये 129.78 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 26.11.2021 को जारी किया जाकर इसका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा कार्यादेश अनुसार परियोजना दिनांक 05.03.2023 को पूर्ण करनी निर्धारित है।

जवाई क्लस्टर प्रथम परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा यह परियोजना माह जून, 2023 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है। उक्त पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति, इनमें सम्मिलित कार्य एवं कार्यादेश संबंधी वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(ब) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के उक्तानुसार शेष 112 ग्रामों हेतु 47 अन्य जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 99.65 करोड़ की जारी की जा चुकी है। कार्यादेश उपरान्त 34 जल योजनाओं (69 ग्राम सम्मिलित) के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं, 11 जल योजनाओं (37 ग्राम सम्मिलित) का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी तथा 02 जल योजनाओं (06 ग्राम सम्मिलित) हेतु तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

उक्त जल योजनाओं को चरणबद्ध रूप से माह मार्च, 2023 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। जल योजनावार स्वीकृति, इनमें सम्मिलित कार्य एवं कार्यादेश संबंधी वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जल जीवन मिशन के अंतर्गत उक्त स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं एवं अन्य जल योजनाओं को पूर्ण करने की प्रस्तावित अवधि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब में निहित है।

उक्त स्वीकृत परियोजनाओं एवं अन्य जल योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाकर, विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के उक्त वर्णित ग्रामों को घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गौवंश संरक्षण के लिए गोपालकों को आर्थिक सहायता

124. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गौवंश संरक्षण के लिए गोपालकों को कोई आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए कोई नीति घोषित नहीं है। वर्तमान में गौसंरक्षण एवं संवर्धन हेतु निम्नांकित मुख्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

(गोपालन मंत्री)

1. गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 अंतर्गत प्रदेश की पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु नियमानुसार सहायता राशि प्रदान की जाती है।
2. आरकेवीवाई-रफ्तार अंतर्गत कामधेनू डेयरी योजना।
3. गौशाला विकास योजना।
4. इन विवो फर्टीलाइजेशन एवं भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा थारपारकर एवं गिर नस्ल के गौवंश संरक्षण-संवर्धन योजना।
5. वध से बचाये गये गौवंश की सहायतार्थ अनुदान।
6. जिला स्तरीय नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना।
7. पंचायत समिति नन्दीशाला जन सहभागिता योजना।

(2) देशी गौवंश के संवर्धन हेतु भारत सरकार की आरकेवीवाई रफ्तार योजना अंतर्गत कामधेनू डेयरी योजना में 30 देशी गौवंश नस्ल की डेयरी (राशि रु. 36,68,900-/ की इकाई) स्थापित किये जाने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 30 प्रतिशत राशि (रु. 11,00,670/-) बैक एण्डेड सब्सिडी के रूप में दिया जाना प्रावधित है।

गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम; 2016 अंतर्गत प्रदेश की पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु वर्ष में अधिकतम 180 दिवसों की सहायता राशि नियमानुसार 90-90 दिवस के दो चरणों में दिये जाने का प्रावधान है। बड़े गौवंश हेतु 40 रु. तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रु. प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से दिया जा रहा है।

गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 से सृजित निधि द्वारा गौशालाओं में आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य जैसे गौ-शैड, चारा भण्डार गृह, गौपालक आवास गृह, पानी की खेली, चारा खेली, तारबंदी आदि के लिए गौशाला जनसहभागिता विकास योजना अन्तर्गत अधिकतम राशि रु. 10 लाख प्रति गौशाला दिये जाने का प्रावधान है। आधारभूत निर्माण हेतु 90:10 के अनुपात में राजकीय अंशदान व जनसहभागिता अंशदान का प्रावधान है।

जिला स्तरीय नन्दीशाला जनसहभागिता योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय नन्दीशाला स्थापित करने हेतु राशि रु. 50.00 लाख (90 प्रतिशत राजकीय अंशदान एवं 10 प्रतिशत संस्था का अंशदान) का प्रावधान है।

(गोपालन मंत्री)

पंचायत समिति नन्दीशाला जनसहभागिता योजनान्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में राशि रु. 1.57 करोड़ की लागत (राज्यांश 90 प्रतिशत एवं संस्था का अंशदान 10 प्रतिशत) से नन्दीशाला निर्मित करने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री सम्बल योजनान्तर्गत गोपालकों को सरस डेयरी में दुग्ध संकलन पर 2 रुपये प्रति लीटर का सम्बल प्रदान किया जाता है।

जोधपुर में लीजधारियों द्वारा अवैध खनन

125. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में विभिन्न खनन लीजधारियों द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा से बाहर अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

(2) विभाग के जोधपुर स्थित कार्यालय में अप्रैल, 2021 से जनवरी, 2022 तक किस-किस लीजधारी के विरुद्ध किन-किन द्वारा कब-कब अवैध खनन व अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुईं? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त में से कितनी शिकायतें सही पाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 31.01.2022 तक प्राप्त शिकायतों की जांच/आकस्मिक चैकिंग में 6 क्वारी लाइसेंसधारकों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र की सीमा के बाहर अवैध खनन किया जाना पाया गया। विभाग द्वारा क्वारी लाइसेंसधारकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विभाग के जोधपुर स्थित कार्यालयों में माह अप्रैल, 2021 से जनवरी, 2022 तक खानधारकों के विरुद्ध अवैध खनन व अनियमितताओं के संबंध में जिन-जिनके द्वारा जब-जब प्राप्त शिकायतें प्रेषित की गईं, का प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(खान मंत्री)

(3) उक्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर अंकित है। जांच में 3 शिकायतें सही पाई गईं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

ग्राम पंचायतों में ड्रेनेज प्लान

126. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में ड्रेनेज प्लान तैयार कर जल निकासी का समुचित प्रबंधन किये जाने की योजना है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों को अब तक चिन्हित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 इंटर लाकिंग सड़क व सीमेंट सड़क का निर्माण किया गया है? उक्त पर कितनी लागत आयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इंटर लाकिंग सड़क के साथ-साथ ड्रेनेज का प्रबंधन किया गया है? यदि नहीं, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में उक्त प्रबंधन का साझा कार्य नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायतों में ड्रेनेज प्लान तैयार कर जल निकासी का समुचित प्रबंधन किये जाने हेतु विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की डीपीआर में चिन्हित ग्राम पंचायतों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त में से इंटर लाकिंग सड़क व सीमेंट सड़क का वर्ष 2020-21 में निर्माण कराने वाली ग्राम पंचायतों का लागतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। इंटर लाकिंग सड़क के साथ-साथ ड्रेनेज का प्रबंधन किया गया है। उक्त इंटर लाकिंग सड़क के साथ-साथ ड्रेनेज का प्रबंधन करने वाली ग्राम पंचायतो का विवरण परिशिष्ट-2 के कालम संख्या 6 पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मालपुरा में भू-संरक्षण कार्य हेतु बजट का आबंटन

127. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या भू-संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कन्हैया लाल)

विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? आबंटित बजट से कौन-कौनसे कार्य कहां-कहां करवाये गये तथा कितना बजट शेष रहा? करवाये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत (आईडब्ल्यूएमपी एवं राजीव गांधी जल संचय योजना) 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक राशि रुपये 1,365.22 लाख आबंटित हुए हैं। वर्षवार बजट आबंटन सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में उक्त अवधि में कुल 2,050 कार्य करवाये गये हैं। ग्रामवार, जलग्रहण उपसमितिवार करवाये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। वर्ततान में विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में राजीव गांधी जल संचय योजनान्तर्गत राशि रुपये 42.65 लाख शेष है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

ब्यावर में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की अपीलें

128. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की अपील उपखण्ड अधिकारी के पास की जाती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जनवरी, 2019 से अब तक कितनी अपीलें आयीं व कितने नाम जोड़े गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का पोर्टल बंद कर रखा है? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पात्रता रखने वाले व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जनवरी 2019 से अब तक

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

1,702 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 101 आवेदनों के 417 नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़े गये।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। प्रदेश में चयनित लाभार्थियों की संख्या निर्धारित सीलिंग से अधिक होने के कारण वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन नाम जोड़ने का कार्य दिनांक 18.05.2020 से बंद है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा में वृद्धि किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को समय-समय पर पत्र लिखे गये है। भारत सरकार द्वारा अवगत करवाया गया है कि कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद ही सम्भव होगा।

(3) जी हां। उत्तर बिन्दु संख्या 2 में समाहित है।

वर्तमान में प्रदेश के पात्र लोगों के नाम जोड़ने की मंशानुरूप चयनित लाभार्थियों की आधार सीडिंग के दौरान विवाह, मृत्यु, स्थाई पलायन, दोहरे तिहरे राशन कार्ड/यूनिट्स एवं स्पष्ट अपात्र यथा सरकारी कर्मचारियों आदि का नाम चिन्हित प्रक्रिया व मापदण्डानुसार हटने पर सीलिंग सीमा में हुई जगह अनुसार राज्य सरकार द्वारा लम्बित अपीलों में से दिनांक 15.02.2022 तक 94,403 अपीलों को स्वीकृत कर खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा गया है।

इटावा व सुल्तानपुर में सीडी.पी.ओ. कार्यालय का भवन निर्माण

129. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार सी.डी.पी.ओ. कार्यालय इटावा तथा सुल्तानपुर में भवन निर्माण करवाये जाने का विचार रखती है? क्या उक्त के कार्यालय हेतु भूमि आबंटित की जा चुकी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों एवं अब कब तक भूमि आबंटित की जाकर भवन निर्माण के लिए अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बाल विकास परियोजना इटावा तथा परियोजना सुल्तानपुर में कार्यालय भवन निर्माण किया जाना है, जिसके लिए नि:शुल्क भूमि आबंटन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

कार्यालय भवन निर्माण का कार्य नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है।

थाक-अड्सा-सांगोद पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण

130. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार कैथून-राजपुरा-बालाजी की थाक-अड्सा-सांगोद पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण स्वीकृत है?

(2) क्या उक्त पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि नही, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

(3) उक्त पुल के निर्माण का कार्य अब कब तक प्रारम्भ किया जाकर कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार कैथून-राजपुरा-बालाजी की थाक-अड्सा-सांगोद पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण की स्वीकृति मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. राज. जयपुर कार्यालय पत्रांक एफ 7 (174)/एएण्डएफ/2021-22/अनु.-2/डी-53 दिनांक 03.05.2021 द्वारा राशि रु. 45.00 करोड़ की जारी की गई थी।

(2) जी नहीं। निर्माण कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनवाये जाने हेतु कन्सल्टेन्सी फर्म को दिनांक 25.10.2021 द्वारा कार्यादेश जारी किया जा चुका है, जिसकी कार्य पूर्णता अवधि दिनांक 03.05.2022 तक है। डी.पी.आर. का कार्य प्रगति पर है।

(3) डी.पी.आर. प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य की निविदायें प्राप्त कर कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारम्भ करवा दिया जावेगा। इस पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2023 के अन्त तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

पिण्डवाड़ा तहसील में मिसिंग रोड का निर्माण

131. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आबू-पिण्डवाड़ा की पिण्डवाड़ा तहसील में मिसिंग सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में बजट घोषणा अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जन प्रतिनिधि विधायकों की अनुंशसा पर 5 करोड़ रुपये के सड़क नवीनीकरण एवं मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य स्वीकृत किये हैं।

विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में माननीय विधायक महोदय की अनुशंसा में मिसिंग लिंक कार्य, नोन पेचेबल सड़कों से वरीयता में नीचे होने के कारण 5 करोड़ तक राशि सीमा में स्वीकृत नहीं हो सके।

नागौर में शहीद सैनिकों के परिवारों को देय परिलाभ

132. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में कई शहीद सैनिकों के परिवार अब तक भी देय परिलाभों से वंचित हैं? यदि हां, तो प्रत्येक के परिलाभ की वर्तमान स्थिति का शहीदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्ष 2015 से 2021 तक सम्पर्क पोर्टल पर विभाग से जुड़े दर्ज प्रकरण व उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शहीद परिवारों को देय परिलाभ के सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाने की सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी हां। शहीदवार वंचित परिलाभ की वर्तमान स्थिति की सूचना परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) नागौर जिले में 2015 से 2021 के बीच सम्पर्क पोर्टल पर सैनिक कल्याण विभाग से जुड़े दर्ज प्रकरण एवं उनकी वर्तमान स्थिति की सूचना परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में आवेदन ऑनलाइन लिए जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूचनाएं पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर ग्रामीण में स्वीकृत मां-बाड़ी केन्द्र

133. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कुल कितने मां-बाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? प्रत्येक का स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत मां-बाड़ी केन्द्रों में से कितनों के भवन निर्मित हैं तथा कितनों के भवनों का निर्माण किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन मां-बाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कुल 18 मां-बाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त मां-बाड़ी केन्द्रों का स्थानवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत मां-बाड़ी केन्द्रों में से 2 केन्द्र क्रमशः मां-बाड़ी केन्द्र मोरडूंगरी एवं वाडाफला पर भवन बन चुके हैं तथा 16 केन्द्रों का निर्माण किया जाना शेष है। (परिशिष्ट-अ)

(3) स्वीकृति प्राप्त होने पर नई मां-बाड़ी केन्द्र खोले जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

बिहारीलाल (नोखा)

नोखा एवं पांचू पंचायत समितियों में 132 के.वी. ग्रिड की स्थापना

महोदय,

नोखा विधान सभा क्षेत्र की पांचू पंचायत समिति में वोल्टेज की भारी समस्या को देखते हुए पांचू में 220 केवी जीएसएस स्वीकृत किया गया था लेकिन लगभग दो साल पूरे होने के बाद भी धरातल पर इस संबंध में काम शुरू नहीं हुआ है और पांचू पंचायत समिति क्षेत्र में दिनोंदिन वोल्टेज की समस्या बढ़ती जा रही है, इसलिए पांचू 220 केवी जीएसएस का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

नोखा पंचायत समिति क्षेत्र में लोड सेंटर पाइंट मुकाम में होने के कारण 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की अत्यन्त आवश्यकता है। इससे आस-पास छह 33 केवी जीएसएस (मुकाम, काकड़ा प्रथम, काकड़ा द्वितीय, हिम्मतसर अणखीसर प्रथम, अणखीसर द्वितीय) को विद्युत आपूर्ति 220 केवी जीएसएस नोखा से की जाती है, जबकि नोखा से मुकाम तक 18 किमी. की दूरी तक कोई भी जीएसएस नहीं है, जिससे लम्बी दूरी के कारण विद्युत छीजत बढ़ रही है तथा विद्युत आपूर्ति में भारी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मुकाम (नोखा) नया 132 केवी जीएसएस बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाये।

साथ ही नोखा में पिथरासर, बंधाला, दासनू, धरनोक क्षेत्र में वोल्टेज की भारी कमी एवं स्थानीय जनता की लंबे समय से आ रही मांग को मध्यनजर रखते हुए 33 केवी के नए जीएसएस (विद्युत ग्रिड सब स्टेशन) स्वीकृत करवाने का श्रम करें।

सुरेश टाक (किशनगढ़)

किशनगढ़ नगर परिषद् में दो बड़े अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के नगर परिषद् में तीन पुराने अग्निशमन वाहन हैं, जो काफी पुराने होकर बेहद क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं, जिनमें दो बड़े एवं एक छोटा वाहन है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ का फैलाव सर्वाधिक है तथा यहां नगर परिषद् क्षेत्र में 60 वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्र के किशनगढ़ एवं अरांई ब्लाक में 41 ग्राम पंचायतें व 210 राजस्व ग्राम हैं। जिनमें नगर परिषद् किशनगढ़ के अतिरिक्त कहीं भी अग्निशमन वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि वर्तमान में केवल नगर निकायों के पास ही अग्निशमन वाहन है। एक तो इतने बड़े क्षेत्र में केवल तीन ही अग्निशमन वाहन हैं और वे भी क्षतिग्रस्त व नाकारा स्थिति में हैं। किशनगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के दिनों मे कई बार कई जगहों पर एक साथ आगजनी की घटनाएं घटित हो जाती हैं, किन्तु उक्त वाहनों के क्षतिग्रस्त होने व वाहन की कमी के कारण आगजनी पर काबू नहीं पाया जा सकता है और न ही अग्निशमन वाहन समय पर संबंधित घटनास्थल पर पहुंच पाता है। ऐसे में कई घटना स्थलों पर लाखों का नुकसान होकर जनहानि जैसी घटनाएं घटित हुई हैं। इन घटनाओं में मवेशी, भेड़, बकरियां, गायें, भैंसें, कृषकों का चारा, कटी हुई फसलों आदि का भी भारी नुकसान हुआ है जो चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में किशनगढ़ नगर परिषद् में दो नए (बड़े) अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाये जाने की नितांत आवश्यकता है ताकि संबंधित क्षेत्रों में आगजनी की घटना पर त्वरित काबू पाया जा सके एवं एक वाहन कहीं अन्यत्र गया हुआ हो तो दूसरा वाहन आगजनी की घटनास्थल तथा दूसरे ग्राम तक पहुंच सके।

साथ ही किशनगढ़ एक औद्योगिक शहर है जहां विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मण्डी होने के साथ हजारों उद्योग लगे हुए हैं वहां दो टैक्सटाइल पार्क हैं व पावरलूम की सैकड़ों इकाइयां लगी हुई हैं जिनमें कई बार आगजनी की घटनाएं हुई हैं और पर्याप्त अग्निशमन वाहन नहीं होने से बड़े नुकसान हुए हैं।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि नगर परिषद् में किशनगढ़ जनहित के दृष्टिगत दो नए (बड़े) अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान करवाकर विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करें। साथ ही सरकार से यह भी आग्रह है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने हेतु राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति पर भी एक अग्निशमन वाहन की स्वीकृति प्रदान करावें ताकि आगजनी की घटनाओं से होने वाले भारी नुकसान से जनता को बचाया जा सके।

धन्यवाद।

नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा)

पश्चिमी राजस्थान में निवासरत पाहुआ जति को एससी/एसटी वर्ग में आरक्षण

महोदय,

निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान के जिले जालौर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जैसलमेर आदि में रहने वाली पाहुआ जाति किसी भी आरक्षित वर्ग में सम्मिलित नहीं होने के कारण अत्यधिक गरीबी में जीने को मजबूर है। पाहुआ जाति के लोग सारंगी बजाकर उससे प्राप्त होने वाले धन से अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आधुनिकता के युग में इनके पारम्परिक जीवन-यापन का प्रमुख कार्य सारंगी बजाकर आजीविका चलाना भी धीरे-धीरे समाप्त हो गया है। गरीबी और अशिक्षा के कारण इनके पास जीवनयापन करने के लिए न तो कृषि भूमि है और न ही कोई नौकरी अथवा काम-धन्धा है। गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन जीने को मजबूर पाहुआ जाति किसी भी आरक्षित वर्ग में नहीं होने के कारण इनको न तो आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है और न ही किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति में इस जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाना बहुत आवश्यक है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में रहने वाली पाहुआ जाति को एससी/एसटी वर्ग में आरक्षण देने की कृपा करें ताकि इस जाति के लोगों का जीवन बेहतर हो सके।

धन्यवाद।

बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर)

गंगानगर जिले में सिंचाई हेतु पानी बंद करने से किसानों को परेशानी

महोदय,

गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है यहां सबसे बड़ी तीन नहर परियोजनाएं भाखड़ा, गंग कैनाल व आई.जी.एन.पी. हैं।

अध्यक्ष जी, आई.जी.एन.पी. राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग को सिंचित करती है जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों को सिंचाई पानी देने के साथ-साथ आधे राजस्थान को पीने का पानी उपलब्ध कराती है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इन कृषि प्रधान जिलों में सिचाई पानी के जो हालात हैं उससे किसान लगातार दुःखी होता जा रहा है। वर्तमान सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में एक फसल भी ऐसी नही है, जिसको पकाने के लिए बिना आंदोलन किए सिंचाई पानी मिला हो।

अध्यक्ष जी, आज भी पौंग बांध में 1335 फीट के आस-पास पानी है और किसान को 2 मार्च के बाद सरकार सिंचाई पानी देना बन्द कर रही है जबकि गेहूं पकाव हेतु मार्च में हर हालात में पानी की जरूरत है। 2021 में खरीफ की फसल के पकाव हेतु सिंचाई पानी बिना रेगुलेशन कमेटी की बैठक बुलाये अधिकारी अपनी मनमर्जी से नहरें चला रहे हैं। फिर रेगुलेशन कमेटी का औचित्य ही क्या है?

अध्यक्ष जी, जनवरी व फरवरी, मार्च माह में अक्सर पौंग बांध की स्थिति 1300 से 1325.30 की रहती है और इस बार तो 1340 फीट है। फिर भी जनवरी से बन्दी ली गई व अब 02 मार्च के बाद सिंचाई पानी नहीं देने से इस कृषि प्रधान जिले में गेहूं के लाले पड़ जाएंगे।

अध्यक्ष जी, एक समय था जब विजयनगर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला में गेहूं के ढेर लगते थे। आप विभाग से रिकार्ड मंगवाएं इस बार गेहूं का रकबा कितना घटा है। ये बहुत चिंताजनक बात है। एक तरफ तो हम हरित क्रान्ति के सपने देखते हैं, दूसरी तरफ गेहूं पैदा करने वाले इलाके को पानी न देकर बरबाद करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि तुरन्त प्रभाव से आई.जी.एन.पी. में गेहूं पकाव हेतु 2 मार्च के बाद भी 4 में से 2 समूह में पानी की व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष जी, हर 1-1 बारी के लिए किसानो को धरना- प्रर्दशन एवं आन्दोलन हेतु सड़कों पर आना पड़ा है। ऐसा कब तक किसानो के साथ अन्याय होता रहेगा। वर्ष 2016 में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष व तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष इसी पानी को लेकर बड़े-बड़े वादे घड़साना जाकर करके आये थे आज आपकी सरकार भूल गयी।

अगर 02 मार्च के बाद पानी नहीं आया तो इलाके के किसानों को मजबूरन आन्दोलन करना पड़ेगा। अतः मार्च माह में गेहूं की फसल के पकाव के लिए सिंचाई पानी उपलब्ध कराया जाये और नहरबन्दी 25 मार्च के बाद ली जाये।

धन्यवाद।

छगनसिंह (आहोर)

आहोर में मिसिंग सड़कों का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान आहोर विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न मिसिंग सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो वर्षों से डामरीकरण से वंचित हैं। उन गांवों मे आज भी छोटा सफर लम्बी दूरी में करना पड़ता है, इसलिए कृपा करके निम्नलिखित मिसिंग सड़कों का निर्माण करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करावें:-

1. कंवला से पेवाणा (पाली बोर्डर) तक 2. कंवला से सुगालिया होते हुए वलदरा तक 3. नोसरा की ढाणी से कालोपादर से बाला तक 4. दुधिया से खेडा 5. मालगांढ से सुरजकुंड (पाली बोर्डर) तक 6. देलदरी से बिबलसर तक 7. पलासिया से बलुपरा (पाली बोर्डर) तक 8. हड़मतगढ़ से सराणा तक 9. मंडला से एनएच-325 ए तक 10. गंगावास से मुख्य सड़क तक 11. नीलकण्ठ से सरवडी तक 12. पादरली से जोडा तक 13. गुढा इन्द्रपुरा से गोगरा (पाली बोर्डर) तक 14. डीगांव से आडवाडा तक 15. देवदा से नारनावास तक 16. मोहीवाडा से कुंडली तक 17. देवकी से देचु 18. देवाड़ा से सुमेरगढ खेडा तक 19. अगवरी से 325 ए तक 20. आईपुरा से सराना 21. कुआडा से थांवला 22. निम्बला से चुंडा तक 23. पाण्डगरा से राजनवाडी तक 24. बागुन्दा से गुडारामा 25. चवरछा से मेडा उपरला आदि कई सडकें हैं जो आज भी डामरीकरण से नहीं जुड़ी हुई हैं जिससे आहोर क्षेत्र की जनता दुःखी है। सरकार इन सड़कों की आवश्यकता को समझते हुए इनका निर्माण करावे।

सुमित गोदारा (लूणकरणसर)

बीकानेर-नापासर-जसरासर सड़क का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीकानेर जिले की सबसे महत्वपूर्ण सड़क मार्ग जो 5 विधान सभा क्षेत्रों लूणकरणसर, बीकानेर पूर्व, कोलायत, श्रीडूंगरगढ़, नोखा से गुजरती है और वर्तमान में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और सरकार द्वारा पिछले साढ़े तीन सालों में खड्डे भी नहीं भरे हैं।

बीकानेर से रिड़मलसर पुरोहितान-गाढवाला-नापासर-सिंथल-मुंडसर-सूरतसिंहपूरा-कुचौर आथूनी-जसरासर स्टेट हाईवे (एसएच-20 बी) का निर्माण कराया जाये जिससे आमजन को राहत मिल सके। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में दो राजमार्ग का हाईवे में निर्माण हुआ।

1. लूणकरणसर-कालू-सरदारशहर
2. कालू-श्रीडूंगरगढ़-बीदासर

पिछले बजट 2021-22 में बीकानेर-नापासर-जसरासर निर्माण हेतु 130 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी। वर्तमान घोषणावीर सरकार से निवेदन है कि बजट घोषणा में स्वीकृत सड़क का जिस तरह पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा कार्य कराया, उसी तरह बीकानेर-नापासर जसरासर सड़क का अतिशीघ्र निर्माण कर पाँच विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करें।

गिरधारीलाल (डूंगरगढ़)

फसल पकाव के समय कनेक्शन काटने और ट्रांसफार्मर उतारने से किसानों को परेशानी

महोदय,

वर्तमान समय में किसान की फसल पकाव पर है। ऐसे समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के अलावा बीकानेर और पूरे राजस्थान में बकाया के नाम पर किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं जिसके कारण किसान की तैयार फसल बरबाद हो रही है। अगर किसान की यह फसल नहीं पकती है तो वह विद्युत निगम का बकाया भी नहीं चुका पायेगा। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फसल पकाव तक प्रदेश में किसी भी किसान का विद्युत कनेक्शन नहीं काटा जायें और विद्युत निगम किसी भी किसान का बकाया के नाम पर ट्रांसफार्मर नहीं उतारें। साथ ही किसानों को बकाया पर पेनल्टी और ब्याज में 31 मार्च तक दी जाने वाली छूट की अवधि को आगे बढ़ाया जावें ताकि किसान फसल लेने के बाद निगम की बकाया को चुका सकें।

हाकम अली खां (फतेहपुर)

खाड़ी देशों में मजदूरों एवं उनके परिजन के हितों की रक्षा हेतु योजना

महोदय,

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खाड़ी देशों में मजदूरी कर जीवनयापन करने वाले प्रदेश के मजदूरों एवं उनके परिवारों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सहित प्रदेश भर से बड़ी

संख्या में मजदूर वर्ग अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए खाड़ी देशों में जाता है। हमारे शेखावाटी अंचल के मजदूरों की आय का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में मजदूरी करने से आता है।

अध्यक्ष/सभापति महोदय, वर्तमान में बेरोजगारी की मार झेल रहे शिक्षित युवा भी रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं। ये वहां जाकर कठोर परिश्रम करते हैं जिससे होने वाली आय से प्रदेश के साथ ही भारत देश सशक्त हो रहा है तथा कई युवा शिक्षित होने के बाद भी रोजगार नहीं मिलने के कारण दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। ये मजदूर जब विदेश जाते हैं तो वीजा के लिए ये ट्रेवल एजेंटों/दलालों के झांसे में आ जाते हैं। कुछ ट्रेवल एजेंटों द्वारा मजदूर वर्ग की बेरोजगारी का फायदा उठाया जाता है, ये एजेंट मजदूरों से झूठे वादे करते हैं तथा अधिक वेतन का तथा अच्छी नौकरी का झांसा देकर हजारों/लाखों रूपये ऐंठते हैं।

विदेशों में कठोर परिश्रम कर प्रदेश के साथ ही देश को मजबूत करने वाले इस मजदूर वर्ग के साथ अनहोनी होने की सम्भावना बनी रहती है। अध्यक्ष/सभापति महोदय, कइयों बार मजदूर विदेश जाने के कुछ समय में ही हृदयघात होने व अन्य किसी गम्भीर बीमारी से अथवा किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो जाने से काल का ग्रास बन जाते हैं तो इनके पार्थिव देह को निवास स्थान तक लाने में बहुत धनराशि खर्च होती है तथा परेशानियों का सामना करना होता है। इन मजदूरों के परिवार जमा पूंजी के अभाव में यह खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। कई परिवार अपने परिजन का पार्थिव देह विदेश से लाने के लिए अपनी जमीन या अन्य सम्पदा बेचते हैं जिससे इन परिवारों का वर्तमान एवं भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

अध्यक्ष/सभापति महोदय, मैं खुद खाड़ी देशों में रहा हूं, वहां मैंने मजदूरी की है तथा इन मजदूरों की पीड़ा को मैंने देखा व समझा है। वहां किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाने पर इन मजदूरों व इनके परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। कई देशों में इन परिवारों को भारतीय समुदाय कल्याण निधि (ICWF) से सहायता मिल जाती है परन्तु जानकारी के अभाव में अधिकतर वंचित रह जाते हैं, वहीं कई खाड़ी देशों में हिन्दू रीतिरिवाज से पार्थिव देह के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं होने के कारण हिन्दू भाइयों की समस्या और अधिक बढ़ जाती है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के मजदूर जो मजदूरी के लिए विदेशों में जाते हैं, उनके एवं उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए योजना बनाकर इनके परिवारों को आर्थिक सम्बल दिया जाये तथा इनके साथ विदेश में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर इनके पार्थिव देह को भारत लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बजट में आवश्यक बजट आबंटित कर इन परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जावे।

अविनाश (जैतारण)

जैतारण में प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

महोदय,

उपयुक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा 02 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया गया था। उक्त अभियान के अंतर्गत ब्लाक लेवल के सभी अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रतिदिन केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ आम लोगों को मिल सके जिसमें पट्टा वितरण, जॉब कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, भूमि सीमांकन, बंटवारे, रास्ते संबंधित विवाद, आबादी विस्तार सहित अन्य कार्य प्रमुख हैं। उक्त अभियान के अंतर्गत जैतारण विधान सभा क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही उदासीनता के कारण आम जनता व ग्रामीणों को उक्त योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने गांवों में अभियान आयोजित कर मात्र खानापूर्ति का कार्य किया। अधिकारियों द्वारा उक्त सभी कार्य नहीं के बराबर किये तथा फोलोअप कैम्पों में भी अधिकारी नियत समय पर नहीं पहुंचते थे। ग्रामीणों व जन प्रतिनिधियों के तय समय पर पहुंचने के बाद अधिकारी यहां पर उपस्थित नहीं मिलते जिससे ग्रामीणों को बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता व अधिकांश समय इधर-उधर भटकना पड़ता और उनके काम नहीं होते तथा अभी भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में आम जनता के आवश्यक काम लंबित पड़े हैं। सरकार उक्त अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर तुरन्त कार्यवाही करवाकर वंचित रहे ग्रामीणों के पट्टे जारी करने हेतु म्यूटेशन भरने, बंटवारे विवादों के समाधान, आबादी विस्तार, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण, रास्ते संबंधित

विवाद सहित अन्य कार्य पूर्ण करवाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित कर लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करवाकर लाभान्वित करवाएं।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रशासन गांवों की ओर अभियान के अंतर्गत जैतारण विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में अब तक लम्बित प्रकरणों को तुरंत प्रभाव से निस्तारित कर आम जनता को राहत प्रदान करावें तथा उक्त अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करावें।

सतीश पूनियां (आमेर)

जालसू पंचायत समिति का तहसील में क्रमोन्नयन

महोदय,

आमेर तहसील मुख्यालय की जालसू पंचायत समिति की कई ग्राम पंचायतों से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण यहां की ग्राम पंचायत के लोगों को जहां आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अधिक समय व धन की हानि भी हो रही है। विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति जालसू में 34 ग्राम पंचायतें स्थित हैं, लेकिन इनमें से 10 ग्राम पंचायतें तो ऐसी हैं, जिनकी दूरी तहसील मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर है। ऐसे में लोगों को तहसील मुख्यालय तक आने-जाने में एक दिन का पूरा समय लग जाता है तथा सीधे यातायात साधन नहीं होने के कारण अधिक किराया चुकाकर तहसील मुख्यालय जाना पड़ रहा है। कई बार एक दिन में काम नहीं होने पर दूसरे दिन भी तहसील मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आमेर तहसील का क्षेत्र दिल्ली रोड और सीकर रोड में आने से दो तहसील होना बहुत जरूरी है। यहां जालसू पंचायत समिति पुलिस चौकी, डाकघर, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय सहित अनेक राजकीय विभागों के कार्यालय हैं, ऐसे में तहसील भी जालसू में बनती है तो लोगों को इसका उचित लाभ मिल सकेगा। यहां पर उपतहसील भवन बना हुआ है जिसमें तहसील स्तर के स्टाफ के बैठने की पर्याप्त जगह भी है।

उक्त विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति जालसू को तहसील बनाये जाने की आवश्यकता पर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

निर्मला सहरिया (किशनगंज)

अनुदानित छात्रावासों को भी राजकीय छात्रावासों के समान मैस भत्ता

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम संचालित 295 के अन्तर्गत सरकार व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण कर निवेदन करती हूं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा गैर राजकीय स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा छात्रावासों को संचालन किया जा रहा है। छात्रावास संचालन हेतु विभाग ने राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम बना रखे हैं। प्रारम्भ से ही समस्त छात्रावासों हेतु अनुदान राशि के आदेश में समानता रहीं, जिसका लाभ राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों को मिलता है लेकिन मेरे द्वारा अवलोकन करने पर दिनांक 07.01.2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रसारित आदेश के अनुसार केवल मात्र राजकीय छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियों के मैस भत्ते की राशि में 2000/- रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 2500/- रुपये प्रतिमाह की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आदेश में अनुदानित छात्रावास को विलोपित कर दिया गया है जबकि पूर्व में समानता रही है।

अतः सरकार से निवेदन करती हूं कि इस उपरोक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर अनुदानित छात्रावासों को भी उक्त आदेश का लाभ दिलावें।

राजकुमार रोत (चौरासी)

जावर माइंस की जिंक फुटबाल एकेडमी में स्थानीय युवाओं को प्रवेश

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन इस प्रकार है कि उदयपुर जिले में जावर माइंस क्षेत्र में जिंक कम्पनी द्वारा खनन कार्य सम्पादित हो रहा है। यहां के स्थानीय युवाओं के लिए सीएसआर फण्ड से फुटबाल एकेडमी खोली गई है। इस क्षेत्र के लोगों में एक आशा जगी थी कि हमारे क्षेत्र में खनन कर रहे हैं तो हमारे युवाओं को लाभ भी मिलेगा, क्योंकि इस खनन से काफी ग्राम पंचायतों का भू-जल खतरे में है और भूमि के भूगर्भ के अन्दर खनन हो रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधि व लोगों की मांग के बाद यह जिंक फुटबाल एकेडमी खोली गई।

यहां अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ट्रेनिंग करवाने के लिए आते हैं, इसका सारा खर्चा सीएसआर फण्ड से होता है लेकिन वर्तमान समय में इस एकेडमी में स्थानीय युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। वहां बैठे अधिकारियों के द्वारा मोटी रकम वसूलकर अन्य जिले व राज्य के युवाओं को मौका दिया जा रहा है। इस प्रकार स्थानीय युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि सीएसआर फण्ड संचालित जिंक फुटबाल एकेडमी जावर माइन्स में स्थानीय आदिवासी युवाओं का प्रवेश दिलाने का प्रावधान कर स्थानीय युवाओं को लाभ दिया जावे।

परिशिष्ट-02

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़)

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में आमजन को यातायात में हो रही परेशानियों के समाधान हेतु निम्नलिखित गांवों में नई सड़कें स्वीकृत करने की मांग करता हूं-

1. बच्छरारा से बीरमसर 6 किमी
2. गोरीसर से मालपुर 5 किमी
3. लधासर से गौरीसर 4 किमी
4. हरिपुरा से मालपुर 02 किमी
5. खारिया से बड़ा खुडेरा 5 किमी
6. भींचरी से खोतड़ी 5 किमी
7. फांसा से चारणवासी 2.5 किमी
8. भुखरेड़ी से किशनपुरा 2.5 किमी
9. सुलखनिया से बिराणिया प्याऊ तक 3 किमी
10. भुखरेड़ी से दीपसर 3 किमी
11. दीपसर से स्वामी की ढाणी 2 किमी
12. कनवारी से चारणवासी 4.5 किमी
13. हनुमानपुरा रोड से मकड़ीनाथ रेलवे स्टेशन तक 1.5 किमी
14. खुडेरा बड़ा से मोलीसर रेलवे स्टेशन तक 3 किमी
15. तोलियासर से खुड़ी 5 किमी
16. मालासी से राजियासर मीठा 9 किमी
17. सीतसर से खींचीवाला 4 किमी
18. मालासी से साण्डन 6 किमी
19. सांडन से जेठवा का बास 3 किमी
20. सांडन से बाटड़ानाउ 2 किमी
21. न्यामा से धानणी 2.5 किमी
22. सांडन डूंगरीमात से खारिया कनिराम 5 किमी

23. खुड़ी से न्यामा वाया भामुओं की ढाणी
24. रिणवां की ढ़ाणी वाया इकताई तलाई होते हुए डूंगरारा अगूणा 6 किमी
25. ढाणी रिणवां से कनवारी 6 किमी
26. बोथियाबास से जैतासर 9 किमी
27. पड़िहारा से धातरी 7 किमी
28. चुहास से मेगा हाईवे बीड़ छापर 5 किमी
29. बड़ाबर से लालपुरा
30. बड़ावर से छापर
31. राजपुरा से चुहास वाया निमड़ी
32. बिलासी से लोणा
33. भानीसरिया से खालिया 4 किमी
34. खालिया से निमड़ी 03 किमी
35. भोजलाई से बोबासर
36. गोपालपुरा से चाड़वास
37. पायली से भावनेदसर 5 किमी
38. आबड़सर से भरपालसर 5 किमी
39. परसनेउ से जेगणिया बीकान 8 किमी
40. आलसर से राजलदेसर 14 किमी
41. छाजूसर से रतनगढ़ 9.5 किमी
42. छाबड़ी खारी से भींचरी 3 किमी सड़क
43. छाबड़ी खारी से थेथलिया 3 किमी सड़क
44. तोलियासर से राजियासर सड़क
45. राजपुरा से पुरण भगत की ओरण तक 1.5 किमी सड़क
46. सेहला से जांदवा 3 किमी
47. सेहला से मोलीसर 3 किमी

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद)

शिक्षा विभाग में कई घोषणाएं हुई

1. शिवपुरा स्कूल क्रमोन्नत भवनों की व्यवस्था नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है। IDNFC योजना में भवनों की व्यवस्था की जावे।
2. जेठाना, रामसर सहित प्रदेश व जिले के ऐसे विद्यालय है जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोली जाए।
3. टीचर्स की भर्तियां की जावें तथा क्षेत्र में कालेज खोला जाए। मिड-डे मील की समीक्षा की जाए।

सड़कें :-

रामगढ़ से, बाबरा रोड मिसंग लिंक की सड़कें बनाई जाएं।

विकास पथ:-

श्रीनगर-अजमेर गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनें, PMGSY में प्रस्ताव जल्द लिए जाएं। पद खाली हैं इनको भरा जाए।

पेयजल:-

1. नसीराबाद वृहद् पेयजल योजना में रामसर पम्प हाउस के साथ ही प्रेशर बढ़ाया जावे।
2. जल जीवन मिशन में पेयजल योजनाओं का कार्य किया जावे।
3. ट्यूबवैल्स लगाने हैं।
4. Hand pumps के मेंटिनेस के लिए अलग बजट दिया जावे।
5. पानी की व्यवस्था की जावे।
6. स्टाफ की कमी।
7. पानी की लाइनों का मेटिनेंस Proper किया जावे।

खेलकूद :-

1. ग्रामीण खेल मैदानों का विकास हो, खेलों का आयोजन किया जावे।
2. District के ग्राउण्ड और खेल अधिकारी किये जावे।
3. जिस प्रकार पिछले बजट में खेलों' को बढ़ावा देने की बातें की गयीं, वह कहीं नहीं दिख रही। राजस्थान में विद्यार्थियों को खेल कूद के भत्तों एवं Sports Complex नसीराबाद बनाया जाए।

चिकित्सा :- निरोगी राजस्थान

1. ट्रोमा सेन्टर विकसित किया जाए।

2. डॉक्टरों की भर्ती की जावे एवं दूरस्थ इलाकों में नियुक्ति की जावे।
3. नि:शुल्क जांच योजनाओं में जांचें नहीं हो पा रही है।
4. चिरंजीवी योजनाओं में इलाज।
5. रामसर को जो CHC में क्रमोन्नत किया गया है, वहां शीघ्र भवन की व्यवस्था करें।
6. हॉस्पिटल की मेंटिनेंस एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जावे। CCTV cameras.
7. कोविड सहायकों को नियमित किया जावे, पीसांगन चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जावें।

अध्यक्ष महोदय,

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि संसदीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र दस्तावेज सरकार का यह बजट है, परंतु जिसको संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, संसदीय परम्पराओं पर विश्वास नहीं, उनकी आदत में शुमार हो जाता है कि सदन में 12 माह में 2 बार आओ, भाषण पढ़ो, भाषण पिलाओ और गायब हो जाओ।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में 15वीं विधान सभा एक रिकार्ड बनाने की ओर अग्रसर है जिसमें सदन के नेता सर्वाधिक कम समय के लिए विराजे।

सदन की गरिमा सदन के नेता की उपस्थिति में बढ़ती है पर शायद सदन के नेता को सदन की गरिमा से कोई सरोकार नहीं है।

मैं सदन में वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 की वो बजटीय घोषणाएं जो आज तक अधर में लटकी हैं, की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बजट वर्ष 2019-20 के पैरा 3 में आपने कहा-

"यकीन से आगे भी बढ़ना है
बहुत कुछ करके ऊंचाइयों पर चढ़ना है।
वो हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं
हम तो तूफानों से टकराकर कारवां चलाते हैं।"

न आप ऊंचाइयों पर चढ़े, न सर्द हवा में आपका दीपक जला, आपका कारवां तो तूफान से नहीं, अपनों से टकराकर चकनाचूर हो गया।

में सदन का ध्यान विगत 3 वर्ष में की गई 66 बजटीय घोषणाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगाः

2019-20	-	26
2020-21	-	14
2021-22	-	26

अध्यक्ष महोदय,

पैरा 31- आपने पहले बजट में प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदी-शालाओं की स्थापना की घोषणाएं की व विधान सभा के इसी सत्र में चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य के प्रत्युत्तर में सरकार ने स्वीकार किया कि अब तक यानी फरवरी 2022 तक राजस्थान में एक भी नंदी गौशाला स्थापित नहीं हुई। यह घोषणा सरकार का आईना दिखाती है।

पैरा 36- 01 लाख से अधिक कुल वाहन भार वाले समस्त फिजिबल रेलवे फाटकों पर रेलवे मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2019-20 में 2 ROB व 32 RUB बनाये जाने की सरकार की घोषणा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही।

पैरा 39- सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में समस्त ग्राम पंचायतों में विकास पथ यानी 10 हजार किमी लम्बाई की सड़कें नाली सहित बनाने की घोषणा तो कर डाली लेकिन विकास पथ राज्य की कितनी पंचायतों में हैं?

पैरा 50- कृषि कनेक्शनों के पृथक् फीडर की स्थापना हेतु 5 हजार 200 करोड़ की योजना में से 1 फूटी कौड़ी भी दी है तो बताओ।

पैरा 52- शहरी क्षेत्रों में एनर्जी आडिट के लिए 80 हजार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर की घोषणा हवा-हवाई हो गई।

पैरा 56- राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना द्वारा 22,831 हैक्टेयर सेम क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिये 207 करोड़ का प्रावधान तथा पाकिस्तान जा रहे पानी को रोकने की योजना दूरबीन से भी दिखाई नहीं दे रही।

पैरा 60- IGNP के दूसरे चरण में नाबार्ड के सहयोग से 179 करोड़ के प्रावधान तथा शहीद बीरबल शाखा प्रणाली में 368 किमी लम्बाई के कार्यों से जैसलमेर तहसील के 25 हजार किसानों को अब तक कोई फायदा नहीं मिला।

पैरा 61- तारानगर सहित 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं विकसित करने के वादे का क्या हुआ?

पैरा 63- फ्लोराइड प्रभावित 1250 नये गांव-ढाणियों में सौर ऊर्जा चलित डीफ्लोरीडेशन यूनिट का क्या हुआ?

पैरा 64- 200 करोड़ रुपये की लागत से सौर ऊर्जा चलित टैंक सहित ट्यूबवैल का कार्य आज भी अधर में है।

पैरा 77- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया होता तो आज उद्यमी आर्थिक संकट में नहीं होते। इसके लिए वर्ष 2019-20 में 50 करोड़ व अगले 5 वर्षों में 250 करोड़ का प्रावधान तो कर दिया लेकिन इसमें से अब तक कितनी राशि खर्च हुई, अपने भाषण में उल्लेख कर दें तो बेहतर होगा।

पैरा 81- 'राजस्थान एम-सेंड नीति 2019' कागजों से बाहर भी निकली है क्या?

पैरा 88- जयपुर मैट्रो द्वितीय चरण की 13 हजार करोड़ लागत वाली संशोधित DPR का कार्य कब पूरा हुआ?

पैरा 92- उदयपुर शहर में ट्रैफिक समस्या के निस्तारण हेतु DPR बनाने व 50 करोड़ का कार्य नहीं होने से आमजन परेशान है।

पैरा 94- जोधपुर शहर में महामंदिर पावटा रोड, सोजती गेट होते हुए आंखलिया चौराहे तक एलिवेटेड रोड की DPR व जोजरी नदी से पहले ROB की DPR बनाने की घोषणा की हकीकत जनता जान चुकी है।

पैरा 95- मोहल्ले/गली में जनता क्लिनिक की घोषणा पर अमल होता तो आज आमजन को इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़तीं।

पैरा 106- प्रत्येक गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान सिर्फ प्लान बनकर रह गया है, धरातल पर नहीं आया।

पैरा 111- मानसिक रुग्णता वाले लोगों के पुनर्वास हेतु जयपुर-जोधपुर में 50-50 क्षमता के हाफ-वे-होम की घोषणा अभी तक बजट में ही है इससे बाहर नहीं निकली।

पैरा 113- जयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने की सच्चाई का पता तो घर से विधान सभा आने के दौरान ही चल गया कि जगह-जगह समूह में भिक्षा मांगने वाले गिरोह सड़क पर थे।

पैरा 120- एक हजार करोड़ की प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि में से कितनी राशि महिलाओं के सशक्तिकरण में खर्च कर डाली?

पैरा 133- मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना 'हुनर का हर हाथ, रोजगार नहीं मिलने से अपराध के साथ' को चरितार्थ कर रहा है। 1 लाख युवाओं को 1 लाख के ऋण देने की घोषणा के बाद सरकारी तिजोरी से ऋण के पेटे कितने पैसे दिये?

पैरा 148- क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित मुखिया जी शायद पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के गठन व नई जलवायु नीति की घोषणा को भूल गये।

पैरा 149- घोषणावीर मुख्य मंत्री जी के शासन में जयपुर में न हैरिटेज वाक-वे रहा, न नो-व्हीकल जोन बन पाया।

पैरा 152- पंडित जवाहर लाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी राजस्थान के गठन की स्वीकृति के अलावा कुछ काम नहीं हुआ ।

पैरा 158- थानों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक थाने में सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगाए गए कि जवाहर सर्किल थाने में हिरासत में अंकित त्यागी की मौत हो गई। इससे पूर्व न जाने कितनी ही बार थाने में परिवादी की अस्मत लूटी गई लेकिन फिर भी यह घटनाएं कैमरे में कैद नहीं हुई। वाह रे घोषणावीर सरकार!

पैरा 169- राजस्व कानून में संशोधन कर निस्तारण प्रक्रिया को इस कदर सरलीकृत किया कि आज लाखों प्रकरण राजस्व न्यायालय में लम्बित पड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय,

बजट 2020-21 की अधूरी बजटीय घोषणाओं का बिन्दुवार जिक्र करूं तो:-

पैरा 11- 100 करोड़ रुपये के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन की घोषणा तो कर डाली लेकिन आज तक दिशा-निर्देश अलग से जारी नहीं किये।

पैरा 13- राज्य के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो तथा वह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके, मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाये जाने के लिए 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' के लिए पृथक् से अथोरिटी बनाने की घोषणा की क्या स्थिति है?

इसी बजट 2022-23 के पैरा 23 में भी आपने प्रदेशवासियों को मिलावट रहित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' कार्य को मूर्त रूप देने के लिए Directorate of Food Safety के अधीन 200 नये खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों के सृजन की घोषणा कर डाली जबकि Directorate of Food Safety का अता-पता तक नहीं और अब पूर्व में घोषित 7 Food Safety Labs का कार्य शीघ्र पूर्ण करते हुए आगामी वर्ष में 10 नई Mobile Food Safety Labs संचालित किया जाना प्रस्तावित कर दिया जबकि धरातल पर कुछ होना नहीं है।

मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में लैब का गठन अधर में है।

मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्यवाही के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी घोषणाओं पर अमल होता तो आज प्रत्येक नागरिक तक शुद्ध भोजन पहुंचता व मिलवाटखोरों में भय होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

पैरा 25- SMS Hospital Jaipur में G+8 मंजिला नया आईपीडी भवन का काम दो वर्ष तो दूर, इसी कछुआ चाल से चला तो 5 वर्ष में पूरा नहीं होगा।

पैरा 29- 18 करोड़ रुपये की लागत से अजमेर-जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय क्या बनकर तैयार हो गया? हां तो कितने विद्यार्थी अध्ययरत हैं?

पैरा 56- 100 करोड़ रुपये के नेहरू बाल संरक्षण कोष से बच्चों की तस्करी व बाल मजदूरी कब रुकी तथा अब तक कितना व्यय किया?

पैरा 65- जनजाति क्षेत्र में संचालित सरकारी आवासीय विद्यालय एवं जनजाति छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों के लिए पृथक कैडर की घोषणा का क्या हुआ?

पैरा 99- कम्प्यूटर शिक्षक कैडर के गठन की घोषणा तो युवाओं पर लाठियां भांज-भांजकर आधी अधूरी ही करी।

पैरा 110- बजट 2019-20 के पैरा 72 में भी की गई चम्बल भीलवाड़ा के आरोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़कर बूंदी जिले के हिण्डौली सहित शेष रहे क्षेत्र को पेयजल पहुंचाने की डीपीआर बनने

के बाद इस 970 करोड़ की परियोजना से बूंदी जिले के कितने गांव ढाणियों को लाभान्वित किया?

पैरा 113- राजसमंद जिले की भीम क्षेत्र हेतु भीलवाड़ा की चंबल पेयजल परियोजना से पानी पहुंचाने की योजना के परीक्षण की डीपीआर, इसके क्रियान्वयन का कोई अता-पता नहीं।

पैरा 118- प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ग्रीन एनर्जी सिटी की घोषणा कौन-कौनसे जिला मुख्यालय में पूरी की?

पैरा 122- राज्य के सभी किसानों को 3 वर्ष में दिन के 2 ब्लाक में कृषि हेतु विद्युत उपलब्ध कराने पर 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें 220 केवी के नये 6 जीएसएस, 132 केवी के 30 नये जीएसएस, 33 केवी के 287 नये सब-स्टेशन बनाना निर्धारित था, अगर इन पर घोषणा के अनुसरण में खर्च किया होता तो आज किसानों को विद्युत समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।

पैरा 126- चूरू तारानगर सड़क (चौड़ाईकरण) जिला चूरू में 16 करोड़ में से एक रुपया भी खर्च नहीं किया जिससे आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

पैरा 137- बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के अंतर्गत बीसलपुर, माही, जवाई, माखम, सोम कमला अम्बा, छापरवाड़ा, मातृकुण्डिया, गम्भीरी, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर व कोटा बैराज सहित 18 बांधों का जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण का कार्य 503 करोड़ रुपये से करवाये जाने की घोषणा आप भूल ही गए।

पैरा 162- 10 करोड़ रुपये के प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष से श्रमिकों का कल्याण तो नहीं, लेकिन अपनी नीतियों से बंटाधार जरूर कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय,

इसी क्रम में बजट 2021-22 की थोथी बजटीय घोषणाओं का बिन्दुवार जिक्र करूं तो:-

पैरा 6- शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर और सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के लिए घोषित आपकी 'इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना' का क्या हुआ? जमीनी स्तर पर फिसड्डी साबित हुई इस योजना में 5 लाख जरूरतमंदों में से कितने को 50 हजार रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया?

पैरा 9- Rajasthan Model of Public Health लागू करने, सबको स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगां का वादा धूलदर्शित साबित हुआ। Right to Health Bill की घोषणा सिर्फ घोषणा ही बनकर रह गई। धरातल पर देखें तो अस्पताल इलाज करने से आनाकानी करते हैं।

पैरा 10- बजट 2021-22 के में 3 हजार 500 करोड़ रु की लागत से यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज की घोषणा **बजट 2022-23 के पैरा संख्या 7** में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने एवं चिरंजीवी कार्ड नहीं होने पर भी जिला कलेक्टर के माध्यम से निःशुल्क इलाज करने की घोषणा तो सरकार ने कर डाली लेकिन निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के नाम पर लूटखसोट चल रही है उस पर सख्त कदम उठाये जाने के बारे में कुछ नहीं कहा।

पैरा 12- राजस्थान के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर 'पब्लिक हैल्थ कालेज' की स्थापना की घोषणा का क्या हुआ? घोषणा को जमीन स्तर पर कब तक लाएंगे?

पैरा 16- राज्य में एक हजार आयुर्वेद औषधालयों को health and wealth center के रूप में विकसित की घोषणा तो थोथी व असत्य ही साबित हुई।

पैरा 21- कोविड महामारी के अनुभव को देखते हुए एक ही छत के नीचे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डिप्थीरिया, दिमागी बुखार, स्वाइन फ्लू, कोविड इत्यादि बीमारियों की जांच, उपचार और रिसर्च के लिए जयपुर में Institute of Tropical Medicine and Virology की स्थापना तथा 50 करोड़ की लागत से जयपुर में राष्ट्रीय स्तर के Institute of Cardiology की स्थापना का क्या हुआ?

पैरा 24- राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों से जुड़े अस्पतालों में जीवनरक्षक उपकरणों से युक्त 22 Advance life Support (ALS) क्रिटिकल एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की घोषणा क्या पूरी हो गई तथा जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर तथा झालावाड़ में 25 करोड़ रुपये की लागत से कितने ट्रोमा सेंटर विकसित किये गये?

पैरा 38- राजस्थान में विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने की घोषणा का धरातल पर क्या हुआ?

पैरा 43- महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइंस की स्थापना का तो कहना ही क्या।

अब बजट 2022-23 के पैरा 30 के बिन्दु संख्या 1 में भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया।

यह वो ही संस्था है जिसने राजीव गांधी स्टडी सर्किल को 80 करोड़ रु. दिये। इसी के जरिये रीट की चीट की पूरी साजिश राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े किरदारों ने रची थी।

पैरा 47- तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जोधपुर में 400 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रस्तावित फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा का क्या हुआ?

पैरा 58- समान पात्रता परीक्षा लागू करने की घोषणा तो सरकार भूल ही गई।

पैरा 63- 40 करोड़ रु. की लागत से एसएमएस स्टेडियम जयपुर में High Performance Training and Rehabilitation Centre की स्थापना कब पूरी होगी?

पैरा 66- 5 करोड़ की लागत से यूथ हॉस्टल जयपुर को यूथ एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा का क्या हुआ?

पैरा 72- कृषि जिंसों एवं उनके प्रोसेस्ड उत्पादों के व्यवसाय व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क की घोषणा के क्रम में कितने जिलों में इसकी स्थापना की गई? साथ ही मथानिया-जोधपुर में 100 करोड़ के मेगा फूड पार्क कहीं पर नजर नहीं आ रहा है।

पैरा 95- राजस्थान के औद्योगिक परिवेश के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की 'Greater Bhiwadi Industrial Township' के अन्तर्गत अलवर में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, टपूकड़ा व आसपास के क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित करने की थोथी घोषणा की गई जबकि एक भी पत्थर वहां नहीं लगा।

पैरा 98- जयपुर में Fintech Park (Financial Technology Park) की घोषणा हवा-हवाई हो गई।

पैरा 99- जोधपुर में 5 करोड़ की लागत वाले Biotech Pharma Business Incubation & Research Centre की घोषणा भी झूठ का पुलिंदा ही रही।

पैरा 112- 8 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन जो मेरे गृह जिले चूरू में भी बनना प्रस्तावित था, भूमि तक आबंटित नहीं हुई।

अब बजट 2022-23 के पैरा 68 के बिन्दु संख्या 1 में चूरू, सवाईमाधोपुर, नागौर, फतेहपुर-सीकर एवं ब्लाक तिजारा-अलवर, घड़साना-श्रीगंगानगर व सम-जैसलमेर में 180 करोड़ की लागत से 7 अल्पसंख्यक बालक-बालिका आवासीय विद्यालयों भवनों का निर्माण की घोषणा कर डाली। घोषणा दर घोषणा के बाद भी धरातल पर कुछ नहीं।

पैरा 122- प्रदेश के 7 संभाग मुख्यालयों में समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों से बच्चों में नशे की प्रवृति को रोक पाने में सरकार कितनी सफल हुई?

पैरा 134- वर्ष 2021 से 2026 तक की अवधि हेतु नवीन राज्य सड़क नीति-2021 की घोषणा के वादे का क्या हुआ?

पैरा 142- सीकर चूरू रेलवे खण्ड पर पूर्व समपार फाटक सं. 32 पर 1 करोड़ 62 लाख रुपये के RUB की आमजन बाट जोह रहे हैं।

पैरा 161- 40 करोड़ रुपये से बीकानेर शहर में गोगा गेट सर्किल से भीनासर ट्रैफिक चौकी तक एवं म्यूजियम सर्किल से हल्दीराम प्याऊ तक 4 लेन सड़क को 6 लेन करने तथा पुगल फांटे से ROB तक सड़क विस्तारीकरण की घोषणा की क्रियान्विति शायद ही इस शासन में हो सके।

पैरा 165- जोधपुर में 60 करोड़ की लागत से 1500 बैठक क्षमता का आधुनिक आडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर के कार्य का क्या हुआ? अभी तक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई प्रोग्राम हुआ क्या?

पैरा 202- तालछापर अभयारण्य चूरू में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र की घोषणा को अमलीजामा पहनाने में इतनी देरी क्यों? चूरू के साथ सौतेला व्यवहार क्यों?

पैरा 217- जैसलमेर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ढोला मारू Tourist Complex इसमें Rajasthan Folk Art Training Institute की स्थापना के लिए 10 करोड़ में से कितनी राशि खर्च की गई व कब बनकर तैयार हुआ?

पैरा 254- 50 करोड़ रु. की लागत वाले Centre for Excellence for Revenue Research and Analysis की स्थापना की घोषणा के अनुसरण में अब तक क्या हुआ?

पैरा 288- प्रदेश में हथकढ शराब बनाने में लिप्त परिवारों की

नशामुक्ति, पुनर्वास, उनके बच्चों को शिक्षा तथा रचनात्मक कार्यों के लिए 100 करोड़ के नवजीवन कोष से एक भी फूटी कौड़ी खर्च नहीं की?

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा)

सभापति महोदय,

आपने बजट पर बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

राजस्थान की सरकार ने बजट पेश किया जो दिशाहीन है। विकास को बढ़ाने वाला नहीं है। आपने इस बजट के माध्यम से अनेकों घोषणा की हैं, परन्तु पूर्व के बजटों में की हुई घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं किया है। परन्तु इस बजट में विपक्ष को (हमें) नजरअंदाज किया है। यह सरासर हमारे क्षेत्र के साथ अन्याय किया है। आपकी मनमर्जी है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें भी जनता ने वोट दिये। वो काफी उम्मीद करते हैं।

1. आपने पिछले बजट में मेरी विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सूरतगढ़ रोड अमरपुरा के पास RO B की घोषणा की थी।
2. पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर नंदीशाला व विकास पथ की घोषणा की थी परन्तु घोषणा पूरी नही हुई।
3. मोहल्लों व वार्डों में जनता क्लीनिक, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात की थी।

सड़क

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीलीबंगा रावतसर व गोलूवाला तीनों ही हाईवे पर स्थित हैं जिसके कारण शहर में पूरे दिन बड़े वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है तो इन तीनों क़स्बों के लिए बाईपास की मांग करता हूं।

किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे बहुत काफ़ी सालों से री-कारपेट नहीं हुआ है पूरी हाईवे पर गड्ढे ही गड्ढे हैं लेकिन फिर भी टोल वसूला जा रहा है, जब तक उसको पूर्णतः री-कारपेट नहीं कर दिया जाता तब तक उस सड़क पर टोल वसूलना बंद करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जिनको चौड़ी करना अत्यन्त आवश्यक है जैसे-

1. डिंगा से भागसर 26 PBN सूरतगढ़।
2. रावतसर से जाखडोंवाली होते हुए सूरतगढ़ तक।
3. चाइया से होते हुए गंधेली लालपुरा नोहर तक।
4. धन्नासर कैंची से होते हुए हरदासवाली थर्मल सूरतगढ़ तक इस सड़क पर तो पूरे दिन बड़े ट्रक धर्मल तक जाते हैं।
5. गोहर वाला से उम्मेवाला श्रीगंगानगर रोड तक।
6. मक्कासर से भाम्भूवाली ढाणी यालकी पीलीबंगा गोलूवाला रोड तक।

गांवों में जो सड़कें PWD व कृषि विपणन बोर्ड से बनाई गई थीं, बनने के बाद आज तक वो सड़कें री-कारपेट नहीं हुई तो सड़कों को सुधाराजाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण ROB व RUB भी हैं जो सरकार को बनाने चाहिए जैसे;-

रावतसर पीलीबंगा हाईवे पर ROB

अहमदपुरा अमरपुरा व रामपुरा रंगमहल दोनों फाटकों पर RUB

PHED (पेयजल की बात करें)

जल जीवन मिशन 50%+50% परंतु आपने 10%+40% कर दिया इसमें आबादी वाले चक व गांव जोड़ने का तो काम चल रहा है परंतु जो ग़ैर आबादी चक जहां लोग अपने खेतों में ढाणियां बना कर रह रहे हैं वे अभी भी खेत में लगने वाले सिंचाई पानी ही पी रहे हैं जो कि दूषित है तो गैर आबादी चकों को भी JJM में जोड़ा जाए।

रावतसर शहर में KWD नहर के माध्यम से पानी आता है जो कि खुले नाले के माध्यम से आता है जहां उद्योग भी हैं तथा वहां रहने वाले जो श्रमिक हैं वे उस खुले नाले में कपड़े धोते हैं तथा आए दिन उसमें आवारा पशु गिर जाते हैं जिससे पानी दूषित होता है तो रावतसर शहर को शुद्ध पेयजल देने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाया जाए।

आपणी योजना (पेयजल योजना है) मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव धन्नासर में है, इस योजना के बनने के बाद आज तक किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं हुआ यहां तक कि जिन आबादी क्षेत्रों में इस योजना द्वारा पहले से पेयजल पहुंचाया जा रहा है उसमें सभी लोगों को इस योजना से पेयजल नहीं मिल रहा है। इसलिए जहां-जहां आपणी योजना द्वारा पेयजल सप्लाई किया जाता है वहां वहां पर SR बनाए जावें व गांव और ढाणियों को इस योजना से जोड़ा जाए।

क़स्बा रावतसर में वार्ड नं. 10 में तो ये हालात हैं कि पिछले 5-6 महीनों से गटर का पानी सप्लाई हो रहा है जहां नई पाइपलाइन डालना भी प्रस्तावित है परंतु अभी तक नहीं डाली गई।

शिक्षा:-

शिक्षा की बात की जाए तो सरकार ने इस मामले में पूर्णतः भेदभाव किया है-

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो उपखण्ड हैं एक उप तहसील है परंतु बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। सरकार ने अपने पार्टी के विधायकों को तो रेवड़ियां बांट दी, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को वोट पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में भी मिलते हैं लेकिन अब वे वोट घट जाएंगे क्योंकि आपने पीलीबंगा के बच्चों के साथ व हमारे साथ अन्याय किया है। इसलिए मैं पीलीबंगा, रावतसर, गोलूवाला व डबली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं।

आपने महात्मा गांधी स्कूल खोलने की बात कही। मैं विधान सभा की बात करूं तो आपने पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में दो जगह अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल खोले। एक तो पीलीबंगा गांव जहां पूरा 12वीं तक चलते हुए स्कूल को खतम कर दिया। आप पीलीबंगा शहर में खोलते और दूसरा स्कूल आपने रावतसर के सीनियर स्कूल को खतम करकर खोलना चाहा परंतु वहां रोष उत्पन्न हो गया तथा उसको अन्य जगह खोला गया और जहां खोला गया वहां पूरे कमरे तक नही हैं। आप पहले उन स्कूलों को तो सम्भालें फिर नए खोलते।

कई राजकीय स्कूल तो ऐसी हैं जहां शौचालय नहीं है। यदि है तो टूटे-फूटे हैं, कमरे नहीं हैं तो आप सुविधाओं की पूर्ति करें।

कुछ निजी स्कूलों में आर.टी.ई. का भुगतान नहीं किया गया। वे दफ्तरों के चक्कर काट रहें हैं।

चिकित्सा व्यवस्था

मेरे द्वारा आदर्श CHC पीलीबंगा की अनुशंसा की गई थी परंतु आज तक उस पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

आदर्श CHC में विधायक कोष से 01 करोड़ की अनुशंसा की है परंतु उसमें भी राजनीति की जा रही है। उन पैसों को वहां पर लगने नहीं दिया जा रहा है। .

पीलीबंगा CHC जर्जर हालात में है। वहां चिकित्सकों व कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था तक नहीं है तो सरकार इस पर ध्यान दे।

पीलीबंगा, गोलूवाला, डबली CHC के स्टाफ़ व बैड बढ़ाकर उसको क्रमोन्नत किया जावे।

वर्ष 2018 में चयनित 1041 पदों पर ANM को आज तक नियुक्ति नहीं दी गई है जबकि माननीय न्यायालय ने भी अभ्यर्थियों के पक्ष में फ़ैसला कर दिया है।

कोविड-19 की असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने कोविड सहायक नियुक्त किए जिन्होंने जान पर खेलकर इन विकट परिस्थितियों में अच्छा काम भी किया परंतु सरकार ने इनका शोषण किया क्योंकि 31 मार्च के बाद इनको हटा दिया जाएगा तथा अभी तक इनको वेतन भी नहीं दिया गया तो सरकार सम्पूर्ण वेतन का भुगतान करे तथा इनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाए।

सिचाई में भी आपने भेद भाव किया

भाखड़ा व IGNP में पक्के खालों का निर्माण प्रथम चरण में होना था आपने जैसलमेर में खालों को पक्का करने के लिए बजट में घोषणा की अच्छी बात है परंतु यह हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के साथ अन्याय है। यहां खाले स्वर्गीय भैरोंसिंह जी के समय में पक्के हुए थे जो आज जर्जर हैं। उनको पुन: बनाये व भाखड़ा नहर व इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र नये खाले बनाए जावें।

IGNP व घग्घर बहाव क्षेत्र में पुल जैसे लखुवाली हनुमानगढ़, 84 RD मोधुनगर, 99 RD, 108 RD खोडां रावतसर से जाखडांवाली रास्ते पर GDC (घग्घर नदी), पुल ये पुल बहुत ही क्षतिग्रस्त अवस्था में है यदि सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित ही कोई बड़ा हादसा होगा। ये पुल बनाए जाएं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जो मात्र ही 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है परंतु काजवे नहीं होने के कारण उनको 15 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है जैसे 29 STG से पीलीबंगा, लुढ़ाना से अमरपुरा, 3 SPD खेदासरी से भैरूसरी, बड़ोपल से भोजासर यहां काजवे बनाने की सरकार से मांग करता हूं।

एक महत्वपूर्ण बिंदु : आपणी योजना में पेयजल रावतसर ब्रांच द्वारा आता है इसमें पानी रावतसर ब्रांच से बंद करके इसको सीधा IGNP से बंद पाइप से या कुंभाराम लिफ़्ट योजना से या साहवा लिफ़्ट परियोजना से पानी दिया जावे क्योंकि आपणी योजना में पानी 100

से 150 क्यूसेक चलता है जिसके कारण नहर में जाला व सिल्ट जमा हो जाती है तथा टेल पर जो किसान है वह सिंचाई के पानी से वंचित रह जाता है अतः आपणी योजना को रावतसर ब्रांच से अलग किया जावे।

एटा सिंगरासर माइनर आपने अपनी पिछली सरकार में घोषणा की थी कि DPR, आज तक कुछ नहीं हु आ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है आपने बंजर भूमि सुधार के लिए भी कुछ नहीं दिया। मेरा विधान सभा क्षेत्र 1980 से लगातार सेमग्रस्त क्षेत्र है, सेम के कारण कृषि भूमि दलदल हो गई है परंतु सेम नाले की खुदाई के कारण सेम के पानी से मुक्त हो गई परंतु वह लवणीय है व बंजर भूमि बन चुकी है। उस पर कृषि नहीं हो सकती। वहां के किसान असहाय व आर्थिक दृष्टि से टूट चुके हैं। उस बंजर भूमि को सुधारने का उनके पास कोई समाधान नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहाँ के किसानों को भूमि सुधार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए व उन किसानों को बीज व कृषि उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाए ताकि वे भी अपना जीवन सही से यापन कर सके। यदि बंजर भूमि में सुधार होता है तथा फिर से उस भूमि पर कृषि होना शुरू हो जाये तो सरकार की टैक्स से आमदनी भी बढ़ेगी।

गोलूवाला को नगरपालिका बनाई जावे।

गोलूवाला स्थागान गोलूवाला निवादन दोनों पंचायतें साथ-साथ हैं। धानमण्डी है। उप-तहसील है। पुलिस थाना C.H.C.- कृषि उपज मण्डी दोनों पंचायतों की आबादी नगरपालिका बनने का मापदण्ड पूर्ण करती है। मैं गोलूवाला को नगरपालिका बनाने की मांग करता हूं।